भाग्त में पद्मायनी राज लगभग उतना ही पुराना है जितना स्वय भाग्त । लेकिन आज हमारे गॉब-गॉब में जो पद्मायते हैं, वे एक अलग और सर्वथा नधी कहानी है। ग्राम. व्लॉक और जिला—इन तीन मस्तरों पर देश भर में फैली हुई इन पद्मायता की स्वतंत्र सर्वधानिक सत्ता है। इसे भारतीय राज्य का तीसरा पाया कहा जा सकता है, जिसकी जरूरत 1990 के आसपास इसलिए बहुन ही नीव्रता से महसूस की गयी कि जनता की वुनियग्दी आवश्यकनाएँ पूरी करने के लिए सिर्फ केंद्र और गान्य सरकारों पर परप्रगणन निर्मरता की सीमाएँ उस समय

नक उजागर हो चूकी थीं ओर सत्ता के विकेदीकरण के अलावा

काई ओर उपाय नहीं रह गया था।
तिहतरवे संविधान संशोधन को लागू हुए एक दशक बीत
चला है। प्रश्न यह है कि क्या इस लक्ष्य को हम किसी बड़ी
मीमा तक हासिल कर पाये हैं, जो इस दूसरी लोकतांत्रिक काति
के तंवैधानिक स्वप्न के केंद्र में था? उत्तर मिला-जुला है।
एचायनी राज के माध्यम से गाँव के स्तर पर एक मोन क्रांति
का सूत्रपान हो चुका है। सत्ता के जमीनी स्तर के प्रयोग में
महिलाओं, दिलतों और आदिवासियों को वांछित स्थान मिल
गया है। लगभग सभी राज्यों में पंचायतों के चुनाव नियमित
अनराल पर होने लगे है। बहुत-सी पचायतों में लोक सत्ता अपने
को अभिव्यक्त भी कर रही है। यचायती राज की सफलता

कथाएँ देश के विभिन्न कोनों से सुनाई पड़ने लगी है। तेकिन किस्सा यह भी है कि सभी कुछ ठीक-ठाक नहीं है। ग्रामीण भारत की परपरागत सत्ताएँ इस नये लोकताबिक निजाम को स्वीकार करने के मृह में नहीं है। छल और वंचना के विभिन्न प्रपचों से नथा जसरत पड़ने पर प्रत्यक्ष हिसा के डारा भी वे पंचायत राजनीति के नये खिलाडियों को दबाने और कुचलने में लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा अफसोम और चिता की बात यह है कि राज्य सरकार नहीं चाहतीं कि ये स्थानीय सरकार भी नरह-तरह से पचायती राज को शक्तिहीन करने की कोशिश कर रही है। इस निर्णायक मुकाम पर 'पंचायती इच्छाशन्ति ही कोई बड़ा कमाल कर सकती है।

भारत में पचायनी राज के स्वप्न, परियोजना और कमजोरियों का यह प्रखर लेखा-जोखा देश के अनन्य समाजविज्ञानी डॉ. जॉर्ज मैध्यू ने तैयार किया है। पचायती राज ओर विकेटीकरण के प्रति उनका जैसा अगाध लगाव है और इस क्षेत्र में सिद्धात और व्यवहार, दोनो स्तरों पर जितनी निग्तग्ता और गहराई से उन्होंने कार्य किया है, उसे देखते हुए यह काम उनसे बेहतर और कौन कर सकता था?



j.

भगन म पचायना गज ल भारत । नेकिन आज हम अलग और सर्वधा न जिला-इन तीन सस्तरी की स्वत्त्र संवैधानिक र पाञा कहा जा मकता है इसलिए वहुत ही नीवर व्नियावी आवश्यकता। राज्य सरकारो पर परप तक उजागर हो चुकी बं कोई ओर उपाय नहीं

तिहत्तरदे संविधा चला है। प्रश्न यह है

सीमा तक हासिल वर

कं संवैद्यानिक स्वप्न पचायती राज के माध क्न सूत्रपात हो चुका

महिलाओ, दतिनों औ गवा है! लगभग सर्भ अतराल पर होने लगे हैं

को अभिव्यक्त भी व कथाएँ देश के विभि लेकिन किस्सा है। ग्रामीण भारत की

निजाम को स्वीकार : क विभिन्न प्रपचीं रे द्वारा भी वे पचायत

और कुचलने में लगी की बात यह है कि मरकार उनकी सत्ता

मरकार भी तरह-तः की कांशिश कर रहें इच्छाशक्ति' ही को भारत में पंच

कमजारियों का ब

समाजविज्ञानी डॉ २ और विकेंद्रीकरण व इस क्षेत्र में निद्धा निरनग्ता और गह

हुए यह काम उनर **जाक्ल चित्र** सर्के

भारत में पंचायती राज परिप्रेक्ष्य और अनुभव

भित्र रामगीहत राय नायवेरी फाउन्हेण्य भित्रकृता के मोजन्य से प्रान्त भारत म प्रचायना राज भारत । लेकिन आज ह अलग और सर्वथा जिला—इन तीन सस्त की स्वतंत्र सर्वधान्कि पाया कहा जा सकता इसलिए बहुन ही ती बुनियादी आवश्यकत गान्य सरकारों पर प तक उजागर हो चुकी काई और उपाय नह

तिहत्तरवं संविध्याना है। प्रश्न यह हैं सीमा तक हासिल के के संवैधानिक स्वप्पंचायती राज के मा का सूत्रपात हो चुक महिलाओं, दिलतों गया है। लगभग स अत्रयल पर होने लगे को अभिव्यक्त भी कथाएँ देश के विं

लेकिन किस्स है : ग्रामीण भारत र निजाम का स्वीका के विभिन्न प्रपचीं द्वारा भी वे पचाय और कुचलने में ला की बात यह है वि सरकार उनकी स मरकार भी तरह-को कोश्निश कर इच्छाजिना है। र भारत में

भारत न कमजोरियों का समाजविज्ञानी डॉ और विकेंद्रीकरण इस क्षेत्र में सिः निरतरना और ' हुए यह काम



अरुणोदय प्रकाशन

दिल्ली-110092

भारत में पंचायती राज परिप्रेक्ष्य और अनुभव

जॉर्ज मैथ्यू

भागत । तिकेन आज व्य अन्य ओर सर्वया : अन्य ओर सर्वया : जिना—इन तीन मस्तरें की स्वनत्र संवैधानिक पाया कहा जा सकता इसिलए बहुन ही तीइ बुनियादी आवश्यकत राज्य सरकारों पर पर तक उज्ज्यार ने चुकी कोई और उपाय नहें

तिहल्तर्ये सिविष् इला है। प्रश्न यह है मीमा नक हासित के के संवैधानिक स्वष् पचायती राज के मा का सूजपान हो चुव महिलाओं, दितितों ग्या है। लगभग ह जनराल पर होने लग् को अभिव्यक्त भी कथाएँ देश के वि

तिक्षन किस है। ग्रामीण भारत निजाम को स्वीका के विभिन्न प्रपंची छारा भी वे पंचाय और कुचलने में त की कात यह है वि सरकार उनकी स सरकार भी नरह की कोशिश कर इच्छाशिक्त' ही

भारत में कमजोरियों का समाजविज्ञानी ड और विक्ट्रीकर इस क्षेत्र में सि निरतरता और हुए यह काम ISBN 81-8143-048-4



अरुणोदय प्रकाशन सी-191, आनन्द विहार, दिल्ली-110092 द्वारा प्रकाशित

> प्रथम संस्करण - 2003 © लेखकाधीन

मृन्य . 300.00

शुभम् ऑफसेट, शाहदरा, दिल्ली-110032

मे मुद्रित

PANCHAYATI RAJ IN INDIA Perspectives and Experiences by George Mathew

विषय सूची

परिप्रेक्ष्य		
1.	एक सिहावलोकन	11
2	राज्य तंत्र का पुनर्गठन	52
3.	गणराज्य और लघु गणराज्य	68
4.	खाद्य सुरक्षा एवं पंचायती राज	73
5.	जनसंख्या स्थिरता के लिए जन सत्ता	81
6.	परिवार कल्याण के उचित उपकरण	95
7.	ग्राम सभा और सामाजिक अकेक्षण	100
8.	विकेंद्रीकरण, सरकार और स्वयसेवी क्षेत्र	108
9.	पंचायतों के लिए स्वयंसेवक	122
ιο.	मानवाधिकारों के रू-ब-रू	127
11.	एक कदम आगे, दो कदम पीछे	150
12.	मीडिया की नजर	157
3.	भविष्य पर मॅडराते ग्रह	161
_	ुभव	
4.	दो पंचायतों की कहानी	169
5.	मेलावलावु का मतलब	178
6.	शोषित वर्ग के लिए मायने	183
7.	पचायतों के बगैर गुजरात	205
.8.	महाराष्ट्र का ग्राम सेवक राज	210
9.	नायडू को पंचायतें नहीं चाहिए	216
20.	स्थानीय लोकतत्र के लिए बेताब कश्मीर	221
) 1	पंचायती राज के दश्मन	226

भारत म प्रचायता ग भारत । लेकिन आउ अनग और सर्वय जिला-इन दीन स की स्वतंत्र संवैधानि णचा कहा जा सब इसनिए बहुत ही बुनिदादी आवश्य राज्य सरकारों पर नक उजागर हो च कोई और उपाय तिहत्तरवे स चला है। प्रश्न य सीमा तक हासिन कं मंबेधानिक र पंचायती राज के का सूत्रपात हो महिलाओं, दति गया है। लगभग अतराल पर होने को अभिव्यक्त कथाएँ देश के लेकिन दि

है। ग्रामीण भा निजाम की स्वी के विभिन्न प्रप द्वारा भी वे पर और कुचलने म की बान यह है सरकारे उनकी सरकार भी त की कोशिश व इच्छाशक्ति' भारत कमजोरियों समाजविज्ञानी और विकेदी? इस क्षेत्र में निरंतरता औ हुए यह का

प्रस्तावना

दस वर्ष पूर्व, 24 अप्रैल 1993 को, पंचायतें भारतीय संविधान के भाग नौ का अंग बन गयी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद मैने जो निबंध लिखे हैं, यह पुस्तक उन्हीं का एक चयन है। इसके माध्यम

से मैंने पंचायतों की दस वर्षों की यात्रा को उकेरने की कोशिश की है। जैसा कि जाहिर है, दस वर्षों की यह यात्रा न तो बाधारहित रही है

और न ही हमेशा वांछित दिशा में। निश्चय ही, हमारे जैसे, ढेर सारी जटिल समस्याओं से भरे, समाज में रेडिकल परिवर्तन लाना कोई आसान काम नहीं

है। कठिनाई तब और बढ जाती है, जब परिवर्तन का लक्ष्य उन बहुसंख्यक

लोगो को सत्ता देना हो जो परपरागत रूप से हाशिये का जीवन जीते रहे

है और समाज से बहिष्कृत रहे हैं। यही कारण है कि पचायते एक ओर तो

सत्ताधारियों की संपूर्ण उपेक्षा का शिकार और दूसरी ओर भूपितयों, सामती तत्वों और ऊँची जातियों की हिंसक और ध्वंसपूर्ण प्रतिक्रिया के निशाने पर रही हैं। दूसरी अजीब-सी बात यह हुई कि जिन हाथों ने यह गत्यात्मक

सवैधानिक ढाँचा निर्मित किया, वे हाथ ही इसे नष्ट करने की कोशिश करते रहे है। ससद सदस्यो और विधान सभा सदस्यों में यह एहसास सताता रहता

है कि उनकी ही बनायी हुई चीज सत्ता और स्वार्थ विस्तार की उनकी उच्छृंखल भूख के मार्ग में बाधक बन रही है। नौकरशाही भी इस रेडिकल कदम से बहुत खुश नहीं है कि तुणमूल स्तर पर गठित 'स्वशासन की संस्थाओ' के

माध्यम से अधिकार आम जनता को दिये जा रहे हैं।

लेकिन देश भर में लोगों ने यह दिखा दिया है कि पीछे लौटना संभव नहीं है। पंचायतों के काम-काज के बारे में बहुत-सी नकारात्मक कथाओं के

नहीं है। पद्मायती के कीम-कीज के बार में बहुत-सी नेकीरात्मक कथाओं के देशव्यापी प्रचार के बावजूद इस तथ्य को विलक्षण स्वीकृति मिली है कि पचायतें भारत म पचावती भारत । लेकिन आ अलग और सर्वा जिला-इन नीन र की म्यनत्र संदेधा पाजा कहा जा सर इस्तिए बहुत ही ब्नियाटी आवश् गज्य सरकारो प

नक उजागर हो र कोई और उपाय तिहत्तरवें र चला है। प्रश्न र

सीमा तक हासिर के सवैधानिक पन्जयनी राज व का सूत्रपात हो महिलाओं, दलि गवा है। लगभ अतगल पर होने को अभिव्यक्त कथाएँ देश के

लेकिन है

है। ग्रामीण भा निजाम को र्ख के विभिन्न प्र द्वारा भी वे प और क्वलन ' की बात यह :

सरकारें उनके सरकार भी न की कोजिश इच्छाशक्ति'

> भारत कमजोरियो समाजविज्ञान और विकेटी

इस क्षेत्र में निरंतरता ३ हुए यह का अपने क्षेत्र मे अच्छा काम कर रही हैं। यह भी लक्षित किया गया है कि जहाँ भी महिलाओं को स्थानीय निकायों के संचालन में स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिला है, परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहे है। इन नयी स्थानीय

लोकतात्रिक संस्थाओं की सक्रियता के दस वर्ष बाद हम पाते है कि स्शासन, जवाबदेही, दूरदर्शिता, सूचना का अधिकार तथा इनसे जुड़े अन्य मुद्दों की राष्ट्रव्यापी चर्चा होने लगी है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह हमारे

समाज और राजनीतिक तंत्र के भविष्य के लिए शुभ साबित होगा। इस पुस्तक के अध्याय इस एकनिष्ठ लक्ष्य से लिखे गये हैं कि जमीनी स्तर का प्रामाणिक लोकतंत्र और लोकतात्रिक संस्थाएँ हमारी सामाजिक व्यवस्था

और संस्कृति का आधारभूत अंग बनें, निर्णय-प्रक्रिया में बहिष्कृत समुदायों की भागीदारी और स्त्री-पुरुष समानता जीता-जागता यथार्थ बन सकें। पंचायतों की विशद संभावनाओं के प्रति लोगों में सचेतनता पैदा करके ही यह लक्ष्य

हासिल किया जा सकता है। यह पुस्तक इसी दिशा में एक छोटा-सा प्रयास है।

अनुवाट कार्य में श्रीमती अन्नू आनद और पांडुलिपि तैयार करने मे सुश्री माधवी मिश्रा का उल्लेखनीय योगदान है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता है।

मेरे सहकर्मी श्री राजिकशोर ने अग्रेजी में लिखे गये इन लेखों के चयन. अनुवाद और संपादन का कष्ट किया है। मैं उनका विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ।

जॉर्ज मैथ्यू

परिप्रेक्ष्य

भारत म पचायता र मारत । लेकिन आ

जनग और सर्वर

जिला—इन तीन स् की स्वतंत्र संवैधार्ग

पाया कहा जा सः इसतिए बह्त ही

बुनियादी आवश्र गज्य सरकारो प

नक उजागर हो र् कोई और उपाट

तिहत्तरवें र चला है। प्रश्न र

सीमा नक हासिर के सवैधानिक

पंचायनी राज वे का सूत्रपात हो

महिलाओं, दलि गया है। लगभ

अतगन पर होने को अभिव्यक्त

का आमध्यक्त कथाएँ देश के

लेकिन वि

है । ग्रामीण भा निजाम को र्स्व

कं विभिन्न प्र द्वारा भी वे पं

और कुचलने र

की बात यह । सरकार उनर्क

सरकार भी न

की कोशिश ? इच्छाशदित'

भाग्न कमजोग्यिं।

ममाजविज्ञान और विकेंद्रीर

इस क्षत्र में

निरतरता अं हुए यह का

चित्र

एक सिंहावलोकन

सशोधित संविधान में राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे न केवल गाँवों के लिए, विल्क माध्यमिक तथा जिला स्तर पर भी पंचायतों को स्वशासन की सस्थाओं के रूप में गठित करें। परिणामस्वरूप सरकार की तीन परते होगी: संघ, राज्य तथा पंचायते। इससे अधिक सारभूत परिवर्तन की कल्पना कर पाना कठिन है। इसके प्रभाव व्यापक होंगे!

–निर्मल मुखर्जी

यह सर्वविदित है कि प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान कृषि अर्थतंत्र में स्वशासित ग्राम समुदायों का अस्तित्व रहा है। न केवल ईसा से बारह सौ वर्ष पूर्व रचित ऋग्वेद में इनका उल्लेख है, बल्कि ईसा के छह सौ वर्ष पूर्व तक के युग में भी 'ग्राम सभाओ' (परिषदों अथवा सभाओं) एव 'ग्रामीणो' (गॉब के वरिष्ठ व्यक्तियों) के विद्यमान होने

का उल्लेख मिलता है। ये सभी ग्राम निकाय गाँवो से सबधित मामले उच्चाधिकारियो

के सम्मुख पहुँचाने के सूत्र थे। उपनिवेश-पूर्व काल में

समय वीतने के साथ-साथ इन ग्राम निकायों का स्वरूप बदला और पंचायते (पाँच व्यक्तियों की समिति) बन गर्यी जो गाँव की गतिविधियों का कामकाज सँभालती

व्याक्तया का सामात) बन गया जा गाव का गातावाधया का कामकाज सभालती थी। उन्हें पुलिस के तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। रीति-रिवाजो तथा धर्म ने उन्हें सामाजिक प्राधिकार का पवित्र स्थान प्रदान किया। ग्राम पंचायतो के अलावा

जातिगत संस्थाऍ भी हुआ करती थीं, जो जाति विशेष के सदस्यों द्वारा उस जाति के सामाजिक आचार-विचार और नैतिक संहिता का पालन सुनिश्चित करती थी

जहीं एक ओर गगा की घाटी में यह आम पद्धति थी वहीं दूसरी ओर दक्षिण में

एव जातियों के प्रितिनिधियों को शामिल कर एक प्रशासी निकाय का गठन किया जाता था। यहाँ कह कहना उचित होगा कि उत्तरी एवं दक्षिणी भारत दोनो ही भागो में ऐसे ग्राम निकाय प्रशासन के केदिबन्दु तो थे ही, वे सामाजिक जीवन के तथा इससे भी बढ कर परस्पर सामाजिक ऐक्यबद्धता के मुख्य बिन्दु थे। यहाँ तक कि मध्य युग एवं मुगल काल में भी ग्राम पचायतों का यह स्वरूप परिवर्तन से अछूता ही गहा। यद्यपि मुगल काल में न्यायिक अधिकारों पर पाबन्दी लगा दी गयी, लेकिन स्थानीय गतिविधियों पर ऊपर का कोई नियंत्रण नहीं था एवं ग्राम अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्तरदायित्व पंचायतों के प्रति ही बना रहा।

भारत के अन्तरिम गवर्नर-जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ (1835-36) ने भारतीय ग्रामीण समुदायों को 'लघु गणराज्यो' की संज्ञा प्रदान की। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये लोकतात्रिक 'गणराज्य' सभी लोगों की भागीदारी से कार्य करनेवाली आदर्श सस्थाएँ थी। ग्रामीण समाज में उस समय व्याप्त जातिग्रस्त सामती सरचना के कारण उनमे बहुत-सी कमियाँ थी। बी आर. आम्बेडकर इन ग्रामीण समुदायों के वारे में ऊँचे विचार नहीं रखते थे। वास्तव मे निजी अनुभवों ने उनके मन पर इन जातिग्रस्त गांवो एव पचायतों की नकारात्मक छाप छोड़ी थी। सविधान सभा मे 4 नवबर 1948 को दिये गये उनके इस प्रमिद्ध वक्तव्य को, 'इन ग्राम गणराज्यों ने भारत को बरवाद किया है और वे स्थानीयता की नाली, अज्ञान, सकीर्णता एव साप्रदायिकता की गुफा है।' उसके सही परिप्रेक्ष्य मे देखा जाना जरूरी है।

आम्बेडकर ने भले ही ग्राम समुदाओं की स्थिति का आकलन तीखं रूप सें किया हो, यह महत्वपूर्ण हैं कि प्राचीन ग्राम प्रणाली को, विशेषकर समानता ओर लोकनंत्र के मूल्यों के संदर्भ में, रंगमांटिक दृष्टि से देखने से बचना होगा। एक बार जयप्रकाश नारायण ने टिप्पणी की थी कि पुराने ग्राम समुदाय किसी और रूप मे नहीं, फकत अपने भौतिक स्वरूप मे ही जीवित है। अब वे ऐसे जीवंत समुदाय नहीं रह गमें हैं जो किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की कठिनाइयों का समाधान ढूँढने ओर उसके नैतिक तथा भौतिक जीवन का विकास करने का काम सामूहिक रूप से कर सके।

ब्रिटिश युग

अंग्रेजो के आगमन के उपरांत आत्मिनर्भर ग्राम समुदाय तथा उनकी पचायतों को पोषण मिलना समाप्त हो गया। काल क्रम मे उनका स्थान औपचारिक रूप से गठित ग्राम प्रशासन ने ले लिया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में एक उत्तरदायी प्रतिनिधि संस्था के रूप मे स्थानीय स्वशासन अंग्रेजो की देन है।

यहाँ यह बात जोर दे कर कही जा सकती है कि ग्राम पंचायतें अंग्रेज शासको के लिए पहली प्राथमिकता नहीं थीं। उन्होंने मुख्यत व्यापारिक केंद्रों के आसपास अपना ध्यान केंद्रित किया था। अतः प्रारम्भ मे प्रमुख नगरो मे नामित सदस्यांवाल स्थानीय निकायों का गठन ही उनका मुख्य उद्देश्य था। इसी के तहत 1687 में मद्रास

में एक नगर निगम स्थापित किया गया। टाउन काउसिल के ब्रिंटिश मॉडल पर बनाये गये इस निकाय को गिल्ड हॉल तथा विद्यालय निर्माण पर कर लगाने का अधिकार

दिया गया। समय बीतने के साथ-साथ इस निकाय तथा अन्य प्रमुख नगरो में गठित इसी प्रकार के निकायों के कार्य कलाप का विस्तार हुआ तथा उनके कराधान अधिकारो

में वृद्धि की गयी। यद्यपि ये निकाय स्थानीय सरकारों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति

करते थे, किंतु इनका सचालन निर्वाचित सदस्यों के वजाय नामांकित सदस्य ही करते मेयो प्रस्ताव : 1870 में लॉर्ड मेयो न अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के लिए

अपनी परिषद द्वारा एक प्रस्ताव करवाया, ताकि जनता की मॉगं पूरी करने की प्रक्रिया मे प्रशासनिक कुशलता लायी जा सके और 'देश की बढ़ती माँगों को पूरा करने में अपर्याप्त इपीरियल संसाधनों में वित्तीय वृद्धि' की जा सके। जैसा कि वायसराय काउसिल के वित्त सदस्य सैमुअल लैंग ने कहा था, 1857 के विद्रोह के कारण इपीरियल वित्तीय व्यवस्था पर भरपूर दबाव पड़ा तथा यह जरूरी समझा गया कि स्थानीय कराधान से ही स्थानीय सेवाओं की वित्त व्यवस्था की जाये। अतः वित्तीय मजबूरी के कारण स्थानीय सरकार सबधी लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फिर भी इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के नीति विकास में यह एक ऐतिहासिक कदम था। इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए वंगाल चौकीदारी अधिनियम के जरिये 1870 में बंगाल मे परपरागत ग्राम पचायत प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया। इस अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेटो को गाँवों में नामांकित सदस्यांवाली ग्राम पचायते गठित करने का अधिकार प्रवान किया। नामाकित सदस्योवाली ये पचायते कर लगा सकती थीं, ताकि वे अपने द्वारा नियुक्त चौकीदारों को वेतन दे सकें। 1880 के अकाल आयोग ने स्थानीय निकायों के न होने से अकाल पीडित लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने में आनेवाली दिक्कतों का जिक्र किया था तथा स्वशासन की संस्थाओं का विस्तार गाँवी

तक भी करने की आवश्यकता पर वल दिया था। रिपन प्रस्ताव: इस पुष्ठपट मे वायसराय के रूप मे लॉर्ड रिपन जैसे उदारवादी के प्रवेश ने देश में स्थानीय सरकारों के संरचनात्मक विकास में एक ऐतिहासिक

मोड का काम किया। उनके वायसराय काल में 18 मई 1882 के सरकारी प्रस्ताव को, जिसमे अधिक सख्या मे गैरसरकारी सदस्यों के भारी वहुमतवाले स्थानीय बोर्डों के गठन तथा गैरसरकारी अध्यक्ष का प्रावधान था, भारत मे स्थानीय सरकार का

मेग्ना कार्टा माना जाता है। इस प्रस्ताव के आने से स्थानीय शासन की भूमिका को विस्तार मिला ! 'जन सेवा की भावना रखनेवाले उस कुशाग्रबुद्धि वर्ग' का इस्तेमाल

करने के उद्देश्य से, जिसका इस्तेमाल कर पाने में विफलता 'न केवल त्रुटिपूर्ण नीति

है, विल्क सत्ता की शुद्ध बरबादी भी', निर्मित इस प्रस्ताव मे ग्रामीण निकायों के गठित करने का प्रावधान था, जिनके दो-तिहाई सदस्य निर्वाधिन प्रतिनिधि होने थे। यद्यपि 1882 के रिपन प्रस्ताव की अपेक्षा के अनुरूप स्थानीय स्वशासन की प्रगति धीमी रही, क्योंकि जिला स्तर पर नगर निगम निकायों तथा बोर्डों के गठन के लिए कुछ ही कदम उठाये गये और वह भी बेमन से, पर यह जस्तर हुआ कि 'स्वशासन' शब्द का प्रचलन शुरू हो गया।

1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने देश के लिए राजनीतिक ध्येय के रूप में 'स्वशासन' को स्वीकार किया। 1907 में सरकार ने विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग का गठन किया, जिसने 1909 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में रिपन प्रस्ताव में समाविष्ट सिद्धांतों को और अधिक विस्तृत किया। यद्यपि इस आयोग में अग्रेज सदस्य पाँच थे तथा भारतीय सदस्य मात्र एक रमेशचद्र दत्त थे। फिर भी इस आयोग ने भारतीय सदर्भ में पंचायती के महत्व को समझा। आयोग ने सिफारिश की कि 'विकेदीकरण के हित में लोगों के लिए भी यह बहुत बांछनीय होगा कि गाँवों के स्थानीय मामलों के प्रशासन के लिए ग्राम पचायतों का गठन और उनका विकास किया जाये। यद्यपि आयोग ने ऐसे प्रयासों में आनेवाली कुछ कठिनाइयो की कल्पना भी की थी, जैसे 'जाति एवं धार्मिक विवाद' अथवा धनी जमीदारी का प्रभाव जो 'किरायेदारों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक काम करने को रोक सकते है।' उसने कहा कि ये दिक्कतें ऐसी नहीं है कि दूर न की जा सकें। इसी वर्ष (1909) लाहीर में हुए काम्रेत के चौवीसवे अधिवेशन मे प्रस्ताव पारित किया गया कि 'ग्राम पंचायतो तथा उनसे ऊपर के सभी स्थानीय निकायों को चुनाव-आधारित बनाया जाये तथा उनका अध्यक्ष गैरसरकारी व्यक्ति हो और उन्हे पर्याप्त वित्तीय समर्थन दिया जाये।' इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया। किंतु रिपन प्रस्ताव की तरह ही विकंदीकरण पर बने शाही आयोग द्वारा प्रस्तुत अधिकाश सिफारिशें कागजी बन कर रह गयीं, जिस पर कराची में दिसंबर 1913 में हुए कांग्रेस के अट्ठाइसवे अधिवेशन में पारित प्रस्तााव में टिप्पणी की गयी। कोलकाता में 1917 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में डॉ. ऐनी वेसेंट ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विकेंद्रीकरण पर गठित शाही आयोग की रिपोर्ट में जो वहुत मामूली सिफारिशे की गयी थीं, उन पर भी कार्यवाही न करने के लिए सरकार को दोषी ठहराया।

मोटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार : द्विशासन की प्रस्तावित योजना के तहत 1919 के मोटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने स्थानीय सरकार को 'हस्तांतरित विषय' बना दिया। इसका अर्थ यह था कि स्थानीय सरकार का विषय प्रदेशों के भारतीय मंत्रियों के अधिकारों के अतर्गन आ गया। यह भविष्य के लिए आशा पैदा करनेवाला और प्रगतिवादी कदम था। स्थानीय स्व-सरकारों को पूर्णतः प्रतिनिधिक और उत्तरदायी बनाने के लिए सुधारों में यह सुझाया गया कि स्थानीय निकाय यथासभव निर्वाचित जन प्रतिनिधियो

क नियत्रण में हाने चाहिए तथा उन्ह बाहरी नियत्रण स अधिकाधिक स्वतत्रता होनी चाहिए।⁷ माटग्यू-चेम्सफोर्ड योजना का यह घोषित लक्ष्य होते हुए भी संगठनात्मक

एव वित्तीय दोनों ही स्तरों पर विभिन्न दवावों के कारण गाँवों के स्तर पर पचायत मस्थाओं को वास्तव में लोकतात्रिक तथा स्वशासन का सक्रिय माध्यम नहीं बनाया जा सका। फिर भी ग्राम पचायतों के गठन के लिए देश के लगभग सभी प्रातों मे

तथा अनेक रियासतों में अधिनियम पारित तो हुए ही। 1929 तक ब्रिटिश भारत के आठ प्रांतों में ऐसे अधिनियम पारित हो चुके थे। वहरहाल, इन साविधिक पंचायतों के अंतर्गत गाँवों की एक छोटी-सी सख्या ही आ सकी और उन्हें भी सीमित कार्य ही सीपे गये।

भारत सरकार अधिनियम, 1935: भारत सरकार अधिनियम, 1935 तथा उसके

अतर्गत प्रादेशिक स्वायत्तता की शुरुआत से देश में पंचायतों के क्रमविकास में एक और महत्वपूर्ण चरण प्रारम्भ हुआ। प्रदेशे में निर्वाचित प्रतिनिधिक सरकारें होने के परिणामस्वरूप लगभग सभी प्रादेशिक प्रशासनों ने अपना यह कर्तव्य माना कि ग्राम पंचायतों सिहत स्वशासन की सभी संस्थाओं को और अधिक लोकतात्रिक बनाया जाये। यद्यपि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने पर प्रदेशों में शासन करनेवाली प्रतिनिधिक कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, फिर भी 1947 तक स्थानीय शासन

की सस्थाओं की स्थिति यथापूर्व बनी रही। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक रूपरेखा में ग्राम पचायतों का स्थान केंद्रीय था। गांधी जी ने 'ग्राम स्वराज' की जो

परिकल्पना की थी, उसमें ग्राम पंचायतों को परिपूर्ण लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित सपूर्ण गणराज्यों के रूप में देखा गया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद

संवैधानिक वहस

लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण के प्रति भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर यह एक दुखद टिप्पणी है कि गाँव के एतिहासिक रूप से प्रशासन की मूलभूत इकाई होने, पंचायतों के प्रति राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिबद्धता और इस विचारधारा को गांधी जी द्वारा अनवरत रूप से प्रचारित किये जाने के वावजूद भारतीय सविधान के प्रथम प्रलेख में पंचायतों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया। गांधी जी को यह पता चला कि प्रस्तावित सविधान में पंचायतों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने

टिप्पणी की कि यह निश्चय ही एक भूल है और भारत की स्वतंत्रता में जनता का स्वर प्रतिध्वनित होना है, तो हमे इसकी ओर तुरंत ध्यान देना होगा।

सविधान सभा में पंचायतों के खिलाफ आम्बेडकर के तर्कों के जवाब मे मैसूर के माधव राव ने कहा था, 'यह सच है कि गाँव लवे समय से गुटबदी की प्रवृत्ति से ग्रस्त है, और वहाँ छोटे-छोटे जुल्म होते रहते है, अथवा व छुआछूत के गढ वन हुए हैं। ज्यादातर गाँवो की दशा या तो दयनीय है या वे मरणासन्न है। 10 तथापि उन्होंने इस बात पर वल दिया कि यदि तीस प्रतिशत गाँव भी अच्छे गाँवो के रूप मे वर्गीकृत किये जा सकते है, तो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने मैसूर की तत्कालीन लोकप्रिय सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का उदाहरण टेते हुए वताया, 'यह उत्साहवर्धक है तथा, कई मामलों में, काफी संतोषप्रद है।' सविधान में ग्राम पचायतों को शामिल करने का आग्रह करनेवाले तर्कों को अतंतः मान लिया गया—हालाँकि एक सीमित स्तर पर। सविधान के भाग चार (गज्य नीति के निदेशक सिद्धातों) मे पंचायतों का प्रावधान शामिल करवाने में सफलता मिली। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि 'राज्य ग्राम पंचायतों का सगठन करने के लिए कटम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।' यह दो परस्पर-विरोधी नजरियों के बीच एक समझौता था।

संविधान में एक अन्य स्थान पर 'स्थानीय शासन' का उल्लेख किया गया है। अनुसूची सात, सूची दो (राज्य सूची) के पाँचवे इदराज में कहा गया है 'स्थानीय शासन अर्थात नगर निगमों, सुधार न्यासो, जिला बोर्डो, खनन प्राधिकरणों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासनो के प्रायोजन के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का गठन और शक्तियाँ।' निश्चित रूप से पचायतो को उनका स्थान दिये बिना स्थानीय शासन को परिभाषित करने का यह एक असाधारण तरीका है।

गाधीवादियों ने पंचायतों को न केवल साधन, बल्कि लक्ष्य भी माना, साथ ही, लोकतांत्रिक विकेटीकरण तथा जनता को अधिकार प्रदान करने की उनकी गहरी क्षमता में भी उनका विश्वास था। यद्यपि आम्बेडकर की आपित्त लोकतांत्रिक विकेटीकरण या जनता को अधिकार सौपने की धारणा के प्रति नहीं थी, जो एक आदर्श पंचायत प्रणाली की निष्पत्ति होती। वे अपने अनुभवों के आधार पर बता रहे थे कि भारत के जातिग्रस्त ग्राम समाज का अर्थ उनके और उनकी तरह के करोड़ो लोगों के लिए क्या था। बेशक उनका अनुबांध भी उनना ही यथार्थवादी था जितना दूसरे वर्गों के लोगों का।

ग्राम पचायते सामाजिक बदलाव तथा विकास कार्यो को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है— इस मूल धारणा की आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। किंतु यह बुनियादी सवाल अभी तक अनुत्तरित ही है: पंचायती को सिवधान के उन हिस्सो में क्यों नहीं रखा गया जो विधिक रूप से लागू किये जा सकते हैं? उन्हें उपयुक्त संवैधानिक दर्जा एवं मान्यता क्यों नहीं दी गयी? इसका उत्तर यह है कि शहरी तथा ग्रामीण संभ्रांत वर्ग तथा राजनीति में उनके प्रतिनिधियों को (राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही) पंचायतों से घृणा थी और यह घृणा

जस की तस वनी हुई है। सत्ता के विकेदीकरण के लिए जो भी सच्चे प्रयास किये गये, इन स्वार्थों ने उन्हे सफल नही होने दिया। स्वतत्रता के बाद से पचायत सस्थाओ की कहानी सक्षेप में यही है।

1977 तक पंचायतों का उत्थान एवं पतन

पचास के शुरुआती दशक में भारतीय विकास की योजना में गांधी जी के ग्राम विकास के विचार को ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन इस दृष्टिकोण की मूर्खता को समझने

मे अधिक समय नहीं लगा। 1952 में उद्घाटित सामुदायिक विकास की योजनाएँ,

जो मारथंडम, शांति निकेतन, बडौदा, इटावा और नीलोखेड़ी के पैटर्न पर बनायी गयी थी. लोगों की भागीदारी के बिना निर्रथक साबित होने लगीं। सामुदायिक विकास

तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों में ऐसी भागीदारी प्राप्त करने के लिए एक संस्थागत

ढाँचे का सुझाव देने के लिए 1957 में योजनागत परियोजनाओं पर बनायी गयी समिति ने इन दो कार्यक्रमो के अध्ययन के लिए एक दल गठित किया। सांसद बलवतराय

मेहता इस अध्ययन दल के अध्यक्ष थे। अध्ययन दल का मत था कि गाँव के स्तर पर ऐसी एजेंसी के बिना, जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सके, और उत्तरदायित्व

ले सक तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सके,¹² ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति सभव नहीं है। उसकी इस सिफारिश

से कि 'सामुदायिक कार्यों मे जन प्रतिभागिता को सांविधिक प्रतिनिधि निकायो के जरिये सगठित किया जाये।'¹³ राष्ट्रव्यापी स्तर पर व्याप्त भावनाओं को बल मिला।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर वलबंतराय मेहता अध्ययन दल की सिफारिशों से सभी राज्यों में पंचायत राज सस्थाएँ गठित करने के कार्य में गति आयी।

यहाँ यह भी याद किया जाये कि तत्पश्चात राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी बलवतराय मेहता रिपोर्ट की सकल्पना में लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण की स्पष्ट अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया तथा प्रत्येक राज्य के लिए उपयुक्त संरचना तैयार करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया।

इसी दौर में शासन की एक प्रक्रिया के रूप मे 'पचायती राज' शब्द प्रचलन मे आया। इसका तात्पर्य था ग्राम सभा से लोक सभा तक आवयविक रूप से जनता को जोड़ने की एक प्रणाली। लेखक के साथ एक मुलाकात मे एस.के. दे ने बताया

को जोड़ने की एक प्रणाली। लेखक के साथ एक मुलाकात में एस.के. दे ने बताया था कि यह शब्द जवाहरलाल नेहरू की देन है। यह 'पंचायत' से भिन्न है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित स्थानीय निकाय की ओर संकेत करता है।

बलवतराय मेहता अध्ययन दल की सिफारिशों के बाद राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पचायती राज का उद्धाटन हुआ। प्रधान मत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की राजधानी जयपुर से 260 किलोमीटर दूर स्थित नागौर में 2 अक्तूबर 1959 की स्वतत्र भारत के प्रथम पचायती राज का उद्धाटन किया। नेहरू ने इस प्रणाली की प्रशसा की तथा इसे 'नये भारत के सदर्भ में सर्वाधिक क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक कदम' की संज्ञा दी। नेहरू को यह अनुभव हो चुका था कि ऊपर के स्तर पर लोकतत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक नीचे के स्तर से उसका निर्माण न किया जाये। इसके आठ दिनों के बाद हैदराबाद (आध्र प्रदेश) से 60 किलोमीटर दूर शादनगर में पंचायती राज का उद्घाटन करते समय भी उन्होंने यही भावना व्यक्त की। नेहरू के केबिनेट में सामुदायिक विकास मंत्री तथ स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के शिल्पकार एस.के. दे ने इस सपूर्ण विचार को दार्शनिक ऊँचाई प्रदान की तथा उसे ऐसे साधन के रूप में देखा जो एक व्यक्ति को पूरे ब्रह्माण्ड से जोड़ता है। राष्ट्रीय लोकतत्र के क्षेत्र मे उन्होंने ग्राम सभा तथा लोक सभा के बीच आवयविक एवं अतरंग संबंध की परिकल्पना की।

1957 तक सभी राज्यों ने पचायती राज अधिनियम पारित कर दिये थे तथा 1960 के मध्य दशक तक सभी राज्यों में पंचायते अस्तित्व में आ चुकी थीं। 5,71,000 गाँवों के 96 प्रतिशत तथा ग्राम आबादी के 92 प्रतिशत भाग को समाहित करते हुए 2,17,300 से अधिक ग्राम पचायतों का गठन हो चुका था। औसतन दो या तीन गाँवों की लगभग 2400 आबादी के लिए एक पचायत थी। ग्रामीण भारत में उत्साह की लहर थी तथा लोगों को लगा कि अब उनके दिन-प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करनेवाले कार्यकलाप में उनकी अपनी भी कुछ भूमिका है। वे भारत में पचायती राज के आशावादी दिन थे। सामुदायिक विकास मंत्रालय ने 1964-65 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से युवा एवं बेहतर नेतृत्व आगे आ रहा है तथा उनके कामकाज से जनता में काफी सतीष है।

राजस्थान के पंचायती राज का मूल्यांकन करने के लिए 1962 में एसोसिएशन ऑफ वालटरी एजेसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट (अवॉर्ड) द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने एसी ही टिप्पणी की : 'ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जनता की यह महसूस हो रहा है कि अपना भविष्य बनाने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार मिले हैं।...उसे इस बात का पूरा ज्ञान है कि जो विशेषाधिकार और लाभ पहले बीडीओ के नियंत्रण में थे, वे अब उसके नियंत्रण में हैं। इस अर्थ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पूरा लाभ हासिल कर लिया गया है।' 15

अध्ययन दल ने आगे बताया कि जन प्रतिनिधियों को अधिकार सौपे जाने के कारण प्राथमिक स्कूलो में अध्यापकों की उपस्थित में सुधार हुआ है, ब्लॉक प्रशासन अधिक उत्तरदायी हो गया है, प्रधानों के सम्मुख जनता अपनी शिकायते रख रही है और उनके माध्यम से राहत पा रही है तथा, सबसे अधिक, अधीनस्थ कर्मचारियों एवं नव निर्वाचित नेताओ में व्याप्त भ्रष्टाचार मे कमी आयी है, क्योंकि ब्लॉक कर्मचारी अब पचायत समिति के अधीनस्थ कर दिये गये थे तथा नेताओं के पुनः निर्वाचित हीने के लिए जनता के बीच प्रधानों की प्रतिष्टा जस्ती थी। दूसरे शब्दो में, पचायती

राज सस्थाओं ने स्थानीय सरकार के सभा कार्य पूरे किये और लोकतत्र की नर्सिरियों—बल्कि उसके प्राथमिक स्कूलों—के रूप में कार्य किया। पचायती राज संस्थाओं द्वारा उत्पन्न रुचि के कारण कई राज्यों ने उनकी कार्यप्रणाली के आकलन एवं उनमें सुधार लाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए समितियाँ गठित कीं।

इस सबके बावजूद, अभिजित दत्त के विचार से पंचायती राज सस्थाएँ 'स्थानीय सरकार का जीवित कैरिकेचर बन कर रह गयी हैं।'¹⁶ थॉमस मथाई ने *डेमोक्रेटिक*

वर्ल्ड (22 जनवरी 1978) के सपादकीय में कहा कि 'ग्राम पंचायतें असंतोष का बिन्दु बन कर रह गयी हैं। ग्राम सभा तो एक तरह का मजाक है।'¹⁷ ग्राम सभा के ससाधन काफी कम थे। यदि राजनीतिक इच्छाशिक्त होती तो इस स्थिति को सुधारा जा सकता था। सर्वाधिक चितनीय समस्या थी आर्थिक रूप से सपन्न एवं सामाजिक सुविधापूर्ण वर्गों का पंचायती राज संस्थाओं पर हावी होना। निश्चित रूप से यह एक सामाजिक-राजनीतिक समस्या थी; समय पर चुनाव करवा कर काफी हद तक इसका समाधान किया जा सकता था। इससे दीर्घ काल से दिमत रहे समुदायों को जो

राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता, उससे परिस्थितियाँ बदली जा सकती थी।

यदि नियमित रूप से चुनाव संपन्न हुए होते, तो मुद्दों पर आधारित समूह
उत्पन्न हो सकते थे, हर स्तर पर समीकरण बदल सकते थे तथा पारंपरिक प्रतिद्विद्विताएँ
समाप्त हो सकती थीं। इस प्रक्रिया मे सपाट तकनीकी एकजुटता आवयविक एकजुटता
का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे राय देने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामूहिक
विचार-विमर्श का उद्भव होता है। लेकिन इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों ने पचायत
चुनावों को बार-बार स्थिगित कर अथवा बिल्कुल न करवा कर वर्षों तक रोके रखा।
जी वी.के. राव की अध्यक्षता में राप्ट्रीय योजना आयोग द्वारा गठित समिति ने पचायतो
के चुनाव नियमित रूप से न करवाने पर चिंता जतायी। क साक्ष्य उपलब्ध हैं कि
स्थानीय निहित स्वार्थों तथा राज्य विधान मडलो एवं संसद मे उनके द्वारा निर्वाचित
प्रतिनिधियों की यह सोची-समझी साजिश थी कि पंचायती राज को पहले अपंग बना
दिया जाये और अन्ततोगत्वा उसका परित्याग कर दिया जाये, क्योंकि उसके उत्कर्ष
से वे भयभीत थे।

इस गुप्त एजेंडा की जड़े 1960 में देखी जा सकती हैं, जब सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की उपेक्षा करते हुए गहन जिला कृषि कार्यक्रम (आइएडीपी) शुरू किया था। 1961 में जयप्रकाश नारायण समिति ने एक स्वतंत्र कार्यक्रम बनाने में सरकार के भीतर मौजूद दोहरे सोच और अंतर्विरोधपूर्ण स्थितियों को पहचाना था। सिमिति ने टिप्पणी की कि योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज को एक एजेंसी के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद 'कोई वैध कारण नहीं रह जाता है कि मदवार आवंटन जारी रखे जाये—भले ही वे मार्गदर्शिका के ही रूप हो। ''' स्पष्टत. सामुदायिक विकास मत्रालय आइएडीपी की शुरुआत से नाखुश था।

इसके बावजूद शीच्र ही निर्वाचित जिला परिषदों के क्षेत्राधिकार से बाहर 'लघु किसान विकास अभिकरण' (एसएफडीए), सूखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएसी) और गहन आदिवासी विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) जैसी योजनाएँ भी शुरू कर दी गयीं। योजनाओं के लिए आबंटन के साथ भी, जो जिला परिषदों का मामला था, छेडछाड की गयी।

1966-67 में सामुदायिक विकास मंत्रालय का स्तर घटा कर उसे एक विभाग बना दिया गया तथा उसे खाद्यान्न एवं कृषि मंत्रालय के अधीन ले आया गया। ऐसा करने के साथ ही मरकार ने 12 राज्यों के 28 जिलों में समेकित जिला आयोजना की कुछेक योजनाएँ प्रारंभ कीं तथा मूल्याकन करने के दो औजार भी समाप्त कर दिये। वे औजार थे-वार्षिक विकास सम्मेलन तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा वार्षिक मूल्याकन। 'ऐसा करने से इस मत को बल मिला कि न केवल सामुदायिक विकास मंत्रालय, बल्कि समाजिक विकास परियोजना का भी स्तर गिरा दिया गया। 20 1971 में 'सामुदायिक विकास' के स्थान पर 'ग्रामीण विकास' शब्द लाया गया। यह केवल शाब्दिक परिवर्तन नही था। एल.सी. जैन कहते हैं, 'इससे परिवर्तन के एजेंडा तथा विकास के अभिकरणों के रूप में 'समुदाय' तथा 'पचायतों' दोनों का ही खाल्मा हो गया है। 121 अशोक मेहता समिति के शब्दों में, ''सभी प्रकार की विकास गतिविधियाँ केवल ब्लॉक स्तर के सगठन के जरिये ही चलायी जानी चाहिए" का मूल विचार अपनी जमीन खो बैठा, यद्यपि पचायत समिति विकेद्रीकरण की आधारभूत इकाई के रूप में, अधिकतर मामलो में, ब्लॉक का ही पर्याय थी। 22 यहाँ इस बात पर बल दिया जा सकता है कि सभी विकास कार्यक्रम नौकरशाही पर केंद्रित हो कर रह गये और उनमें जनता की कोई प्रतिभागिता शायद ही वची रह गयी। पंचायनी राज अंततः केंद्र में ग्रामीण विकास मत्रालय का एक अग वन गया, जिसका कार्य देखने के लिए एक संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया। यही स्थिति अब तक जारी है। इस प्रकार राज्य तथा केंद्र स्तर के 'सभ्रात' राजनेताओं के एक बृहत गठबंधन में पंचायती राज को वर्तमान दयनीय स्थिति में ला खड़ा करने में नौकरशाही की भूमिका को अशोक मेहता समिति ने तीखे रूप मे उजागर किया।²³

यह घटना स्वतंत्र भारत के चरित्र का बखान करनेवाला एकमात्र प्रतीक नहीं है। ब्रिटिश काल में भी नौकरशाही ने यही किया था। स्थानीय स्वाशासन का जी भी कमजोर ढाँचा भारत में विद्यमान था, अफसरों ने उसे ढाह दिया। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश काल में ग्राम पचायतों के विखडीकरण के मुख्य कारणों का विश्लेषण करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ग्राम पचायत समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि 'सरकारी अधिकारियों के हाथों में कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकारों के अत्यिविक केंद्रीकरण के कारण पूर्व काल से प्राप्त अधिकारों एवं प्रभावों से ग्रामीण प्राधिकारियों को हाथ धोना पड़ा। 124

आयोग ने टिप्पणी की थी कि लॉर्ड रिपन की मंशा कुछ भी रही हो, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में उनके सुधार सरकारी नियत्रण से मुक्त नहीं थे। स्थानीय निवासियों की अभिलापा के अनुरूप प्रणाली शुरू करने की लिए कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं किया

हमने ऊपर कहा है कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को शुरू करने के लिए गंभीर प्रयास किये थे, किन्तु वे विफल रहे। क्यों ? 1929 के भारतीय साविधिक

अभिलाया के अनुरूप प्रणाली शुरू करने की लिए कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं किया गया।²⁵ 'संभ्रात' राजनेता नौकरशाहों के इशारों पर कार्य क्यो करते रहे? कारण जानना कठिन नहीं है। पेशेवर राजनेता नहीं चाहते कि स्थानीय नेतत्व की नयी पौध उनकी

शक्ति को कम करे। इसीलिए, यह निष्कर्ष निकालना तर्कयुक्त है कि नीकरशाही, व्यापारिक स्वार्थ, मध्य वर्ग, पुलिस तथा राजनेता लोकतात्रिक विकेंद्रीकरण के खिलाफ एकजुट हो गये। एक अभिधारणा तैयार की गयी तथा यह प्रचारित किया गया कि सभी निर्वाचित 'निहित स्वार्थी' के मुकाबले केंद्रीकृत नौकरशाही गरीव ग्रामीणों को

सभी निर्वाचित 'निहित स्वार्थी' के मुकाबले केंद्रीकृत नौकरशाही गरीव ग्रामीणों को ज्यादा लाभ पहुँचा सकती है। इसका परिणाम क्या हुआ? रजनी कोठारी कहते है, 'शहरी अधिकारी वर्ग तथा धनी ग्रामीणों का एक ऐसा अभेद्य गठबधन बन गया, जिससे गरीब ग्रामीणों को दूर रखा गया।'²⁶
स्थानीय शक्तियों और राज्य तथा केंद्र स्तर के राजनेताओं के साथ मिल कर

नौकरशाही ने नयी प्रणाली की किमयों को बढ़ा-चढ़ा कर दर्शति हुए उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। इस गठबधन ने स्थानीय निकायों में महज उच्च अथवा प्रभावशाली जातियों, भ्रष्टाचार तथा अक्षमता के दबदबे को देखना आग्भ कर दिया। अगर नेहरू जीवित होते, तो कहते, 'ग्राम प्राधिकारियों को काम करने दो, लाखों गलतियाँ करने दो।' ग्राम पचायते हताशा का प्रतीक बन कर रह गयी।

नेहरू युग के पंचायती राज को हम पहली पीढ़ी का पचायती राज मान सकते है। इस अवधि के दौरान पचायती राज सस्थाओं की कल्पना ऐसे स्थानीय निकायों के रूप में की गयी जिनका लक्ष्य विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था।

अशोक मेहता समिति

1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति पंचायती राज की संकल्पना एव व्यावहारिक स्वपातरण मे एक नया मांड थी। अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जाँच करने एवं ऐसे उपाय सुझाने के लिए किया गया था जो इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनायें, तािक आयोजना और विकास की विकेद्रीकृत प्रणाली प्रभावी हो सके। सिमिति की रिपोर्ट (1978) एक बीजगर्भित दस्तावेज है, जिसमे पचायतों को हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आवयविक एव एकीकृत हिस्सा बनाये जाने की माँग की गयी थी। अशोक मेहता सिमिति की सिफारिशों के बाद अनेक राज्यों में जो पचायती राज लाया गया, उसे दूसरी पीढी की पचायते कहा जा सकता है।

1978 में अशांक मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप पश्चिम वंगाल सरकार द्वारा पचायती राज संस्थाओं में नयी जान फूँकने को दूसरी पीढ़ी की पचायती राज संस्थाओं की शुरुआत कहा जा सकता है। अशोंक मेहता समिति की रिपोर्ट को सद्धातिक रूप से स्वीकार करते हुए पश्चिम बगाल, कर्नाटक, आध्र प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर में या तो तत्कालीन पचायत अधिनियमों में संशोधन किया गया अथवा नये अधिनियम पारित किये गये। इन राज्यों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार सिफारिशों को अपनाया तथा एक-दूसरे के अनुभवों के आधार पर नये विधेयक पारित किये अथवा वर्तमान अधिनियमों में संशोधन किया।

दूसरे चरण में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि पचायतें स्थानीय स्तर के विकास संगठनो से बदल कर राजनीतिक संस्था का रूप धारण कर ले। ताकत नौकरशाही से हट कर राजनीतिक तत्वों के हाथ में आ गयी। यह एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति थी। बलवंतराय मेहता अध्ययन दल ने पंचायती प्रणाली को विकास-केद्रित रखा था, जब कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट का अनुसरण करनेवाले पश्चिम बगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं बाद मे जम्मू एवं कश्मीर राज्यो में पचायतो को एक प्रामाणिक राजनीतिक संस्था बनाने का प्रयास किया गया।

संवैधानिक समर्थन की आवश्यकता

यह सिद्ध हो चुका है कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संवैधानिक समर्थन तथा साविधिक उपाय जरूरी होते है, किन्तु लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह शर्त ही पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा 55 वर्षों का अनुभव इस तथ्य का साक्षी है। लोकतात्रिक विकेद्रीकरण के बारे में भी यही सच है। कोई यह तर्क दे सकता है कि अप्रैल 1993 तक राज्य सरकार से निचले स्तरों पर स्वशासन हेतु संवैधानिक समर्थन नहीं था, अत किसी भी राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के निचले स्तरों पर लोकतात्रिक विकेद्रीकरण लाने के लिए संवैधानिक गारंटी के साथ-साथ राजनीतिक इच्छाशिक्त तथा जनता की राजनीतिक जागरूकता भी आवश्यक है। अतः त्रि-आयामी दृष्टिकोण—राजनीतिक संकल्प, जनता की जागरूकता तथा स्वस्थ्य परपराएँ बनाना, जिनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक तथा साविधिक उपाय मौजूद हो—से ही हमारे समाज मे दूरगामी परिवर्तन लाये जा सकते हैं। इनमें से एक भी तत्व कमजोर पडता है, तो अन्य सभी उपाय प्रभावहीन हो जाते हैं।

स्पष्ट है कि निष्क्रिय पचायती राज सस्थाओं के कारण इस पूरी सकल्पना एव उसके व्यावहारिक स्वरूप को बदनामी मिली। धीरे-धीरे यह बात समझ मे आ रही थी कि संवैधानिक समर्थन के अभाव मे ही ये घटनाएँ हुई। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में पद्रह वर्षो तक पंचायत चुनाव न करवाने पर (तमिलनाडु मे बीस बार चुनावो था कि 'हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि संविधान में संशोधन कर समय पर स्थानीय चुनाव करवाना अनिवार्य बना दें? उनका कहना था कि तिमलनाडु में स्थानीय चुनावों को स्थिगत करने के लिए दिये गये सभी बीस कारण लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों को स्थिगत करने के लिए भी दिये जा सकते है। उन्होंने कहा, 'यहाँ मैं अपनी यह दलील पेश करता हूँ कि लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों की भाँति ही पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए संवैधानिक संशोधन लाने के लिए

की घोषणा की गयी तथा हर बार कोई न कोई बहाना बना कर उन्हें स्थगित कर दिया गया) टिप्पणी करते हुए मेलकम आदिशेषय्या ने यह प्रासंगिक प्रश्न उठाया

हमे गभीरता से कार्य करना चाहिए।'²⁸

यद्यपि राज्य सरकारें सवैधानिक निर्देश के अभाव में पूर्णकालिक पंचायती राज
गठित करने के लिए बाध्य नहीं थीं, फिर भी कुछ राज्य पंचायतों को अधिकार सौपने
के क्षेत्र में यथासभव आगे बढ़े। उन्होंने महसूस किया कि केंद्र में अधिकारों के केंद्रीकरण
से गभीर अडचने पेश हो रही हैं। उदाहरणार्थ कर्नाटक की जनता सरकार में पंचायती
राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अब्दुल नजीर साब ने कहा कि सवैधानिक सशोधन
द्वारा चौखंभा राज की गारंटी के बिना हमारे प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते।²⁹
दिल्ली में इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज द्वारा 1985 में आयोजित एक विचार गोष्ठी
में नजीर साब ने बुद्धिजीवियों से इस प्रश्न पर विचार करने तथा सवैधानिक संशोधन
की आवश्यकता पर बहस छेड़ने का अनुरोध किया।

यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि पंचायती राज को ध्यान मे रखते हुए पहली बार अशोक मेहता समिति ने ही पचायती राज को संविधान मे शामिल करने की सिफारिश की थी। समिति की यह सिफारिश उसके इस दृष्टिकोण के अनुरूप ही थी कि पचायतों को विकास का औजार न हो कर राजनीतिक सस्थाएँ होना चाहिए। इस समिति ने राजनीतिक दलों को पचायत चुनावों मे अपने चुनाव चिह्नों के साथ भाग लेने का भी पक्ष लिया था।

चूँिक दूसरी पीढ़ी के पंचायती राज ने स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार प्रदान किये तथा उनके व्यक्तित्व के केंद्र में विकास कार्य नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता का सचालन था, उनकी कार्यप्रणाली एवं उनके द्वारा होनेवाले कार्यान्वयन के प्रति व्यापक उत्साह पैदा हुआ। पश्चिम बंगाल के मॉडल को सफलता का प्रतिमान माना गया। 1985 में कर्नाटक में जनता पार्टी की विजय का एक मुख्य कारण 'जनता को अधिकार' देने का आश्वासन था। अब्दुल नजीर साब के अनुसार जनता को जब पता चला कि निचले स्तरों पर सत्ता में भागीदारी हो सकती है, तो चारों ओर जागरण की लहर फैल गयी। पंचायती राज के कार्यान्वयन में पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक के सामान्य लोगों के उल्लेखनीय उत्साह के कारण पंचायतों को संवैधानिक प्रावधानों मे शामिल करने के प्रयासों को काफी बल मिला।

एक 23

यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1980 के मध्य में जिला सरकार का विचार सामने आया। इस अवधि के दौरान इस विषय पर निर्मल मुखर्जी का लेखन ही इसका मुख्य कारण था। ³⁰ वास्तव में निर्मल मुखर्जी ने ही पहली वार 'जिला सरकार' की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पश्चिम वंगाल तथा कर्नाटक में जिला परिषदों की सापेक्षित सफलता से जिला सरकार की अवधारणा को प्रोत्साहन मिला।

73वॉ संविधान संशोधन

1988 के अन्त में पी के. थुगन की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति ने पंचायती राज प्रणाली को सदृढ़ बनाने के लिए अनेक सिफारिशे की। सलाहकार समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि पंचायती राज निकायो को सवैधानिक मान्यता प्रदान की जाये। इस पृष्टभूमि के कारण 15 मई 1989 को संविधान (64वॉ सशोधन) विधेयक का प्रारूप तैयार कर ससद मे पेश किया गया। यह विधेयक कमोबेश अशोक मेहता रिपोर्ट के मॉडल पर (जिसका मसौदा एल. एम. सिघवी ने बनाया था) तैयार किया गया था। यद्यपि 1989 का विधेयक स्वागत योग्य कदम था, कितु इसे दो मूल मुद्दो पर तथा इसके राजनीतिक अभिसकेतो के कारण गभीर विरोध का सामना करना पडा। ये टो मूल मुद्दे थे . (क) विधेयक मे राज्यो की अनदेखी की गयी थी तथा केंद्र द्वारा पचायती राज संस्थाओं से सीधे संबंध रखने की व्यवस्था के कारण यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण था, और (ख) स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को कानून बनाने की अनुमति देने के स्थान पर इस विधेयक में समृच देश पर एक समान पद्धति थोपने की बात थी। राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों एवं सरोकार-संपन्न नागरिको ने इस विधेयक का विरोध किया। इस व्यापक विरोध को देखते हुए विपक्षी दलों के राष्ट्रीय मोर्चा ने एस.आर. बोम्मई की अध्यक्षता में एक वैकल्पिक विधेयक तैयार करने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति की रिपोर्ट में, जो 10 जुलाई 1989 को जारी की गयी, जरूरी मुद्दों को वह फोकस दिया गया³¹ जिसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी । रिपोर्ट ने एक गहन बहस को जन्म दिया। रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया, उसकी छाप पंचायतों से संबंधित उन सभी विधेयको पर दिखाई पड़ती है जो वाट में ससद में दाखिल किये गये।

यद्यपि सविधान (चौसठवॉ संशोधन) विधेयक को लोक सभा मे दो-तिहाई बहुमत मिला, कितु राज्य सभा मे दो मतो की कमी से यह पराजित हो गया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने संक्षिप्त शासन काल मे 7 सितबर 1990 को 74वॉ संशोधन विधेयक (पंचायतो तथा नगरपालिकाओ पर संयुक्त विधेयक) पेश किया, किंतु इसे विचार-विमर्श के लिए नहीं लिया जा सका।

इस समय तक सभी राजनीतिक दल अपने वक्तव्यो तथा घोषणाओं में पचायतों

को सुदृढ बनान के लिए सपैधानिक मशाधन का समधन कर चुके थे तथा देश भर मे पचायती राज के पक्ष में वातावरण तैयार हो रहा था। सितबर 1991 मे नरसिंह राव के नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकार ने 72वॉ (पचायत) तथा 73वॉं (नगरपालिका) सविधान संशोधन पेश किया। संसद की सयुक्त चयन समिति को ये दोनों विधेयक

सर्विधान संशोधन पश किया । ससद का संयुक्त चयन सामात का य दाना विधयक भेजे गये । लोक सभा ने दोनों विधेयक 22 दिसंबर 1992 को तथा राज्य सभा ने दुसरे दिन पारित कर दिये । संसद द्वारा इन दोनो विधेयको को पारित करने के क्रम

दूसर 16न पारित कर 16य । संसद द्वारा इन दोना 1वयवका का पारित करन के क्रम में इनकी क्रम संख्या क्रमश- 73वी तथा 74वी हो गयी। आधे राज्या की विधान सभाओ द्वारा मजूर करने के बाद राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को दोनो विधेयको को अपनी सहमति प्रदान की। संविधान संशोधन (73वॉ सशोधन) अधिनियम, 1992

24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ तथा संविधान संशोधन (74वॉ सशोधन) अधिनियम, 1992 1 जून 1993 को। संविधान में इन संशोधनों से न केवल स्थानीय शासन के क्षेत्र में, विल्कि भारत के संघीय स्वरूप में भी मौलिक परिवर्तन आये। इस प्रकार 'स्थानीय स्वशासन' के लॉर्ड रिपन के विचार से 73वे सविधान

इस प्रकार 'स्थानाय स्वशासन' के लाड रिपन के विचार से 73व सावधान संशोधन की 'स्वशासन की संस्थाएँ' धारणा तक की यात्रा पूरी होने में एक शताब्दी का समय लगा। देश के संधीय राज्यतंत्र के इस क्रम विकास को विशेष रूप से रेखांकित करने की जरूरत है।

पंचायती राज को स्वशासन की संस्थाओं के रूप मे कार्य करने मे पूर्वाश्यकताएँ इस प्रकार है—

(क) स्पष्ट रूप से चिहिनत क्षेत्राधिकार,

है।

- (ख) उत्तरदायित्वों के अनुपात मे पर्याप्त अधिकार,
- (ग) अपनी व्यवस्था करने के लिए आवश्यक मानव तथा वित्तीय संसाधन, और
- (घ) सघीय ढाँचे के दायरे में कार्यकारी प्राधिकार

चूँिक संवैधानिक सशोधनों में इन शर्तों को पूरा करने की सभावना है, अत नयी पंचायतों को सरकार के 'तीसरे स्तर' के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ भारतीय लोकतात्रिक राजनीति में आये दो मूलभूत परिवर्तनों का उल्लेख किया जाना जरूरी है।

एक, भारतीय राज्यतंत्र का लोकतात्रिक आधार विस्तृत हुआ है। इन सशोधनों से पहले, चुने हुए प्रतिनिधियों के जिरये हमारा लोकतात्रिक ढॉचा ससद के दो सदनो, राज्यों की विधान सभाओं तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली तथा पाडिचेरी) की विधान सभाओं तक ही सीमित था तथा उनमें केवल 4963 चुने हुए सदस्य थे। अब ग्रामीण भारत में 500 से अधिक जिला पंचायते, लगभग 6000 खंड/तहसील/मंडल पंचायतें तथा 2.50.000 ग्राम पंचायतें हैं जहाँ भारत की 73 प्रतिशत जनसंख्या बसती

शहरी भारत में, जहाँ 27 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, 96 नगर निगम, 1700 नगरपालिकाएँ तथा 1900 नगर पंचायते है। प्रत्येक पाँच वर्ष में जनतात्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जनता द्वारा लगभग तीस लाख प्रतिनिधि चुने जाते है, जिनमें महिलाओं की संख्या दस लाख है। महिलाएँ लगभग 175 जिला पचायतों, 2000 से अधिक खड/तहसील/मडल पचायतों तथा लगभग 85,000 ग्राम पंचायतों की प्रमुख है। इसी प्रकार, 30 से अधिक नगर निगमों तथा लगभग 600 नगरपालिकाओं की अध्यक्ष महिलाएँ हैं। मुख्य धारा से बहिष्कृत समूहों तथा समुदायों की बहुत बड़ी संख्या अब इन निर्णयकर्ता निकायों में शामिल है। भारतीय जनसंख्या का 14.3 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ तथा 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियाँ है। सो ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के कुल 6,60,000 निर्वाचित सदस्यों में 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रतिनिधि हैं (देखें तालिका: विस्तृत होती लोकतांत्रिक प्रणाली, पृष्ठ 29)।

वं, इन संशोधनों से भारत की संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे है। जिला तथा उससे नीचे के स्तर पर निर्वाचित स्थानीय निकायों के साथ भारत बहुस्तरीय सघ राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ³² बेशक ग्यारहवी (पचायत) तथा बारहवी (नगरपालिकाएँ) अनुसूची में उल्लिखित विपयो को अनुसूची सात के अधीन शामिल किया जायेगा, तभी स्थानीय निकायो को केद्र तथा राज्य स्तर के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि स्थानीय निकायों को कोई विधायी अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा केद्र तथा राज्य, यही दोनो मिल कर कानूनी रूप से भारतीय सघ का गठन करते है, परंतु स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद भारतीय सघीय ढाँचे में हुए गुणात्मक परिवर्तन के परिणाम दूरगामी होंगे।

विस्तृत लोकतात्रिक आघार तथा साथ ही नयी पचायतो एवं नगरपालिकाओ द्वारा लाये गये नये टॉचागत परिवर्तनो के कारण हमारी संघीय प्रणाली में क्रांतिकारी संभावनाएँ पैदा हो गयी हैं। चूँिक केंद्र में साझा सरकारें रहेंगी ही, अतः केंद्र को राज्यो पर निर्भर रहना होगा, जिन पर राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय पार्टियों का नियत्रण होता है। यदि राज्य सरकारें पचायती राज संस्थाओ की उपेक्षा करती हैं तो उनके फिर से न चुने जाने की पूरी सभावना है। अर्थात राज्य सरकार अथवा राज्य की सत्ताधारी पार्टी की लोकप्रियता इस पर निर्भर है कि वह स्थानीय निकायों को अधिकार सौंपने तथा संविधान के शब्दों और भावना के अनुसार उन्हे शक्तिशाली बनाने के मामले में कितनी गंभीर और ईमानदार है।

पंचायतो की उपेक्षा करनेवाले राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व को इसकी बडी कीमत चुकानी पड़ी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (1993-1998) तथा उत्तर प्रदेश में (1998-2000) की सरकारों ने पंचायतों को दरकिनार कर दिया था। राजस्थान के लिए अनुपालन विधेयक पारित करने पर भी ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक की जनता सरकार (1995-1999) ने पंचायतों को सुदृढ बनाने की दिशा में सकारात्मक कार्य किया था, लेकिन इसके बाद वह उन्हें कमजोर बनाने में लग गयी, यहाँ तक कि

सरकार ने तो पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक 73वें संविधान संशोधन को विस्तृत करने

किया था, लेकिन इसके बाद वह उन्हें कमजोर बनाने में लग गयी, यहाँ तक कि उसने पंचायत चुनाव भी स्थगित कर दिये गये। इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान मे भारतीय जनता दल की तथा कर्नाटक मे जनता दल की सरकार को क्रमश 1998

चुनाव परिणामों (जून 2000) से भारतीय जनता पार्टी को गहरा झटका लगा, यहाँ तक कि राज्य में पार्टी की सरकार के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में कायम रह सकी, क्योंकि उसने पंचायती राज

तथा 1999 में विधान सभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश के पंचायती

को गभीरता से लिया था। यही बात पश्चिम बंगाल मे वाम मोर्चा की अनवरत चुनावी सफलता पर लागू होती है। सीधी-सी सच्चाई यह है कि कोई राज्य सरकार तथा उसका क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व पचायतों की उपेक्षा अपनी जोखिम पर ही कर सकता है।³⁸

महिलाओं का नेतृत्व

जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर की लोकतात्रिक सस्थाओं मे बडी सख्या में महिलाओं की सहभागिता 73वें संविधान सशोधन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। इसके फलस्वरूप आज लाखो महलाएँ नेतृत्व की भूमिका में हैं।

फलस्वरूप आज लाखो महलाएँ नेतृत्व की भूमिका में हैं। देश के विभिन्न भागो से महिलाओं के अनुभवों से पता चलता है कि उन्हें हाशिये पर रखने की कठोर संस्कृति का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निकायो

मे महिला प्रतिनिधियों को वह सम्मान नहीं दिया गया है, जिसकी वे हकदार है। विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव बताते हैं कि पंचायतों की बैठकों में निर्वाचित महिला सदस्यों को उनके पुरुष साथियों के मुकाबले भिन्न व्यवहार मिलता है, नौकरशाही उन्हें वाछित

को उनके पुरुष साथियों के मुकाबले भिन्न व्यवहार मिलता है, नौकरशाही उन्हें वाछित सम्मान नहीं देती, परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा छाया-सदस्य के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी उनके नाम पर पुरुष ही राज करते है। साथ ही, कई मामलों में देखने में आया है कि यदि वे बैठकों में भाग लेने अकेली जाती है अथवा असहमति

प्रकट करती हैं, तो उनके साथ हिंसा भी होती है। पचायतों की कार्य स्थितियाँ किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं हैं। इन मुश्किलों के अलावा, राजनीति का आम परिवेश भ्रष्टाचार, हिंसा तथा ओछी मानसिकता से सराबोर है। चुनाव लड़ने के लिए काफी

प्री खर्च करना होता है। ये सभी कारक महिलाओ मे योग्य उम्मीदवारों के चयन तथा साथ ही चुने जाने के बाद उनकी कुशलता को प्रभावित करते हैं।

महिला प्रतिनिधियों पर अत्याचार हुए हैं तथा अनेक राज्यों में अब भी जारी है।³⁴ ऐसे अनेक मामले हैं, जहाँ महिला सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये गये हैं, ताकि पुरुष उपसरपंच महिला पदाधिकारियों को पंचायती राज सस्थाओं से

एक 27

वाहर कर सके और अगले चुनावा तक स्वय सत्ता सभाल सक। पचायतो के पुरुष सदस्यों में काम कर रही हीनना ग्राँथ को कोई भी अनुभव कर सकता है। इसके विपरीत निर्वाचित महिलाएँ अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में ज्यादा जवाबदेह, सहानुभूतिशील और सरोकारमयी साबित हुई है। उनमें पुरुष सदस्यों की बनिस्वत ज्यादा निष्ठा तथा पेय जल, स्वास्थ्य सुविधाओं और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाई पडती है। अपनी तमाम समस्याओं के बावजूद उनमें से बहुत-सी सदस्य अपने मिशन में सफल हुई हैं। इस वजह से पुरुष सहयोगी आम तौर से पंचायतों में महिलाओं की उपस्थित को सहन नहीं कर पाते। बहरहाल, 1994 से महिला पचायत सदस्यों की सफलता कथाओं की फेहरिस्त लबी है। उनकी निष्ठा और नेतृत्व क्षमताओं को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन विष्ठा और नेतृत्व क्षमताओं को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन विष्ठा और नेतृत्व क्षमताओं को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन विष्ठा आहा की एक किरण है।

जमीनी ऑकड़ों और चुनावी रुझानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दस से पंद्रह वर्षों के बाद महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरो पर पचास प्रतिशत से अधिक सीटों पर होगी। पंचायतो और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की सवैधानिक व्यवस्था का एक सकारात्मक परिणाम यह है कि संसद और राज्यों की विधायिकाओं मे महिलाओं को आरक्षण देने पर राष्ट्रीय स्तर पर गरमागरम बहस चल रही है और कुछ राजनीतिक दलों ने आरक्षण के इस विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है।

अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार

चूँिक सिवधान के अनुच्छेद 244 के उपवाक्य (1) के अनुसार 73वें सिवधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान आठ राज्यों—आध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार— में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे, ससद ने 1996 में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम पारित कर 24 दिसंबर 1996 को 73वें संशोधन अधिनियम का विस्तार इन क्षेत्रों तक कर दिया। यद्यपि उपर्युक्त आठ राज्यों को एक वर्ष का समय दिया गया था कि वे अपने-अपने पंचायत अधिनियमों में इस तरह के संशोधन करें कि वे विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हो जाये, बिहार और राजस्थान ने इस अविध में अपने अधिनियमों का सशोधन नहीं किया। राजस्थान ने 26 जून 1999 को राजस्थान पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों मे उनके अनुप्रयोग से सबंधित प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 1999 जारी किया, जो अब अधिनियम की शक्ल ले चुका है। बिहार ने अभी तक अपने पंचायत अधिनियम में संशोधन नहीं किया है।

विस्तार अधिनियम आदिवासियों के स्थानीय निकायो को जितने विस्तृत अधिकार देता है, उसके कारण वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन अशात के प्रति निर्मम हैं और आदिवासियों को इतने ज्यादा अधिकार देना नहीं चाहती। ³⁶ यहीं कारण है कि इन क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है तथा आदिवासी जहाँ थे, वहीं हैं। जब तक सरकार और जन संगठन इन दूरवर्ती प्रभावोंवाले प्रावधानों को यथार्थ में बदलने के लिए ठोस प्रयत्न नहीं करते. यह अधिनियम एक रही कागज

करनेवाली बात यह है कि राज्य मरकारे, विशेषकर राजनीतिक नेता, आदिवासी क्षत्रो

1993 के बाद विस्तृत होता लोकतांत्रिक आधार

बना रहेगा।

73वें तथा 74वें सशोधनों के बाद लोकतांत्रिक 1993 तक सरकारी विभागो और उनके अधिकारी, विभागीय निदेशको से ग्राम स्तर के आधार में काफी विस्तार हुआ, जिससे योजना तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को कर्मचारियो तक, कार्यक्रमो की निगरानी करते थे। यह ऊपर से नीचे तक आनेवाला ढाँचा था। क्षेतिज रूप दिया जा सका। संसद के दो सदनों में 790 सदस्य 25 राज्य विधान सभाओं तथा केंद्र तथा राज्य है (लोक सभा 545, राज्य सभा स्तर पर चुने गये दिल्ली तथा पाडिचेरी की सदस्यां की कुल विधान सभाओं मे 4.173 245) सदस्य है (राज्य सख्या 4,963 4.072. केंद्र शासित क्षेत्र 101) राज्य स्तर से नीचे : अब * 532 जिला पचायते इनमे 95 नगर निगम इनमे 22 में महिला मेयर है 175 से अधिक जिलो मे तीसरे स्तर पर महिला अध्यक्ष है 1.436 नगरपालिकाएँ 30,00,000 सदस्य इनमें 749 से अधिक में 5.912 खड/तहसील मडल चुने जाते हैं। इनमें पयाचते : इनमे 1970 महिला अध्यक्ष है 10,0000 महिलाएँ महिला अध्यक्ष हैं 2.055 नगर पंचायते : हैं और 6,60,000 इनमें 685 से अधिक मे 2,31,630 ग्राम पचायतें अ. जाति∕अ इनमे 77,210 से अधिक महिला अध्यक्ष है जनजाति के हैं ग्राम पंचायतो मे महिला अध्यक्ष हैं

टिप्पणी तीमरी तालिका (राज्य स्तर से नीचे अब) में दी गयी सख्याएँ बदलती हुई स्थितियों के कारण वास्तविक सख्याओं के मुकाबले कुछ कम-ज्यादा हो सकती है।

राज्य वित्त आयोग

27 राज्यो और सातों केंद्र-शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने राज्य कित्त आयोगों का गठन कर लिया है और इनमें से 27 ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी है। चूँिक 73वें और 74वें संशोधनों के मुताबिक राज्य कित्त आयोगों का गठन प्रत्येक पाँच साल पर होता है, दूसरे राज्य वित्त आयोगों के गठन का समय भी आ गया है और कुछ राज्यों में तो इन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है।

बहरहाल, राज्य वित्त आयोगों की स्थिति विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। संविधान की व्यवस्था यह थी कि 24 अप्रैल 1993 से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन हो जाना चाहिए। इसके बावजूद उड़ीसा जैसे प्रमुख राज्य ने आयोग का गठन नवंबर 1996 में किया—एक साल की अविध बीतने के ढाई वर्ष बाद और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1998 में सरकार को दी। युजरात मे रिपोर्ट जुलाई 1998 में दाखिल की गयी, यद्यपि राज्य वित्त आयोग का गठन सितंबर 1994 मे हो चुका था। बिहार में राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है, परंतु यह रिपोर्ट विधान सभा में पेश नहीं की गयी है।

अनुच्छेद 243 और 243वाई के उपवाक्यों 2 और 4 के प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) अधिकांश राज्यों में विधान सभा के पटल पर रखी जा चुकी है। लेकिन गुजरात, हरियाणा और बिहार तीन ऐसे राज्य हैं, जहाँ इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई है। जिन राज्यों में कार्रवाई रिपोर्ट पेश हो चुकी है, वहाँ भी राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।

राज्य कित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय साधनों के प्रभावशाली प्रवाय के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचना कठिन है। तथापि उपलब्ध साक्ष्यों का संकेत यही है कि पंचायतीं की वित्तीय स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। तथ्य यह है कि किसी भी राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों को वित्तीय साधन नहीं दिये। कुछ तदर्थ व्यवस्थाएँ कर दी गयीं, लेकिन जो राशियाँ दी गयीं, वे आयोगों द्वारा सुझायी गयी राशियों की तुलना में नहीं के बराबर है। न ही राज्यों ने इन राशियों का आवटन उस तरीके से किया जैसा राज्य वित्त आयोगों ने सुझाया था।

जिला योजना समितियाँ

संविधान के अनुच्छेद 243जेडडी (जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया) में प्रावधान है कि राज्य सरकारें प्रत्येक जिले मे जिला योजना समिति का गठन करेंगी। यह लोगो और समुदायों की भागीदारी पर आधारित विकेद्रित योजना निर्माण की दिशा में मील का पत्थर है। जिला योजना समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मिला कर पूरे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेंगी। सभी राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो इस प्रावधान को अपने पंचायती राज और

जिले की सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को

नगरपालिका अधिनियमों में शामिल किया है या इसके लिए अलग से कानून बनाया है। संविधान के अनुच्छेद 248जेडडी (2) में जिला योजना समितियों के गठन का

काम और यह तय करने का काम कि यह गठन किस प्रकार होगा और सिमिति का अध्यक्ष पद किसे सौंपा जायेगा, राज्यों की विधायिकाओं पर छोड़ दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने जिलाधीओं को यह अध्यक्ष पद सौंप दिया, तो कुछ राज्यों मे मित्रयों को, जिनका चयन मुख्य मंत्री करते है, इन सिमितियों का चार्ज दे दिया गया। यह

के सिद्धांतो का भी।³⁷ बहरहाल, ज्यादातर राज्यों मे जिला योजना समितियो का अध्यक्ष पद जिला पचायत के निर्वाचित अध्यक्ष को दिया गया है।

न केवल सविधान संशोधन की भावना का उल्लंधन था, बल्कि लोकतात्रिक विकेद्रीकरण

यद्यपि जिला योजना समितियों का गठन राज्य सरकारो का संवैधानिक दायित्व है. कुछ राज्य सरकारो ने सिर्फ औपचारिक रूप से उनका गठन कर दिया है और

उन्हें काम करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। आध्र प्रदेश ने तो उनका गठन तक नहीं किया है। मध्य प्रदेश ने इस प्रावधान को बदलते हुए जिला सरकारों का गठन कर दिया है, जिनमें पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की कोई उल्लेख योग्य भूमिका नहीं है। केरल और पश्चिम बगाल जैसे कुछ राज्यों ने विकेंद्रीकृत योजना निर्माण को निष्ठा के साथ अपनाया है, लेकिन अन्य राज्यों द्वारा जिला योजना समितियों के गठन तथा उन्हें कार्यशील बनाने में जो शिथिलता दिखायी जा रही है, उससे यह उम्मीद नहीं बॅधती कि जिला योजना समितियों विकेंद्रित योजना प्रक्रिया का सक्षम औजार बन सकेंगी। यदि यह आशंका सही निकलती है, तो विकास की प्रक्रिया को नीचे से ऊपर ले जाने का उपक्रम, जो वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक पंचायती

ग्राम सभा का अभ्युदय

1995 से ग्राम सभा पंचायती राज पर केद्रित सभी चर्चाओं का मुख्य मुद्दा हो गयी है। जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1999 के बजट भाषण में वर्ष 1999-2000 को ग्राम

राज व्यवस्था का सारतत्व है. तत्वतः अर्थहीन हो कर रह जायेगा।

सभा का वर्ष घोषित किया, जो इससे भी ग्राम सभा के प्रति आकर्षण बढा। ग्राम सभा वह एकमात्र माध्यम है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित कर सकता

है। यह गाँव के सभी नागरिको को पंचायत की कार्यपालिका के प्रस्तावों पर विचार करने, उनकी आलोचना करने और उन्हें मंजूर या नामंजूर करने तथा पंचायत के विगत कार्य निष्पादन का मुल्याकन करने का एक अनुपम अवसर देता है। इस तरह

एक सिंहावलोकन : 31

ग्राम सभा तृणमूल स्तर पर लोकतत्र के पहरेदार की भूमिका निभाती है। यद्यपि ग्राम सभा अब एक विधिक इकाई है, इसे वह हैसियत और भूमिका नहीं मिल पायी है जो इसका प्राप्य है। ग्राम सभा आज भी पंचायती राज व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है। अधिकाश राज्य सरकारों ने इसे इसका उचित स्थान नहीं दिया है।

यद्यपि ग्राम सभाओं को गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों का चयन करने, वार्षिक योजना का प्रस्ताव करने, बजट और अकंक्षण रिपोर्ट पर विचार करने और पंचायत की प्रगति की पुनर्वीक्षण करने का अधिकार है, ज्यादातर राज्यों में उनके निर्णय पचायतों के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ग्राम सभाओं को सिर्फ परामर्शदाता की भूमिका दी गयी है। नतीजतन निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम सभाओं की परवाह नहीं करते। सिर्फ कुछ राज्यो—हरियाणा, पंजाब, उडीसा और तमिलनाडु—ने ग्राम मभा को पचायत का बजट स्वीकृत करने का अधिकार दिया है।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों का संकेत यह है कि ग्राम सभा की बैठके बुलाने की दिशा में कुछ राज्यों को सफलता मिली है, कुछ को नहीं मिली है। इस मामले में पश्चिम बगाल का रिकॉर्ड वेहतर है। 1995 में पश्चिम बंगाल की ग्राम ससदों ने बैठकों की विधि-विहित सख्या का 63 प्रतिशत तक पालन किया। 1998 में यह ऑकडा 88 प्रतिशत तक पहुँच गया। ³⁸ मई 2000 में 97 प्रतिशत ग्राम संसदों की बैठक हुई।

मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त रिपोर्टी से पता चला है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ग्राम सभा की बैठक की तारीख बहुत-से लोगों को पता नहीं रहती। चूँकि ग्राम सभा की बैठक पंचायत के मुख्यालय में होती है, दूरवर्ती गाँवों के लोगों के लिए इन बैठकों में भाग लेना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त उपस्थिति जरूर बढ़ जाती है, जब लाभार्थियों का चयन होना होता है। सामान्यत पचायत चुनावों में हारे हुए उम्मीदवार सरपच का विरोध करने के लिए लोगों को एकजुट करते हैं और ग्राम सभा में उसके द्वारा प्रस्तुत विकास योजनाओं को अवरुद्ध करने में सफल हो जाते है।

दरअसल, हमारे समाज में ग्राम सभा की संस्कृति का ही अभाव है। जाति और वर्ग के विभाजन भारत के गाँवों को एक ऐसे संगठित समुदाय के रूप में काम करने से रोकते है जो सभी के साझा हित में काम करें। ग्राम सभा को जमीनी स्तर के लोकतंत्र का प्रभावशाली औजार और हमारी पचायती राज और समाजिक व्यवस्था का अविच्छिन्न हिस्सा बनाने के लिए भूमि सुधार जैसे प्रगतिशील कदम उठाने की सख्त जरूरत है।

सामाजिक अंकेक्षण का महत्व

देने के बाद आयी। सामाजिक अकेक्षण का मतलव है समाज के बहुसंख्य लोगो की दृष्टि से, जिनके नाम पर और जिनके हित मे यह पूरा सास्थानिक ढाँचा बनाया जाता है, विकसित किया जाता है और वैधता प्राप्त करता है, किसी भी सामाजिक उपयोगिता की वस्तु या सेवा की कार्यविधि तथा उसकी सामाजिक प्रासंगिकता की जॉच और विश्लेषण। मौजूदा चर्चा के संदर्भ में इसका मतलव है लोगों द्वारा पंचायती राज सस्थाओ

सामाजिक अकेक्षण की अवधारणा भारत में पंचायती व्यवस्था द्वारा काम शुरू कर

के कार्य निष्पादन का स्वतंत्र आकलन। कई राज्यों में पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गयी है। पचायतों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विभिन्न स्तरो पर असरदार सामाजिक अंकेक्षण के लिए समितियों का गठन कर सकती है। ब्लॉक समिति तथा जिला पंचायत के

स्तर पर सामाजिक अकेक्षण समितियों का गठन, जिनकी सदस्यता सम्मानीय नागरिकों तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को दी जाये, जरूरी है, ताकि वे जब भी जरूरी और उचित समझे, विकास कार्यक्रमों का अंकेक्षण कर सके। विभिन्न संगठनो

के अवकाशप्राप्त व्यक्ति, अध्यापक और अन्य सार्वजनिक सरोकारवाले व्यक्ति, जिनकी निष्ठा सदेह से परे हो, सामाजिक अकेक्षण का गठन खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह ग्राम पचायत और नगरपालिका स्तर पर महिलाओ की प्रहरी समितियाँ. जिनमे

प्रत्येक ग्राम सभा या वार्ड सिमिति की प्रतिनिधि को स्थान दिया जाये—इनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जरूर हो—बनायी जाये, तो स्थिति मे काफी सुधार आ सकता है। इन महिला सिमितियों को वही अधिकार होने चाहिए

काफा सुधार जो सकता है। इन महिला सीमातया का वहा जाधकार होने चाहिए को नामाजिक अंकेक्षण समितियों को है। उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वे लागतो, लागत के आकलनों, विभिन्न कार्यों में लगायी गयी वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा या संख्या, चयन में मानकों का पालन आदि पहलुओं की जाँच कर सके। 99

हमारे नये लोकतांत्रिक ढाँचे में सामाजिक अंकेक्षण की शायद सर्वोत्तम ईकाई ग्राम सभा है। ग्राम सभा के सभी सदस्य तथा स्थानीय निकायो—ग्राम पंचायतों, पचायत सिमितियों और जिला परिषदों—के सभी वर्ग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सामाजिक सरोकार तथा जन हित के मुद्दे उठा सकते हैं और स्पष्टीकरण की मॉग कर सकते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से आनेवाली रिपोर्टों के अनुसार ग्राम सभा की अनेक बैठके सामाजिक अंकेक्षण का बहुत ही प्रभावशाली माध्यम साबित हुई है। ग्राम सभा की संस्था को सामाजिक अंकेक्षण का सर्वोत्तम औजार बनाने के लिए जमीनी स्तर पर अभी काफी काम करने की जरूरत है।

सूचना का अधिकार

पंचायती राज के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में एक सार्थक विकास हुआ है सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए मंघर्ष के रूप में। राजस्थान की पाली और राजसमंद जिला परिषदों में मजदूर किसान शक्ति सगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह तथ्य उद्वादित हुआ है कि विकास परियोजनाओं के अनुमानित बजट का 85 प्रतिशत हिस्सा विकास कार्यों पर खर्च हुआ ही नहीं। पंचायत प्रतिनिधियों ने व्यय की गयी राशि पर सरकार की स्वीकृति लेने के लिए फर्जी वाउचर और बिल दखिल किये थे। ये घपले सगठन द्वारा आयोजित जन सुनवाइयों के दौरान सामने आये। ऐसी ही घटनाओं से यह माँग पैदा हुई कि जनता को सूचना का अधिकार होना चाहिए।

सूचना के अधिकार के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन के संघर्ष के फलस्वरूप राजस्थान के मुख्य मत्री ने अप्रैल 1995 में राज्य की विधान सभा में घोषित किया कि प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है तथा वह भुगतान दे कर अपने गाँव में पिछले पाँच वर्षों की अविध में हुए विकास कार्यों पर हुए खर्च का विवरण प्राप्त कर सकता है तथा प्रमाण के रूप में भविष्य में इस्तेमाल के लिए सभी दस्तावेजों की फोटो-प्रित भी ले सकता है। तिमलनाडु, गोआ, केरल और मध्य प्रदेश में भी सूचना के अधिकार के सदर्भ में ऐसी ही व्यवस्थाएँ की गयी है। मध्य प्रदेश में भी सूचना के अधिकार के सदर्भ में ऐसी ही व्यवस्थाएँ की गयी है। मध्य प्रदेश ने 1998 के शुरू में अपने बहुत-से विभागों में, जिनमें से एक पंचायती राज भी था, जनता द्वारा जॉच के लिए खोल दिया। उत्तर प्रदेश ने भी पचायती राज के बहुत-से विभागों को इसी तरीके से पारदर्शी बना दिया है। सूचना के अधिकार का आदोलन धीरे-धीरे जोर पकड रहा है। इस आंदोलन की गति धीमी जरूर है, पर यह निरंतर आगे बढ रहा है। जैसे-जैसे दूर्सरे-राज्य भी सरकारी रिकार्डों को जनता के लिए पारदर्शी बनाते जायेगे, सामाज़िक अंकेक्षण का विचार फैलता जायेगा और तृणमूल स्तर के लोकतत्र को ज्यादा असंग्दार तरीके से काम करनेवाला बनायेगा। "

गैरसरकारी संस्थाएँ

गैरमरकारी संस्थाएँ, सामुदायिक पहले, जन संगठन और स्वैच्छिफ संगठन पचायतो और नगरपालिकाओं को मजबूत वनाने की दिशा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 73वें और 74वे संविधान संशोधन के बाद से बहुत-सी गैरसरकारी संस्थाएँ जागरूकता वढान, निर्वाचित प्रतिनिधियों—खासकर महिलाओं—को प्रशिक्षित करने, चुनावों मे महिलाओं की सिक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और सामाजिक विकास की रणनीतियाँ वनाने तथा उन्हें लागू करने के कार्यक्रमों के मध्यम से पचायतों की सफलता के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा करने मे उद्येशक की भूमिका निभा रही हैं। भारत मे स्थानीय निकाय अपनी सवैधानिक वैधता और नागरिक समूह्ये और स्वैच्छिक संगठनों के साथ अन्तर्क्रिया के कारण राज्य और समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का आदर्श मिलन बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का सम्बन्धा सिक्स बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का सम्बन्ध सिक्स बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का सम्बन्ध सिक्स बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। भार समाज का स्वत्य सिक्स स्वत्य समाज स्वत्य समाज सम्बन्ध सिक्स सिक्

पचायतो की भूमिका पर काफी सरगर्म बहस हुई है। स्वशासन की संस्थाओं के रूप मे पचायते तो सभी जगह हैं, लेकिन गैरसरकारी सस्थाओं की उपस्थिति व्यापक नहीं है। सच तो यह है कि आवश्यकता और विशेषज्ञता के आधार पर गैरसरकारी संस्थाओं

यहा यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों मे गैरसरकारी सस्थाओ और

है। सच तो यह है कि आवश्यकता और विशेषज्ञता के आधार पर गैरसरकारी संस्थाओ का काम कुछ ही जिलो, ब्लॉको और गाँवो तक सीमित है। नयी पचायतों के अस्तित्व

में आने के बाद चार तरह की स्थितियाँ सामने आयी हैं : (क) उन जन संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों ने, जो ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे जहाँ न तो पंचायतें थीं और न ही स्थानीय पहले. अपने आपको उन क्षेत्रो

में स्थापित कर लिया है। ये संगठन पंचायतों को ऐसे नवागतुको के रूप में देखते हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में दखल देंगे। (ख) नव-गठित पंचायतें स्वैच्छिक क्षेत्र को—जो सामुदायिक पहलों और स्वैच्छिक

सगठनो तथा गैरसरकारी सस्थाओ को मिला कर बनता है—अपने विधि-विहित कार्य

क्षेत्र में प्रतिद्वर्द्धी की तरह देखती है। (ग) तीसरी स्थिति यह है कि पंचायतें और स्वैच्छिक संगठन, दोनों अपनी-अपनी भूमिका और उसकी सीमाओं को अच्छी तरह समझते हैं और एक-दूसरे के पूरक

की तरह सहयोग और समन्वय के साथ काम करते हैं। (ध) कुछ इलाको में स्वैच्छिक संगठन पंचायत चुनावों में हिस्सा लेते हैं और

अपने उम्मीदवार भी खड़े करते है। राजनीतिक दल भी पंचायत चुनावो में सिक्रिय भागीदारी करते हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र के उम्मीदवार या तो किसी पार्टी का टिकट पा लेते हैं या निर्वलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं। सबसे निचले यानी ग्राम पंचायत के स्तर पर उनकी सफलता दर सबसे ज्यादा है। यह भी देखा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने स्वैच्छिक संगठनों में काम किया है या उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया

है, वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में ज्यादा दक्षता के साथ काम कर पाते हैं। ⁴² बहुत-से राज्यों में कुछ पचायतें निष्क्रिय हैं और लोग उनसे विमुख है। गैरसरकारी सगठन ऐसी पंचायतों के प्रति नकारात्मक रुख अख्तियार कर लेते है। डी. बद्योपाध्याय ने ठीक ही लिखा है स्वैच्छिक संस्थाओं को 'सपने में भी यह नहीं सोचना चाहिए

ने ठीक ही लिखा है स्वैच्छिक संस्थाओं को 'सपने में भी यह नहीं सोचना चाहिए कि पंचायतें उनकी हैसियत, स्थान और शक्ति से होड़ कर रही हैं। यह बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्तरों की पंचायते, प्रतिनिधिक शासन की इकाइयों के रूप में, बुनियादी स्थान की हकदार हैं।'⁴³

भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या काफी बड़ी है। एक जीवंत और सक्रिय समाज तथा उसका आलोचनात्मक समर्थन पचायती राज सस्याओं के भविष्य के लिए सर्वाधिक मुल्यवान संपत्ति है।

पंचायतों का अतिक्रमण

पिछले पाँच-सात वर्षो में पंचायतो के काम-काज की समीक्षा करते समय नीन चिताजनक रुझान दिखाई देते है जिनका उल्लेख जरूरी है : (1) पंचायत चुनावों को स्थिगित करना, (2) समानातर ढाँचे खड़ा करना, और (3) सांसदो का चुनाव क्षेत्र विकास कोष।

1. पंचायतों का चुनाव स्थिगत करना : कुछ राज्य सरकारो पर यह एक दुखद टिप्पणी है कि पंचायतो का पाँच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर उनके चुनाव कराने की संवैधानिक व्यवस्था को उन्होंने गभीरता से नहीं निया है। संविधान का अनुच्छेद 243बी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में गाँव, मध्यवर्ती स्तर और जिले के स्तरो पर पंचायतें होगी; और (1) प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की निर्धारित तारीख से पाँच वर्ष तक काम करेगी—उससे ज्यादा नहीं, और (2) पचायत का गठन करने के लिए चुनाव उसका पाँच वर्ष का कार्य काल समाप्त होने के पहले या उसे भंग किये जाने की स्थिति में भंग होने के छह महीनों के भीतर सपन्न कराया जाना चाहिए। (अनुच्छेद 243ई (1) तथा (3))

कई राज्यों में यह व्यवस्था है कि राजनीतिक दल ब्लॉक और जिला पचायतो के चुनावों में तो आधिकारिक रूप से हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ग्राम पचायतों के स्तर पर नहीं। बहरहाल. राजनीतिक दल ग्राम स्तर से ही पचायतों पर कब्जा करने के प्रति तत्पर रहे हैं और सत्तारूढ दल या सत्तारूढ दलों का गठबंधन अपने कार्य काल के मध्य में या उसकी समाप्ति के आसपास जनता का सामना करने से डग्ता है। कोई भी सत्तारूढ दल या सत्ता पाने का अभिलाषी दल अगले विधान सभा चुनावो के पहले विभिन्न स्तरों की पंचायतों में सीट खो कर अपनी राजनीतिक साख गिरते नहीं देखना चाहता। भारत के परिपक्व हो रहे लोकतत्र की तारीफ में यह कहना ही होगा कि प्रत्येक चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित होते है यानी राजनीतिक दल यह मान कर नहीं चल सकते कि उन्हे मतदाता का समर्थन मिलेगा ही। इसलिए हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि सरकारी दल और विपक्षी दल दोनो पंचायत चुनावों को स्थगित करने या करते जाने के मामले मे हाथ मिला लेते हैं. ताकि उन्हे मतदाताओं का सामना न करना पड़े। पचायत चुनाव टालने का एक तरीका यह होता है कि राज्य के मौजूदा पंचायत अधिनियमों में यहाँ या वहाँ कोई कमी निकाल कर या प्रतिक्ल मौसम के नाम पर या राज्य के किसी हिस्से में नागरिक अशांति के हवाले से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी जाये, ताकि पंचायत चुनावा को संपन्न करने पर स्थगन आदेश प्राप्त किया जा सके।

राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं की तरह काम नहीं कर रहे हैं। बहुत-से राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकारों के दबावों के सामने झुक जाते है। कुछ ने तो ऐसी स्थिति में भी चुनाव स्थिगत कर दिये है, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी होती है। बहरहाल, इस आम स्थिति के शानदार अपवाद भी है—कई राज्य चुनाव आयोगो ने राज्य सरकारों के दबावो को अमान्य करते हुए पंचायत चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह किया है।

जब कोई मामला न्यायालय में जाता है, तो फैसला आने में समय लगता है। इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार है। 9 अप्रैल 1996 को बिहार सरकार ने पटना

उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे अपील की कि पचायत चुनावों मे (अन्य) पिछड़ी जातियों को दिया गया आरक्षण वैध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 1977 में इस अपील को सविधान खंडपीठ के पास विचारार्थ भेज दिया। अभी तक, यानी 26 वर्ष बीतने के बाद भी, इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश न होने का लाभ बिहार सरकार ने इस तरह उठाया कि काफी समय तक पचायत चुनाव कराये

ही नही।

पचायतो के खिलाफ जो एक निर्णायक कारक हमेशा सिक्रय रहता है, वह यह है कि राज्य सरकारें उनके साथ उच्चतर शासन और प्रशासनिक तंत्र के गरीब रिश्तेदारो जैसा नजिरया अपनाये हुए है। सिवधान की नजर में ससद का सदस्य, विधान सभा का सदस्य और पचायत का सदस्य—तीनों ही हमारे लोकतात्रिक ढाँचे में बराबर हैसियत के हकदार हैं। सिर्फ उनकी शक्तियाँ और भूमिकाएँ उनके चुनाव क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग हैं। इस स्थित को स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय एक साफ-साफ फैसला दे दें, तो उससे देश में लोकतांत्रिक संस्कृति स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी।

2. समानांतर ढॉचे : केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकारों के विभाग, जिनका कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास तथा कल्याण जैसे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंध है, लगातार ऐसे ढॉचे खडे कर रहे है जो पंचायता के समानांतर काम करते हैं—खासकर जिला स्तर पर। इनमें से कुछ रजिस्टर्ड सोसायटियाँ हैं, जो पंचायती राज सस्थाओं की कीमत पर बनायी गर्या है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागो द्वारा इन्हें भारी कोष दिया जाता है। ये सोसाटियाँ अगर इस कोष का कुछ अंश पचायत समितियों या ग्राम पंचायतों को आवंटित करती है, तो उसके उपयोग के साथ शर्ते लगी होती है। केंद्र सरकार के बहुत-से मत्रालय ओर राज्य सरकारों के बहुत-से विभाग केंद्र या राज्य द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रमों का संचालन या क्रियान्वयन करते हैं। इसके लिए राज्यों में ब्लॉक या ग्राम स्तर तक सरकारी कर्मचारी होते हैं। यह कार्य पद्धित भी पचायती राज संस्थाओं की उपेक्षा करती है। जो काम पंचायतों का है, वह दूसरे लोग करते हैं।

इन समानांतर ढाँचो के तहत आनेवाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है .

- (क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) यद्यपि केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने जिला प्रामीण विकास अभिकरणों को खत्म कर जिला पचायतों में उनका विलय कर दिया है, इन अभिकरणों को पुनर्जीवित करने पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मत्रालय गंभीरता से यह सोच रहा है कि डीआरडीए का अध्यक्ष सांसद को और सचिव जिला कलक्टर को बना दिया जाये।
- (ख) जलागम विकास कार्यक्रम : इन कार्यक्रमों को ज्यादातर कृषि मत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। कुछ गैरसरकारी संस्थाएँ भी इनसे जुड़ी हुई है। यद्यपि जलागम विकास के लिए जिला पचायतों को कोष का आवंटन करने में कोई कठिनाई या तकनीकी बाधा नहीं है, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। कायदे से होना यही चाहिए कि जो एजेंसी जलागम कार्यक्रम को लागू कर रही है, उसे जिला पचायत से कोष मिले। इसका लाभ यह होगा कि इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी एक लोकतात्रिक रूप से चुनी गयी संस्था, जिला पंचायत, पर होगी।
- (ग) सयुक्त वन प्रबंध समितियाँ . फिलहाल संयुक्त वन प्रबंध समितियाँ पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन काम कर रही हैं। वे ग्राम सभा या ग्राम पचायत या पचायत समिति—किसी के प्रति भी जिम्मेदार नही है। जिन इलाकों में वन लगाने और सामाजिक वानिकी मे पंचायती राज सस्थाओ की भूमिका काफी बड़ी हो सकती है और अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज के प्रबंध में तो ऐसा है ही, सयुक्त वन प्रबंध समितियाँ पंचायती राज के दायरे के बाहर काम कर रही हैं।
- (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : 73वॉ संविधान सशोधन अधिनियम, 1992 राज्य सरकारों को यह भार देता है कि वे शिक्षा का विषय, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रौढ़ और अनीपचारिक शिक्षा शामिल हैं, पचायतों को दे दें। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीर्डपी) पाँच वर्षों की अविध का है। इसके लिए कोष विश्व बैंक ने प्रदान किया है। इसका लक्ष्य पिछड़े इलाकों में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना है। इसमें जोर बच्चों की निरक्षरता को समाप्त करने पर है। यह कार्यक्रम कुछ चुने हुए राज्यों के लगभग 150 जिलों में चल रहा है। नेशनल काउसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने चार राज्यो—हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार—में डीपीईपी की सरचना का पंचायती राज सस्थाओं से किस प्रकार का अन्तरसंबंध है, यह जानने के लिए एक अध्ययन कराया। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि डीपीईपी एक समानांतर ढांचे की तरह काम कर रहा है और पंचायती राज संस्थाओं से इसका कोई सिक्रिय अन्तरसंबंध नहीं है। है

केद्रीय मत्रालयों और विभागों द्वारा बनाये गये समानानर टॉचों के अलावा राज्य सरकारें भी पंचायतों को उपेक्षा करने और उन्हें कमजोर वनाने के लिए अपनी योजनाएँ चला रही है। इस संदर्भ में आध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के उदाहरण विशेष रूप सं उल्लेखनीय है।

बस्ती विकास कार्यक्रम आदि केंद्र प्रायेजित योजनाओं के लिए आवंटित की गयी राशियों को जन्मभूमि कार्यक्रम मे लगा दिया गया है। अध्ययनो से पता चलता है कि इन कोषों के उपयोग के लिए जो मानक निर्धारित किये गये हैं, उनकी उपक्षा होती है। दसवें चक्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण, महिला विकास ओर बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, श्रम, शिक्षा, युवा कल्याण, खेल, नगरपालिका प्रशासन, पशु पालन, कृषि, बागवानी और रेशम उत्पादन से हटा कर राशि जन्मभूमि कार्यक्रमां को दे दी गयी। नोडल अफसरो को विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेट, हैदराबाद द्वारा किये गये एक अध्ययन का निष्कर्प है - 'पंचायती राज संस्थाओं के उन सदस्यों की, जो सत्तारूढ़ दल में न हो कर अन्य दलों के सदस्य है. इस कार्यक्रम में कोई भागीदारी नहीं है। इसने पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों की उपेक्षा कर प्रशासन का एक समानातर ढाँचा खड़ा कर दिया हे. जिसमे विधायकों तथा अन्य राजनेताओ को ज्यादा महत्व दिया गया है।'* (च) जिला सरकार: 1999 के शुरू में मध्य प्रदेश सरकार ने जिला सरकारो की स्थापना की, जिसके मुख्य अधिकारी थे राज्य सरकार का एक मंत्री, जिला कलक्टर, विधायक, क्षेत्र का सासद और जिला परिषद के प्रतिनिधि। जिला सरकार को विस्तृत अधिकार प्रदान किये गये है। कलक्टर ही जिला सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिस कारण उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ गयी है। यह सब किया गया है सविधान के अनुच्छेद 243जेडडी का उपयोग करते हुए, जिसके तहत जिला योजना समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। कायदे से जिला सरकार की सज्ञा जिला पंचायत जैसी विकेद्रित लोकतात्रिक संस्था को दी जानी चाहिए, क्योंकि जिला पचायत के सदस्यों का चुनाव जिले के लोगों द्वारा होता है। लेकिन जिला पंचायत को दरिकनार कर मध्य प्रदेश ने जो जिला सरकार बनायी है, वह एक प्रतिनिधि नहीं, नामांकित संस्था है। इसके दो निहितार्थ हैं: (1) जिला पंचायत अध्यक्ष की हैसियत कम हो गयी है—उसका स्थान जिला सरकार के नीचे हो गया है। (2) जिला मरकार के माध्यम से, जो संवैधानिक इकार्ड नहीं है, एक स्पष्ट रूप से समानातर

(ङ) जन्मभूमि आध्र प्रदेश में जन्मभूमि कार्यक्रम ने पचायतो को काफी आघात पहुँचाया है। 'आध्र प्रदेश एक कपनी का नाम है, लोग इसके शेयरहोल्डर है ओर मुख्य मत्री जनरल मैनेजर हैं'—1 जनवरी 1997 को दक्षिण कोरिया के सीमॉल उनडॉग (नया समुदाय आदोलन) की तर्ज पर शुरू किये गये जन्मभूमि कार्यक्रम का उद्देश्य-वाक्य यही है। जन्मभूमि के नौ चक्रो के लिए राज्य सरकार ने 1521 करोड़ 89 लाख रु. का लक्ष्य रखा है। इसमें सरकारी अंशदान 975 करोड़ 95 लाख रु का है। सरकारी अशदान के लिए रोजगार आश्वासन योजना, ग्रामीण पेय जल योजना, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित आदिवासी विकास एजेसी, डीपीईपी. राष्ट्रीय मलिन

एक 39

ढाँचा खड़ा कर दिया गया है। यह पचायती राज प्रणाली के विकास को बहुत दूर तक प्रभाविन करेगा। दूसरे राज्य स्वशासन की स्थानीय इकाइयों की शक्तियों के साथ भितरधात करने के लिए मध्य प्रदेश के उदाहरण का अनुकरण कर सकते है।

3. सांसद कोष: सांसद चुनाव क्षेत्र विकास योजना की घोषणा तत्कालीन प्रधान मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में 23 दिसंबर 1993 को की। इस योजना के तहन प्रत्येक सांसद को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने चुनाव क्षेत्र में जिला कलक्टर को ऐसे विकास कार्यक्रम सुझा सकता है जिनका वार्षिक मूल्य एक करोड़ से अधिक न हो। सांसद चुनाव क्षेत्र विकास योजना के तहत किये जा सकनेवाले 23 कामों की सूची बनायी गयी थी; जैसे, स्कूल भवनों, ग्रामीण सड़कों, पुलो तथा वृद्धों के लिए आश्रय स्थानों और ग्राम पचायतों, अस्पतालों और सांस्कृतिक व खेलकूट की गतिविधियों के लिए निर्माण कार्य, नल कूपों की खुदाई आदि। केद्रीय सरकार समय-समय पर इस सूची में संशोधन कर सकती है। इस योजना के लिए राशि ग्रामीण विकास मत्रालय द्वारा जिला कलक्टरों को भेजी जाती है। किसी एक निर्माण या विकास कार्य के लिए अधिकतम दस लाख रु. खर्च किये जा सकते है। फिलहाल सांसद कोष की रकम दो करोड़ रु. प्रतिवर्ष है।

स्पष्टतः सासद कोष की पूरी परिकल्पना 73वे सिवधान संशोधन के प्रावधानों और भावना पर कुठाराघात है। कि ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243जी) और बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243जब्दू) में 47 विषयों की मूची दी गयी है, जिनसे संबधित काम करना स्थानीय सरकारों का विशेपाधिकार है। वैसे, तकनीकी तौर पर यह सूची भी अंतिम नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारे स्थानीय निकायों के कार्यों का वितरण करने में किसी भी हद तक जा सकती है। दिलचस्प यह है कि सासद कोष का उपयोग जिन 23 कामों के लिए विहित किया गया है, वे सभी ग्यारहवीं अनुसूची में बताये गये 29 विषयों से संबधित हैं और पंचायतों के विषय हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 74वं सिवधान संशोधन के अनुच्छेद 248जेडडी के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला योजना सिमित का गटन अनिवार्य है। लेकिन जिला स्तर पर कोई योजना कैसे बनायी जा सकती है, जब सासदों की अपनी प्राथमिकताएँ हों और उन्हें भारी रकमें खर्च करने की सुविधा दी गयी हो? कई रिपोर्टो में यह बात कही गयी है कि सासद कोष का दुरुपयोग हो रहा है या यह कोष भारी मात्रा में अव्यवहृत पड़ा रहता है।

कुछ राज्यों में, ऐसी ही योजनाएँ विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी शुरू की गयी है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि कुछ नगरपालिकाओं ने (जैसे, राजस्थान और दिल्ली में) पार्षदों के लिए भी इस प्रकार का कोष आवंटन करना शुरू कर दिया है। यह एक खतरनाक लक्षण है और स्थानीय निकायों के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण करने का निदनीय प्रयास है।

तिरोध ओर बाधाए

चायती राज का मूल आधार अनुवर्तित्व का सिद्धात है। अनुवर्तित्व का सिद्धात ह है कि जो काम निचले स्तर पर सर्वोत्तम हम से किया जा सकता है, वह काम सी स्तर पर किया जाना चाहिए—उससे ऊँचे स्तर पर नहीं और जो काम निचले तर पर नहीं किया जा सकता, सिर्फ वहीं काम ऊपर के स्तर पर किया जाना चाहिए। ह स्वाभाविक है कि शुरू के वर्षों में गलतियाँ हो और उनसे सीख कर भविष्य ह लिए उचित कदम उठाये जायें। वस्तुतः यह पंचायती राज की प्रयोगावस्था है। देखले कई दशकों में राजनीतिक नेताओं और नौकरशाही का जो नजरिया हावी रहा ', उसे बदलना आसान नहीं है। प्रयोगावस्था की अविध को कम करने के लिए हीन-से उपाय करने की जरूरत है। यह एक महत्वपूर्ण सरोकार है।

केंद्र, राज्य और जनता के स्तर पर जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान खोजा ज्ञाना चाहिए, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- * राज्यों ने 73वं और 74वें सविधान सशोधनों के शब्दों का पालन किया है—उनकी भावना का नहीं। बहुत-से राज्यों के पंचायत अधिनियमों में नीकरशाहा को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकायों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दे दिया गया है। पंचायतों को शिक्तयों और कार्यों का अवगमन बहुत ही मथर गति से हो रहा है। यह अवगमन उचित तरीके से हो सके, इसके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि नीचे से यानी ग्राम सभाओ, ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों तथा जागरूक नागरिकों के सगठनों से आवाज उठायी जाये।
- * यद्यपि सभी राज्यों ने सविधान संशोधनों के अनुरूप अधिनियम पारित कर दिये हैं, पर उनमें से बहुतों ने पंचायतों के रोजमरें के काम-काज के लिए नियम-उपनियम नहीं बनाये है। विभिन्न प्रशासनिक विभाग अभी भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे वे नयी पंचायतों के गठन के पहले काम कर रहे थे। बहुत-से राज्यों में प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी राजधानी के विभागीय प्रमुखों के अधीन काम कर रहे हैं और इन कर्मचारियों पर पंचायतों का कोई नियंत्रण नहीं है। परिणामस्वरूप पंचायत स्तर पर कर्मचारियों का घोर अभाव है, जिससे पंचायतों का काम-काज प्रभावित हो रहा है। अधिकाश राज्यों में, ग्राम पंचायतों का काम-काज प्रभावित हो रात पंचायतों का कार्य भार सँभाल रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान में 9187 ग्राम पंचायतों के लिए 3668 सचिव है यानी औसतन 2.5 ग्राम पंचायतों पर एक सचिव। जनजातीय क्षेत्रों में एक ही सचिव तीन से चार पंचायतों की देखभाल करता है। इस्टीट्यूट ऑफ सोशल

साइमेज द्वारा कियं गये एक अध्ययन से पता चला है कि सरपंच कई बार पचायत की वैठक को इसलिए स्थिगित कर देते है कि पचायत सचिव उस बैठक में उपस्थित नहीं हो सका था। 48 इस समस्या का एक समाधान यह है कि शासकीय कर्मचारियों का एक पचायत कांडर बनाया जाये।

- * शासन के निचले स्तर पर यानी पचायतों के महत्व, उनकी स्वायत्तता. उनकी शक्तियों और उनके कार्य क्षेत्र को मान्यता देने में राज्य स्तर के राजनेताओं की हिचकिचाहट भी शक्तियों के हस्तातरण में समस्या पैदा कर रही है। मत्री, विधायक और वरिष्ठ राजनेता चितित है कि अगर पचायते और नगरपालिकाएँ शक्तिशाली हो जाती है, तो वे स्वयं जिन अधिकारों का उपभोग करते आ रहे हैं, उनमें कटौती हो जायेगी। राज्य स्तर के नेता स्थानीय स्तर के नेतृत्व का उभरना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे भविष्य में उनके लिए चुनौती खड़ी हो जायेगी। सासद और विधायक पनायतो की बाधारहित कार्यशीलता के मार्ग मे अवरोध खडे करते है, ताकि उन्हे पूरे कद की स्थानीय सरकारों के रूप में उभरने से रोका जा सके। विधायक उन भारी-भरकम रकमो पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उतावले हैं जो डीआरडीए जैसी एजेसियो के जरिये केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए भेजी जा रही है। जब पचायते निर्वाचित प्रतिनिधियो की बड़ी संख्या के साथ और विपक्ष की आलोचनात्मक दृष्टि के रू-ब-रू पूरी सक्रियता से अपना काम-काज शुरू कर देगी, तो लोग पचायतों के कार्यक्रमो और गतिविधियों में भागीदारी के जरिये अपने अधिकारों से वाकिफ हो जायेंगे। इसका नतीजा होगा विधायकों को इस समय जो अतिरिक्त अधिकार मिले हुए हैं, उनमें कटौती । अतः पंचायती राज सस्याओं के प्रति सांसदों और विधायको के मौजूदा रुख को बदलने के लिए सभी स्तरो पर प्रयत्न करने की जरूरत है।
 - * सरकारी अधिकारी आम तौर पर किसी दूरस्थ नियत्रण बिन्दु अर्थात राज्य की राजधानी से अनुशासित होना पसद करते हैं। वे नहीं चाहते कि पंचायती राज के प्रतिनिधि निकट से उन पर निगरानी रखें। इसलिए पंचायत सदस्यों के साथ उनका असहयोगपूर्ण व्यवहार एक प्रमुख मुद्दा है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के अखिल भारतीय संघ ने पंचायतों के अधीन काम करने की शिक्षकों की अनिच्छा जतानेवाले प्रस्ताव पारित किये। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी, जहाँ पंचायती राज का लबा इतिहास है, जब भी सरकारी कर्मचारियों को पंचायतीं के अधीन किया जाता है, वे ऐसं तबादलों को रुकवाने के लिए अदालत से स्थगन आदेश लाने में सफल हो जाते है। इसी से सबधित मुद्दा यह है कि जो अफसर जिला या उससे

नीचे के स्तर पर कार्यरत है, वे निर्वाचित पचायत कार्यकारियां—जैसे, जिला पचायत अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष या ग्राम पंचायत अध्यक्ष से आदेश

लेने में झिझकते हैं। स्पप्ट है कि स्थानीय सरकारों को सुदृढ बनाने क लिए हमें नौकरशाही के अपने ढॉचे में लोकतत्र की नयी सस्कृति का संचार करना होगा।

देश के वहुत-से हिस्सों में राजनीतिक सचेतनता का निम्न स्तर, सामाजिक पिछडापन, निरक्षरता और जातिवाद—ये ऐसे कारक है जो नये पचायनी राज को पीछे की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। सामंती मूल्य आर

सस्कार अब भी काफी दृढ़ है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा मे—जहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 40 करोड़ लोग रहते है—पचायती राज के कार्यक्रम का स्तर संतोपजनक नहीं है। यद्यपि मध्य प्रदेश 73वें सविधान संशोधन के बाद पचायत चुनाव करानेवाला

यद्याप मध्य प्रदश 73व सावधान संशोधन के बाद पचायत चुनाव करानपाला पहला राज्य है, इन चुनावों के बाद जल्द ही इस आशय की रिपोर्टे आन लगी कि पंचायतों का हाल ठीक नहीं है और स्त्रियों, अनुसूचित जातियों

तथा कि पंचायता का हाल ठाक नहां है जार स्त्रिया, जनुसूचत आरापा तथा अनुसूचित जनजातियों के जो प्रतिनिधि निर्वाचित हो कर आये है, वे कॅची जातियों के अत्याचार का शिकार हो रहे है। इन हिसक घटनाओं

व ऊचा जातिया के अत्याचार का शिकार हा रहे हैं। इस हिसके बटनाओं की एक समाजशास्त्रीय तहकीकात का निष्कर्य यह है कि 'पचायत उस समाज का एक सुक्ष्म संस्करण होती है गाँव जिसका हिस्सा होता है। 73व

सशोधन में प्रतिपादित स्वशासन की सस्थाओं के उच्च आदर्शों को मानृदा अन्यायपूर्ण समाज में यथार्थ में रूपातरित नहीं किया जा सकता।'" इस

दिशा में खास-खास मामलों के जो भी अध्ययन किये गये, उन सभी में एक ऐसी सामाजिक प्रणाली की झलक थी, जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन करती है और एक ऐसी सामाजिक मूल्य प्रणाली की भी, जो किसी

व्यक्ति या उसके द्वारा धारण किये जानेवाले पद को वह सम्मान नहीं देती जो उसे मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश, सामाजिक परिवर्तन का निर्णायक मुद्दा किसी की कार्य सूची में नहीं है—न तो सरकार की, न राजनीतिक दलों की और न ही नागरिक संगठनों की कार्य सची में। वहत-सी जगहों पर

की और न ही नागरिक संगठनो की कार्य सूची में। वहुत-सी जगहों पर पुरानी व्यवस्था किसी नयी व्यवस्था के लिए स्थान खाली नही कर रही है। स्वयं पचायते ही अत्याचार के औजार के रूप मे काम कर रही है। भूमि सुधारों का न होना, स्त्रियों में साक्षरता का नीचा स्तर, पितृसत्तात्मक

सत्ता इत्यादि गाँवों में कमजोर वर्गों के खिलाफ जाते हैं। इससे महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। बहुसख्य लोग, जो परपरागत अत्याचारी सत्ता ढॉचे द्वारा दबाये हुए है, पंचायतो द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अवसरो का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। शक्तिशाली पचायतो की नयी प्रणाली क अस्तित्व में आनं के बाद चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद पचायतों के कामकाज के दौरान गंभीर सघर्ष हुए हैं। पिछड़े हुए इलाकों में पचायत चुनावों के समय व्यापक हिंसा होती है। अतएव समय की माँग यह है कि समाज के जिन वर्गों को सत्ता के दायरे से बहिष्कृत रखा गया है, उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया जाये।

 पंचायत सदस्यों की अधिसंख्या अल्प शिक्षा-प्राप्त और निरक्षर भी है। इनमं से बहुतों ने, खास तौर से महिलाओं ने, सार्वजनिक जीवन की तो छोडिए. पचायतों में ही पहली बार प्रवेश किया है। अतः स्वाभाविक है कि तकनीकी पहलुओं को समझने और उनके अनुसार काम करने में उन्हे दिक्कत आती हो। उन्हें पंचायत के काम-काज में प्रशिक्षण देने की सख्त जलरत थी। नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेट, हैदराबाद, राज्यों में गठित इस्टीटयट ऑफ रूरल डेवलपमेट और कतिपय गौरसरकारी संस्थाएँ पंचायती राज सस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण देने में जुटी हुई है। इंस्टीर्यूट ऑफ सोशल साइसेज द्वारा किये गये एक अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र मे अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण की अवधि छोटी थी. प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाओं या जहाँ प्रशिक्षण दिया गया, उन केंद्रों का हाल ठीक नहीं था, प्रशिक्षण देनेवाली टीमो को मिला ढॉचागत समर्थन अपर्याप्त था, बहुत-से प्रशिक्षक अपने काम के प्रति उदासीन थे-उनमे कोई उत्साह नहीं था, दूरस्थ माध्यमों से दिया गया प्रशिक्षण काम का साबित नहीं हुआ, इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ कि प्रशिक्षण कार्यक्रमो का प्रभाव क्या पडा, न ही प्रशिक्षण के बाद का अनुवर्ती कार्यक्रम चलाया गया, प्रशिक्षण देनेवाली सस्थाओं के बीच तथा उनके और सरकार के बीच समन्यय का अभाव था। इसके अलावा प्रशिक्षण की विषयवस्तु और उसका दायरा, दोनो ही अपर्याप्त थे। 50 प्रत्येक पाँच वर्ष पर या इसमें कम अन्तराल पर भी 30 लाख निर्वाचित पंचायत सदस्यो को प्रशिक्षित करना एक बृहत काम है। उनके प्रशिक्षण पर ही लोकतंत्र और जिला तथा उससे नीचे के स्तर पर काम कर रही लोकतांत्रिक संस्थाओ का भविष्य निर्भर है। साथ ही, प्रशिक्षण एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। इसिलए इस बृहत चुनौती का मुकाबला करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों, भारत में कार्यरत अन्तरराष्ट्रीय विकास सगठनों तथा गैरसरकारी संगठनों के पास जो भी ढाँचागत सुविधाएँ हैं, सूचना की जो भी टेक्नोलॉजी है और जितने भी प्रशिक्षक हैं, उन सभी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सशोधनों की जरूरत

पिछले एक दशक के अनुभवों के आधार पर यह आम भावना बनी है कि संविधान के ग्यारहवें भाग में समाविष्ट 73वे और 74वे संशोधनों पर पुनर्विचार की जरूरत है, तािक उनके प्रावधानों को सशक्त बनाया जा सके और अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इन प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है—(1) ग्राम सभा और उसका कार्य क्षेत्र, ग्राम सभा को उपयोगिता और प्रभावशीलता को केसे बढ़ाया जाये, (2) पचायती राज सस्थाओं की समरूप त्रिस्तरीयता तथा विभिन्न स्तरों के वीच आवयविक एकसूत्रता की बांछनीयता, (3) पंचायतों में सासवों और विधायकों की उपस्थित, (4) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण—चूँकि विधान सभाओं और ससद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं है, क्या पंचायतों में इसे जारी रखना चाहिए? (कुछ राज्यों में इस मुद्दे पर काफी विवाद है और अदालतों में मामले भी चन रहे हैं) (5) अनुच्छेद 243जी और ग्यारहवीं अनुसूची को किस तरह सशोधित किया जाये कि पंचायतें स्वशासन की संस्थाएँ बन सके? (6) न्याय पंचायते—क्या सविधान में न्याय पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए?

ससद में कोई व्यापक सशोधनोंवाला विधायक लाने के पहले इन तथा अन्य मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श और बहस की जरूरत है। सविधान के इस भाग के साथ फुटकर छेडछाड, जैसा कि दिसम्बर 1999 में राज्य सभा में लाये गये 87वे संशोधन विधेयक के माध्यम से हुआ, पंचायती-राज के उद्देश्य के लिए हानिप्रद तथा उदीयमान स्थानीय निकायों के लिए खतरनाक है।

लघु गणराज्यों की ओर

प्रारम्भिक किटनाइयो और नयी व्यवस्था के लिए स्थान बनाने में पुरानी व्यवस्था द्वारा पेश किये अवरांधों के बावजूद बहुत-सी ऐसी चीजें घटित हुई हैं और घटित हो रही हैं जो आशावाद के लिए सामग्री प्रदान करती है। नयी पचायतों के अस्तित्व में आने के बाद जन भागीदारी के आधार पर नये और सार्थक कार्यक्रम शुरू किये जा रहे है। केरल की पंचायतों और नगरपालिकाओं में शुरू किया गया 'लोगों के लिए लोगों के द्वारा योजना निर्माण' के नारे के साथ जन भागीदारी पर आधारित और स्थानीय स्तर पर टिकाऊ विकास आयोजन ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना है। स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने का यह प्रयास, ताकि वे अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर परस्पर ग्रन्थित योजनाओं का एक पूरा खाका वैज्ञानिक ढंग से तैयार कर सकें, 51 एक आंदोलन की शक्त ले चुका है तथा उसने देश भर का ध्यान आकर्षित किया है। योजना कोष का लगभग 40 प्रतिशत भाग पंचायती राज और नगरपालिका संस्थाओं के माध्यम से बिना कोई बंधन लगाये, सिर्फ इस मार्ग निर्देश के साथ आवन्टित

किया जा रहा है कि इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक क्षेत्रों, सामाजिक सवाओं और आधारभूत ढॉचे के निर्माण पर 40-30-30 के अनुपान में किया जाना चाहिए।²² यह एक ऐसा उदाहरण है, जिसका अनुकरण दूसरे राज्य कर सकते हैं।

हम इस तथ्य से अवगत है कि सर्विधान संशोधन स्पंदनशील स्थानीय सरकारों को अस्तित्व में लाने की सिर्फ एक जरूरी (पर काफी नहीं) शर्त है। हम इस तथ्य से भी अवगत है कि पंचायते जड़ जमा सकें, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशिक्त का होना एक इतना ही महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन जहाँ इस राजनीतिक इच्छाशिक्त का सम्पूर्ण अभाव है, पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में ऐसे काम हुए है जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। उडीसा में राज्य सरकार ने पचायत चुनावों को रोकने के लिए क्या नहीं किया। लेकिन राज्य चुनाव आयोग, प्रेस, लोग और न्यायपालिका—सभी ने उडीसा सरकार पर अपने-अपने स्तर पर दबाव डाला कि वह पचायत चुनाव कराने के अपने सवैधानिक दायित्व का पालन करें। उड़ीसा सरकार को जनवरी 1997 में पचायत चुनाव कराने पड़े, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख जन प्रतिनिधि निर्वाचित हो कर पंचायतों में आये। इसी तरह आध्र प्रदेश में पचायत चुनावं को स्थिगत करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया, तो राज्य चुनाव आयोग तथा कर्ड अन्य सगठनों और व्यक्तियों ने अदालत में याचिका दायर की। आध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया। यह सब इसीलिए सम्भव हुआ कि सविधान सशाधन के बाद देश में एक नया माहौल बना है।

भ्रष्टाचार मे, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिशाप बना हुआ है, काफी कमी आ सकती है, यदि स्थानीय निकायों को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की जा सकें। इस बारे में यह व्यग्यपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के साथ-साथ भ्रष्टाचार का भी विकेद्रीकरण हो जायेगा। निश्चय ही यह आशका सच साबित हुई है—लेकिन एक फर्क के साथ। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार तत्काल दिखाई पड जाता है और उसका प्रतिरोध भी तत्काल ही सामने आ जाता है। चूँकि लोगों की सतर्क निगाहे हर चीज पर रहती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेही स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। जैसे-जैसे ग्राम सभाएँ सामाजिक अंकेक्षण का मच बनती जा रही है, जन प्रतिनिधियों में सतर्कता भी बढ़ रही है।

नया पचायती राज सूचनाओं के बेहतर प्रवाह के द्वार खोल रहा है। सूचना शिक्त है और वर्चस्वशाली वर्गों ने साधारण लोगों को ॲधेरे में रखा है। सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता नहीं थीं, क्योंकि हर सरकारी काम गोपनीय था और जनता को उसके बारे में नहीं वताया जाता था। जब 30 लाख निर्वाचित पंचायत सदस्य जन जीवन को प्रभावित करनेवाले मामलों के बारे में सूचनाओं की माँग करते हैं, तो सूचनाओं की यह केंद्रीकृत प्रणाली दरकने लगती है। सभी संकेतकों की कसौटी

कमी की पूर्ति पंचायतें कर सकती हैं-लोगों में अपनी जिन्दगी का नियन्नण अपने हाथ में लेने की भावना पैदा कर। नयी सहस्राब्दी के इन प्रारम्भिक वर्षों में नयी पचायते इन राज्यों के गाँवों में जीवन का एक नया गवाक्ष खोल सकती हैं। इसका प्रतिरोध होगा जरूर-वह हिसक भी हो सकता है, लेकिन लोकतंत्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है. जिसे इस प्रकार के अवरोध से रोका नहीं जा सकता है। जब लोग सत्ता का स्वाद चख लेते है, तो वे किसी के आगे नहीं झकते। दुर्भाग्यवश पचायतों को सशक्त और स्थानीय लोकतत्र को सुदृढ़ करने के विरुद्ध कार्यरत शक्तियाँ अभी भी काफी ताकतवर हैं। यथास्थिति को बनाये रखने मे जिनका निहित स्वार्थ है, वे योजनाबद्ध ढग से यह प्रयास कर रहे है कि स्थानीय सरकारों की कार्यकुशलता के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर सदेह पैदा हो जाये। सकारात्मक आलोचना या रचनात्मक कार्य नदारद है। लेकिन नया पंचायती राज हम सभी का पद्य प्रदर्शन कर रहा है। पंचायतों को लोगों की जिन्दगी का अविच्छिन्न हिस्सा बनाने के लिए सुदृढ अभियान आज के समय की माँग है। सच तो यह है कि यह प्रक्रिया अब पीछे नहीं ले जायी जा सकती। यह हमारे राज्य तत्र का पुनर्निर्माण करने का दुसरा मौका है। पहला मौका वह था जब हमने एक गणराज्यवादी संविधान अपने आपको सीपा। 'लघु गणराज्यों' का देश बनना ही भारत की नियति है। प्राचीन काल मे यह देश ऐसा ही था और शताब्दियों तक उसने अपनी यह विशेषता बनाये रखी।

पर उत्तर भारत के राज्य—उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश और राजस्थान-सामाजिक विकास के मामले में पिछडे हुए है। इसका एक कारण है सामाजिक आंदोलनों का अभाव, जब कि दूसरे राज्यों में समय-समय पर ये आंदोलन होते रहे हैं। इस ऐतिहासिक

गणराज्य' समानता और जन समृद्धि के लिए कार्य करने को बाध्य है। संदर्भ

निर्मल मुखर्जी, तीसरा स्तर, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 1 मई 1993, पृष्ठ 859-62

लोकतांत्रिक क्रान्ति और आधुनिकता की विमुक्तिकारी ऊर्जा के साथ नये 'लघु

- 2. एच डी मालवीय, *विलेज पंचायत्स इन इण्डिया*, आर्थिक और राजनीतिक श्रोध विभाग, अखित भागतीय काग्रेस समिति, नर्ड दिल्ली, 1956, पृष्ठ 258
- भाग्ताय काग्रस सामात, नड दिल्ला, 1956, पृष्ठ 258
 3. एम, वेंकटरगेया तथा एम पद्मभिरामन (सपादित) लोकन गवर्नमेट इन डिण्डया ' सेलेक्ट गैडिंग्स, एलाइड पिन्नशर्स, मुंबई, 1969, पृष्ठ 97
- 4 पूर्व उद्धृत पृष्ठ 190
- 5 एच.डी मालवीय, पूर्व उद्धृत, पृष्ठ 215-16
- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ 109
- आर.एल खन्ना, प्रचायती राज इन इण्डिया, इ डिग्लिश बुक डिपो, अचाला छावर्ना, 1972
- 7 आर.एक खन्ना, प्रवासता राज इन इन्डिया, इ अलाज युक्त विचार, उपलास अस्ति, 1372 8 ये प्रान्त थे मद्राम (1920 का पंचायत अधिनियम), बाबे (1920 का ग्राम पंचायत अधिनियम)

वगाल 919 का स्वजासन आधानवम), ग्वेहार (1920 का स्वशासन अधिनियम), मध्य पात और वरार (1920 का ग्राम पचायत जीधनियम), उत्तर प्रदेश (1920 का ग्राम पचायत अधिनियम) भाग्न मे पजाब (1922 का पंचायन अधिनियम), और असम (1925 का स्वशासन अधिनियम)। नारत है 1926 तक छह रियामती राज्यों न ग्राम पद्मायन अधिनियम अपना तिये थे। व राज्य अस्य . र्थ काचीन (पचायत विनियम अधिनियम, 1919), इदोर (पचायत अधिनियम, 1920), बावनकोर जिला-" (ग्राम पंचायत अधिनियम, 1925), वडोडा (ग्राम पंचायत अधिनियम, 1926), कोल्हापुर (प्रायत क्री स्वतं अधिनियम 1926) और मैस्र (ग्राम पचायत अधिनियम, 1926)। बाद के वर्षों में, कुछ अन्य पाया क राज्या मे भी इस प्रकार के अधिनियम अपनायं गये वीकानेर (ग्राम पंचायत अधिनियम, 1928) <u>इसतिए</u> वनियार्ड करोली (ग्राम पचायत अधिनियम, 1939), हैदरावाद (ग्राम पचायत अधिनियम, 1940), मेवाड गुज्य स (ग्राम पचायत अधिनियम, 1940), जसदन (ग्राम पंचायत अधिनियम, 1942), भावनगर (ग्राम नक उज पचायत अधिनियम, 1943), पोग्बदर (ग्राम पचायत अधिनियम, 1943), भरतपुर (ग्राम पचायत काई औ अधिनियम, 1944), मारवाड (ग्राम पचायत अधिनियम, 1945), वाडिया (ग्राम पचायत अधिनियम Ť 1946). घरनगद्मा (ग्राम पचायत अधिनियम, 1946), मोरवी (ग्राम पचायत अधिनियम, 1946) चला है सिरोही (ग्राम पचायत अधिनियम, 1947), और जयपुर (ग्राम पचायत अधिनियम, 1948)। सीमा त 9 पम.क. गार्चा, ग्राम स्वराज की मेरी धारणा, *हरिजन*, 26 जुलाई 1912 के संदेष एम. वेकटरगेथा और एम पद्मिभरामन, पूर्व उद्धत, पुष्ठ 97-103 पचायर्त पूर्व उद्धत का सूत्र 12 भारत सरकार, सामुदायिक प्रकल्पा और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिए दल की रिपाट महिला (अध्यक्ष - वलवंतराय मेहता), योजना प्रकल्पो पर समिति, राष्ट्रीय विकास परिवद (नर्ग दिल्ली, गया है नवम्बर 1957), खण्ड 1, पृष्ठ 23 अनस्ट 13. पूर्व उद्धत को आं 14 *हिन्दुस्तान राइम्स,* 3 अक्टूबर 1959 कधाएँ 15 एसासिएशन ऑफ वालटरी एजेमीज फॉर रूरल डेवलपमेट (अबार्ड), राजस्थान मे पचायती राज पर अध्ययन दल की रिपोर्ट (नयी दिल्ली, 1962) है। ग्राप् 16 य राज्य ओर समितियाँ थीं—जाद्र प्रदेश : पुरुषोत्तम समिति, 1964, रामचद्र रेडुडी समिति, 1965 निजाम के वि और नर्ससहम समिति, 1972, कर्नाटक : वामप्पा समिति, 1963, महाराष्ट्र नाडक समिति द्राग १ 1961 ओर बोगदीवार समिति, 1963, राजस्थान . माथुर समिति, 1963, सादिक अली समिति, और व 1963 ओर जी एल व्यास समिति, 1973, उत्तर प्रदेश - गोविद सहाय समिति, 1959 और की बा मूर्ति समिनि, 1965 सरका 17 जिमिजित टत्त, भारत में विकेद्रीकरण तथा स्थानीय सरकार सुधार, इंडियन जनरल ऑफ पिलक सरका एडमिनिस्देशन, खंड 31, सख्य 3, जुलाई-सिनम्बर 1985, पृष्ट 562 की के 18 'अपर्याप्त ससाधनों के अलावा, इन निकायों के चुनाव नियमित रूप में नहीं कराये गये हैं। उच्छाः वम्नुत य्यारह राज्यो में पचायती राज संस्थाओं के एक या एकाधिक स्तरों के चुनाव काफी समय से बकाया हैं और आठ राज्यों में ग्राम पंचायतो तक के चुनाव वकाया है। चुनावा को कमज इस या उस बहाने स टाला जाता रहा है ओर मौजूदा निकायों का कार्य काल बढा दिया गया समाङ है या उन्हे निनवित कर दिया गया है।' देखे, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों ओर र् के निए मोजूरा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पुनर्वीक्षण (कार्ड) *रिपोर्ट*, ग्राम विकास विभाग कृषि इस ६ निरंत भारत में पचायती राज 48 हुए

मत्रालय, नयी दिल्ली, 1985, पृष्ठ 41 एल सी जेन इत्यादि, *ग्रास विदाजट रूट्स,* सेज पब्लिकेशस, नयी दिस्ली, 1985 पृष्ठ 39

पूज उद्धृत पृष्ठ 40

पूव उद्धृत, पृष्ठ 44

भारत सरकार, *पचापती राज सस्थाओ पर समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष अंशोक मेहता), कृषि तथा सिचाई मत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (नयी टिल्ली, 1978), एप्ट 5

'पचायती राज सस्थाओं को विकास की प्रक्रिया से वित्तम करने में सम्भवत नोकरशाही की अपनी भूमिका थी। उसका नजिया दनाने में कई कारको का यागदान प्रतीत होता है। प्रशासनिक पदानुक्रम की प्रणाली सगठन के सिद्धात के रूप में उन्हें अपन अनुकृत लगती है। अफनरा

मे यह एहसाम होता है कि वे परिणामों ओर वित्तीय नियमों के पालन क लिए भूनत राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह है। उन्हें अपने भाई-वंदों पर भरोसा करने क अलावा कुछ ओर पना ही नहीं होता। अत वे एक ओर तो यह नहीं चाहेंगे कि पचायती राज सस्थाओं को अतिरिक्त काय सोपे जाये और दूसरी आर निर्वाचित प्रतिनिधियों के तहत काम करने के साथ वे जल्दी

सामजस्य नहीं बेठा सकेंगे।' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ 5-6 अखिल भारतीय काग्रेस समिनि, *काग्रेस ग्राम पचायत समिति की रिपोर्ट* (नयी दिल्ली, 1954)

ਸੂਲ 10-11

आई पी शुक्त, ए हिस्टमी ऑफ विलेज पचायत्म इन इंडिया, इस्टीट्यूट ऑफ डकॉनॉमिक रिसच (धारवाड, 1964), मृष्ठ 10 एल सी जैन इत्यादि, पूर्व उद्धत, मे देखिए भूमिका। पंचायती राज सस्थाओं के विकास में वाधा

डालने में राजनीतिक सुविधावाद की भूमिका के लिए देखिए जॉर्ज मैध्यू, प्रधायती राज फ्रॉम लेजिस्लेशन टु मूवमेट, कसेप्ट पर्वितिशिग कपनी (नयी दिल्ली, 1994)

मलकॉम एस. आदिशेपेया, संवैधानिक सुरक्षाओं की जरूरत, जॉर्ज मैथ्यू द्वारा सपादित *पचायती* राज इन कर्नाटक टुडे में, कसेप्ट पव्लिशिंग कपनी (नयी दिल्ली, 1986), पृष्ठ 25

पूर्व उद्धुत, पृष्ठ 25

अब्दुल नजीर माब, चौखबा राज्य की ओर, जॉर्ज मेथ्यू द्वाग सपादित पूर्व उद्धुत पुस्तक म पृष्ठ 53

निर्मल मुखर्जी, वैकल्पिक जिला सरकार, एम एल दाँतवाला डन्यादि सपादित *करल डेबलपमट* द *इडियन एक्सपीरिएस*, ऑक्सफोर्ड इंडिया बुक हाउस (नयी दिल्ली, 1986) में

नोकतांत्रिक विकेदीकरैंग के मूल आधार पचायतो ओर स्वशासन पर रिपार्ट, जनता दल (नर्या दिल्ली, 1989)

जॉर्ज मैथ्यू, भारत में स्वशासन बहुस्तरीय संघवाद की ओर, रिव्यू ऑफ डवलपर्मेंट एड चंज खंड 2, अरु 2, जुलाई-सितंबर 1997, महास इस्टीट्यूट ऑफ डेवलपर्मेंट स्टजीज, चेन्नई

मणिशंकर अय्यर, तृणमूल स्तर पर उभा*र, इंडियन एक्सप्रेस*, 1 दिसम्बर 1998 जॉज मैथ्यू ओर रमेश सी नावक, पद्मायतें व्यवहार में क्या लाभ है इनसे शोषित वर्गों को र

इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खड 31 अक 27, 6 जुलाई 1996, पृष्ठ 1765-1771। ये भी देखे : हिदुस्तान टाइम्स, 22 अगस्त 1998, नयी दिल्ली, इडियन एक्सप्रेस, 21 अगस्त 1998, नथी दिल्ली, पी साईनाथ, वास्तविक दुनिया की कार्यशालाएँ, हिन्द्र, 26 जून 1998, नयी दिल्ली

- अग्रद्म प्रदेश के कुरनूल जिले की केलवा ग्राम पचायत की सरपच फातिमा बी को उनके गरीवी उन्मूलन कार्य के लिए सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा रेस अगेस्ट पाँवर्टी पुरस्कार के लिए चना गया। यह पुरस्कार उन्हें न्यू यॉर्क में सयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा 17 अक्टूबर
- 1998 को प्रवान किया गया। 36 नयी दिल्ली में 2 अगस्त 1997 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों और पंचायत मंत्रियों के सम्मेलन
- ने लक्ष्य किया कि कई राज्यों के अनुपालन अधिनियमों ने गॉबो का वर्गीकरण नहीं किया गया या। ये अधिनियम आदिवासी जनसख्या के सकेद्रणवाले क्षेत्रों में चालू मामुटायिक कानूनों के बारे में भी कुछ नहीं कहते। सम्मेलन ने मुझाव दिया कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की यिभिन्न व्याख्याओं से उत्पन्न होनेवाली इन तथा अन्य समस्याओं का
- 37 तिमिलनाडु ने कलक्टर को जिला योजाना समिति का अध्यक्ष बना दिया और मध्य प्रदेश ने मंत्री को। बहरहाल, कटु आलोचना के बाद तिमलनाडु ने मई 2000 में अपने पंचायत राज अधिनियम (1994) में संशोधन कर जिला परिपद के अध्यक्ष को जिला योजना समिति का अध्यक्ष और जिला कलक्टर को उपाध्यक्ष बना दिया।

समाधान करने के लिए मुख्य मत्रियों की एक दूसरी बैठक बुलायी जाये।

- 38 प्रभात दत्त, ग्राम सभा का अनुभव, फ्रन्टलाइन, 30 नुलाई 1999, पृष्ठ 52
 39 केरल सरकार, विकेन्द्रीकरण पर समिति (अध्यक्ष : सत्यब्रत सेन), द्वितीय अतिरम रिपोर्ट, 1
- 39 केरल सरकार, विकेन्द्रीकरण पर समिति (अध्यक्ष : सत्यब्रत सेन), द्वितीय अतिरम रिपोर्ट, 1996 पृष्ठ 19-20
 40. इस विषय के दिस्तृत अध्ययन के लिए देखे माधव गोडवोले, सूचना का अधिकार, इकॉनॉमिक एड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड 35, अंक 17, 22-28 अप्रैल 2000, पृष्ठ 1423-28। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2000 मे मूचना के अधिकार के लिए सघर्प मे एमकेएसएस की भूमिका
 - को इस प्रकार रेखाकित किया गया है : भाग्त में मजदूर किसान शक्ति सगठन सार्वजनिक ससाधनों, व्ययों और विकास प्रकल्पो पर नियमित रूप से जन सुनवाइयों का आयोजन करता है। सोग इन मुद्दों से सवधित सरकारी दस्तावेजों की फोटोप्रनियों की मॉग कभी भी कर सकते है और मार्वजनिक अधिकारी इनकी पूर्ति करने के लिए बाध्य हैं। (भानव विकास रिपोर्ट 2000,
 - 41 जॉर्ज मेथ्यू, स्थानीय सरकार जहाँ राज्य और नागरिक समाज का मिलन होता है, राजेंद्र के साइल और अजित मुरिकेन द्वारा सपादित ट्रॉसेंडेटिंग बाउण्डरीज पर्स्पेक्टिक्स ऑन फंध, मोश्रल एक्शन एड सॉलिडरिटि, मुम्बई 1995, फूट 166-82

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू यॉर्क, 2000, पृष्ठ 39)

- 42. र्जार्ज मेथ्यू, विकेंद्रित संस्थान संस्कार नथा स्वयसेवी क्षेत्र, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड 34, अक 9, 27 फरवरी 1999। यह भी देखे फिलिप ओल्डर्नबर्ग, नॉनगवर्नमेटल
- ऑर्गनाइजेशन्स एड पचायती राज, नयी दिल्ली, अवार्ड ओर प्रिआ, 1999 43. डी बंधोपाध्याय, स्वैध्छिक सगठन ओर पचायतें, मैनस्ट्रीम, 29 मार्च 1977
- 44. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और पचायतें दशरों से मरा सब्ध, *पंचायती राज अपडेट,* अगस्त 1999, इंस्टीट्यूट ऑफ सीशल साइंसेज, नयी टिल्ली
- 1999, इस्टार्ट्यूट आफ साशल साइसज, नयी दिल्ली 45 जन्मभूमि एन इन्नोवेटिव अप्रोच दु पार्टिसेपेटरी डेबलपमेट इन आद्य प्रदेश, आङ्आरडी, राजेंद्रनगर, हैदराबाद, 1998, पृष्ठ 38
- 46 ई एम वेंकटरमैया, सांसद चुनाव क्षेत्र विकास योजना संविधान पर आधात, *इडियन एक्सप्रेस*,
- 50 भारत में पचायती राज

- नयी दिल्ली, 13 फरवरी 1997
- अोर अधिक विवरणों के लिए देखें, प्रचायती राज अपडेट, इस्टीट्यूट ऑफ सांशल साइंसेज, नयी दिल्ली, जुलाई, 1998। यह भी देखें एम. ए. ऊम्मन ओर महीपाल, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अशुभ संकेत, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड 14, अंक 5, 29 जनवरी 1994, एष्ट 223-25
- 48 रमेश मी नायक (इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज) द्वारा राजस्थान के अलवर, कोटा और पाली जिलों में किये गये क्षेत्र कार्य के आधार पर, 1996-2000
- 49 पचायते व्यवहार मं क्या लाभ है इनसे शोपित वर्गों को?, पूर्व उद्धृत
- 50 एस वी *शरण, मध्य प्रदेश मे पचायती राज, प्रशिक्षण एक मूल्याकन,* इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज, पाइलिपि रिपार्ट 11, 1998
 - 51 *नीवी योजना के लिए जन अभियान : एक परिप्रेक्ष्य पत्र,* केरल राज्य योजना **बोर्ड**, तिरुवनतपुरम, 1996, एष्ट 1
 - 52 जॉर्ज मैंध्यू, केरल की सफलता कथा, हिंदू, 24 मई 1999, यह भी देखे जन योजना केरल की कथा, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मत्रालय, भारत सरकार, अगस्त 1999, पृष्ठ 15-17, 29

राज्य तंत्र का पुनर्गठन

एम.एन. राय का एक बीज-विचार था, सत्ता का विकेद्रीकरण। अपनी मृत्यु के कुछ माह पहले लिखे एक लेख में उन्होंने सत्ता के विकेद्रीकरण पर अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा, 'लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया की समस्या अततः विकेंद्रीकरण करने की है।' उन्होंने आगे कहा, 'लोकतत्र का विकेंद्रीकरण सत्ता के केद्रीकरण को रोकेगा और राज्य का काम स्वायत्त सामाजिक सस्थाओं के कार्यों के समन्वय का रह जायेगा।'

राय के मुताबिक, उन्होंने देखा है कि तमाम सामाजिक विषमताओं के बावजूद आम लोगों में अपने मसलों को हल करने की क्षमता होती है। 'यह सच है कि आम लोग अशिक्षित होते हैं। उनमें देश पर शासन करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन सच यह भी है कि अगर उन पर छोड़ दिया जाये तो बेहद अज्ञानी किसान भी अपने मसलों को हमारी मौजूदा सरकार से बेहतर ढम से हल कर सकते हैं। आम लोग अपने बारे में सोचने या अपनी देखभाल करने की क्षमता नहीं रखते, यह धारणा उनके नाम पर सत्ता हथियाने और उनकी ताकत को कोस कर उनकी स्थतंत्रता को दबाने का बहाना है।'

राय का मानना है कि एक संगठित लोकतत्र की वुनियादी इकाई जन समिति होनी चाहिए। 1949 में उन्होने लिखा कि देश के कुछ हिस्सो में गठित मौजूदा ग्रामीण पंचायतो को संगठित लोकतत्र की इकाइयो के रूप में विकसित किया जा सकता है।

पचास के दशक में उन्होंने पार्टी राजनीति और उससे भी अधिक एक पार्टी के शासन की सत्ता देखी और फिर सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ कड़े शब्दों में लिखा। उन्होंने पार्टी-रहित लोकतत्र का समर्थन किया। राय के विचार में, जन समितियों को राजनीतिक पार्टियों से जुड़े बिना कार्य करना चाहिए।

भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अमीकृत किया गया। इस सविधान के मुताबिक भारत राज्यों का संघ है। सविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए वी आर. आबेडकर ने कहा कि 'सघ' शब्द का इस्तमाल जान-बूझ कर किया गया है। प्रारूप तैयार करनेवाली समिति यह स्पष्ट करना चाहती थी कि 'भारत महासघ होने के बावजूद राज्यो द्वारा आपसी समझौते के कारण अस्तित्व में आया

महासंघ नहीं है !' आबेडकर के मुताबिक, संघीय शासन (फेडरलिज्म) की दो मुख्य कमजोरियाँ है लचीलेपन का अभाव और कानुनवाद। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली

इस मामले में अनोखी है कि इसकी नागरिकता तो एक ही है, मगर राज्य तत्र दुहरा है। समय और परिस्थिति के मुताविक यह एकात्मक अथवा संघीय बन जाता है।

हा तमय जार परिस्थात के नुतायिक यह एकात्मक अथवा संधाय बन जाता है। सामान्य समय में यह संरचनात्मक तथा कार्यकलाप के स्तर पर संधीय है एव आपातकाल में इसे एकात्मक राज्य तत्र में बदला जा सकता है।

भारत का सविधान कोई पूर्ण दस्तावेज नहीं था और समय बदलने के साथ

इसमे निरंतर परिवर्तन करने की जरूरत थी। आज तक ससद ने सविधान में तिरानवें सशोधन पारित किये हैं। हालाँकि भारतीय सघ का अभिप्राय केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन है, लेकिन पिछले चार दशको का अनुभव सत्ता के केंद्रीकरण का रहा है। संघ ने अनुच्छेद 249, 250, 252, 352 और 356 का इस्तेमाल केंद्र के अधिकारों और शक्तियों के विस्तार के लिये किया, जो सचीय सिद्धांतों के विपरीत था।

सविधान सभा द्वारा पारित भारतीय सविधान में गंभीर दोष यह था कि वह स्थानीय सरकारो, पचायतो और नगरपालिकाओ को प्राथमिकता नहीं देता। इन्हें केवल नीति निदेशक सिद्धांतों (संविधान के चालीसवें अनुच्छेद) में स्थान मिला, जो न्यायसगत नहीं था। संघ की संरचना द्वि-स्तरीय थी: संघ सरकार और राज्य सरकार। स्थानीय निकायो की कोई भूमिका नहीं रखी गयी—न तो विकासात्मक और न ही शासन सं संबधित। यह राज्यों पर छोड़ दिया गया कि 'वे ग्राम पंचायतो का गठन करे

निकायों की कोई भूमिका नहीं रखी गयी—न तो विकासात्मक और न ही शासन सं संबंधित। यह राज्यों पर छोड़ दिया गया कि 'वे ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें ऐसी सत्ता और अधिकार सौंपे जायें जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक हों।'⁵ भारत के संविधान को अपनाने के बाद देश के स्थानीय निकायों को वैधानिक निकाय बनने में तैतालीस वर्ष लग गये। 22 दिसंबर 1992 को संसद ने 73वाँ संशोधन

निकाय बनन में ततालास वर्ष लग गय। 22 दिसंबर 1992 का संसद न 73वा संशोधन विधेयक पारित किया और कई अन्य औपचारिकताओं के बाद 24 अप्रैल 1993 को सिविधान के भाग नौ में जोड़ा गया। इस संशोधन विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया, 'इसका उद्देश्य संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कतिपय बुनियादी और आवश्यक विशेषताओं को स्थापित करना है ताकि उन्हें स्थिरता, निरंतरता और शिक्त मिल सके।' इसी के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों को मान्यता देने के लिये 74वॉ संविधान संशोधन भी पारित किया गया। इन सवैधानिक संशोधनों की एक पृष्ठभूमि है। दरअसल, अनेक वर्षों से राजनैतिक और आर्थिक शिक्तयों के विकेंद्रीकरण की माँग बढ़ रही थी। 1980 दशक के मध्य तक यह स्पष्ट हो गया

था कि सत्ता के केंद्रीकरण से भारत का राजनीतिक तंत्र बिखर सकता है। इसी दौरान,

पश्चिम बगाल, कनाटक और आध्र प्रदेश में राजनीतिक सस्थाओं के रूप में पचायता की सफलता के चलते और 'लोगों को सत्ता' के नारे के साथ सत्ता के विकेद्रीकरण की आम माँग ने भी सविधान संशोधन की गति को बढ़ाने का काम किया। कर्नाटक के तत्कालीन पंचायती राज मंत्री अब्दुल नजीर साब ने 1980 में कर्नाटक के पचायत अधिनियम को गभीरता से लागू करने के बाद स्वीकार किया कि 'राज्य शासन के ढाँचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की हमारी मशा भले ही प्रशसनीय हो, लेकिन संविधान संशोधन के बिना 'चौंखंबा राज' के हमारे प्रयास वैसे परिणाम नहीं दें सकते जैसा हम चाहते हैं। मेरे विचार से यह एक मुख्य प्रश्न है जिस पर इस देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों को विचार करना चाहिए। उन्हें संविधान संशोधन की आवश्यकता पर लोगों में बहस छेड़नी चाहिए।' नजीर साब ने यह वक्तव्य अक्तूबर 1985 में दिल्ली में दिया था।

चार वर्षों के भीतर 15 मई 1989 को पचायतो को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए संसद में चौसठवाँ संवैधानिक संशोधन पेश किया गया। इसके मूल में सत्ता के केद्रित होने के कारण देश में उत्पन्न अशासनीय स्थितियों और निचले स्तर पर व्यक्त हो रही निराशा को माना गया, क्योंकि लोगों के हित में कुछ नही हो रहा था।

संविधान संशोधन का महत्व

संविधान सशोधन के पहले तक भारतीय लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र तक सीमित था, जिसके तहत पाँच वर्षों में एक बार संसद और राज्य विधान सभाओं के लिये पाँच हजार सदस्यों का चुनाव किया जाता था। यह लोकतंत्र विशिष्ट वर्ग के लिए था, क्योंकि चुनावों में बाहु बल, धन बल और जाति बल की निर्णायक भूमिका थी। यह लोकतंत्र उपयुक्त सहयोगात्मक संरचना के अभाव में गहरी जड़ें नहीं जमा पाया।

पिछले पचास सालों में संसद और विधान सभाओं के चुनाव जमीनी (ग्रासरूट) स्तर पर लोकतात्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं कर पाये। सविधान के 73ये और 74ये संशोधन के बाद से हर पाँच साल के बाद पंचायतों के तीन स्तरों और नगरपालिकाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं। 20 लाख से अधिक जनसंख्यावाले राज्यों में तीन-स्तरीय पंचायतों का विधान है. निचले स्तर पर ग्रामीण पंचायत, मध्य स्तर पर ब्लॉक पचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायत। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में शहरों और कस्बों की जनसंख्या के आधार पर भी तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ हैं—नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। इस प्रकार देश में 500 से अधिक जिला पंचायते, 5100 के आसपास ब्लॉक या तालुक पंचायतें और 2,25,000 के आसपास ग्राम पंचायते हैं। देश भर में लगभग 90 नगर निगम, 1500 नगर परिषदे और 1800 नगर पचायते हैं। ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए लगभग तीस लाख प्रतिनिधियों का चुनाव

होना है। इस प्रक्रिया ने भारतीय लोकतत्र के आधार को मजबूत करने का काम किया है।

स्थानीय निकायों को संवैधानिक सत्ता मिलने के परिणामस्वरूप देश के संधीय राज्य तत्र में जो बदलाव आया है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये क्रांतिकारी भी हो मकते हैं। 73वे और 74वे संशोधन के पारित होने से पंचायते और नगरपालिकाएँ वस्तुत. देश में शासन का तीसरा स्तर हो गयी हैं।

पचायतो को 11वीं अनुसूची में 29 विषय और नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में 18 विषय हस्तांतरित करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा कमोबेश इन सभी विषयों के हस्तांतरण के बाद यह कहा जा सकता है कि जिला और उससे निचले स्तरों पर स्थानीय निकाय भारतीय संघ को एक नया अर्थ देते हुए भारतीय संघीय स्वरूप में तीसरे स्तर का शासन बन जायेंगे। फिलहाल यह प्रक्रिया चल ही रही है, क्योंकि स्थानीय निकायों के पास कानून बनाने के अधिकार नहीं है। न ही वे कानून-व्यवस्था यानी पुलिस विभाग के और न्यायिक अधिकार रखते है। कुछ ही राज्यों ने अपने अनुपालन अधिनियमों में न्याय पंचायतों को स्थान दिया है।

यहाँ इस तथ्य का विशेष उल्लेख जरूरी है कि संविधान के अनुच्छंद 243जी और 243पी(ई) पचायतों और नगरपालिकाओं को 'स्वशासन की संस्थाओं के रूप मे परिभाषित करते हैं, लेकिन कहीं भी 'स्वशासन की संस्थाओं' के कार्य क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ यह याद दिलाना जरूरी है कि केवल तीन राज्यो—पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार—के अनुपालन कानूनों मे साफ-साफ लिखा गया है कि उनके पचायती कानूनों का लक्ष्य पंचायतों को ऐसे अधिकारों और कार्यों से सपन्न बनाना है जिससे वे स्वशासन की जीवत संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य हो सर्कें। दूसरी ओर हरियाणा है। हरियाणा का पंचायत अधिनियम साफ तौर पर कहता है कि पचायत प्रणाली का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को बेहतर दग से चलाना है। यानी, यही बात दूसरे ढंग से कही गयी है कि राज्य अभी भी जिला स्तर और उससे निचले स्तर पर प्रशासन के लिए 'कलक्टर राज' और 'एसएचओं राज' में विश्वास करता है।

'स्वशासन की सस्थाएँ' पद की व्याख्या दो प्रकार से की गयी है। पहली व्याख्या यह है कि जब संविधान कहता है कि पचायत स्वशासन की संस्था है, तो इसका अनिवार्य अभिप्राय यह है कि वह स्वायत्त हो और उसे अपने क्षेत्राधिकारवाले विशेष इलाके मे शासन चलाने का अधिकार हो। इसलिए संविधान के प्रावधानों के मुताबिक लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन इसका आवश्यक तत्व है। संविधान का 73वाँ सशोधन पंचायतों को अलग ही पहचान देता है, इसलिए यह वस्तुतः शासन का तीसरा स्तर है। दूसरी व्याख्या कहती है कि यह नयी व्यवस्था 'संघीय प्रशासन' को मजबूत करती है, इससे अधिक कुछ नहीं। उदाहरण के लिए प्रोफेसर एस. गुहन का तर्क है कि 73व सशोधन के प्रावधान 'प्रशासनिक संघ' को ही मजबूत बनाते है, तािक राज्यों में म्थानीय निकायों को प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार उपलब्ध हो सकें। गुहन कहते हैं, 'स्थानीय निकायों के प्रशासकीय अधिकार और दाियत्व तथा इन अधिकारों और दाियत्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय ससाधन राज्य द्वारा पारित होनेवाले कानून में प्राप्त होते है।'

स्थानीय निकायों के पास विधान निर्माण के या न्यायिक अधिकार नहीं है, इसलिए गुहन के विचार से, केवल संवैधानिक दर्जा दे कर या नियमित चुनाव कराने से उन्हें शासन तंत्र के तीसरे स्तर का दर्जा नहीं मिल जाता। कहा जा सकता है कि हरियाणा अनुपालक अधिनियम इसी सोच पर चलता है।

प्रोफेसर गुहन का तर्क तकनीकी रूप से सही है। फिर भी, जिन देशों में स्थानीय निकाय मौजूद है, उन्हें कानूनी अधिकार प्रदान किये गये है, जैसे बजट, उपनियम बनाना, विनियमन करना। उन्हें अपने कामो और दायित्वों से जुड़े नियंत्रण के अधिकार भी उपलब्ध है। इसी तरह, पुलिस से जुड़े और न्यायिक अधिकार भी पचायतों को दिये जा सकते है।

निर्मल मुखर्जी लिखते हैं: 'स्थानीय स्वशासन के बारे में सोचने-विचारनेवाले ज्यादातर लोगों ने जिन दो लक्ष्यों पर विचार नहीं किया है, वे हैं न्यायिक प्रणाली का विकेद्रीकरण और इसी के समानातर पुलिस प्रणाली का विकेद्रीकरण। स्पष्टत इन दोनों में अंतरसबंध है। जिन सवैधानिक संशोधनों ने नयी पंचायतों और नगरपालिकाओं को जन्म दिया है, वे इस विषय पर पूरी तरह खामोश हैं। ...सभवत यह जान-बूझ कर नहीं हुआ है। कारण कोई भी हो, विकेद्रीकृत न्याय प्रणाली पर जोरदार पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि स्थानीय 'न्याय व्यवस्था' के बिना स्थानीय शासन पूरी तरह अधूरा रहेगा।'

प्रकट है कि विकेद्रीकृत न्याय व्यवस्था (न्याय पचायत) विकेद्रीकृत पुलिस व्यवस्था के बिना सभव नहीं है। इसलिए वह समय अधिक दूर नहीं जब शहर और कस्बा पुलिस के साथ-साथ गाँव, ब्लॉक और जिला पुलिस भी होगी।

भारत में स्थानीय निकायों को यथार्थ के स्तर पर प्रशासन का तीसरा स्तर बनाने के प्रयास निरतर होते रहे, लेकिन उनकी आधिकारिता में कोई वृद्धि नहीं हुई। 73वें और 74वें संविधान सशोधन की घटना को इस दिशा में मील का पत्थर माना जा सकता है, क्योंकि इनसे देश में जिला सरकार बनाने का रास्ता खुला है। इन संशोधनों के माध्यम से दरअसल जिला स्तर की योजनाओं का दायित्व भी स्थानीय निकायों को दिया गया है और यह सही दिशा की ओर एक प्रमुख कदम है। जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित जिला पंचायतों के सदस्य और अध्यक्ष नये प्रशासनिक तंत्र की धुरी हैं। अभी तक जिलाधिकारी पर ही सब कुछ निर्भर था। लेकिन नयी

व्यवस्था मे 'कलक्टर राज' पचायती राज में परिवर्तित हो जायेगा।

आखिरकार, अर्धशती के बाद राजनीतिक प्रणाली को पलटने के रास्ते खुले हे। आज तक 'ऊपरवाले' ही प्रमुख थे, सब कुछ ऊपर से नीचे आता था। हर चीज

'ऊपर' से व्यवस्था को देखनेवालों की सद्भावना पर निर्भर थी। निचले स्तर के लोगों की आवाज नहीं थी। लोगों द्वारा निर्वाचित कुछ हजार प्रतिनिधियो द्वारा देश को

चलाने के स्थान पर अब हमारे समक्ष विभिन्न स्तरों पर जन मुद्दो को आवाज देनेवाल

कई लाख प्रतिनिधि हैं। इस तरह नये संशोधन और स्थानीय निकाय राजनीतिक

प्रबंधन के क्षेत्र में एक लंबी छलॉग है। संसदीय लोकतत्र की संरचना को पहली बार नीचे से ऊपर देखा गया। अब

अधिक समय तक निचले स्तर के लोगो यानी गाँव और नगर वार्ड की उपेक्षा नही

की जा सकेगी। विधायक इस तीसरे स्तर से डर महसूस कर रहे है। राज्य स्तर के राजनेता राजनीति की इस नयी घटना से असुरक्षा का अनुभव करते है। मुख्य मत्रियां

और राज्य स्तर की सत्तारूढ पार्टियों को डर है कि सभवतः लोग अपने अधिकारो

की मॉग करेगे और उन्हें दंड देंगे, इसलिए वे पचायत चुनावों को बार-बार स्थिगित

करते रहे हैं। संविधान संशोधनो से स्थानीय शासन प्रणाली को मिलनेवाले महत्व को सन 1962 में 'अनुग्रह नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले मे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले मे व्यक्त किया था। याचिकाकर्ता की पीड़ा यह थी कि राज्य में लंबे समय से नगरपालिकाओं क

चुनाव नहीं हुए थे और सरकार का मत था कि चुनाव का समय तय करने का अधिकार उसका है-उसे चुनाव कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपने

विस्तृत और प्रबुद्ध फैसले में अदालत ने आदेश दिया कि स्थानीय स्वशासन भारतीय

सविधान की एक आधारभूत विशेषता है। फैसले में कहा गया कि स्थानीय स्वशासन के बिना शेष लोकतांत्रिक ढॉचा बिखर जायेगा। विद्वान जज ने लिखा : 'स्थानीय स्वशासन का अर्थ है : गाँव हो या शहरी क्षेत्र, लोगो की भागीदारी के साथ निरतर

उन्नित करते रहना । लोकतंत्र के जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी के साथ स्थानीय स्वशासन निरंतर बना रहे, इसे भुला न दे कर इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे पर्णता तक ले जाना चाहिए। स्थानीय स्वशासन वह तोरण है जिस पर इस राष्ट्र

का ससदीय लोकतत्र टिका है। राज्य विधायिका और संसद का गुवज इसी पर टिका है। तोरणों के बिना यह संरचना बिखर जायेगी।'¹⁰ चूँकि राप्ट्र ने तीन दशको से इस तथ्य को नहीं स्वीकारा, यह संरचना काफी हद तक ध्वस्त हो चुकी है। राजनीतिक

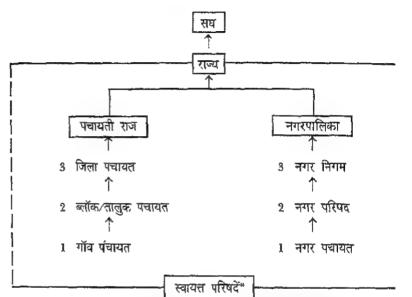
आपातकाल, लोकतात्रिक अधिकारों का स्थगन और आपातकाल के बाद भी उनका उल्लंघन, आतंकवाद और हिंसा की शुरुआत, राजनीतिक हत्याऍ—यं सब बताते हे

कि यह संरचना टूट और बिखर रही थी। यह महत्वपूर्ण है कि हम भारत के लोगो ने इन तोरणों को, जिस पर संसदीय व्यवस्था का गुबज टिका है, संवैधानिक मंजूरी

राज्य तत्र का प्नर्गठन : 57

दे दी है। इससे सघीय स्वरूप को नीचे से देखने की सभावना पैदा हुई है।

भारत के संघीय स्वरूप पर शासन के तीसरे स्तर के रूप में पंचायती राज तथा नगरपालिकाओं का प्रभाव



* स्वायत्त परिपदे कुछ राज्यों, जैसे पश्चिम वगाल, जम्मू और कश्मीर तथा असम. में कुछ विशेप क्षेत्रों के विकास और प्रबंध के लिये बनायी गयी हैं. लेकिन वहाँ वैधानिक स्थानीय निकाय भी है।

स्थानीय निकायों के चुनाव

भारत में पचायतों का चुनाव लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का उत्कृष्ट बैरोमीटर रहा है। मतदान प्रतिशत ऊँचा रहता है। हाल ही में उड़ीसा में हुए पंचायत चुनावों में कुछ पचायतों में मतदान 90 प्रतिशत तक था।

पचायत चुनाव प्रक्रिया के बारे में और कर्नाटक में 1995 और तमिलनाडु में 1996 में चुनावी मुद्दों पर किये गये अध्ययन निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कुछ दिलचस्प तथ्य उजागर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले पचास वर्षों में जाति और धर्म जैसे मुद्दे चुनावों के परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन कुछ राज्यों के पंचायत चुनावों में उनका महत्व कम हुआ है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में 1996 के पचायत चुनावों में लोगों में बढ़ती लोकतांत्रिक चेतना स्पष्ट दिखाई दी। एक सर्वेक्षण में 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने

बताया कि धार्मिक या जातीय नेताओं ने उन्हें किसी भी प्रकार से अपने वोट के

58 - भारत में पंचायती राज

भारत अन्दर्ग जिला की रू पाया इसिंग बुनिय राज्य

भारत

नकः कोई चना

मीमा

के स पचार का र

महित गया

अतर को .

को . कथा

> हैं!3 निजा

के हि द्वारा और

की ^इ सरक

सरक की १

इच्छ

कम समा और

इस निरत हुए मधिकार का इस्तेमाल करने का निर्देश नहीं दिया।

इस सीधे और स्पष्ट सवाल पर कि क्या किसी विशेष उम्मीदवार को वोट दने में अपनी जाति से लगाव उनके लिए महत्वपूर्ण था, 73.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके लिए उम्मीदवार की जाति महत्व की बात नहीं थी। गाँवो में आम मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण यह था कि उम्मीदवार भ्रष्ट तो नहीं है और विकास के काम करने में उसने कितनी सिक्रयता दिखायी है। कर्नाटक में 63.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए उम्मीदवार की जाति कोई मुद्दा नहीं थी, 44.9 प्रतिशत का मानना था कि उन्होंने अमुक उम्मीदवार को इसलिए वोट दिया क्योंकि वह अच्छा पुरुष या अच्छी महिला थी।

ये चुनाव अध्ययन बताते है कि स्थानीय निकायों के चुनावों में जातिबाद और क्षेत्रीयता की सघनता कम हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि आम लोग जाति या पार्टी राजनीति के मुकाबले गाँवों या ब्लॉकों में कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता देते है। मई 1993 में पश्चिम बंगाल के पचायत चुनावों ने भी जमीनी स्तर पर इस सकारात्मक पहलु को उजागर किया।

पंचायत चुनावों में राजनीतिक दत्त

यह सर्वविदित है कि एम.एन गय राजनीतिक पार्टियों की राजनीति से दूर हट गये थे। सिक्रय राजनीति और राजनीतिक पार्टियों में अपने लंबे अनुभव के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'राजनीतिक पार्टियों का गठन लोकतत्र को चलाने के उद्देश्य से नहीं, बिन्क सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए किया जाता है। वे इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि लक्ष्य ही साधनों को न्यायोचित ठहराता है और साधनों से प्रायः फैलता है तथा लोकतंत्र भ्रष्ट और अततः नष्ट होता है।'12

गांधीवादियो, सर्वोदयवादियों, जयप्रकाश नारायण—इन सभी ने पचायतों में पार्टी-रहित चुनावों की वकालत की है। वास्तव में पंचायती राज चुनावों पर संतानम समिति ने 1964 में कहा था कि समिति के समक्ष सबसे विवादास्पद मुद्दा यह था कि क्या राजनीतिक पार्टियों को पचायत चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और अगर हॉ तो किस हद तक?

फिर भी, मौजूदा भारतीय राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय शासन के चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी जरूरी हो गयी है—लेकिन सामाजिक परिवर्तन के किसी सकारात्मक पहलू के बिना नहीं। मध्य प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जाति की महिला सरपचो (प्रधानों), सदस्यों और अन्य निर्वाचित अधिकारियों के साथ हुए उत्पीडन और दुर्व्यवहार के कुछ मामले इसीलिए प्रकाश में आये क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने पीडितों का साथ दिया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि पश्चिम बंगात जैसे उच्च राजनीतिक

सचेतनतावाले राज्य में भी चुनाव खत्म होने के वाद सभी सदस्य गाँव के विकास के लिए सहयोग करते हैं। आखिरकार यदि हम विधान सभाओं और मंसद में बहु-दत्तीय चुनाव प्रक्रिया को बनाये रखते हैं, तो निचले स्तर पर पार्टी-रहित चुनाव अर्थहीन हो जायेंगे। इससे जमींदारों, जाति और धर्म की मत्ता ही आगे वढेगी।

ग्रामीण सौहार्ट के मामले को ने कर इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल नजीर साब अक्सर कहते थे, 'वैसे भी गाँवों मे रामन्ना-भीमन्नावाली राजनीति है। यह वास्तविकता है। क्या यह बेहतर नहीं कि वे जाति, धर्म इत्यादि की अपेक्षा लोकतात्रिक पार्टी लाइन पर एकजुट हों?'¹⁸

स्थानीय शासन में महिलाएँ और कमजोर वर्ग

नयी पचायतें और नगरपालिकाएँ पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, जो हमारी जनसङ्मा का 25 प्रतिशत है, स्थानीय शासन में सिक्रय भागीदारी करने और इन संस्थाओं का सदस्य या अध्यक्ष निर्वाचित होने के अवसर प्रदान करती हैं। उनकी सदस्यता क्षेत्र की जनसङ्मा के आधार पर निर्धारित होती है। सिवधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों को विशेष दर्जा और प्राधिकार मिला है। वास्तव में, आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में गैर-आदिवासी उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं और आदिवासी परपराओं को नष्ट कर रहे हैं। आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों द्वारा जब्त कर ली जाती थी।

जुलाई 1994 में केंद्र सरकार द्वारा 73वें सविधान सशोधन का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक करने के हेतु प्रस्तावों पर सुझाव देने के लिए संसद सदस्य दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के सुझाव थे

(1) सभी आदिवासी गाँवों में ग्राम सभा गठित की जानी चाहिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में स्व-शासन की बुनियादी इकाई समुदाय होना चाहिए;

(2) निर्वाचित इकाइयो के सभी स्तरों पर अधिकतर सीटें अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखी जायें, और

(3) आदिवासी ही सरपंच के रूप में निर्वाचित होना चाहिए।

ससद के दोनो सदनों ने दिसंबर 1996 में भूरिया समिति के सुझावों के अनुरूप तैयार किये गये पचायत (अनुसूचित क्षेत्रो तक विस्तार) विधेयक, 1996 को अपना लिया। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 के उपवाक्य (1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं, को लाभ पहुँचायेगा।

भारत में पचायतो और नगरपालिकाओं के नये चरण की एक विशेषता यह है कि यह स्थानीय निकायों में महिलाओं का एक-तिहाई प्रतिनिधिन्व सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह उनके लिए ग्रामीण और शहरी निकायों के सभी स्तरो पर एक-तिहाई अध्यक्ष पद भी सुनिश्चित करता है। इससे पचायता और नगरपालिकाओ में दस लाख महिलाओं के निर्वाचित होने की संभावना बनी है।

अभी तक* हुए पचायत चुनावों के ऑकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देश मं 7,16,234 महिलाऍ निर्वाचित हो चुकी हैं। इसमें मणिपुर की सख्या (विवरण उपलब्ध न होने के कारण) शामिल नहीं है, विहार, जम्मू और कश्मीर में चुनाव होना अभी बाकी है। (जब यह लेख लिखा गया था, तब तक इन राज्यों मे प्रचायत चुनाव नहीं हए थे।) जब हम नगरपालिकाओं के तीनो स्तरों पर महिला सदस्यो को शामिल करेगे, तो यह ऑकड़ा दस लाख तक पहुँच सकता है। यह कोई साधारण उपलब्धि नही है। यह लक्ष्य करने की वात है कि कई राज्यों में 33.3 प्रतिशत की अनिवार्य सख्या से ज्यादा महिलाएँ पंचायतो मे निर्वाचित हुई। ताजातर पंचायत चुनावो से साबित होता है कि महिलाओं ने चुनाव में भाग लेने के अवसर का पूरा-पूरा उपयोग किया। पश्चिम बागल मे ग्राम पचायत और पंचायत समिति के स्तर पर महिलाओ के लिए आरक्षित प्रत्येक सीट के लिए औसतन तीन उम्मीदवारों ने चुनाव लडा, जिला पंचायत के स्तर पर यह औसत चार का था। तीनो स्तरों की पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित 24,855 सीटों में से सिर्फ 561 सीटों पर, 2 प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा, सर्वसम्मित से चुनाव हो सका। 14 पिछले दो-तीन वर्षों के अखबार इन खबरो से भरे हुए हैं कि महिला पंचायत सदस्य और सरपंच किस प्रकार अपने अधिकारों की दावेदारी करती हैं और इससे स्थितियों में सुधार आता है। आज यदि 25 प्रतिशत महिलाएँ भी सफलतापूर्वक काम कर रही है, तो यह भविष्य की उज्ज्वल संभावनाओं की ओर सकेत करता है।

शासन के तीसरे स्तर की समस्याएँ

पचायती राज प्रणाली की कल्पना जिस बुनियादी सिद्धात पर की गयी है, उसके मुताबिक निचले स्तर पर जो भी अच्छा काम किया जा सकता है वह उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, उससे ऊपरी स्तर पर नहीं। जो काम निचले स्तर पर सभव नहीं है, सिर्फ वही ऊँचे स्तर पर होना चाहिए।

लेकिन यह कहना जरूरी है कि नयी पंचायतो और नगरपालिकाओं के पहले पाँच या दस वर्षों की अवधि में गलतियाँ होना सभव और स्वाभाविक है। यह गर्भाविध यानी शुरुआती दौर है। स्वतत्रता के पाँच दशकों से जो मनोवृत्ति हावी रही है, उसे बदलना आसान नहीं है। हम इस गर्भावधि को छोटा कैसे कर सकते हैं. सभी चितको का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए।

मार्च 1997 तक

ये कुछ ऐसे मुद्दे है जो पचायतो को 'स्वशासन संस्थान' बनने मे बाधा डालते है।

- 1. 1993 के वाद राज्य पचायत और नगर निगम अधिनियमों में पाया गया कि राज्यों ने 73वे और 74वे सशोधनों को उनकी आत्मा के बजाय उनके शब्दों में स्वीकार किया है। बहुत-से राज्य अधिनियमों में सिविल कर्मचारियों को निर्वाचित निकाय से बढ़ कर अप्रत्यक्ष अधिकार दिये गये हैं। पंचायतों को कार्यो का स्थानातरण बहुत धीमा है। उचित अधिकारों की प्राप्ति नीचे से यानी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला पचायतों के अलावा जागरूक नागरिक सस्थाओं की जोरदार मॉग पर ही होगी।
- 2. दूसरी समस्या यह है कि हालाँकि राज्यों ने अनुपालन अधिनियम लागू कर दिये है, बहुत-से राज्यों ने दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली के लिए नियम और उपनियम नहीं बनाये हैं। इसके साथ ही, बहुत-से राज्यों में पंचायतों के लिए आवश्यक वृत्तियादी सुविधाओं की भी कमी है।
- 3. शासन के निचले स्तरों की महत्ता, उनकी स्वायत्तता, अधिकार और कार्यक्षेत्र को समझने सबंधी राज्य स्तर के राजनेता की अनिच्छा भी पंचायतों को अधिकार प्रदान करने में बाधा पैदा कर रही है। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ राजनेताओ को चिता है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के ताकतवर होने से जिन अधिकारो का मजा वे लूट रहे हैं, वे कम हो जायेगे। राज्य स्तरीय नेता नही चाहते कि निचले स्तरों से ऐसा नेतृत्व उभरे जो कुछ समय के पश्चात उनके लिए चुनौती बन जाये। सिक्रिय स्थानीय निकायों को सदैव ही नेतृत्व की पौधशाला माना जाता रहा है। पचायतो की कार्यप्रणाली में विधायक रोड़ा अटकाते हैं, ताकि वे परिपूर्ण स्थानीय सरकारे न बन सकें। उड़ीसा में 1995 की शुरुआत में जब नयी सरकार सत्ता मे आयी, तो उसने निर्वाचित पंचायतों और नगरपालिकाओ को भंग करने का फैसला किया। इस कार्रवाई का वास्तविक कारण यह था कि विधायक ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से पचायतो को मिलनेवाली भारी धनराशि को पूरी तरह अपने काबू में करने को बेताब थे। यदि पचायतें बड़ी संख्या मे निर्वाचित प्रतिनिधियों के साय और विपक्ष की आलोचनात्मक दृष्टि के तहत उचित रूप से कार्य करे तो लोग पंचायती कार्यक्रमो मे नियमित भागीदारी से अपने अधिकारो के प्रति जागरूक हो जायेगे। इससे विधायको की अनुचित ताकत में भी कमी आयेगी।
 - 4 सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी दूरवर्ती नियंत्रण पद्धति, जिसका केंद्र राज्य की राजधानी में होता है, के तहत काम करना पंसद करते हैं। वे पंचायती राज के तहत नजदीक से नियंत्रित या पर्यविक्षित होना नहीं चाहते। इसलिए निर्वाचित पचायत सदस्यों के प्रति उनका असहयोगात्मक रवैया एक मुख्य मुद्दा है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के एक संगठन ने प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट रूप से कहा था

कि वे पंचायतों के तहत काम करना नहीं चाहते। पंचायती राज के लंबे इतिहासवाले राज्य पश्चिम बंगाल में भी जब कर्मचारियों को पंचायतो के अधीन किया जाता है, तो अदालत की ओर से ऐसी कार्यवाही के खिलाफ स्थगन आदेश आ जाता है।

पश्चिम बंगाल के पचायत मंत्री ने हाल ही में बताया कि विभागीय आदेशों के खिलाफ ऐसे सैकड़ो स्थगन आदेश हैं। इससे जुड़ा मुद्दा यह भी है कि जिला स्तर और उससे नीचे के स्तरो पर कार्यरत अधिकारी निर्वाचित पंचायत सदस्यों, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष या ग्राम पचायत अध्यक्ष, से आदेश लेना नहीं चाहते। स्पष्टतः स्थानीय सरकारो को मजबूत बनाने के लिए लोकतत्र

की नयी संस्कृति की जरूरत है।

5. देश के बहुत-से भागों में राजनीतिक जागरूकता की कमी नये पंचायती राज को पीछे खीचने का दूसरा बड़ा कारण है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उडीसा राज्यो में, जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 37 करोड़ थी, पंचायती राज के कार्य निष्पादन की दर कम है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक जागरूकता का निम्न स्तर तथा सामंती ताकतों और सामंती मूल्यों का प्रचलन है। 73वें सविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश पचायत चुनाव करानेवाला पहला राज्य था। इस चुनाव से निर्वाचित स्थानीय निकाय अस्तित्व मे आये। लेकिन चुनाव के बाद ही समाचारपत्रों में रिपोर्टे आने लगीं कि पंचायतों की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। राज्य के विभिन्न भागों से विभिन्न घटनाएँ सुनने को मिलीं। एक महिला प्रधान को नंगा किया गया, एक निम्न जाति के उपप्रधान को प्रताडित किया गया, एक अनुसूचित जाति के पचायत सदस्य को पीटा गया। इन घटनाओं के एक समाजशास्त्रीय अध्ययन ने दर्शाया कि पचायत उस समाज का, गाँव जिसका एक हिस्सा है, एक लघ् संस्करण है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 'स्वशासन की संस्थाओं से जिन आदर्शों की अपेक्षा की गयी थी, उन्हें मौजूदा अन्यायपूर्ण समाज मे लागू नही किया जा सकता।¹⁵ सभी घटनाओं का अध्ययन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की ओर सकेत करता है जो व्यक्ति की गरिमा को नही मानती, जिसके सामाजिक मुल्य व्यक्ति या उसके पद को उचित प्रतिष्ठा प्रदान नही करते।

 बहुत-से स्थानों पर पंचायते स्वयं शोषण का औजार बनी हुई हैं। भूमि सुधारों की अनुपस्थिति, साक्षरता का निम्न स्तर-विशेषतः महिलाओं मे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था इत्यादि कारक गाँवों मे कमजोर वर्गो के खिलाफ काम करेंगे। इससे महिलाऍ गभीर रूप से प्रभावित होंगी। ताकत के पारंपरिक शोषक ढाँचे के प्रभावो से पीडित अधिकतर लोग पंचायतों के माध्यम से मिले नये अवसरों का असरदार उपयोग करने मे असमर्थ हैं। नयी पंचायतों के कारण चुनावों के दौरान और चुनावो के पश्चात गॉवों में उनकी कार्यप्रणाली को ले कर गभीर तनाव पैदा हुए हैं। उडीसा के पंचायत चुनाव में भारी हिंसा के कारण जाने भी गयीं।

7. कंद्र सरकार खुद भी ऐसी स्थितियाँ पैदा करती है जो पचायतों के विकास में सहायक नहीं है। ऐसा कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना या संस्था, जो पचायतों की कार्य प्रणाली के समानातर शुरू की जाती है, स्थानीय सरकारों की व्यवस्था को कम करके आँकेगी। इस उभरते स्थानीय शासन के खिलाफ एक अत्यत गभीर अपराध

कम करके आकर्गा। इस उभरत स्थानाय शासन का खिलाफ एक अत्यत गंभार अपराध ससद सदस्यों को दो करोड़ रुपये (जिसे सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना कोष कहा जाता है) की राशि प्रदान करना है। यह केवल संवैधानिक प्रावधानों में ही दखल

नहीं है, बल्कि उस संघीय भावना में भी हस्तक्षेप है जिसके तहत नये स्थानीय निकाय

कार्य करते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश ई.एस. वैंकटरमय्या ने लिखा हे किसी राज्य में ऐसी परियोजनाओं पर, जो राज्य के क्षेत्राधिकार में हो, सासद के निर्देशों पर खर्च किया जानेवाला निर्वाचन क्षेत्र विकास फंड, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और संविधान की वैध सीमा रेखा में परपीड़ा का आनंद लेनेवाला हस्तक्षेप करता है। यह सिर्फ संघीय योजना के साथ ही नहीं, बल्कि शिक्त पृथककरण के स्वस्थ संवैधानिक सिद्धांत के साथ छेडछाड है। वि

भविष्य की आशा

संवैधानिक संशोधनो के बाद बहुत-सी घटनाएँ आशावादी स्थिति का सकेत करती है।

गैरसरकारी संगठन, सामुदायिक प्रयास और जन संगठन पंचायतों और

नगरपालिकाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। 73वं और 74वें संवैधानिक सशोधनों के बाद भारत में बड़ी संख्या में गैरसरकारी सगठन पंचायतों की सफलता के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। जागरूकता निर्माण कार्यक्रम, निर्वाचित सदस्यों विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण देने और चुनावों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, सामाजिक विकास के कार्यक्रम और नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में पंचायतों की सहायता कर रहे ये संगठन पंचायती राज का सामाजिक आधार बन रहे हैं। इस तरह भारत में स्थानीय निकाय अपनी सवैधानिक वैधता तथा नागरिक समूहों और स्वयंसेवी सस्थाओं के साथ संवाद के जरिये राज्य और नागरिक समाज के बीच एक आदर्श मिलन बिंद प्रस्तृत करते हैं।

नयी पंचायतो के अस्तित्व में आने के बाद से ग्रामीणों की भागीदारी से नये कार्यक्रमों को अर्थपूर्ण तरीके से लिया जा रहा है। इसका उदाहरण केरल में 'पार्टीसिपेटरी एड सस्टेनेबल पचायत लेवल डेवलपमेंट प्लानिंग' (पीएलडीपी) का नारा 'लोगों द्वारा लोगों की योजना' है। इस राज्य में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जन अभियान कार्यक्रम मील का पत्थर है। प्रस्तावित दस्तावेज में कहा गया है कि यह

पचायती निकायों को संशक्त करने की एक कोशिश है। इसके लिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पचायती राज/नगरपालिका निकाय वैज्ञानिक तरीके से एकीकृत योजनाओं को तैयार करें और उन्हें प्राथमिकता दे। 17

इस कार्यक्रम ने पंचायती राज को एक जन आंदोलन की शक्ल दी है ओर समूचे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया है। 1997-98 के बजट में वार्षिक योजना की 36 प्रतिशत राशि पचायती राज और नगरपालिका सस्थानों को वितरित की गयी।

इसके दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक क्षेत्रों, समाज सेवा और बुनियादी सरचना पर खर्च की जानी चाहिए। पचायती राज के निराशाजनक इतिहासवाले राज्य भी पंचायतो को अधिकार और वित्त देने के लिए

अपो आ रहे है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु इसके उदाहरण हैं। पचायत चुनावों के तत्काल बाद तमिलनाडु सरकार ने नव निर्वाचित पंचायतों को विकास कार्यक्रमो

से सबधित सृजनात्मक दायित्व सौंपने के लिए राज्य योजना आयोग से विशेष दल गठित करने को कहा, जो राज्य सरकार को परामर्श दे कि कौन-से अधिकार और

कार्य (जो अभी राज्य विभाग के पास है) स्थानीय निकायों को सौंपे जा सकते है। इस विशेष दल की सिफारिशों के आधार पर तमिलनाडु के मुख्य मंत्री एम करुणानिधि ने अपने बजट अभिभाषण में घोषणा कर दी कि अब स्थानीय निकाय

ही निर्णय लेगे और अधिकारियों का दायित्व डन्हे लागू करना होगा। पचायत प्रधान को कार्यकारी अधिकारी घोषित करते हुए सरकार ने आदेश जारी कर दिये कि उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ससाधन और स्टाफ प्रदान किये जायेगे।

हम जानते हैं कि जीवत स्थानीय सरकारो को अस्तित्व में लाने के लिए संवैधानिक संशोधन केवल एक आवश्यक शर्त है। हम यह भी जानते है कि पंचायते अपनी जड़े जमा सके, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति बिल्कुल नदारद है, वहाँ भी पचायतों को

मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाये गये है जो इसके पहले असभव थे। उडीसा में राज्य सरकार और विधायकों ने चुनावों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन संविधानिक प्राधिकार यानी चुनाव आयोग, प्रेस और लोग चुनाव चाहते

थं और न्याय प्रणाली ने उनका साथ दिया। सभी अड़चनों के बावजूद उडीसा में पचायत चुनाव हुए और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के करीब दस हजार प्रतिनिधि चुन गये। यह सब नये सवैधानिक संशोधन के कारण ही संभव हुआ है। बहुत-से देश बेहद रुचि के साथ हमारे इस स्थानीय सरकार के प्रयोग को देख रहे है। पाकिस्तान की नयी सरकार भारत की तरह स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने

की सोच रही है। भ्रष्टाचार, जो राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप वन चुका है, मजबूत स्थानीय निकायों के माध्यम से काफी हद तक कम हो सकता है। वैसे, यह आशका भी

राज्य तत्र का पुनर्गठन - 65

प्रकट की जा रही है कि राजनीतिक और आर्थिक विकंद्रीकरण के साथ भ्रष्टाचार का भी विकेद्रीकरण हो जायेगा। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि निचले स्तर पर लोगों के प्रति जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही का स्तर ऊँचा है। बहुत-से मामलों मे ग्राम सभाएँ सामाजिक ऑडिट का केंद्र विंदु बन रही है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि भी सचेत होते जा रहे हैं।

नया पंचायती राज सूचना के प्रवाह की बेहतर संभावनाएँ खोल रहा है। सूचना ताकत है और प्रभावशाली वर्ग ने सामान्य लोगों को अंधेरे में रखा था। सार्वजनिक मामलो में पारदर्शिता नहीं थी और हर चीज मे आधिकारिक गोपनीयता बनी हुई थी। पंचायत इस केद्रीकृत सूचना प्रणाली को तब तोड देगी, जब तीस लाख निर्वाचित सदस्य लोगों के जीवन को प्रभावित करनेवाली विभिन्न जानकारियाँ मॉगेंगे। राजस्थान मे मजदूर किसान शक्ति सगठन द्वारा किया गया कार्य सभी राज्यों मे फैलेगा और पंचायते इसके लिए सबसे प्रभावशाली हथियार होंगी।

उपलब्ध सामाजिक सूचकों के मुताबिक उत्तर भारत के राज्य सामाजिक विकास के संदर्भ में पिछड रहे है। इसका एक कारण इन राज्यों में ऐसे सामाजिक सुधार आदोलनों की कमी है जो समय-समय पर देश के अन्य हिस्सों में होते रहे हैं। इक्कीसबी शताब्दी की दहलीज पर खड़ी नयी पंचायतों में इन राज्यों के ग्रामीणों के जीवन में नया अध्याय शुरू करने की क्षमता है।

जब लोकतत्र आम नागरिको के हाथ में हो, तो वह गरीबी को मिटाने का जीजार बन सकता है। वह समान आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकता है। स्वस्य बाताबरण को स्थायित्व प्रदान कर सकता है और मानवाधिकारों के लिए काम कर सकता है। दुर्भाग्य से जमीनी स्तर पर लोगों को लोकतंत्र साँपने के खिलाफ काम करनेवाली ताकते अब भी काफी शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि यथास्थिति को बनाये रखने के लिए स्वार्थी तत्वों द्वारा जान-बूझ कर कोशिश की जा रही है, तािक स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली के बारे में संशय का वातावरण बनाया जा सके। लेकिन नया पंचायती राज अपना रास्ता बना रहा है। इस प्रक्रिया को उलटा नहीं जा सकता। राज्य तंत्र के पुनर्गठन का यह दूसरा अवसर है। पहला अवसर वह था, जब हमें गणतंत्रात्मक सविधान प्राप्त हुआ।

संदर्भ

- एम एन रॉय, शक्ति का विकेंद्रीकरण, व रेडिकल ह्यूमनिस्ट का सपादकीय, 30 अगस्त 1953
- 2. उपर्युक्त
- 3 उपर्युक्त
- 4 एम एन रॉय, दलविहीन राजनीति, द रेडिकल ह्यूमिनस्ट, 25 सितबर, 1949
- 5 अनुच्छेद 40, भारत का संविधान

- 6 लक्ष्यों का विवरण, सर्विधान (72वॉ संशोधन) विधेयक, 1991
- ७ अब्दुल नजीर साब, चौखवा राज की ओर, जॉर्ज मेथ्यू द्वारा सपादित प्रधायती राज इन कर्नाटका टुडे इट्स नेशनल डाडमेशस में सग्रहीत, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज तथा कसेप्ट पिलिशिंग कपनी, नयी दिल्ली, 1986, पृ 53
- 8 एस. गुहन, फेडरिलिंग्म एंड द सेवेटी-थर्ड अमेडमट सम रिफ्लक्शस, अप्रकाशित पाडुिलिपि, इस्टीट्युट ऑफ सीशल साइसेज, नयी दिल्ली
- 9 निर्मल मुखर्जी, एस एन. माथुर द्वारा लिखित न्याय पवायन्त एज इस्ट्रमेट ऑफ जस्टिस की अपनी भूमिका में, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज तथा कसेप्ट पब्लिशिग कपनी, नयी टिल्ली, 1997, पृ. 8
- 10 ए आई आर 1992, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में उद्धृत, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज नथा नेशनल डेयरी डेंबेनपमेट बॉर्ड, नयी दिल्ली, 1992, पृ. 24-25
- 11 के शुभा, कर्नाटका प्रधायत इतंक्शस 1995 प्रोसंस, उशूज एड मेक्रिशप प्रोफाइल, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज तथा कसेप्ट पब्लिशिग कपनी, नयी दिल्ली, 1996, 'तमिलनाडु मे स्थानीथ चुनाव की प्रक्रिया तथा चुनावी मुद्दे, 1996' पर प्रेस वक्तव्य, इस्टीट्यूट ऑफ सांशल साइसेज, नयी दिल्ली, 20 नवबर 1996
- 12 एम एन. रॉय, लोकतत्र तथा दलगत राजनीति, द रेडिकल ह्यूमनिस्ट, 22 अप्रेल 1951
- 13 जॉर्ज मैथ्यू, कर्नाटक मे पचायत चुनाव, हिदुस्तान दाइम्स, नयी दिल्ली, 9 फायरी 1987
- 14 गिरीश कुमार तथा बुद्धदेव घोष, वेस्ट बगाल पचायत इलेक्शस 1993 अ स्टडी इन पार्टिलिपेशन, इस्टीट्यूट ऑफ मोशल साइसेज तथा कर्सेप्ट पब्लिशिंग कपनी, नयी दिल्ली, 1996
- 15 जॉर्ज मेथ्यू तथा रमेश ती नायक, प्रचायतें व्यवहार में क्या लाभ है इनसे शोपित वर्गों को , इकॉनॉमिक एड पोलिटिकल वीकली, मुबई, 6 जुलाई 1996, खड 31, सख्या 27, पृ. 1765-1771
- 16 ई एस वैकटरमेया, सासद क्षेत्र विकास योजना ' सविधान पर हमला, *इंडियन एक्सप्रेस*, नयी दिल्ली, 13 फग्बरी, 1997
- 17 योजना के लिए जन अशियान एक दृष्टिकोण, केरल गज्य योजना बोर्ड, तिरुवनतपुरम, 1996, पृ 1
- 18 ग्रामीण स्थानीय निकायो को अधिकारों का हस्तांतरण' पर राज्य योजना आयोग की पहली रिपोर्ट, राज्य याजना आयोग, तमिलनाडु संग्कार, चेन्नई, 1997, पृ 9-10

गणराज्य और लघु गणराज्य

चौवन साल पूर्व जब हमने यानी भारत के लोगों ने देश के सभी नागरिकां के लिए न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत को 'सप्रभु लोकतात्रिक गणतंत्र' चनाने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय हमारे गणतंत्र के गठन की परिकल्पना में एक गभीर खामी रह गयी थी। हमने इस बात पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया कि उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। यानी, उस समय हमारे लगभग पाँच लाख गाँवों की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गयी थी। सविधान के प्रवर्तनीय भाग में किसी जिक्र के बजाय उनके बारे में सिर्फ नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 40) में ही चर्चा की गयी, जिनकं अनुसार 'राज्य ग्राम पचायतों को सगठन करने के लिये कदम उठायेगा ओर उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।' आश्चर्य यह है कि यह बुनियादी खामी इस दावे के बावजूद चली आ रही है कि स्वतंत्रता आंदोलन का मकसद ग्राम स्वराज हासिल करना है। गाधी जी ने यह बात बार-बार दुहरायी थी कि 'स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। तभी प्रत्येक गाँव संपूर्ण अधिकार सपन्न पचायत अथवा गणराज्य होगा।'

दिल्ली में ससद और राज्यों में विधान सभाओं के स्तर पर भारतीय गणतत्र का ऊपरी ढॉचा तो बना दिया गया, मगर गॉव, ब्लॉक और जिला स्तर पर लोकतत्र की पूरी तरह अनदेखी की गयी। इसी के परिणामस्वरूप हमारे गॉव आज भी लगभग उतने ही गरीव, जातिवाद से त्रस्त, देश-दुनिया से कटे हुए तथा अविकसित है जितने वे गणतत्र की नींव रखें जाने के समय थे।

भारत के ग्रामीण समुदाय प्राचीन काल से ही पंचायतों के रूप मे सगिठत थे। यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की पहचान थी और इनमे मानवीय गतिविधि, विकास तथा प्रगति के जीवंत केंद्र बनने की सभावना इसी कोटि के पश्चिमी सगठनों से कहीं ज्यादा थी। रूस में ये संगठन 'मीर', जर्मनी मे 'मार्क' तथा मध्यकालीन इग्लंड में मेनार कहलात थे सामाजिक ओर राजनीतिक जीवन में इन सबकी भूमिका सीमित थी। इसके विपरीत, हमारी पचायतें प्रशासन की धुरी, सामाजिक जीवन का केट्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की वुनियाद तथा, इन सबसे भी ऊपर, सामाजिक

भाईचारे का केंद्र-बिंदु थीं। उनके कामकाज को देख कर ही 1830 में सर चार्ल्स मेटकॉफ जैसे सतर्क पर्यवेक्षक ने 'लघु गणतंत्र' कह कर उनकी तारीफ की थी। मरा

आशय कर्ताई यह नहीं है कि ये लघु गणराज्य सभी लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर आधारित फल-फूल रहे आदर्श समुदाय थे। भारतीय समाज के जाति-ग्रस्त ओर सामती ढॉचे के कारण डॉ. आबेडकर ने अपने निजी अनुभवो के आधार पर सविधान

सभा में जो बयान दिया था, उसमें काफी सच्चार्ड है। उन्होंने इन ग्राम पंचायतों को भारत की बरबादी का कारण बताया था। यह बात तय है कि आंबेडकर को लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण अथवा एक आदर्श पंचायती राज प्रणाली के द्वारा जनता को सत्ता देने के सिद्धात से कोई आपत्ति नहीं थीं, उनका आक्रोश तो ग्रामीण समाज में प्रचलित

हमारे तर्क की पुष्टि संविधान सभा में मैसूर के माधव राव द्वारा दिये गये वक्तव्य से होती है। उन्होंने यह बात स्वीकार की थी कि कुछ गाँव अरसे से गुटबाजी से ग्रस्त हैं; वे अत्याचार के छोटे-छोटे तंत्र तथा छुआछूत के गढ है। पर उन्होंने यह

जातिगत भेदभाव के प्रति था।

भी याद दिलाया कि यदि 30 प्रतिशत गाँवों को भी अच्छा कहा जा सकता है तो उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र में मैसूर की लोकप्रिय सरकार

द्वारा किये जा रहे कार्यों का उदाहरण भी दिया था। पचायती राज के विचार की ओर जवाहरलाल नेहरू काफी बाद में आकर्षित

हुए थे। बलवतराय मेहता समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन तथा एस.के. दे से प्रभावित हो कर नेहरू ने यह राह पकड़ी थी। दे ने ग्राम सभा से लोक सभा तक सस्थाओं के जीवंत क्रमिक सिनसिले की कल्पना की थी। जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक

पत्र में गांधी जी ने कहा था कि सत्य एव अहिंसा सिर्फ ग्रामीण जीवन की सादगी मे ही प्राप्त किये जा सकते है। इस पर नेहरू की प्रतिक्रिया यह थी, 'मेरी समझ मे यह नहीं आता कि गाँव अनिवार्य रूप से सत्य और अहिसा की प्रतिमूर्ति केसे हो सकते हैं? आम तौर पर तो गाँव बौद्धिक तथा सास्कृतिक रूप से पिछडे हुए है तथा उलटे चल कर तरक्की नहीं की जा सकती। संक्चित सोच के लोगों के

असत्यवादी एवं हिसक होने की सभावना ज्यादा रहती है।' लेकिन नये गणतत्र की खामियों तथा उसके शासन की तरह-तरह की समस्याओं को अनुभव करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण लोकतत्र के सबसे बड़े समर्थक बन गये थे।

1959 में राजस्थान के नागौर कस्बे मे स्वतंत्र भारत की पहनी ग्राम पंचायत का उद्घाटन करते हुए पंडित नेहरू ने उसे 'नये भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी एव ऐतिहासिक कदम' बताया था।

पिछले पाँच दशको मे भारत में मूलभूत परिवर्तन आया है। इसके बावजुद हमारे गणतात्रिक संविधान ने समय की कसोटी पर खरा उतरते हुए अपनी मूलभूत खुबियों को बरकरार रखा है। इसके साथ ही, मूलभूत सिद्धातों के दायरे में ही परिवर्तन की माँगों के अनुरूप नयी व्यवस्थाएँ विकसित करने के लिहाज से यह काफी लचीला भी सावित हुआ है। इसी प्रक्रिया में यह स्पष्ट हुआ कि संविधान एवं संधीय ढाँचे अथवा प्रशासनिक ढाँचे के अतर्गत गाँवों की दिये गये अस्पष्ट स्थान से गणतंत्र की नीव का मजबूत करने में सहायता नहीं मिल सकती। इस दृष्टि से 1993 का वर्ष, जब पचायतों को सविधान के नौबे भाग में शामिल किया गया, ऐतिहासिक वर्ष था। अब सबैधानिक मान्यता के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित तीस लाख महिलाएँ और पुरुष हमारे सामने हैं। इन पर बहुत वडी तादाद मे-500 से ज्यादा जिला पंचायतों, लगभग 5100 ब्लॉक अथवा तालुक पंचायतों तथा लगभग 2,25,000 ग्राम पचायतां—स्थानीय स्तर की राजनीतिक संस्थाओं के संचालन का दायित्व है। नयी प्रणाली में हमारे पास 89 नगर निगम, 1500 नगरपालिकाएँ तथा लगभग 1800 नगर पंचायते है। दुर्भाग्य से इन सस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ससद तथा 27 राज्यो एव केंद्र शामित प्रदेशो की विधान सभाओं के 4862 जन प्रतिनिधि अपने लिए खतरा मान कर चल रहे हैं।

उन्हें खतरा मानने की मानसिकता से दो परिस्थितियाँ बन गयी हैं। पहली परिस्थिति यह है कि 5000 से भी कम सख्यावाले ये जन प्रतिनिधि अपने आपको और अधिक अधिकारो, आर्थिक फायदों एवं विशेषाधिकारो से लैस करते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, सासद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष की राशि रातो-रात एक करोड़ रुपये से बढ़ा कर दो करोड़ रुपये कर दी गयी है तथा राज्यों में विधायको के विवेकाधिकार से खर्च की जानेवाली राशि भी शीघ्र ही बढ़ा कर दुगुनी कर दी जायेगी। यह प्रवृत्ति इसी तरह बढ़ती जायेगी; इसका कोई अंत नहीं है। दूसरी परिस्थिति यह है कि भारतीय संविधान के तकाजे के अनुरूप राज्य इन पचायतों को 'स्वशासन की मस्थाएँ' बनाने को तैयार नहीं हैं। यहाँ 'राज्य' से तात्पर्य राज्यों की विधान सभाओ तथा उनके सदस्यों से है। कुछ अपवादों को छोड़ कर, राज्यों ने ग्राम पचायतो अथवा उनसे ऊपर की मस्थाओं को स्वायत्तता एव स्वतंत्रता से कार्य करने के अधिकारों एव औजारो से सुसज्जित नहीं किया है। लगभग सभी राज्यों ने संविधान की इबारत का तो पालन किया है, लेकिन उसकी भावना की अनदेखी कर दी है। ज्यादातर राज्य जिलो में निर्वाचित जिला शासन के बजाय अब भी कलक्टर राज को ही बढ़ावा दे रहे है। विधायकों तथा राज्यों के मंत्रियो एवं किसी हद तक सांसदों को भी यह डर सता रहा है कि यदि जन प्रतिनिधि होने के अपने एकाधिकार को उन्होंने किसी से बॉट लिया, तो उन्हे हासिल सामाजिक हैसियत एव अधिकारो मे कटौती हो जायेगी; इसलिए इसे रोकने के लिए नये पंचायती राज को खत्म करने की धीरे-धीरे, मगर

लगातार काशिश चल रही है इसी षड्यत्र के अतगत पचायत प्रतिनिधियो पर अयोग्यता, अक्षमता, श्रष्टाचार तथा अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियो का आरोप लगाया जा रहा है। पचायती राज की सफलता के एक भी किस्से पर फोकस नहीं किया

जाता। इस षड्यत्र में राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ नौकरशाही ने भी सॉठ-गॉठ कर रखी है। पड्यत्र यह है कि लोगों तथा जनमत निर्माताओं के मन में इन सस्थाओं के प्रति संदेह का बीज बो कर ग्रामीण जनता की सत्ता को नष्ट कर

दिया जाये तथा सारे अधिकार अपने तक सीमित कर लिये जाये। भारतीय गणतंत्र की पचासवी वर्षगाँठ सिर्फ एक वर्ष दूर है। क्या गाँवो को

सचमुच 'लघु-गणराज्य' बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग किया जा सकता है? सौभाग्य से हमारे पास पचायतो का सविधान प्रदत्त उपकरण भी मौजूद है। लेकिन विस्तृत अधिकारों एव डायित्वों के साथ पचायतों के संविधान के नौव भाग का अग बनने संबंधी जानकारी एव जागरूकता लोगा में बहुत कम है। निहित स्वार्थ के लोग

यह नहीं चाहते कि नये विचारों से जनता में जागरूकता आये, इसलिए लघु गणराज्यों के अस्तित्व की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। यह अभियान इस नारे पर केंद्रित होना चाहिए: गणराज्य के पचासवे वर्ष

चाहिए। यह अभियान इस नारे पर केंद्रित होना चाहिए: गणराज्य के पचासवे वर्ष में हर गाँव बने एक लघु गणतत्र। पचायती राज को मजवूत बनाने के लिए कार्यरत स्वयसेवी संगठनों को देश

भर की 2,25,000 ग्राम पचायतों को लघु गणराज्य बनाने के लिए इस विषय पर सभाएँ एवं भाषण आयोजित करने चाहिए। विधायकों और मंत्रियों को जनता के

सामने यह शपथ दिलायी जानी चाहिए कि वे पंचायतों को संविधान के अनुरूप सपूर्ण अधिकार तथा वित्त देने की राह में रोडा नहीं बनेगे। विद्यालयों और महाविद्यालयों में हमारे गाँवों के महत्व तथा लोकतात्रिक प्रक्रिया द्वारा उनकी स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता के विचार पर पदयात्रा, वाद-विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन

किया जाना चाहिए। इससे महिलाओं की भागीदारी, सूचना के अधिकार, चुनाव के मूल्यों तथा जाति, धर्म अथवा जन्म को भूल कर सभी नागरिकों की समानता तथा ग्राम स्तरीय लोकतत्र से जुडे ढेर सारे मुद्दों को सामने लाने मे मदद मिलेगी। गॉबो मे इन विषयो पर नारो, परदों, पोस्टरों, दीवार लेखन आदि का अभियान चलाना

चाहिए। विद्यालयो, महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से जन संगठनों, व्यापारियों, लघु उद्यमियों आदि को इन कार्यक्रमों का प्रायोजन करना चाहिए। लघु गणराज्यों के विचार का प्रसार करने के लिए गाँवों में रह रहे बुजुर्ग और सेवानिवृत्त

गणराज्यों के विचार का प्रसार करने के लिए गाँवों में रह रहे बुजुंग और सवानिवृत्त लोग वैचारिक योगदान और समर्थन दे सकते हैं। भारतीय गणतंत्र का पचासवाँ वर्ष नयी सहस्त्राब्दि के साथ शुरू हो रहा है।

यह हमारे समकालीन इतिहास में गणतत्र के संस्थापकों के सपनों को सच बनाने की राह में रोडे अटकानेवाली ताकतों से दी-चार होने का सबसे बढिया अवसर है।

गणराज्य और लघु गणराज्य . 71

अपने नेताओ पर भरोसा करते हुए लोगों ने अपने सपनों और आदर्शों को अमली जामा पहनाने का जिम्मा उन्हीं पर छोड़ दिया था, लेकिन उनके सपने सच नहीं हो पाये। इसलिए इस उद्देश्य को पाने के लिए लोगों को पंचायतों के माध्यम से गाँवों के नवीकरण एव उन्हें नये सिरे से खड़ा करने के आदोलन में शरीक हो कर यह जिम्मा अब अपने कंधों पर लेना होगा। हरेक राज्य के हिसाब से इस आदोलन की स्थानीय कार्यप्रणाली तय की जा सकती है। संचार क्रांति के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचने से गाँवों को लघु गणराज्य बनाने के विचार का प्रसार आज काफी आसान हो गया है।

हमारा प्रतिनिधिक लोकतंत्र अभी तक कार्य करता रहा है, लेकिन कभी-कभी आश्चर्य होता है कि यह सिर्फ ढाँचा ही है या इसके भीतर किसी आत्मा का भी निवास है। यह हम सभी के लिए अपने लोकतत्र में जान डालने का अवसर है। यह जान सिर्फ प्रत्यक्ष लोकतत्र से ही पड़ सकती है। 73वे संविधान सशोधन तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 ने ग्राम सभा के जिर्ये प्रत्यक्ष लोकतत्र के लिए अनुकूल कानूनी खाका तैयार कर दिया है। भारत के प्राचीनतम निवासियों के क्षेत्र यानी सभी आदिवासी गाँवों (पाँचवीं अनुसूचा में वर्णित क्षेत्रों) में ग्राम सभा की स्थापना को इस आधार पर अनिवार्य कर दिया गया है कि समुदाय को ही स्वशासन की बुनियादी इकाई होनी चाहिए। इन ग्राम सभाओं को काफी अधिकार दिये गये हैं।

इसी किस्म का प्रत्यक्ष लोकतंत्र लघु गणराज्यो की आधारशिला है। भारत का गणतंत्र इन्ही लघु गणराज्यो के बल पर फल-फूल सकता है—क्योंकि यही उसकी जड़े हैं। इसलिए गणतत्र के पचासवे वर्ष में प्रत्येक गाँव को लघु गणराज्य बनाने में हमे कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। अगली सहस्त्राब्दि में इस देश में लाखों लघु गणराज्यों को फलने-फूलने दीजिए।

खाद्य सुरक्षा एवं पंचायती राज

1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के दौरान इस विषय पर ध्यान दिया गया। विश्व बेक के अनुसार खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है, 'भौतिक एवं आर्थिक रूप में सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकतानुसार भोजन मुहैया करना।' विश्व खाद्य सम्मेलन कार्य-योजना (1996) में इस विषय की सर्वाधिक सटीक परिभाषा प्रस्तुत की गयी, 'खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का जन्म हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। सर्वप्रथम

का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा ऐसे भौतिक एव आर्थिक अवसर उपलब्ध रहे जिनसे पर्याप्त, सुरक्षित एवं पोषक भोजन पाने के साधन एवं सक्रिय एव स्वस्य जीवन जीने के लिए उसकी भोजन सर्वधी आवश्यकताएँ उसकी खाद्य रुचियों के

अनुसार पूरी हो सके।'⁵ खाद्य सरक्षा के तीन

खाद्य सुरक्षा के तीन मुख्य अग है : खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनका वितरण तथा आम नागरिक तक पहुँच।*

उपलब्धता का अर्थ है जनसख्या के अनुपात में खाद्य पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सुलभ होना तथा जनसख्या के प्रत्येक वर्ग को उत्पादन का हिस्सा मिलना। इसके निए जम्बरी है, उचित वितरण व्यवस्था। खाद्य पदार्थों की सुलभता के भौतिक एव आर्थिक दोनों ही पहलू है। भौतिक सुलभता को प्रभावकारी वितरण प्रणाली से हल किया जा सकता है। कितु आर्थिक सुलभता के लिए व्यापक स्तर पर काम करना होगा। इसका तात्पर्य है प्रत्येक परिवार की व्यय करने की क्षमता की सीमा में उचित

पंचायतें एवं खाद्य सुरक्षा

मुल्य पर खाद्य पदार्थो का उपलब्ध होना।

गॉव, तहसील तथा जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासी निकायों के रूप मे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पचायतो की अहम भूमिका है। स्थानीय स्वशासी व्यवस्था खाद्य सुरक्षा के उपर्युक्त वर्णित तीनो अगो—उपलब्धता, विरतण और पहुँच—के सक्षम

कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

खाद्य उत्पादन

आज देश में पर्याप्त खाद्य उत्पादन हो रहा है। आम जनता की भोजन संबधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह उत्पादन पर्याप्त भी है। फिर भी कुछ क्षेत्री में उत्पादन की दर अत्यत ही निम्न है। जहाँ भी पचायतें शक्ति-संपन्न है, कृषि उत्पादन बढ़ाने में उनकी विशिष्ट भूमिका रही है।

ग्यारहवी अनुसूची के अनुसार कृषि उत्पादन संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्र पचायतो को सौपे गये है। ये क्षेत्र इस प्रकार है:

- (1) कृषि एवं कृषि विस्तार
- (2) भूमि का उन्नयन, भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, चकबदी एव मृदा-संरक्षण
 - (3) लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा जल संरक्षण विकास कार्यक्रम
 - (4) पशुपालन, डेयरी एवं मुर्गी पालन
 - (5) मत्स्य पालन

इसके अतिरिक्त पंचायतो को इन क्षेत्रों में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं के निर्माण का दायित्य भी सौपा गया है। स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं एवं योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी पचायतों को ही निभानी है।

कृषि के लिए नयी तकनीक हासिल करने तथा उसका उपयोग करने में भी पचायते एक प्रभावकारी संस्था के रूप में कार्य कर सकती है। चूँिक उन्हें स्थानीय वस्तुस्थिति की जानकारी होती है, इसलिए वे स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में अधिक कारगर रूप से काम कर सकती हैं। कृषि विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार तकनीक के विकास में सहयोग दे सकती हैं। उन्हें आवश्यक तथ्य मुहैया करा सकती है।

उत्पादकता की उच्च दर सुनिश्चित करने में भूमि सुधारों का महत्व तथा खाद्य सुरक्षा में उनका योगदान कम करके नहीं ऑका जा सकता। भूमि सुधारों के कारण गरीब गॉववालों (छोटे एव सीमात किसानों की) आमदनी बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप उनकी व्यय करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

इस सबध में पश्चिम बंगाल सबसे अच्छा उदाहरण है। जाना-माना 'ऑपरेशन बरगा' बंगाल में इसीलिए सफल हो सका, क्योंकि इसके लिये पंचायतों ने भरसक प्रयास किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल स्तरीय दबाव के चलते भूमि सुधारों को जारी रखने में वर्ष 1978-1983 में पंचायतों की निर्णायक भूमिका रही। भूमि सुधारों

के परिणामों का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के

पास देश की कृषि योग्य भूमि का केवल 3.5 प्रतिशत हिस्सा है, किंतु देश की कुल अधिशेष भूमि वितरण में उसका योगदान 20.77 प्रतिशत रहा।

कृषि के विकास में भूमि सुधारों का योगदान 1980 के दशक में हुए कृषि विकास की वृद्धि दर से जाहिर होता है। 1983 के बाद के कालखड़ में पंचायतों ने मजबूती से काम करना आरंभ कर दिया था। 1950-60 के दौरान पश्चिम बंगाल में चावल के उत्पादन की वृद्धि दर सिर्फ 101 प्रतिशत थी, जो 1980-81 में 641

प्रतिशत हो गयी। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों मे घूम कर देखा जाये तो कृषि वृद्धि दर, पंचायतो की भूमिका, जानकारी का उपयोग तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण जनता और जागरूक पंचायती व्यवस्था के बीच का गहन सबंध स्पष्ट हो जायेगा। सरकार

द्वारा विभिन्न विभागो द्वारा किये जानेवाले कार्यो को पचायतो की परिधि में लाया गया, जिसके कारण स्थानीय सामुदायिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक कार्य के लिए स्थान बन सका।

देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खाद्य सामग्री की वितरण प्रणाली का सर्वाधिक

खाद्य वितरण

उचित माध्यम सार्वजिनक वितरण प्रणाली है। लक्षित जन वितरण प्रणाली 1997 में लागू की गयी थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों को कम मूल्य पर चावल एवं गेहूं उपलब्ध करवाना था। यह वह वर्ग है, जिसकी खाद्य सुरक्षा अनिश्चित रहती है। चूँिक जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ऐसे बिदु अनेक हैं जहाँ से अनाज दूसरी जगह ले जाया जाता है, प्रधान मंत्रों को हाल ही में स्वयं स्वीकार करना पड़ा कि जन वितरण प्रणाली अनेक स्थानों पर अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। जिन राज्यों के अधिकाश लोग गरीब है, वहाँ अनाज का सीमित उठाव व्यवस्था में व्याप्त प्रशासकीय अक्षमताओं की ओर संकेत करता है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि इस स्थिति से निपटने के लिए श्रीग्र ही कोई हल निकाला जाये तथा पचायतों के योगदान के लिए राह बनायी जाये, तािक 'सबके लिए भोजन' अभियान को सफल बनाया जा सके।

जन वितरण प्रणाली में पंचायतो की भागीदारी से जरूरतमंदों को भोजन मिलना और अधिक सुनिश्चित होगा। इसीलिए 11वी अनुसूची में जन वितरण प्रणाली को शामिल किया गया है।

इस प्रावधान को अमली जामा पहनाने के लिए उड़ीसा के क्योझर जिले में किये गये प्रयोगों के समान ही और भी नये कदम उठाने की जरूरत है। उड़ीसा ग्राम पचायत अधिनियम, 1965 की धारा 44(1) (एक्स-3) के तहत जन वितरण प्रणाली ग्राम पंचायत का दायित्व है। ग्राम पंचायतो का यह कर्तव्य है कि वे वित्तीय

स्थिति के अनुरूप, गाँवो में जन वितरण प्रणाली का संचालन करे तथा उस पर नियत्रण

रखे। साथ ही जन वितरण प्रणाली की कार्य कुशलता के लिए भी पचायतें ही उत्तरदायी होगी। इस प्रावधान के अनुसार क्योझर में पचायतों को जन वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री का दायित्व सौपा गया है। इस प्रकार निजी विक्रेताओं को इस क्षेत्र से हटा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इससे पंचायतों की वित्तीव स्थिति में सुधार होने के साथ भ्रष्टाचार में भी कमी आयी है। वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो गयी है। जिम्मेदारी की भावना वढी है।

राजस्थान में राज्य सरकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम सभा का प्रयोग एक सार्वजनिक मच के तौर पर कर रही है। 'अन्नपूर्णा परियोजना' के तहत ग्राम पचायतों को लाभार्थियों का चयन करना होता है। उनकी सूची तैयार कर सभी के द्वारा अवलोकन हेतु प्रदर्शित करना होता है। आम तौर पर यही देखा गया है कि ग्राम सभा की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तथा कार्यक्रमों की मार्गदर्शिका के अनुरूप होती है।

हाल ही में पचायती राज संस्थाओं को दायित्व एवं सत्ता के हस्तांतरण के सदर्भ में कार्य दल की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में पचायती राज के विभिन्त स्तरों पर किये जानेवाले अनेक दायित्वों की पहचान की गयी है। है रिपोर्ट में ठोस हग से बताया गया है कि जन वितरण प्रणाली के तहत पचायतें कौन-कौन-से कार्य कर सकती है। ये कार्य इस प्रकार हैं '(1) आवश्यक पदार्थों की उपलब्धता एव वितरण तथा जन वितरण प्रणाली कार्यक्रम के तहत माँग का अनुमान लगाना; (2) यातायात, भंडारण तथा आपूर्ति प्रणाली; (3) निरीक्षण तथा नियमों का प्रवर्तन; तथा (4) जन वितरण प्रणाली को गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों से जोडना।

पचायती राज के प्रत्येक स्तर पर किये जानेवाले कार्यो का ब्यौरा भी रिपोर्ट में दिया गया है। जिला पंचायतों को समग्र रूप से आकलन तथा नियोजन का दायित्व निभाने के उपयुक्त समझा गया है। उदाहरण के लिए जिला पंचायतों को जन वितरण प्रणाली केंद्रों का जिला स्तरीय नक्शा तैयार करने तथा नयी दुकानें खोलने की जिम्मेदारी दी गयी है। मध्य स्तरीय पंचायतें इन कार्यो की योजना बनाने, अपने क्षेत्रों में कार्यान्वयन की दिशा तैयार करने तथा ग्राम पंचायतों एवं जिला पचायतों के बीच संबंध सूत्र की भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम पंचायतों का कार्य है उचित मूल्य की दुकानों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करना तथा उन पर नियत्रण रखना, फर्जी राशन कार्डधारियों के नाम सूची से हटाना तथा उचित लाभार्थियों को इस प्रणाली का लाभ पहुँचाना।

कार्य दल की रिपोर्ट में कोई चिकित करनेवाली बात नहीं हैं। जनवरी 2002 में उपभोक्ता मामलों तथा सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय ने एक छह सूत्री कार्ययोजना बनायी थी। इस योजना का उद्देश्य था, ग्राम पचायतों को उचित मूल्य की दुकानों की कार्य प्रक्रिया का निरीक्षण करने, उसके लिए नियम बनाने और उन नियमों को लागू करने का अधिकार देना। बहरहाल, कार्य दल की रिपोर्ट इस मामले में ज्यादा विस्तृत है कि इसमें पचायती राज सम्थाओं की गतिविधियों को एक मुसंगत स्वरूप दिया गया है तथा उन अधिकारों एवं वित्तीय स्रोतों को रेखांकित किया गया है जो प्रत्येक गतिविधि को सपन्न करने के लिए आवश्यक हैं। इस अर्थ में यह नवीनतम रिपोर्ट कई स्तरों पर पूर्व-उल्लिखित पहलों और प्रयोगों तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की निर्णायक भूमिका के आधार पर अर्जित देश की सामूहिक बुद्धिमता का प्रतिनिधित्व करती है।

भोजन की उपलब्धता

खाद्य मुरक्षा के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग की आय के साधन वढ़ाना आवश्यक है। यदि जनता के पास व्यय करने का साधन होगा तब ही वह अपनी भोजन संवंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। हाल ही में उड़ीसा के काशीपुरा में भूख से हुई मृत्यु की घटनाएँ ग्रामीण निर्धन जनता की अपर्याप्त क्रय क्षमता का प्रमाण हैं। यह पंचायतों की उपेक्षा कर जनता पर ऊपर से लादी गयी विकास-मूलक तथा कल्याणकारी परियोजनाओं की असफलता का भी प्रमाण है। पंचायते परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर जिम्मेटारी और पारदर्शिता ला कर समाज के कमजोर एव उपेक्षित वर्गों को सशक्त कर सकती है। वे गाँव के प्रभुत्वशाली वर्गों तथा भ्रष्ट अधिकारियों के बीच की साँठ-गाँठ को समाप्त कर सकती है। सामाजिक अकेक्षण का प्रयोग कर तथा जानकारी के अधिकार को भली भाँति लागू कर जन वितरण प्रणाली तथा उचित मूल्य की दुकानों को जनता के प्रति जवाबदेह बना सकती है। यह सर्वविदित है कि पचायतों में समाज के हाशिये के लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हासिल करने की अतर्निहित क्षमता है।

पूर्व वित्त मत्री पी. चिदबरम ने जन वितरण प्रणाली को समाप्त कर पचायतो द्वारा 'काम के बदलें भोजन' जैसे कार्यक्रमों के पक्ष में दलील दी थी। ' इस प्रकार के कार्यक्रम निर्धन लोगों (जिनके पास न काम है न भोजन) के लिए भोजन मुहैया कराने की दिशा में बहुत महत्त्व रखते हैं। इसके साथ ही चिदबरम ने पचायतों की अब तक की सीमित भूमिका को चिस्तृत करने का भी आह्वान किया था। उनका कहना था कि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गेहूँ एवं धान पचायतों को सोप दिया जाये। पंचायते निश्चित करें कि उनके क्षेत्रों में कौन-से काम होने चाहिए। कार्य के अनुपात में गेहूँ और धान देने की मात्रा भी वे ही तय करें। इस प्रकार पचायतों के द्वारा ग्रामीण विकास तथा खाद्य सुरक्षा दोनों ही लक्ष्यों को पाना सभव होगा।

योजना का विकेंद्रीकरण

खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में पंचायते अनेक प्रकार से योगदान कर सकती है, यह अब तक की चर्चा सं स्पष्ट है। कितु यदि तृणमूल स्तर पर जनता को सही अर्थों में सशक्त नहीं किया जायेगा तो इस लक्ष्य को पाना या तो असभव होगा अथवा दीर्घकाल में इसका कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ स्थानीय निकायों को स्वायत्तता प्राप्त है, विकास सबधी प्राथमिकताएँ तय करने, प्रकल्प बनाने तथा उनके कार्यान्वयन का अधिकार है, वहाँ भूख के कारण मृत्यु होगी—ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई भी संवेदनशील समुदाय आज अपने सदस्यों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकता। इस प्रकार तृणमूल स्तरीय लोकतंत्र के माध्यम से स्थानीय जनता का सशक्तीकरण तथा विकेद्रित योजना निर्माण खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी गारटी है। गत पाँच वर्षों में केरल राज्य का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि यदि लोगों की भागेदारी के आधार पर नीचे के स्तर से वैज्ञानिक योजना निर्माण किया जाये, तो विकेदीकरण जनता के विकास तथा खाद्य सुरक्षा का सबसे अनुकूल तथा उचित तरीका है।

देश में सर्वप्रथम केरल राज्य सरकार ने 1996 मे नौवीं राज्य पचवर्षीय योजना के तहत बजट का 35-40 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को देने का निर्णय किया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को और अधिक स्वायत्तता देने के लिए 75 प्रतिशत निधि बंधनरहित अनुदान राशि के रूप में देने का भी निर्णय किया गया। शर्त केवल एक ही रखी गयी थी कि प्रदत्त निधि का 40 प्रतिशत भाग उत्पादक क्षेत्र (कृषि तथा संबंधित गतिविधियाँ, उद्योग, स्य-रोजगार आदि) पर व्यय करना होगा।

जन योजना अभियान के माध्यम से योजना निर्माण मे विकेंद्रीकरण की अवधारणा जिस रूप में की गयी, उसके माध्यम से जनता अपनी जरूरतो और प्राथमिकताओं को जिस रूप में देखती है और केद्रीकृत नौकरशाही द्वारा देखा जाता है, उनके बीच के फर्क को भी सामने रखने का प्रयास किया गया। इसके पूर्व राज्य द्वारा बनायी गयी योजनाओं और पचायतों द्वारा बनायी गयी योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि दोनों की प्राथमिकताओं में कितना बड़ा फासला है। स्थानीय निकायों ने राज्य की तुलना में कृषि को काफी ज्यादा तरजीह दी। उन्होंने स्थानीय बजट का 19 प्रतिशत कृपि के लिए रखा, जबिक राज्य सरकार की योजना में यह मात्र 10.5 प्रतिशत था। 11

इसी तरह पशु पालन को 7.57 प्रतिशत अंश दिया गया। यह तथ्य अपने आपमे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल में डेयरी का काम वहुत बड़े व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जाता। 12 आम तौर पर यह देखा गया कि डेयरी एवं पशुपालन से छोटे किमानो की आय में बढोत्तरी हुई। अनेक अध्ययनो से ज्ञात होता है कि पचायतो द्वारा किये गये प्रयासों से कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। उदाहरण

कं लिए कॉजीकुझी पचायत (अलाप्पुज्हा, केरल) ने पारंपरिक सब्जी उत्पादन को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। कृषि भवन ने तकनीकी जानकारी दी तथा उनका

मार्गदर्शन किया। वित्तीय पहलू पंचायतों का दायित्व था। पंचायतों ने जन जागरूकता और जन सपर्क अभियान चला कर स्थानीय लोगों को अभिप्रेरित भी किया। इस कार्यक्रम की सफलता नि रसदेह उल्लेखनीय रही। फसल कटाई के दौरान तीन महीनों तक सब्जियो की कीमतो में 20-30 प्रतिशत की गिरावट आ गयी। इसी प्रकार लघु

तिंचाई परियोजना तथा कृषि के लिए अन्य सरचनागत सुविधाओं को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया। इससे ज्ञात होता है कि जनता के लिए खाद्य सुरक्षा का क्या मूल्य है। यदि तोगों को अवसर दिया जाये, तो वे स्थानीय समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा सनिश्चित करने में जुट जायेगे, बशर्ते उनकी जरूरतों तथा प्राथमिकताओं के मुताबिक

योजना बनाने एव उन्हें लागू करने के लिए स्थानीय सरकारों को अधिकार सपन्न बनाया जाये। कार्यान्वयन के स्तर पर, जिम्मेदारी एव पारदर्शिता के लिए अनेक कदम उठाये

गयं, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार मे भी कमी आयी। अनाज का गायब होना भी कम हुआ। विकेद्रीकरण से न केवल विकास कार्यक्रमां ने जनता की प्राथमिकताओं को बहुत हद तक पूरा किया, अपितु आम जनता की क्षमता एवं कौशल में भी इजाफा हुआ। इससे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य सुरक्षा आम जनता की सर्वोच्च पाथमिकता है—विशेषकर ग्रामीण जनता की।

निष्कर्ष

उपर्युक्त चर्चा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि पंचायती राज संस्थाओं मे असमर्थ व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की कितनी क्षमता है। 73वे सविधान सशोधन एव 11वी अनुसूची ने खाद्य सुरक्षा हेतु पंचायती राज सस्थाओ द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए काफी गुजाइश बनायी है—चाहे वह उत्पादन में बढोत्तरी का मामला

हो या सुचारु वितरण के द्वारा उपलब्धता को सुनिश्चित करने का। इस सभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए पश्चिम बगाल ने, जहाँ पहले पर्याप्त खाद्य उत्पादन नहीं होता था, और बाद में एक हद तक केरल ने कुछ पहल की है। लेकिन अभी बहत कुछ करना शेप है। इस दिशा में दो-सुत्री रणनीति बनाने की जरूरत है। प्रथम,

बहुत कुछ करना शेप है। इस दिशा में दो-सूत्री रणनीति बनाने की जरूरत है। प्रथम, यह सुनिश्चित करना होगा कि पचायतों को वित्तीय अधिकार, दायित्व और कर्मचारी दिये जाये। द्वितीय, पचायतें ग्राम स्तरीय योजनाएँ प्रभावकारी ढंग से बनायें। राज्य

सरकारें इन योजनाओं को मान्यता दें तथा स्थानीय निकायों को इन योजनाओं के कार्यान्वयन की पूर्ण स्वतंत्रता भी दे। इस प्रकार की व्यवस्था में जनता के प्रति जवाबदेही

खाद्य सुरक्षा एव पचायती राज

Ī

अतर्निहित है। केरल का अनुभव इस रणनीति के सकारात्मक परिणामों का साक्षी है। इस दोहरी रणनीति को अपनाने से पचायते खाद्य सुरक्षा के सबसे मजबूत तत्र के रूप में सामने आयेंगी।

संदर्भ

- 1 विश्व खाद्य सम्मेलन (1974) की रिपोर्ट, संयुक्त राप्ट्र सघ का प्रकाशन, 5-16 नवबर, रोम, इटली
- 2 विश्व बैक, गरीबी और भूख विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा के विकल्प एव मुद्दं, 1968, वाशिगटन डी सी. सयुक्त राज्य अमेरिका
- 3 *विश्व खाद्य सम्मेन (कार्य योजना)*, 1996, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, 18-17 नवबर, रोम, इटली
- 4 फूड सिक्यूरिटी एड पंचायती राज (1997), (सपादित) प्रदीप चतुर्वेदरे, कसेप्ट, नयी दिल्ली, पृ 267-269
- 5 डी बद्योपाध्याय, पश्चिम वगाल में भूमि सुधार, इकॉनामिक एड पॉलिटिकल वीकली,
- 6 फाइनेशियल एक्सप्रेस, 25 अप्रेल 2001
- 7 सौरभ गर्ग, जन वितरण प्रणाली की वस्तुओं के विक्रोता के रूप मे प्रचायते, कंपास, मानसून अक, 2000-2001
- 8 पचायती गज सस्थाओं की अधिकार तथा प्रकार्य सीपने पर कार्य दल की रिपोर्ट, भारत सरकार, कृषि भवन, नयी दिल्ली, अगस्त 2001
- 9. उपर्युक्त, पृ 81-82
- 10 पी चिदवरम, प्राचुर्य की समस्या, इडिया टुडे, 24 सितबर 2001
- टी.एम थामस आइजक एव रिचर्ड डब्ल्यू फ्रांक लोकल डेमोक्रेसी एड डेवलपमेट पीपुल्स केंप्रन फॉर डीसेट्रलाइण्ड प्लानिग इन केराला, लेफ्टवर्ड बुक्स, निर्दा दिल्ली, 2000, पृ. 205
- 12 उपर्युक्त पृ 206

जनसंख्या स्थिरता के लिए जन सत्ता

सत्ता यदि केवल दिल्ली या अन्य राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित रही तो राष्ट्रीय समस्याओं का हल नहीं ढूँढा जा सकता । यह तर्क आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है। इतना ही नहीं, यह भी लोगों के सामने स्पष्ट होता जा रहा है कि ये समस्याएँ नौकरशाही अथवा सरकारी विभागों द्वारा भी नहीं सुलझायी जा सकती। देश के सामने मुंह वाये खड़ी प्रमुख समस्याओं का एकमात्र जवाब तत्ता का विकेट्रीकरण एवं विकेट्रित नियोजन ही है।

आजाटी के बाद से विकेद्रीकरण की प्रक्रिया में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को संविधानिक दर्जा देनेवाले दिसंबर 1992 के दो संविधान संशोधन (73वॉ एवं 74वॉ) मील का पत्थर साबित हुए है। 'भारत में शासन और प्रशासन को लोगा की देहरी तक ले जाने के लिए गाँवों में भारत की 76 प्रतिशत आबादी के लिए पंचायते तथा 26 प्रतिशत शहरी आबादी के लिए स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण उपकरण बन गये है।'

जनसंख्या स्थिरता अपने आपमे कोई अलग मुद्दा नहीं है। यह गरीबी मिटाने, पर्यावरण की गुणवत्ता, महिलाओं की बेहतर स्थिति, शिक्षा तथा रहन-सहन की उन्नत परिस्थितियों पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में कहें तो गरीबी उन्मूलन, सुचारु खाद्य आपूर्ति, कुपोषण का नाश, उत्तम आवास सुविधा, महिलाओं की स्थिति में सुधार, साक्षरता और सभी के लिए प्रारिभक शिक्षा जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ है।

गाँव या शहर में लोगों के जीवन की उपर्युक्त सभी जरूरतों की पूरा करने के लिए ग्यारहवी अनुसूची में 29 विषयों तथा बारहवीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित, पद्मायतों के प्रकार्यों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जनसंख्या स्थिरता सबधी दायित्व पंचायतों पर है। ग्यारहवीं अनुसूची में जो 29 विषय सुझाये गये हैं, उनमे 24वॉ विषय हैं परिवार कल्याण!

इस सूची के साकेतिक होने के बावजूद राज्यों ने इसमें उल्लिखिन विषयों को तीन स्तरीय पंचायतों के अनिवार्य दायित्यों के रूप में अपने अनुपालन-अधिनियमों में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया है।

जनसंख्या नियोजन का विकेंद्रीकृत मॉडल

सरकारी नीति के हिसाब से योजना आयोग की नौवीं पचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र का परिवार नियोजन एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया पर काफी प्रभाव पड़ा है। इस दस्तावेज में परिवार कल्याण के बारे में भी एक खंड है। इसके अनुसार, परिवार कल्याण सेवाओं का दायरा तथा उनकी गुणवत्ता बढाने के लिए प्रयास तेज करने के साथ ही इस कार्यक्रम में 'पचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जायेगा. ताकि अतरक्षेत्रीय समन्वय बन सके और नियोजन, निगरानी एवं प्रबधन में सामुदायिक भागीदारी भी हो पाये।'2 इस कार्यक्रम को दो अन्य वर्गो की भागीदारी के साथ जोड़ा गया है। ये वर्ग हैं स्वैच्छिक तथा संयुक्त क्षेत्र मे कार्यरत चिकित्सक तथा सगठित और असंगठित क्षेत्रों के उद्योग तथा श्रीमक प्रतिनिधि। मेरे विचार से योजना आयोग पचायतो की भूमिका को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाया। यदि तीन स्तरीय पचायतो को सवैधानिक रूप से निर्वाचित जन प्रतिनिधियो द्वारा सचालित 'स्वशासन की संस्थाओं' के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना है, तो पंचायतों और नगर परिपदों के साथ सामान्य सस्थाओं जैसा व्यवहार करने के बजाय उन्हें शीर्षस्थ महत्व देना होगा। किसी जिले या ब्लॉक अथवा गाँव के जन समृह में जनसंख्या नियत्रण में सहायता करने के लिए चिकित्सकों को कौन प्रोत्साहित करेगा? उद्योगो, श्रमिक सगठनों आदि को परिवार कल्याण कार्यक्रम मे शामिल होने के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएँ कौन देगा? यह कार्य केवल स्थानीय स्वशासी संस्थाओ द्वारा ही किया जा सकता है, क्यांकि वे जनता के काफी नजदीक है और उसके विचारा, संस्कृति और समस्याओं को समझती है.

परिवार नियोजन सवेदनशील मुद्दा है और इसे किसी निवेशक, कलक्टर अथवा बीडीओ द्वारा थोपा या लागू नहीं किया जा सकता। अफसोस यह है कि हमारे नीति निर्धारक आज तक इस सच को गहराई से समझ नहीं पाये हैं। यही कारण है कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कई दशकों से चलते आने के वावजूद आबादी के मीर्चे पर कई बातें अभी तक ज्यों की त्यों चली आ रही हैं (अ) दुनिया में हर साल बढ़नेवाली मनुष्यों की कुल आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सा भारत का ही है; (ब) दुनिया में सबसे प्रतिकूल लिग अनुपातवाले वेशों में भारत भी शामिल है, (स) असमान विकास टिकाऊ नहीं हो सकता; (द) आजादी के समय वेश की कुल आबादी जितनी थी, उतने ही लोग आज भारत में गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

डॉ एम एम. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रारूप बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट मे इन तथ्यों का ध्यान दिया हे। साथ ही, जनसख्या को स्थिग करने के लिए उमने विकेदित संस्थाओं के महत्व

पर विशेष वल दिया है। इस विशेषज्ञ समूह ने मई 1994 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपी थी।

विशेपज्ञ समूह की रिपोर्ट में 'ऊपर से नीचे की ओर जारी वर्तमान परिवार

कल्याण कार्यक्रम' के बजाय 'पंचायतों, नगरपालिकाओ एवं राज्यों की विधान सभाओ के जरिय विकेंद्रित लोकतांत्रिक नियोजन' पर जोर दिया गया है। रे रिपोर्ट मे लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के जरिये गंटित पंचायती राज तथा नगरपालिका सस्थाओं को यह

दायित्व सौपने की सिफारिश की गयी है, क्योंकि 'विकेदित कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए ये सस्थाएँ नये अवसरों का अरोखा प्रदान कर रही है।"

विशेपज्ञ समूह के अनुसार वुनियादी स्तर के लोकतात्रिक ढाँचे (यानी पचायतो ओर नगरपालिकाओं) को 'गर्भनिरोधक उपायो को अपनाने में वर्तमान लिगगत

असत्लन को दूर करने के नये अवसर' प्रदान करने के साथ ही साथ अपने गाँव, कस्वे या शहर के लिए सामाजिक-जनसाख्यिक घोषणापत्र बनाना चाहिए। गाँव/कस्बा स्तर के घोषणापत्र में उस क्षेत्र के लोगों के बीच विचार-विमर्श के बाद तैयार किये

गये. जनसंख्या स्थिरता के स्पष्ट लक्ष्य शामिल होने चाहिए। घोषणापत्र मे मानव आबादी तथा भूमि एव जल संसाधनों के बीच सतुलन बनाने की तरफ विशेष रूप

महिलाओं-पुरुषों की निरक्षरता आदि सामाजिक बुराइयो को दूर करने के लिए स्थानीय लांगो द्वारा किये जानेवाले उपायो का योजनाबद्ध विवरण भी घोपणापत्र मे दिया जायंगा। यह जीवन स्तर वेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण भी करेगा।

स ध्यान दिया जायेगा। इसके साथ ही, दहेज, बाल विवाह, मादाभ्रूण एवं शिशु हत्या,

ऐसे घोषणापत्र मे कार्रवाई का स्पष्ट खाका रहेगा, जिसमें वित्तीय एव तकनीकी सहायता की आवश्यकताओं का विवरण शामिल होगा है स्वामीनाथन रिपोर्ट में स्थिर एवं उचित जनसंख्या के लिए बनाये गये कार्यक्रमो

क संवर्धन के लिए पंचायतो एव नगरपालिकाओ से स्थानीय संसाधन, विशेषकर सामान के रूप में, जुटाने का भी सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जनसंख्या एवं मामाजिक विकास समितियों तथा राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग के गठन का सुझाव दिया गया था। केंद्रीय सरकार द्वारा विशेषज्ञ समूह की

रिपोर्ट की अस्वीकृति एव इन सिफारिशों को किसी न किसी रूप में लागू करने पर विचार न किया जाना एक दयनीय स्थिति है। इस सिलसिले मे यह उल्लेखनीय है कि केरल द्वारा शुरू किया गया नौवीं योजना के लिए अभियान, जो अब 'पीपल्स

प्लान' के रूप में सफलतापूर्वक चल रहा है, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तावित सबद्ध

स्थिरता के लिए जन सत्ता

गाँव, कस्बे या शहर के लिए सामाजिक जनसाख्यिकी घोषणापत्र तैयार किये जाने के कार्यक्रम के काफी नजदीक है।⁶

यहाँ मैं उन दी महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करूँगा, जिनके द्वारा जनसंख्या को स्थिर करने में काफी सफलना प्राप्त की जा सकती है, वशर्ते पंचायतों और नगरपालिकाओं को सवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सुदृढ़ बना दिया जाये। ये उपाय हैं (क) स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी तथा (ख) शिक्षा।

स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी

पद्मायतो और नगरपालिकाओं के तीनों स्तरो पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटे आरक्षित किये जाने से इन संस्थाओं के जनसंख्या को स्थिर करने के लिए प्रभावी उपकरण बनने में काफी सहायता मिलेगी। मोटे तौर पर पंचायती राज एव नगरपालिकाओ में तीनों स्तरों पर अनुमानतः 30 लाख निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने चाहिए। इनमे 10 लाख महिलाएँ होंगी, जो अपने आपमें बहुत बडी ताकत बन सकती है। यदि वे अपेक्षित गमीरता के साथ जनसंख्या से संबद्ध मुद्दों की उठायें तो वे महिलाओ के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के साथ ही पूरे परिवार एव समाज का जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक उपायो की महत्वपूर्ण शुरुआत कर सकती हैं। लेकिन लगातार उठता प्रश्न यह है कि कई राज्यो में, जहाँ पुरुष वर्ग का वर्चस्व अभी भी कांयम है, क्या महिलाएँ अपेक्षित ढायित्वों के न्यायपूर्ण निर्वहन मे सफल हो पायेगी, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण के वावजूद पचायती राज संस्थाओं में पुरुष सदस्यों की दो-तिहाई संख्या यानी पुरुष-वहमत तो रहेगा ही। क्या परिवार में मौजद पुरुष वर्चस्व पचायतों तक फैल जायेगा? इसके साथ ही, हमारे देश में बालिकाओं की उपेक्षा, महिलाओं की घटती संख्या, बालिका शिशु की ऊंची मृत्यु दर, महिला मजदूरी की अधिक संख्या, महिलाओं की अल्प साक्षरता टर, बालिकाओ द्वारा विद्यालय बीच में छोड़ देने की ऊँची दर, छोटी आयु में विवाह, किशोरावस्था में मॉ बनने के जोखिम का ऊँचा अनुपात, उच्च प्रसूति एवं शिशु मृत्यु दर एव महिलाओ के प्रति बढ़ती हिंसा जैसे अनेक सामाजिक कारक महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रहे है। इन सामाजिक कारको के बने रहते हुए परिस्थितियाँ कैसे सुधरेंगी? यदि पंचायत ऐसे ही समाज का आईना है, तो सुधार की क्या उम्मीद की जाये?

इस बारे में मेरा कहना यह है कि यह तर्क सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रति अज्ञान की अभिव्यक्ति है, जबिक, इसके विपरीत, सच यह है कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई पहल की जाये, तो परिवर्तन अवश्य होता है। स्वामीनाथन समिति • की रिपोर्ट में निर्वाचित महिला सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को यह कहते हुए रेखांकित किया गया है कि उन्हें 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं में स्त्री-पुरुष सैमानता समाहित करने की नयी शुरुआत तथा बालिकाओं की घटती सख्या पर रोक लगाने म हमारी सहायता करनी चाहिए पचायता म महिलाओ का विगत पाच छह वर्षा की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया है कि लैगिक असतुलन में सुधार तथा महिलाओ

के हितों को प्रोत्साहित करने का वे सबसे प्रभावशाली एव सर्वदनशील माध्यम है। पचायतों के माध्यम से समाज की जड़ता को तोड़ने में महिलाओं की सफल भूमिका

के नये-नये किस्से आये दिन सामने आ रहे हैं। अब यह माना जा चुका है कि देश भर में पंचायतों में 10 लाख महिलाएँ

राजनीतिक एवं सामाजिक संशक्तीकरण की लहर ला सकती हैं, बशर्ते निर्णय करने की प्रक्रिया में महिलाओं को सक्षम किये जानेवाले उपायों को प्रोत्साहित किया जाये।

दो वच्चों का पंचायत विरोधी नियम

राजस्थान, हरियाणा और आध्र प्रदेश ने अपने पंचायती राज कानूनों में अधिकतम दो संतानवाले परिवार के नियम का उल्लंघन करनेवाले लोगो पर पंचायतों, जिला

पिषदो एव नगरपालिकाओ के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। कुछ लोगों ने यह कहते हुए इन उपायों की प्रशसा की है कि इनसे इन तीनों गज्यों की राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर हो रही है। नि सदंह जन प्रतिनिधियों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसका जनता अनुकरण करे। संसद से ले कर पचायतों तक जन प्रतिनिधियों

चाहिए जिसका जनता अनुकरण कर। ससद स ल कर पचायता तक जन प्रातानाध्या को स्वय ही छोटे परिवार के नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राज्यों एवं केंद्र का राजनीतिक नेतृत्व क्या स्वयं भी इस सिद्धात

प्रश्न यह है कि राज्यों एवं कड़ का राजनीतिक नेतृत्व क्या स्वयं भी इसे सिद्धात का वास्तव में पालन करेगा? इन राज्यों में हुआ यह है कि जिन लोगों की दो से अधिक सतानें हैं, स्थानीय शासन तत्र में उनके हिस्सा लेने पर रोक लगा कर राजनीतिक

नेतृत्व ने एक बड़े वर्ग पर अपनी इच्छा थाप दी है। यहाँ उठनेवाला एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि जब विधान सभाओं अथवा संसद जैसी उच्चस्तरीय संस्थाओं के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, तो फिर इस पंचायती राज पर क्यों आरोपित किया जाये?

तीन राज्यों (राजस्थान, हरियाणा तथा आध्र प्रदेश) के पचायत प्रतिनिधियों के लिए दो संतान के नियमवाले इस कानून के अन्य परिणाम भी चिताजनक ही है। उदाहरण के लिए हरियाणा राज्य को लिया जाये। यहा स्त्री-पुरुष अनुपात (874

है। उदाहरण के लिए हरियाणा राज्य को लिया जाये। यहा स्त्री-पुरुष अनुपात (874 1000) देश भर में न्यूनतम है। राजस्थान भी इस मामले में कोई पीछे नहीं है। इस राज्य में स्त्री-पुरुप अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 913 महिलाओं का है।

अलबत्ता आंध्र प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 973 महिलाएँ होने के चलते लैगिक अनुपात कुछ बेहतर है। इन तीनो राज्यों मे पंचायती राज्य के विभिन्न स्तरों की संस्थाओं के लिए लगभग 5,00,000 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इनमें 1,50,000 से ज्यादा महिलाएँ होगी। यदि इन सीटो के लिए चुनाव में मुकाबला हो,

तो कम से कम 10,00,000 उम्मीदवारों को मैदान में होना चाहिए।

जनसंख्या स्थिरता के लिए जन सत्ता

ऐसे में इन राज्यों में अपने गाँव, व्लॉक अथवा जिला परिपट स्तर पर नेतृत्व की समृचित योग्यतावाले इतने सारे लोग कैसे उपलब्ध होगे, क्योंकि अभी तक चलन बड़े परिवारों का ही है? क्या दो बच्चों का नियम बहुत-से दंपतियों को स्थानीय चुनाव में उम्मीदंवार बनने से नही रोकेगा? सदियों पुराने सामाजिक एवं आर्थिक शोषण के शिकार लोगों को लोकतात्रिक संस्थाओं से इस तरह वंचित रखने की यह प्रक्रिया अलोकतात्रिक है। उन गरीब गाँववालों (महिलाओं के मामले में यह वात और भी गंभीर है) पर अचानक यह नियम थोप कर विधि निर्माताओं ने शहरी अभिजन के साथ मिल कर सामाजिक यथार्थ की अनदेखी की है। आध्र प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 23.91 प्रतिशत है, हरियाणा की 26.27 प्रतिशत और राजस्थान की 28.07 प्रतिशत। आध्र प्रदेश और हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 71 है और राजस्थान में 84 है। राजस्थान में इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का वुनियादी अनुभव यह है कि पचायत सदस्यों के लिए अधिकतम दो सतान के नियम का खिमयाजा महिलाओं को ही भुगतना पड रहा है। तीसरी सतान पैदा होने पर पंचायतों के बहुत-से पुरुष सदस्य अपनी सदस्यता बचाने के लिए अपने पितृत्व को नकार कर पत्नी का 'कागजी' रूप से तलाक दे देते है।

शिक्षा ही कुंजी है

आबादी को स्थिर करने की कुजी है, शिक्षा । तिहत्तरवें संविधान सशोधन की ग्यारहवी अनुसूची मे पचायतो को विभिन्न प्रकार की शिक्षा की जिम्मेदारी सौपी गयी है

- 1. प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा,
- 2. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, तथा
- प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा एवं पुस्तकालय।¹⁰

दुनिया भर मे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकन का सर्वश्रेष्ठ उपाय महिलाओ की शिक्षा को माना गया है। साक्षरता दर के बारे में कहा जा सकता है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सिर्फ 49.9 प्रतिशत है, राजस्थान की ग्रामीण आबादी में 69.6 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं एवं आध्र प्रदेश में यह दर 64.3 प्रतिशत है। इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में (सात वर्ष एवं उससे अधिक उम्र की) महिलाओं की साक्षरता दर 1991 की जनगणना के अनुसार इस प्रकार है : राजस्थान 11 59 प्रतिशत, आध्र प्रदेश 23.92 प्रतिशत तथा हरियाणा 32.51 प्रतिशत।

इस लिहाज से पंचायतों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा को पंचायतों के अंतर्गत लाने के लिए कोई असरदार उपाय नहीं किया गया है, जिसके कारण संपूर्ण साक्षरता की राह दिन पर दिन लबी होती जा रही है। इसका एक और दुष्परिणाम यह हो रहा है कि शिक्षा पर निर्भर अन्य मुद्दे भी पिछड़ रहे हैं, जिससे परिवार कल्याण को भारी नुकसान हो रहा है। कई अध्ययनो

86 : भारत में पंचायती राज

से यह स्पष्ट हुआ है कि जहाँ-जहाँ प्राथमिक और उच्च स्कूली शिक्षा पचायतो के अतर्गत कर दी गयी है, वहाँ-वहाँ शिक्षण की गुणवत्ता तथा शिक्षको एवं छात्रों दोनो की ही कक्षा-उपस्थिति काफी हद तक सुधरी है।¹¹

आइए, इन टो महत्वपूर्ण कारणो, महिलाओं की भागीदारी एवं शिक्षा, के लिहाज स्वार महत्वों केरल पश्चिम लगत और उन्हार प्रवेश की शिक्षी कर समान है।

से तीन राज्यों केरल, पश्चिम बगाल और उत्तर प्रदेश की स्थिति का जायजा ले। केरल को इसलिए चुना गया है कि वह इन दोनों क्षेत्रों में उपलब्धियों के हिसाब

से शीर्ष राज्य है। पश्चिम बगाल मध्यम तथा उत्तर प्रदेश न्यूनतम स्तर पर है। करेल : भारत एवं केरल के उपलब्ध ऑकड़ों से यह एकदम स्पष्ट है कि

जन्म दर पर प्रभाव डालनेवाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं साक्षरता, शिशु मृत्यु दर एव जीवन प्रत्याशा का स्तर।

रैटक्लिफ तथा अन्य विद्वानों के अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि गरीब परिवारों में अधिक सतानों से होनेवाले लाभ से जुड़ी उनकी आवश्यकता घट रही

है। बच्चों के पालन-पोषण पर बढते खर्च के साथ-साथ वेहतर स्वास्थ्य उपायो के द्वारा जीवित रहने की अधिक उम्मीद तथा वृद्धावस्था में सुरक्षा की आशा ने गरीब

परिवारों को अधिक बच्चे रखने की जरूरत और प्रोत्साहन को कम कर दिया है।¹² जॉन रैटक्लिफ ने इस मुद्दे को इन शब्दों में रखा है : '(केरल में) सीधे और शब्द

रूप से समता के सामान्य सरोकारों पर आधारित विकासकारी रणनीतियों के क्रियान्वयन के द्वारा विकास के लक्ष्य हासिल किये गये है। इनसे उभरी अधिक न्यायपूर्ण एव

समतापरक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कारण केरल भारत के अन्य राज्यों से वहतर दिखाई दे रहा है। उसी के कारण इसका जनसाख्यिक चरित्र भी अलग से दिख रहा

है। केरल के अनुभव से यह सैद्धातिक अवधारणा सही सिद्ध हो रही है कि जनन क्षमता के उपयोग में कमी उन सार्वजनिक नीतियो से आती है, जिनसे पूरे समाज

में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता निर्णायक रूप से बढते हैं।¹³ इसमें कोई सदेह नहीं है कि केरल ये उपलब्धियों जन आंदोलनों और सामुदायिक भागीदारी के बलबूते ही हासिल कर पाया है। केरल का यह विशिष्ट इतिहास ह

कि वहाँ सुधारवादी एवं राजनैतिक आंदोलनों के शुरू होने से पहले सामुदायिक सगठनो ने, वे चाहे जाति आधारित हों या धर्म आधारित, सामाजिक जागरूकता के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अटा की है। ऐसे आदोलनो के कारण ही बीसवीं शताब्दी के

में महत्वपूर्ण भूमिका अटा की है। ऐसे आदोलनों के कारण ही बीसवीं शताब्दी के 40, 50 और 60 के दशक में सामाजिक जागरूकता शीर्प पर थी। इसी का परिणाम है कि 'केरल में स्वास्थ्य की देखभाल जन अधिकार है। आम लोगों ने उसके लिए

सघर्ष किया है। वे इसकी अपेक्षा करते हैं। वे इसकी माँग करते हैं। वे इसे बरकरार रखने, सुधारने एव बढ़ाने के लिये सघर्षरत है। वे केरल के गाँवों में पंचायतें 73व सिवधान संशोधन से पहले से ही सामाजिक जीवन में काफी सिक्रय भूमिका निभा रही थी। कोचीन और ट्रावनकोर में 1925 से पंचायतें सिक्रय है। जॉन मेंकर के

जनसंख्या स्थिरता के लिए जन सत्ता

हवाले से पी.आर. गोपीनाथन नायर ने भी स्वास्थ्य एवं साक्षरता का काफी ऊँचा स्तर तथा निम्न जन्म दर हासिल करने में स्थानीय समर्थन की वडी भूमिका पर जोर दिया है। 15 राज्य की जनता के सोच में 73वें सशोधन के बाद रेडिकल परिवर्तन आया है।

केरल संग्कार के स्वास्थ्य मंत्री ने 1997 में दिल्ली के एक भाषण में कहा था, 'जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमां में स्वयंसवी संस्थाओं तथा गैरसरकारी संगठनों की सेवाओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया गया है। स्वास्थ्य शिक्षण की गतिविधियों तथा अभियानों एवं संवा शिविरों, मेलों आदि स्वास्थ्य संवंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा आयोजन में महिला समाजो, युवा क्लबों, खेल क्लवों एवं अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों का सिक्रय रूप से शामिल किया गया है। वित्तीय दिक्कतों के बावजूद जन स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता बरकरार है। हाल में सरकार ने नियोजन के विकेदीकरण के लिए अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रवंधन को भी विकेदीकृत करने की योजना है। इससे आशा है कि स्वास्थ्य सेवाऍ लोगां की आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनेंगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में वचाव के वजाय उपचार के प्रति बढ़ रहे रुझान को संतुलित करने में भी सहायता मिलेगी।

परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने में शिक्षा की प्रमुख भूमिका का उल्लेख करते हुए तथा जनसंख्या स्थिरता के लिए अपने प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, 'हम इस दिशा में अपने प्रयास और भी तेजी से जारी रखने के लिये प्रतिबद्ध है। केरल ने परिवार कल्याण को जनता के कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया है। अपने ससाधनों में से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए भारी राशियाँ उपलब्ध करा कर सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता रही है।'¹⁷

केरल के 73वे सविधान संशोधन के बाद की स्थिति के अध्ययन के बाद सामाजिक स्वास्थ्य के पैरोकार डॉ. एन एच. अतिया ने ये विचार प्रकट किये थे, 'पंचायती राज इस अत्यंत किफायती एव मानवीय दृष्टिकोण के रूपायन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है, जिससे असली फायदा डॉक्टरो तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नहीं, विल्क जनता को मिलता है। यह स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण है।'¹⁸

पश्चिम बंगाल: आम जनता एव उसके प्रतिनिधियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पश्चिम बगाल में विभागीय कामकाज के लोकतंत्रीकरण के प्रयासों का प्रयोग चल रहा है। इस भागीदारी को औपचारिक रूप देने के लिए विभिन्न सलाहकार समितियाँ बनायी गयी है। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा, दवाओं की खरीद एवं वितरण आदि के लिए तकनीकी सलाहकार समितियाँ बनायी गयी हैं। प्रत्येक जिले में विभागीय गतिविधियों की निगरानी के लिए सभाधिपति की अध्यक्षता मे

88

अधिकार सपन्न जिला म्वास्थ्य समिति बनायी गयी है। स्वास्थ्य सबधी प्रत्येक नयी परियोजना को जिला स्वास्थ्य समिति ही स्वीकृति दे, इस व्यवस्था पर विचार किया

जा रहा है। जिला परिपदो एव पचायत समितियों में स्वास्थ्य संवधी स्थायी समितियाँ बनायी गयी है तथा ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य संवा एव स्वास्थ्य अभियान की जिम्मेदारी

पचायत के ही एक सदस्य को सौंपने की व्यवस्था की गयी है।¹⁹ राज्य में 22 वर्ष के पचायती राज के वाद अब साक्षरता एवं परिवार कल्याण

तेज ने 22 पन पर पनाचार राज पर जाप जाप सावारता एवं पारवार करवान दोनों ही मोर्चो पर सफलता मिलती दिख रही है। पश्चिम वंगाल में इन मुद्दों के सबध में स्थानीय निकायों के कार्यकलाप की दिलचस्प झलक डच विद्वान जी के. लीटन

द्वारा 1995 में किये गये अध्ययन में मिलती है। इस अध्ययन के अनुसार, 'जमीनी स्तर पर शोध के नतीजे जता रहे हैं कि गॉवों में अधिकतर गरीव लोग यह महस्रस

कर रहे हैं कि गॉव के मामलों में उनके अधिकार बढ़े है तथा विशेषकर ग्राम सभाओ

के कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उनकी जानकारी बढी है।²⁰ पश्चिम बंगाल में पचायतों ने महिलाओं को समाज में बेहतर स्थान दिलाया है। लीटन के अध्ययन से यह भी स्पप्ट है कि देश के ग्रामीण इलाकों में पचायतें दूसरी क्रांति ला सकती है। ग्रामीण महिलाओं की परिस्थितियों में सर्वागीण सुधार के लिए पंचायतों के नये विधायी प्रावधान ठोस शुरुआत का माध्यम बन सकते है। ममारी जैसी पंचायतों

विधायी प्रावधान ठोस शुरुआत का माध्यम बन सकते है। मिमारी जैसी पंचायतो की वर्तमान महिला सदस्यों ने दिखा दिया है कि मौका मिलने पर महिलाएँ भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकती है। शर्मीली और सीधी-सादी दिखनेवाली एक महिला सदस्य ने बताया कि 'पंचायतो और दूसरे मचों पर मैं जरूर दखल देती हूँ। यदि मैं नहीं बोलूंगी, तो कौन वोलेगा?' 22

मेमारी ही) में भी उल्लेखनीय अभियान चल रहे हैं। शिक्षा मे पचायतों की भूमिका पर नये सिरे से दिये जा रहे जोर के वारे में लीटन का कहना है, 'स्थायी आर्थिक विकास के लिए चूँकि बेहतर स्वास्थ्य स्तर एव शैक्षिक उपलब्धियाँ अत्यत आवश्यक है, इसलिए गाँवो मे शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों को पचायतों ने अपने हाथ में ले लिया है। पश्चिम वंगाल सबको शिक्षित करने के लिए कमर कसता दिखाई

साक्षरता एवं परिवार नियाजन के लिए दूरदराज के गाँवों (उदाहरण के लिए,

में ले लिया है। पेश्चम वंगाल सबका शिक्षत करन के लिए कमर कसती विखाइ दे रहा है, जिससे विकास की सभावनाएँ बढेगी। 123 शिक्षा के माध्यम से परिवार नियोजन का संदेश धीरे-धीरे पश्चिम बगाल के गाँवों में पहुँच रहा है। उत्तर प्रदेश: केरल और पश्चिम वंगाल में जो कुछ घटित हो रहा है, उसके

ठीक विपरीत 139 करोड़ की आबादीवाले उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण अथवा विकास संबंधी मुद्दों को अभी तक स्थानीय निकायों द्वारा कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाना चिताजनक है। उत्तर प्रदेश के तीन जिलों—मुजफ्फरनगर, जौनपुर और रायबरेली—में

जी के लीटन और रिव श्रीवास्तव द्वारा 1990 से 1997 के बीच किये गये अध्ययन का निष्कर्प यह है कि इस इलाके में पचायनों को बहुत अधिक सामाजिक महत्त. नहीं मिला है। लीटन और श्रीवास्तव ने तीन क्षेत्रों में अत्यत निर्धन, मध्यवर्गीय परिवारों की प्राथमिकताओं का अध्ययन किया था। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि सबसे निर्धन लोग परिवार नियोजन को विकास एवं बढ़ाने का माध्यम मानने को तैयार नहीं हैं। उनके परिवार बड़े हैं, फिलए परिवार कल्याण की कोई अहमियत नहीं है। अध्ययनकर्ता अततः पर पहुँचे है कि सबसे गरीब तबके के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और परिवार नियोजन जैसे विकासमूलक कार्यक्रम उनकी प्राथमिकता 'गरीब और सबसे गरीब ग्रामीणों को परिवार नियोजन के परिणामों में

भी खास तौर पर सपित के बँटवारे यानी भूमि सुधारों में ही अधिक लाभ कि इन क्षेत्रों में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ज्यादातर लोग एवं सही प्रशासन के पक्ष में थे। उदाहरण के लिए, मुजफ्फरनगर एक है और वहाँ 240 लोगों के सर्वेक्षण (वर्ष 1994 के मध्य में) से ये उल्ले हासिल हुए:

फायदा नही दिखाई देता। अत्यंत गरीब परिवारो तथा एक हद तक गरीब

मुजफ्फरनगर में विकास की प्राथमिकताएँ

हस्तक्षेप की किस्म	अत्यंत गरीब	गरीब	मध्यवर्गीय
परिवार नियोजन	-3.16	-2.00	-0.06
विकास के लिए अधिक वित्त	-2 84	-2.78	-2.20
भूमि सुधार	0.32	-0.63	-3.42
स्वच्छ एव निष्पक्ष प्रशासन	3 37	2.76	3.32
रोजगार का सृजन	2 32	2.52	2.38
बारंबारता (एन)	19	92	69

स्रोत ⁻ जी के लीटन एव रिव श्रीवास्तव, अनइक्वल पार्टनर्स : पावर रिलेशस, f डेवलपमेट इन उत्तर प्रदेश, सेज पिललकेशम, 1999, प 249

ये निष्कर्प दो अन्य जिलो, जौनपुर एवं रायबरेली, से कमोबेश हैं।

इस प्रकार, छोटे परिवार के आदर्श का महत्व उन लोगों की सग नहीं आता, जिनके लिए यह सबसे अधिक फायदेमद है—गॉवों के निर्धन

90 : भारत में पचायती राज

निर्धन। विकास की प्राथमिकताओं के पैमाने में लीटन एवं श्रीवास्तव द्वारा सर्वेक्षित तीनो जिलों के ग्रामीण समाज के विभिन्न तबको द्वारा परिवार नियोजन को दी गयी प्राथमिकता उनकी आवश्यकता के विपरीत अनुपात में है—ऊँचे तबकों के लोगों की

तुलना में गरीब और अत्यत गरीव अपने जीवन पर इसके प्रभाव का बहुत कम फायदा समझते हैं। गरीबो द्वारा छोटे परिवार के आदर्श का समर्थन न करने के ठोस कारण हो सकते हैं लेकिन इस बात से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि उनके इस रवैये में सुधारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए पंयायते सर्वथा उपयक्त

हे, क्योंकि वे प्राथमिक स्तर पर लोकतात्रिक पद्धति से चुन कर बननेवाली संस्थाएँ हे और गॉववालो से उनका निरंतर और सीधा संपर्क रहता है।

निर्धन तथा अत्यत निर्धन व्यक्तियों द्वारा जनसंख्या स्थिरता को कम महत्व दिये जाने का कारण आम तौर पर आर्थिक मजबूरी माना जाता है। वे बच्चों में आर्थिक संसाधन की गुंजाइश देखते है और उन्हें लगता है कि वे परिवार की जरूरतो

को पूरा करने में हाथ बॅटा सकते है। ग्रामीण भारत के ज्यादातर गरीबो की आम तौर पर यही मान्यता है, मगर महिलाएँ विशेष रूप से इस प्रवृत्ति में अपने लिए

तौर पर यही मान्यता है, मगर महिलाएँ विशेष रूप से इस प्रवृत्ति मे अपने लिए सहारा ढूंढती हैं। महिलाओं के पास चूँिक कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए

वे ज्यादा बच्चों के होने पर उनके द्वारा अपने काम में हाथ बॅटाने की आशा करती है, तािक वे स्वय बाहर निकल कर किसी कामकाज के जरिये थोडा पैसा कमा सके। इसी से यह भी स्पप्ट होता है कि अत्यत गरीब और गरीब लोग भूमि सुधारों के

जिरये सपित के बॅटवारे को पिरवार नियोजन से ज्यादा अहम क्यो मानते हैं। उन्लेखनीय है कि तिहत्तरवे संविधान सशोधन में पचायतों को भूमि सुधार का कार्यान्वयन करने की भूमिका भी सौपी गयी है। यह भूमिका निभाने के साथ-साथ यह आवश्यक है

कि पंचायते शैक्षिक एव परिवार कल्याण तथा बच्चों के जन्म मे अतर रखने जैसे

अन्य कार्यक्रमों में भी पूरी तरह भागीदार रहे। उत्तर प्रदेश में पचायते कमजोर है एवं वहाँ अब तक किसी भी सरकार ने

तिहत्तरवें संविधान सशोधन को मुकम्मल तौर पर लागू करने में कोई दिलयस्पी नहीं दिखायी है, इसी के नतीजे उपर्युक्त अध्ययन में परिलक्षित हो रहे हैं।

उपसंहार

अब मै जमीनी स्तर पर काम करने के दौरान हासिल अनुभवो से उपलब्ध कुछ अतर्दृष्टियों को रेखािकत करना चाहूँगा।

अतदृष्टियां का रखाकित करना चाहूगा। एक, स्थानीय सरकारी संस्थाएँ, पंचायते तथा नगरपालिकाएँ जनसंख्या स्थिरता

कार्यक्रमो को चलाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं। दो, किसी भी जनसंख्या स्थिरता नीति की सफलता के लिये जनता की भागीदारी

एव शिक्षा मुख्य तत्त्व हैं। यह महिलाओं के मामले में विशेष रूप से सच है, क्योंकि

जनसंख्या स्थिरता के लिए जन सत्ता - 91

परिवार कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में उन्हें पूरी तरह अपने साथ जोड़ कर तथा उनकी प्रभावशाली हिस्सेटारी मुनिश्चित करके ही सफलता पायी जा सकती है।

तीन, स्थानीय निकायों को जनसंख्या नियंत्रण के आधुनिकतम उपायों एवं उपकरणों की जानकारी लगातार हासिल करते रहना चाहिए। इसके साथ ही, परिवार कल्याण, पोषण, घरेलू आर्थिक प्रबंधन, श्रम बचाने की प्रौद्योगिकी तथा रोजगारपरक परियोजनाओं की भी जानकारी हासिल कर उसे सामूहिक बैठको अथवा निजी सपक के जिरये अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुँचाते रहना चाहिए।

चार, पहने पचायतो को प्रजनन की आयुवाली महिलाओं को जनसंख्या नियत्रण परियोजनाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने अथवा उनके तौर-तरीके बदलने में वहुत कम सफलता मिलती थी। इसका एक कारण शायद यह था कि ग्रामीण महिलाओं के लिए पचायतो द्वारा किये जा रह इन प्रयासों का कोई विशेष महत्व नहीं था। अतः पंचायत सदस्यों को ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं जनसंख्या से संबंधित उच्च प्राथमिकतावाले क्षेत्रों की पहचान अवश्य करनी चाहिए। रणनीति यह होनी चाहिए कि उन्हे स्वास्थ्य के मुद्दों से जोड कर परिवार के आकार के मुद्दों की तरफ आकर्षित किया जाये।

पॉच, पितृसत्तात्मक ग्रामीण परिवारों में आम तौर पर औरतों की बात पंचायतों द्वारा नहीं सुनी जाती। इस बारे में पुरुषों को अपना व्यवहार बदलने के लिए शिक्षित करना और मनाना आवश्यक है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र में छोटे परिवारों के फायदों का प्रचार करके किया जा सकता है। इस मामले में निर्वाचित पंचायते महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

छह, पुरातनपंथी रिवाजों, मान्यताओं एव रवैयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है। नये विचारों का प्रसार करने के लिए सूचना की नवीनतम तकनीकों का उपयोग, वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि का सहारा लिया जाना चाहिए।

सात, परिवर्तन के खिलाफ पारंपरिक प्रतिरोध को तोड़ने के लिए पंचायती को जनसंचार कार्यक्रमों तथा प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा गाँवों में जनजागरण अभियान चलाने चाहिए।

अतत, अकसर कहा जाता है कि बिना राजनैतिक इच्छाशक्ति के राष्ट्रीय महत्व का कोई भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। मुझ ऐसा लगता है कि जनसंख्या स्थिरता कार्यक्रमों के मामले में सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ 'पचायती इच्छाशक्ति' अथवा स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता एव दृढ संकल्प भी उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही आवश्यक है। क्या नयी सहस्राद्धि में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जैसी सर्वाधिक फौरी समस्या कं लिए 'पचायती डच्छाशक्ति' बन पायंगी? जनसंख्या नियत्रण में पंचायती की भूमिका पर केंद्रीय गंभीर अभियान आज की सबम बड़ी आवश्यकता है।

संदर्भ

- आंध्र प्रदेश में 1985 में पचायती राज प्रणाली की दूसरी पीढी की शुरुआत करने हुए यह विचार तलुगु देशम पार्टी ने प्रचारित किया था।
- श्रेनी पचनर्पीय योजना, 1997-2000, खड 2, धीमेटिक इश्वूज एड सैक्टोरल प्रोग्राम्स, योजना आयोग, भारत सरकार, पृ 207
- उनसङ्या नीति पर विशेषज्ञ समृह, भारत सरकार के स्वास्थ्य एव पिरवार कल्याण मञ्जालय को प्रवत्त राष्ट्रीय जनसङ्या नीति का प्रारूप 21 मई, 1994, पृ 10
- 4 उपर्युक्त, पृ 3
- 5 उपर्युक्त, पृ 7-8
- तिरुवनतपुरम में राज्य योजना बोर्ड ने इस विषय पर कई रिपार्टी एव शोध निष्कर्षों का प्रकाशन किया है।
- 🤋 उपर्युक्त, पृ 4
- 8 जॉर्ज मैथ्यू, ट स्वामीनाथन ग्रुप रिपोर्ट, द हिंदू, चेन्नई और नयी दिल्ली, 26 अगस्त 1994
- 9 गजस्थान के अलबर जिले में 1997-1998 के टोरान इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइमेज के रमेश सी नायक द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित। साथ श्री देखें रमेश मी नायक, मेन वर्क अगस्ट द वीमेन सरपंच, द पायनियर, नयी दिल्ली, 12 मई 1998
- 10 िक्षशा के प्रवधन के विकेदीकरण के सदर्भ में राज्यों के पचायती गज कानूनों के विस्तृत विश्लेषण के लिए टेखें, रीन्द्रक्विरिंग ऑफ एलीमेटरी, प्राइमरी एड नॉनफॉरमल गुजुकंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू पचायती राज कमीशन रिपोर्ट्स, पाडुलिपि रिपोर्ट न 8, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साडमेज, नयी दिल्ली. 1996, पृ 2
- 11 उदाहरण के लिए देखें, कर्नाटक सरकार, रिपोर्ट ऑफ ट जिला पचायत एड मडल पचायत इवैल्युएशन कमेटी (कृष्णमूर्ति कमेटी), 1989
- 12 िचर्ड डब्ल्यू फ्रांक तथा वारवग एच चेसिन, की कैरल डेबलपमेट धू रेडीकल रिफॉर्म्स, प्रामिला एड कपनी, नयी दिल्ली एव द इस्टीट्यूट फॉर फूड एड डेवलपमेट पॉलिसी, मैन फ्रांसिस्का, 1991 से उद्धृत
- 13 उपर्युक्त, पृ. 68
- 14 उपर्युक्त, पृ 69
- 15 पी आर गोपीनाथन नायर, डायनॉिंग्यिस ऑफ डेमोग्राफिक ट्राजिशन इन केरल ए क्रिटिकल एनेलिसिस। यह पग्चा 'फेक्टर्स ऑडरलाइग ट सक्सेमफुल परफॉरमैंन ऑफ ट सेलेक्टेड स्टेट्ट्स एड द डिस्ट्रिक्ट्स शंयरिंग ऑफ एक्सपीरियेसेज विद अटर स्टेट्स एड डिस्ट्रिक्ट्स' शोर्पक सं ज आर डी टाटा पुग्स्कार अर्पण समारोह के अवसर पर नयी दिल्ली में 13 नवबर 1997 को आयोजित सगोप्टी में पढा गया था।
- 16 भारतीय जनसंख्या प्रतिष्ठान द्वारा नयी दिल्ली में 13 नवंबर 1997 को आयोजित संगोष्ठी में एसी घन्मुखदास का भाषण, पृष्ठ 5-6
- 17 उपर्युक्त, 5
- 18 एन एच अतिया, द सोशल पाथ टु करेल्स हेन्य, फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्य,

मुंबई, मिमिओ

2

ত তেত

de

THE THE THE CHE TO S.

存 形 3 写 章 6

- 19 गौरीपद दत्त, *पृ प्ली फॉर प्रो-पीपल हेल्थकेयर,* राज्य योजना बोर्ड, कोलकाता, पृ 17
- 20 जी के लीटन, *डेवलपमेट, डिवॉल्यूशन एड डेमोक्रेसी विलेज डिस्कोर्स इन वेस्ट बगाल*. सेज पब्लिकेशम, नयी दिल्ली, 1996, पृ 223
- 21 जी के. लीटन, पूर्व उद्धत, पृ 218
- 22 जी के लीटन, पूर्व उद्धृत, पृ 217
- 23 जी के लीटन, पूर्व उद्धृत, पृ 219
- 24. जी के लीटन और रिव श्रीचास्तव, अनंडक्वल पार्टनर्स पावर रिलेशस. डिवॉल्यूशन एड डेवलपमेट इन उत्तर प्रदेश, सेज पब्लिकेशस, नयी दिल्ली, 1999, पु 248

परिवार कल्याण के उचित उपकरण

यह स्तब्ध कर देनेवाली बात है कि मौजूदा सरकार और उसके नीति निर्माता भारत की जनसंख्या की असाधारण वृद्धि से पैदा होनेवाली स्थिति की गंभीरता से तनिक भी चितित नहीं है। दुनिया की कुल भूमि के मात्र 2.4 प्रतिशत का स्वामी होते हुए

भी भारत दुनिया की आबादी के 16.7 प्रतिशत लोगों का घर हो गया है (1991 से 2001 की दस वर्षों की अविधि में भारत की आबादी में 18.1 करोड़ की वृद्धि

हुई है, जो कनाडा, फ्रांस और जर्मनी तीनो की सम्मिलित आबादी के वराबर है), तब भी हमारे शासको ने देश की इस सबसे बड़ी समस्या का सामना करने के लिए

कोई सचेत प्रयास किया हो, ऐसा दिखाई नही पड़ता।

जो दिखाई पड़ता है, वह यह है कि जनसंख्या विस्फोट से जो भयावह संकट कभी भी पैदा हो संकता है, उसे रोकने के लिए क्या किया जा संकता है, इसका कोई सूत्र सरकार और उसके नीति निर्माताओं के पास नहीं है। विडबना यह है कि

इस विपय पर देश में विचारों का अभाव है, इसिलए नहीं, बल्कि इसिलए यह किकर्तव्यविमूढता बनी हुई है कि सरकार और उसके कर्ता-धर्ता इन विचारों पर अमल नहीं करना चाहते और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए देश में उपलब्ध समाधनों

का इस्तेमाल नही करना चाहते। इतनी ही कष्टपूर्ण बात यह है कि पग्विार कल्याण ओर जनसंख्या स्थिरता के नाम पर जो कदम उठाये जाते है, वे या तो आधे-अधूरे

मन से उठाये जाते है या उनके पीछे जमीनी वास्तविकता की कोई समझ नहीं होती। दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादीवाले देशों ने जनसंख्या वृद्धि पर अकुश लगाने के लिए दो अलग-अलग और परस्पर-विरोधी रास्ते अपनाये थे। चीन ने

सर्वसत्तावादी रास्ता अपना कर एक बच्चे का नियम लागू किया और वाछित लक्ष्य हासिल कर दिया। भारत ने दो बच्चों का नियम बनाया और इसे लोकतांत्रिक तरीको से लागू करने का प्रयास किया—जो ज्यादा कठिन और जटिलतर रास्ता है, और अभी

तक लक्ष्य-प्राप्ति मे विफल रहा है।

कांन नहीं जानता कि परिवार कल्याण जैसे उपाय किसी लोकतात्रिक व्यवस्था में ऊपर से जारी आदेशों के माध्यम से कारगर नहीं हो सकते। यह मामला दरअसल दृष्टिकोण, व्यक्तिगत निष्ठा, संस्कृति और व्यवहार का होता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज की वुनिवादी इकाई यांनी परिवार के स्तर पर एक मूल्य व्यवस्था का जन्म होता है। यह मूल्य व्यवस्था किसी भी सरकारी आदेश से ज्यादा प्रभावशाली होती है।

चूँकि परिवार स्थानीय समुदाय का एक आवयविक अंग है, परिवार नियोजन जैसे व्यक्तिगत और अंतरग विषय पर गाँव या कस्बे के लागों से बेहतर ढग से इसे कान प्रभावित कर सकता है? यह काम सलीक से सपन्न करने की स्थिति में और कान है—सिवाय पंचायतो और नगरपालिकाओं के, जो लोकतात्रिक ढग से निर्वाचित और लोगों के सर्वाधिक करीब होती है?

इस दिशा में विचार और ढॉचागत सभावनाओं के स्तर पर पहला और बेहद असरदार हस्तक्षेप था तिहत्तरवॉ और चौहत्तरवॉ संवैधानिक सशोधन. जिनके माध्यम से पचायनों को 'स्वशासन की सस्थाएँ' बनाया गया और उन्हें परिवार कल्याण, महिला तथा बाल कल्याण, स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा औषधालय जैसे विषय सौपे गये। चूँिक जनसंख्या स्थिरता के लिए वहु-क्षेत्रीय कार्य योजना अपरिहार्य है, शिक्षा, विशेषन स्त्री शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे विषय, जो एक-दूसरे को प्रभावित करने है, पचायतों के अधीन कर दिये गये।

इन संविधान संशोधनों के वाद से ही, जनसख्या स्थिरता की दिशा में स्थानीय शासन के निकायों की निर्णायक भूमिका को भारत सरकार के प्रायः सभी नीति-दस्तावेजों में बार-बार चिहित किया गया है। लेकिन क्या राजनेताओं या उनकी मातहती में काम करनेवाले अफसरों ने दस साल बाद भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संवैधानिक मंशोधन की अर्थपूर्णता का कभी अहसास किया है? उत्तर है, नहीं।

इस सदर्भ में यह याद करना दिलचस्प होगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से ही सरकारी चितन और दस्तावेजीकरण इस बात पर केंद्रित होने लगा था कि परिवार कल्याण के लक्ष्य को विकेंद्रित योजना निर्माण और कार्यान्वयन से ही हासिल किया जा सकता है। आठवीं योजना के दस्तावेज में कहा गया था कि चूँकि सामाजार्थिक तथा जनसाख्यिक दृष्टि से हर क्षेत्र अपने आपमें विशिष्ट है और देश भर मे काफी विविधता है, परिवार नियोजन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए पचायते ही आदर्श

इकाइवॉ है। अतः जनसंख्या स्थिरता के कार्यक्रमों का विश्लेषण, योजना निर्माण और प्रशासन पंचायत स्तर से ही शुरू होना चाहिए। 1994 में, एम.एस. स्वामीनाथन विशेषज्ञ सिमिति ने जोर दे कर कहा था कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों का जो मौजूदा स्तूपनुमा ढाँचा है, उसे हटा कर उसके स्थान पर पंचायतो और नगरपालिकाओं के जिरये विकेदित

96 भारत में पचायती राज

कौन नहीं जानता कि परिवार कल्याण जैसे उपाय किसी लोकतात्रिक व्यवस्था में ऊपर से जारी आंदेशों के माध्यम से कारगर नहीं हो सकते। यह मामला टरअसल दृष्टिकाण, व्यक्तिगत निष्ठा, संस्कृति और व्यवहार का होता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज की बुनियादी इकाई यानी परिवार के स्तर पर एक मूल्य व्यवस्था का जन्म होता है। यह मूल्य व्यवस्था किसी भी सरकारी आंदेश से ज्यादा प्रभावशाली होती है।

चूँिक परिवार स्थानीय समुदाय का एक आवयविक अंग है, परिवार नियोजन जैसे व्यक्तिगत और अतरंग विषय पर गाँव या कस्वे के लोगों से बेहतर दग से इसे कौन प्रभावित कर सकता है? यह काम सलीके से सपन्न करने की स्थिति में और कौन है—सिवाय पचायतां और नगरपालिकाओं के, जो लोकतात्रिक ढग से निर्वाचित और लोगों के सर्वाधिक करीब होती हैं?

इस दिशा में विचार और ढॉचागत सभावनाओं के स्तर पर पहला और वेहद असरदार हस्तक्षेप था तिहत्तरवाँ और चौहत्तरवाँ संवैधानिक संशोधन, जिनके माध्यम से पचायतों को 'स्वशासन की संस्थाएँ' बनाया गया और उन्हें परिवार कल्याण, महिला तथा बाल कल्याण, स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल, प्राथिनिक स्वास्थ्य केंद्र तथा औपधालय जैसे विषय सौंपे गये। चूँकि जनसंख्या स्थिरता के लिए बहु-क्षेत्रीय कार्य योजना अपिरहार्य है, शिक्षा, विशंषतः स्त्री शिक्षा, प्राथिमिक स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे विषय, जो एक-दूसरे को प्रभावित करते है, पचायतों के अधीन कर दिये गये।

इन मंविधान सशोधनों के बाद से ही, जनसंख्या स्थिरता की दिशा में स्थानीय शासन के निकायों की निर्णायक भूमिका को भारत सरकार के प्रायः सभी नीति-दस्तावेजों में बार-बार चिहित किया गया है। लेकिन क्या राजनेताओं या उनकी मातहती में काम करनेवाले अफसरों ने दस साल बाद भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संवैधानिक सशोधन की अर्थपूर्णता का कभी अहसास किया है? उत्तर है, नहीं।

इस सदर्भ में यह याद करना दिलचस्प होगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना

से ही सरकारी चितन और दस्तावेजीकरण इस बात पर केंद्रित होने लगा था कि पिरवार कल्याण के लक्ष्य को विकेंद्रित योजना निर्माण और कार्यान्वयन से ही हासिल किया जा सकता है। आठवीं योजना के दस्तावेज में कहा गया था कि चूँकि सामाजार्थिक तथा जनसांख्यिक दृष्टि से हर क्षेत्र अपने आपमे विशिष्ट है और देश भर में काफी विविधता है, परिवार नियोजन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए पचायतें ही आदर्श इकाइयाँ है। अतः जनसंख्या स्थिरता के कार्यक्रमों का विश्लेषण, योजना निर्माण ओर प्रशासन पंचायत स्तर से ही शुरू होना चाहिए। 1994 मे, एम एस. स्वामीनाथन विशेषज्ञ

समिति ने जोर दे कर कहा था कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों का जो मौजूदा स्तूपनुमा ढॉचा है, उसे हटा कर उसके स्थान पर पचायतो और नगरपालिकाओं के जरिये विकेद्रित

96 भारत में पचायती राज

इन स्थानीय निकायों से विकेदित कार्रवार्ड के लिए अवसरों का एक नया समवाय उपलब्ध हो गया है। इस विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि जनसख्या स्थिरता के कार्यक्रम वनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जिला स्तर पर जनसख्या तथा सामाजिक विकास समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। इस सिफारिश पर कोई कार्यवार्ड नहीं हुई।

लाकतात्रिक योजना निमाण का चारस ढाचा स्थापित किया जाना चाहिए, क्यांकि

उसके छह साल बाद, 2000 में, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (राजनी, 2000) ने स्वास्थ्य योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायतों और नगरपालिकाओं की केद्रीय रणनीतिक भूमिका को चिह्नित किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के दस्तावेज में कहा गया : 'चॅ्कि निर्वाचित पंचायतों की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जनसंख्या स्थिरता के लिए स्त्री-पुरुष की हैसियत के प्रति संवेदनशील और बहुक्षेत्रीय एजंडा के संवर्धन के लिए पचायतों की प्रतिनिधिक समितियाँ (जिनकी सवारत कोई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि करे) बनायी जानी चाहिए जो 'स्थानीय स्तर पर सोचेगी. योजना बनायेगी और काम करंगी और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग देगी।' ये समितियाँ गर्भाधान और प्रजनन से सबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने क्षेत्र की विशेष स्थितियों में उपेक्षित जरूरतों की पहचान करेंगी और गाँव के स्तर पर जरूरत-आधारित, मॉग-प्रेरित सामाजिक-जनसाख्यिक योजनाओं का निर्माण करगी, जिनका उद्देश्य होगा गर्भाधान, प्रजनन तथा शिशुओ की वुनियादी स्वास्थ्य-सृश्रुपा के लिए सवेदनशील, जन-केंद्रित, आवयविक रूप में समन्वित तथा एकाग्र कार्य करना। जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था के अनिवार्य पंजीकरण, छोटे परिवार के मानक को व्यापक स्वीकृति दिलाने, सुरक्षित जचगी बढ़ाने, शिशु तथा मात् मृत्यु दर की दरों में कमी लान और चौटह साल की उम्र तक अनिवार्य शिक्षा का सवर्धन करने मे जो पंचायतें आदर्श तथा अनुकरणीय उदाहरण पेश करेंगी, उन्हें राप्ट्रीय स्तर प

राजनी 2000 ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किये थे। तात्कालिक लक्ष्य था स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढाँचे का निर्माण, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सख्य बढाना, मॉ-शिशु के लिए बुनियादी एकान्वित सुविधाएँ मुहैया कराना और गर्भनिरोधव की जहरत पूरी करना। मध्यवर्ती काल का लक्ष्य था अतर-क्षेत्रीय कार्यक्रमों अ रणनीतियों के सशक्त कार्यान्वयन के माध्यम से 2010 तक समग्र उर्वरता दर व प्रतिस्थापन दर तक ले आना। दीर्घकालीन लक्ष्य था : 2045 तक जनसंख्या की स्थिर सुनिश्चित करना। नवीनतम नीति दस्तावेज पर आये, तो दसवी योजना के दस्तावे में भी जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्थानीय स्तर ' योजना निर्माण, परिवेक्षण तथा कार्यक्रमों को बीच अविध में ही सुधारने की प्रक्रि में पंचायतों को शामिल करने के महत्व पर ओर दिया गया है।

मान्यता दी जा सकती है और सम्मानित किया जा सकता है।

नीति दस्तावंजो को स्वीकार करने के बाद सरकार को उन पर अमल करने के लिए दृढ और कठोर कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि आज 2003 में भी ये सभी योजनाएँ कागज पर ही है।

वर्तमान स्थिति का निचोड़ दो सरोकारों में व्यक्त होता है। एक, स्थानीय सरकार की संस्थाओं को मजबूत करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायत कर्मियों के क्षमता निर्माण और बुनियादी ढाँचे के विकास में विनियोग करना। दो, विशेषतः जनसंख्या स्थिरता से सबधित क्षेत्रों में शिक्षा और चेतना के प्रसार, जागरूकता बढ़ाने की प्रक्रिया और कार्यक्रमों में विनियोग करना।

इन सरोकारों को कैसे चिंग्तार्थ किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि स्थानीय सरकार की संस्थाओं के पास करने के लिए कार्य, कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारी और कोष तथा कार्यपद्धति में स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों की यह शिकायत दूर की जानी चाहिए कि केंद्रीय सरकार से ले कर राज्य सरकारों तक, जिनके पास भी कुछ ताकत है, वे सभी पचायतों और नगरपालिकाओं को कमजोर करने में एक-दूसरे से प्रतिद्वद्विता कर रहे है। यह काम कभी बहुत बारीकी से और अकतर बहुत ही स्थूल ढग से हो रहा है।

दूसरे, मौजूदा स्थिति के सकेतों को समझते हुए, भविष्य की रणनीति इस तरह वनायी जानी चाहिए कि भविष्य में देश के प्रत्येक गाँव को 'लघु गणराज्य' बनाने के लिए जनता को जाग्रत और लामबंद किया जाये और उसकी अंतश्चेतना को उभारा जाये।

यह उचित समय है जब शासन प्रणाली में जनसाधारण की भूमिका के बारे में जागरूकता तथा प्रतिबद्धता पैदा करने के लिए एक आक्रामक अभियान चलाया जाये। स्त्रियों और वंचित वर्गों को उनका प्राप्य मिल सके, इस दिशा में विशेष प्रयास की जरूरत है। इस अभियान का एक केंद्र-बिद्ध होना चाहिए पंचायतों के माध्यम स विकेदित शासन, ताकि ग्रामीण विकास के केंद्रीय मुद्दों पर कारगर काम किया जाये और यहाँ स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए—साथ ही वरबादी और चोगी खत्म करने, संसाधनों को बनाये रखने और संपत्ति निर्माण करने के माध्यम से लोगों की गरीबी दूर करने और आय बढाने की भी कोशिश होनी चाहिए। परिवार कल्याण के उपायों का प्रचार-प्रसार करने में ग्राम सभा की भूमिका एक और महत्वपूर्ण सरोकार है।

यह अभियान जन सामान्य यानी गाँवो मे रहनेवालों के बीच सीमित नहीं रहना चाहिए। इसमें नीति निर्माताओ, विधायकों, सांसदो, राजनीतिक दलो के नेताओ, नोकरशाहों तथा जनमत निर्माताओं, जन सचार माध्यमों—खासकर प्रेस ओर टेनीविजन—और बुद्धिजीवियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रो, महिला संगठनों तथा अन्य गैरसरकारी संगठनों को इस अभियान का वाहक बनाया जा सकता है।

सरकार नीतियों और कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है, पर योजना निर्माण और कार्यान्वयन में दूसरे घटकों को आगे आना चाहिए। फिलहाल देश में 595 जिले हैं। मौजूदा वातावरण में सर्वोत्तम तरीका यह है कि औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कंपनियों और सार्वजनिक ट्रस्टों, फाउंडेशनों, साख-संपन्न और सक्षम गैरसरकारी सगठनों तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सस्थाओं को एक-एक जिला गोद लेने के लिए तैयार किया जाये। उचित कर सुविधाएँ दी जाये, तो व्यावसायिक घराने अपने प्रोफेशनल लोगों, कार्यक्रम अधिकारियों और विशेषज्ञों को पंचायतों को मजबूत करने और नवाचारपूर्ण कार्यक्रमों के जिरये उपर्युक्त सरोकारों को यथार्थ में बदलने में लगा सकते है। वित्त मंत्री ने अपने वजट भाषण में कहा है कि भारत सरकार द्विपक्षीय साझीदारों को कुछ रियायते दे सकती है ताकि उनके ससाधन गैरसरकारी सगठनों को हस्तांतरित किये जा सकें। यह हस्तातरण पंचायतों को क्यों नहीं किया जा सकता?

ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षण

पचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा भारतीय लोकतत्र की बुनियादी इकाई है। यह गाँव मे रहनेवाले सभी मतदाताओं की सभा है। हालाँकि आबादी के आधार पर गाँव को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, फिर भी इस पर कोई मत-विभिन्नना नहीं है कि लोकतत्र को सिर्फ ग्राम सभा द्वारा ही सीधे लागू किया जा सकता है। हमारे लोकतंत्र को जीवंत और जन भागीदारी पर आधारित प्रणाली बनाने में इसका विशेष महत्व है।

इस सदर्भ मे वर्ष 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष घोषित करने का वित्त मंत्री का बयान काफी अहम हो जाता है। इससे इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी का ध्यान खीचने में सहायता तो मिली है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्राम सभा वर्ष को सार्थक बनाने के लिए अभी तक कोई उपयोगी पहल नही की गयी है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुरूप उड़ीसा के अतावा अभी तक किसी भी राज्य ने इस विषय पर राज्य स्तरीय बैठक तक बुलाने के लिए कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है।

यदि इस वर्ष को पंचायत वर्ष घोषित किया जाता तो वह शायद ज्यादा सार्थक साबित होता, क्योंकि पंचायत यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत— कार्यकारी संस्थाएँ तो यही है। अभी तक लोगों की सभा यानी ग्राम सभा को गाँव में कोई कार्यकारी अधिकार हासिल नहीं हैं और वह सिर्फ जनता की आकांक्षाओ, विचार, आलोचना आदि की अभिव्यक्ति का मंच बनी हुई है।

विभिन्न राज्यों के कानूनों के अतर्गत ग्राम सभाओं को हासिल अधिकारों एवं प्रदत्त कार्यकलाप के एक अध्ययन के अनुसार ग्राम सभा के कार्य क्षेत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार है - 1. खानों के सलाना विवरण एवं ऑडिट रिपोर्ट की जॉच, 2 पिछले वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट पर चर्चा, 3. चालू साल के लिए निर्धारित कार्यक्रमों की समीक्षा तथा नये कार्यक्रमों पर चर्चा; 4. नये करों के प्रस्तावों अथवा

वर्तमान करों मे वृद्धि पर विचार, 5. विभिन्न विकास कार्यों के लिए योजनाओ, लाभार्थियो एव स्थान का चयन; 6. सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमो के लिए लोगो

को स्वेच्छया श्रम, सामान तथा नकदी देने के लिए अभिप्रेरित करना, 7. विकास योजनाओं को लागू करने तथा गाँवों के लिए सेवाएँ प्रदान करने मे सहायता देना,

श गाँव के भीतर प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण आदि कार्यक्रम चलाना: 9. समाज

के सभी वर्गों में परस्पर एकता एव भाईचारे को बढावा देना: 10. किसी विशेष

गतिविधि, योजना, आमदनी तथा खर्च के बारे मे ग्राम पचायत के मुखिया या सदस्यो से स्पष्टीकरण मॉगना: 11. पिछली ऑडिट रिपोर्ट एव उस पर दिये गये जवाब पर विचार, 12. ग्राम पंचायत द्वारा तैयार बजट एवं ग्राम सभा क्षेत्र के भविष्य के विकास

की योजनाओं एव कार्यक्रमो पर विचार: 13. वर्तमान योजनाओं एवं पंचायतों की सभी तरह की गतिविधियों पर विचार एवं उनकी पड़ताल, 14. ग्राम पंचायत अथवा

किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा किये गये विकास कार्यो का सपूर्ण विवरण रखना:

15 पुरे हो चुके कार्यो की पड़ताल; 16. पंचायत की गतिविधियों, आमदनी, खर्ची. योजनाओं एवं अन्य मामलो के बारे में ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा पंचों से पूछताछ।

इस प्रकार कुल मिला कर ग्राम सभा की बैठक चर्चा एव आलोचना करने की सस्था है। लेकिन वर्तमान परिस्थित में 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष घोषित करने का प्रयास महज धोखे की टट्टी साबित हो सकता है और इससे स्थानीय शासन

में ग्राम सभा की प्रमुख भूमिका को मजबूती से स्थापित करने में कोई खास मदद मिलने के आसार नहीं हैं। इस मामले में राज्य सरकारें भी आम तौर पर नाकाम

साबित होती रही हैं, यद्यपि कुछ क्षेत्रो में सामाजिक संस्थाएँ एवं जन संगठन ग्राम सभा को गंभीरता से ले रहे हैं।

केरल सरकार ने 4 जुलाई 1996 को विकेद्रीकरण के लिए डॉ सत्यब्रत सेन की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी। ग्राम सभाओं के बारे में उस समिति की सिफारिशे शायद इस विषय मे पहला ब्यौरेवार विश्लेषण हैं। समिति ने यह साफ-साफ कहा है कि (क) ग्राम सभाओं को ज्यादा से ज्यादा बैठक करनी चाहिए और तीन

महीने मे कम से कम एक बैठक तो करनी ही चाहिए; (ख) हरेक परिवार को लिखित निमंत्रण भेजा जाना चाहिए, ताकि दस प्रतिशत कोरम की शर्त पूरी हो सके; (ग) ग्राम सभाओं के अधिकार और कर्तव्य संबंधी सरकारी आदेश की प्रति, ग्राम पचायत

के अध्यक्ष के पत्र सहित, सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए।² सेन समिति ने ग्राम सभा के अधिकारों को भी विस्तार से परिभाषित किया

या। समिति की सिफारिशों के मुताबिक ग्राम सभा को यह सब जानने का अधिकार

(क) अगले तीन महीने के लिए योजनाओं को लागू करने की कार्य योजना, (ख) प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत पूर्व-आकलन; (ग) ग्राम सभा क्षेत्र में किये गये

हरएक खर्च का विस्तृत मदवार विवरण; (घ) उस क्षेत्र के बारे में पंचायत द्वारा किये

ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षण

101

गये हरएक फैसले का आधार; (ड) अगले तीन महीनो में अधिकारियो द्वारा दी जानेवाली सेवाओ एव उनके द्वारा किये जानेवाले कार्यो का विवरण; और (च) पचवर्षीय एव

वाषिक योजनाओं को नैयार करने के लिए वरीयताओं का निर्धारण। 3

ग्राम सभा को लाभार्थियों के चयन के लिए योग्यताएँ तथा नियम निर्धारित

करने होते हैं एव उन्हीं के मुताबिक चयन करना होता है। ग्राम सभा के अधिकारो और कर्तव्यों के अनुरूप ही उपसमितियों को काम हाथ मे लेने चाहिए या उन पर निगरानी रखनी चाहिए।

ग्राम सभा के कर्तव्यों की सेन समिति द्वारा बनायी गयी सूची ऑख खोल देनेवाली है। ये जिम्मेदारियाँ हैं : विकास एव कल्याण कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार: स्वास्थ्य. साक्षरता एवं ऐसे ही विकासात्मक अभियानों में हिस्सा लेने के

लिए लोगों को तैयार करना, आवश्यक सामाजिक-आर्थिक ऑकडों का संग्रहण; विकास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे मे सूचना देना; करों के भुगतान, ऋण वापस करने, पर्यावरण की स्वच्छता को बढावा देने, सामाजिक सद्भाव बनाये रखने आदि के लिए

लोगों को नैतिक रूप से तैयार करना आदि। ग्राम सभा के संयोजक को हरएक बैठक

में किये गये फैसलों का रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा उसे पंचायत के दफ्तर में सदर्भ के लिए एवं प्रतिलिपि लेने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। केरल में ग्राम सभा की बैठक बुलाने में विफलता के लिए केरल पंचायत राज

अधिनियम में सजा की कार्रवाई का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रावधानों का लगातार दो बार उल्लंघन करने पर संयोजक की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। पिछले दो वर्ष से ग्राम सभा एवं उससे निचले स्तर की इकाई अयाकुट्टगल (पडोसी समूह)-केरल की पचायती राज प्रणाली में सिक्रय भूमिका निभा रहे हैं। केरल में

जन योजना ग्राम सभा की इन्ही नियमित बैठको के कारण सफल हो रही है। केरल के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्राम सभा एव पचायतों का रिश्ता द्वद्वात्मक है। पंचायते तभी असरदार हो सकती हैं, जब ग्राम

सभाऍ नियमित रूप से बैठक करें और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इन वैठकों हैं हिस्सा ले। इसी तरह, पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत होने पर ही ग्राम सभाओं का असर बढेगा।

का असर बढेगा। वर्तमान सदर्भ मे ग्राम पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए गहराई से यह महसूस िया जा रहा है कि इसके लिए सविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट

अर्फ संशिल साइंसेज, नयी दिल्ली ने 1999 की जनवरी के शुरू में 'संविधान (73वॉ एवं 74वॉ सशोधन अधिनियम, 1992) में सशोधन' विषय पर बगलूर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। उस सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिशें ध्यान देने योग्य

हैं। सम्मेलन की राय यह थी कि संविधान में संशोधन कर ग्राम सभाओ को आवश्यक अधिकार देना राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया जाये। ग्राम पचायतों के कार्यकलाप

102 भारत में फ्वायती राज

की निगरानी के लिए ग्राम सभा की अपनी समितियाँ होनी चाहिए। ग्राम सभाओं को योजना, बजट, लाभार्थियों की सूची, विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त स्थान तथा प्चायतों के खातों को मजूरी देने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि मामाजिक अकेक्षण (ऑडिट) को भी ग्राम सभाओं का एक प्रमुख कार्य बनाया जाये। पंचायत से बाहर के कुछ सदस्यों को उसके खातों की जॉच करने तथा उनकी पुष्टि के लिए दस्तखत करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। 5

सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अकेक्षण और ग्राम सभा के बारे आजकल काफी चर्चा हो रही है। यह सामाजिक अंकेक्षण है क्या? अकेक्षण अंग्रेजी शब्द ऑडिट का अनुवाद है, जो लातिनी मूल का शब्द है और इसका भावार्य 'सुनना' है। पुराने जमाने में अपने साम्राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए सम्राट ऑडिटर रखा करते थे। ये ऑडिटर महल के कर्मचारियों तथा स्थानीय अधिकारियों की छवि, सरकारी कर आदि प्रशासनिक मामलों के बारे में जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर घूमा करते थे, लेकिन ऑडिट का आधुनिक स्वरूप किसी संगठन द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों आर कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन आम तौर पर खाता अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धान्तों के आधार पर मूल्य आधारित व्यवहार की परिधि में किया जाता है। इस प्रकार ऑडिट किसी गतिविधि के निष्पादन एवं तर्कसगत मानकों के बीच तुलना किया जाना है। भारत में सरकारी ऑडिट व्यय-उन्मुख रहा है।

सामाजिक अकेक्षण की अवधारणा ज्यादा विस्तृत है। उसमें पारंपिक अकेक्षण के मुकाबले ज्यादा गुंजाइश रहती है। चार्ल्स मेडोवर के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोकतत्र में फैसला करनेवाले लोगों को अपने अधिकारों के प्रयोग के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसके साथ ही उनके अधिकारों का उपयोग, जहाँ तक संभव हो, सभी सबद्ध पक्षों की सहमति एवं समझ के साथ होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण किसी सगठन के कार्य निप्पादन का स्वतत्र मूल्याकन है, क्योंकि उसका उद्देश्य सामाजिक जिम्मेंबारी निभाना है। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि यह किसी संगठन की सामाजिक जवाबदेही को ऑकने का उपकरण है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक अंकेक्षण को किसी भी सार्वजनिक संगठन के कार्यकलाप की उसके सामाजिक संदर्भ में गहराई से जॉच एवं विश्लेषण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

सामाजिक अंकेक्षण से हमारा तात्पर्य जनता के नजरिये से प्रशासनिक प्रणाली का मूल्याकन करना है, क्योंकि उसी के नाम पर तथा उसी के लिए प्रशासनिक प्रणाली विकसित की जाती है और वैधता हासिल करती है। प्रशासन के सामाजिक अकेक्षण का तात्पर्य आम जनता के लिए उसकी भूमिका की दृष्टि से प्रशासनिक प्रणाली तथा उसकी अदरूनी गत्यात्मकता को इस दृष्टि से समझना है कि बहुतसंख्यक आम जनता के लिए उसका कार्य क्या है—आम जनता वह है जो मरकार या उसकी मशीनरी अथवा सत्तारूढ वर्ग का कल-पुर्जा नहीं है। सामाजिक ऑडिट को प्रभावशाली वनाने के लिए किसी कार्यक्रम के लाभों के प्रति लाभार्थी समूहों को जागरूक करना तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में रह जानेवाली किमयों को जानना; जनता पर प्रौद्योगिकीय चयन के असर की पडताल; सागठिनक ढॉचे एवं जनता के लिए नीतियाँ बनाने की उसके हितों, वरीयताओं एवं आकाक्षाओं के अनुरूप पड़ताल; तथा तंत्र को लोगों के लिए खुला एवं जवाबदेह बनाना आदि आवश्यक है।

सूचना तक पहुँच

सामाजिक अंकेक्षण को लागू करने के लिए आज पंचायतें सबसे उपयुक्त मच है। प्रभावशाली सामाजिक अकेक्षण के लिए केरल मे विकेंद्रीकरण पर सिमित ने सुझाया था कि पंचायतों को विभिन्न स्तरों पर सिमितियों बनानी चाहिए। सामाजिक अकेक्षण सिमितियों सबसे पहले ब्लॉक पचायत एवं जिला पंचायत के स्तर पर बनायी जानी चाहिए। इन सिमितियों मे सम्मानित नागरिको एव पेशेवर लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वे जब उचित समझे विकास कार्यक्रमों की पडताल कर सके। दूसरे, ग्राम पचायत एवं नगपालिकाओं के स्तर पर महिलाओं की विशेष निगरानी सिमितियों बनायी जानी चाहिए। इस सिमिति मे प्रत्येक ग्राम सभा अथवा वार्ड सिमिति के दो नामांकित प्रतिनिधि होने चाहिए। उनमे से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति मे हो। ऐसी सिमितियों को भी सामाजिक अकेक्षण सिमितियों जैसे ही अधिकार दिये जायें। ये सिमितियों लागत, अनुमान, कार्य में प्रयुक्त सामग्री की यात्रा एव गुणवत्ता तथा चयन संबंधी नियमों के अनुपालन आदि की पडताल करेगी। न

सत्यब्रत सेन समिति ने सामाजिक अंकेक्षण को सुगम बनाने के लिए कई उपाय सुझाये हैं: (क) किसी भी नागरिक द्वारा जॉच के लिए सभी पूर्वानुमानो, लाभार्थियों की सूची, प्रत्येक योजना में दी गयी सहायता, मस्टर रोल, बिल, वाउचर, खातो आदि की फोटो-कॉपी उसकी वास्तविक लागत के भुगतान के बाद उपलब्ध करायी जाये, (ख) विभिन्न लाइसेसो, परिमटों, प्रमाणपत्रों आदि के लिए स्थानीय निकायों को दी जानेवाली अर्जियो पर एक क्यू नबर दिया जाना चाहिए और इस वरीयता क्रम का किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं होना चाहिए; (ग) कर ऑकने, छूट देने आदि से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक किये जाने चाहिए, ताकि कुछ लोगों के प्रति पक्षपात की शिकायते न आयें। यदि इन दिशा निर्देशों का ठीक से पालन किया जाये, तो सामाजिक अंकेक्षण काफी असरदार सामाजिक सस्था बन जायेगा।

हमारी नयी लोकतांत्रिक संस्थाओं में सामाजिक अकंक्षण के लिए ग्राम सभा शायद सबसे उपयुक्त इकाई है। सामाजिक अकंक्षण का आधार चूँिक जन हित के लिए समर्पित नागरिक और उनकी सामूहिकता ही है, इसलिए ग्राम सभा के सदस्य नथा प्रतिनिधि संस्थाओं के सभी स्तरो—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद—के सदस्य सामाजिक सरोकार तथा जनहित के मुद्दे उठा सकते है तथा उनका जवाब मॉग सकते हैं। विभिन्न सगठनों से, सेवानिवृत्त लोगों से, शिक्षकों एव बेटाग चरित्र के अन्य लोगों को मिला कर सामाजिक अंकेक्षण मच अथवा सामाजिक अकंक्षण समिति बनायी जा सकती है।

सामाजिक अकेक्षण मंच वार्षिक योजना के बजट प्रावधानों, परियोजनाओं के क्रियान्ययन आदि के बारे में पंचायतों की गतिविधियों की पडताल के लिए मासिक बैठक बुला सकता है। इस बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की ओर से प्रगति रिपोर्ट दी जा सकती है और हर महीने किये जानेवाले कार्यों की जानकारी भी दी जा सकती है। समस्याओं को चुन कर उनके हल का रास्ता ढूँढ़ा जा सकता है। इस विचार मंथन के आधार पर सबद्ध विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई पर जोर देते हुए मासिक कार्रवाई रिपोर्ट बनायी जा सकती है। ग्राम सभा चूँकि लोगों की ऑखें और कान है, इसलिए उसकी वेठकों में भी इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हमें, दरअसल, जनमत निर्माण के द्वारा यह आम भावना पैदा करनी है कि कोई ग्राम सभा को धाखा नहीं दे सकता।

विभिन्न राज्यों में ग्राम सभाओं के कार्यकलाप की जॉच की जाये, तो दो तरह की परिस्थितियाँ सामने आती है। पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ सामाजिक एव विकास से जुड़ी समस्याओं के प्रिन सामाजिक अकेक्षण एक स्वस्थ, लोकतात्रिक, मानवीय नजरिया अपना रहा है। ग्राम सभा द्वारा गाँव की भलाई तथा ससाधनों के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सामाजिक अंकेक्षण के उपयोग की कई सफलता कथाएँ है। दूसरी स्थिति उन ग्राम सभाओं की है जहाँ लोग परेशान करनेवाले सवाल पूछते है, जिससे हिसा भड़कती है।

उदाहरण के लिए, कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले के मुंडगोड तालुक की इंट्रर ग्राम पचायत की बैठक में जनता पचायत की गतिविधियों के बारे में सचिव में सवाल पूछ रही थी। सिचव से एक नाली के निर्माण के लिए खरीदे गये सीमेंट का ब्यारा पूछा गया और उसके बिल भी मॉगे गये। सचिव ने कहा कि सीमेंट खरीदा गया है, लेकिन एक सदस्य ने इसका खंडन कर दिया। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि इस मामले में पैसे का गबन हुआ है, इसलिए बहस छिड गयी। जॉच करने पर पता लगा कि सीमेंट के बस्ते तो खरीदे गये थे, मगर कुछ सदस्यों ने सचिव पर दवाव डात कर उस सीमेंट को बेच दिया था।

कं नाम पढ़ने को कहा गया। उसने लोगों को बताया कि सूची बीडीओ के दफ्तर में भेजी जा चुकी है। इस तरह वह सूची पेश करने से बच गया। इसके बावजूद लगातार मॉग उठने पर सचिव को लाभार्थियों के नाम सबको बताने पड़े। 'भाग्य ज्योति' योजना के अतर्गत ट्यूबलाइट पानेवाले लोगों के नाम पढ़े जाने के बाद अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य ने यह सवाल उठाया कि पच्चीस ट्यूवलाइटों में से तेईस अनुसूचित जाति के लोगों को क्यों दी गयी है और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सिर्फ दो ट्यूबलाइटें क्यों मिली हैं। इस पर काफी शोर-शराबा हुआ। स्पष्टत पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों की अच्छी-खासी सख्या होने के बावजूद उनकी उपेक्षा की गयी थी।

उमी ग्राम सभा में सचिव को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चुने गय लाभार्थियो

दूसरी परिस्थिति का उटाहरण मध्य प्रदेश की चौपाल बैटकें हैं, जिनमें हिसा की कई वारदातें हुई। नवंबर 1995 में रायगढ जिले मे सल्हौना गाँव की एक महिला पच को सरिया खड विकास अधिकारी के सामने ही निर्वस्त्र कर दिया गया, छतरपुर जिले मे कड़की गाँव की एक उपसरपच को सताया गया और नवबर 1995 मे रायसेन जिले के बरवतपुर गाँव मे एक दलित सदस्य को पीटा गया।

गाँवों में इस तरह के असभ्य और हिसक व्यवहार के उदाहरण अकसर उजागर होते रहते हैं। यदि सरपंच, पच, वीडीओ तथा ग्राम सचिव सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर सके, तो ग्राम सभाएँ कही ज्यादा प्रभावशाली एवं सशक्त बन पायेगी। अलवर के आसपास के गाँवों में कभी ग्राम सभा की बैठक ही नहीं हो पाती। पाया यह गया कि बैठकों में लोग छाँट कर बुलाये जाते हैं, ताकि प्रस्तावों को बिना किसी विरोध के पास कराया जा सके।

उपसंहार

देश में ग्राम सभा का कामकाज ठीक से चलाने के लिए हमें अभी लंबा सफर पूरा करना है। ग्राम सभा के अतर्गत आनेवाले क्षेत्र के सभी मतदाता हालाँकि उसके सदस्य होते हैं, फिर भी उसकी वैठकों में बहुत कम लोग जुटते है। कई अध्ययनों से यह वात सामने आयी है कि ग्राम सभा की ज्यादातर बैठकों में कोरम भी पूरा नहीं हो पाता। संवैधानिक परिभाषा के अनुसार ग्राम सभा में गाँवो का समूह भी शामिल हां सकता है। राज्यों के कानूनों में इसी परिभाषा को आधार बनाया गया है, जिसके कारण किसी असरदार भागीदारी के लिहाज से ज्यादातर ग्राम सभाएँ बहुत बड़ी और दुःसाध्य हो गयी हैं। ग्राम सभा की बैठकों के लिए काफी दूर से लंबा फासला तय करके आना पड़ता है, इसलिए महिलाओं एवं दिततों का उनमें भाग लेना और भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार पंचायतों में महिलाओं को मिले आरक्षण का फायदा

ज्यादातर मामलों में मिट्टी मे मिल जाता है।

सूचिया पर विचार करने तथा निर्माण कार्यो एवं ठंको से जुड़े मामलो पर बहस में ही निकल जाता है। ग्राम सभा के कार्यो एवं अधिकारों के बारे में सविधान में कीई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। यह मामला पूरी तरह राज्यों की विधान सभाओं पर छोड़ दिया गया है (अनुच्छेद 248ए) और राज्यों द्वारा वनाये गये कानूनों में इन्हें

इसका अधिकार क्षेत्र राजस्व, नियमन कार्यो, ग्रामीण पुलिस व्यवस्था आदि शासन के विभिन्न पहलुओ पर ध्यान ढेने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही

जहाँ ग्राम सभाओं की वेटकें होती है, वहाँ भी सारा समय लाभार्थियों की

वहुत ही मामूली भूमिका दी गयी है। पचायत प्रणाली में ग्राम सभा की भूमिका केंद्रीय महत्व की हो सकती है।

ग्राम सभा के सामाजिक चरित्र को बदलने के लिए काफी जार लगाना पड़ेगा। हमें जनता में निवेश करना होगा तथा उसकी शिक्षा तथा क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने होंगे। सामाजिक परिवर्तन की ताकतों को मजबूत बना कर समाज के बहिष्कृत तबकों को लोकतांत्रिक प्रणाली की मुख्य धारा में लाना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। 1999-2000 को 'ग्राम सभा वर्ष' घोषित कर सरकार को शायद इस दिशा में अर्थपूर्ण कदम उठाने चाहिए थे तथा उनकी सफलता के लिए मानव एवं अन्य ससाधनों को संचारित करने के लिए आंदोलन एवं अभियान चलाना चाहिए था। दुर्भाग्य से सरकार अभी भी इस मामले में वांछित गंभीरता के साथ कोई कदम नहीं उठा रही

संदर्भ

है।

- 1. एस पी जैन, ग्राम सभा जमीनी लोकतत्र का सिहद्वार, *जर्नन ऑफ हरल डेवलपमेट,* एनआईआग्डी हेटराबाद
- 2 विकेद्रीकरण पर भमिति, दूसरी अतरिम रिपोर्ट, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम, 1997, पृष्ट 17
- 2 विकद्राकरण पर सामा 3. उपर्युक्त, पृष्ठ 17-18
- 4. एस.वी शरण (सपादित) 'संविधान (७३वॉ व ७४वॉ सशोधन अधिनियम, १९९२) में संशाधन' पर राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशे, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज, नयी दिल्ली, १९९९ पुष्ठ 4
- 5 इस विषय पर विस्तृत बहस के लिए देखिए, महीपाल, पचायतों के लिए सामाजिक अकेक्षण एक पद्धतिशास्त्र, मेनस्ट्रीम, 31 अक्टूबर, 1998, नयी दिल्ली, पृष्ठ 29-30
- 6. महीपान में उल्लिखित, वही, **प**ष्ठ 29
- 7 सारा रस्किन्हा, ग्राम सभा : पचायती राज, उमा प्रचार, खंड 4, अर्क 1, जनवरी-मार्च 1997
- ८ उपर्युक्त
- उन्तुन्तः
 जॉर्ज मैथ्यू एव रमेश सी. नायक, पचायतें व्यवहार में क्या लाभ है इनस शोषित वर्गों का,
 इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नयी दिल्ली, ऑक्जेनल पेपर सीरीज नवर 19, 1996

विकेंद्रीकरण, सरकार और स्वयंसेवी क्षेत्र

इस परचे मे जिला, ब्लॉक या तालुक और ग्राम तीनों स्तरों के पंचायती राज संस्थानों के साथ-साथ नगरपालिकाओं और नगर निगमों को राज्य और सरकार के विकेद्रित सस्थानों के रूप में लिया गया है। स्वयंसेवी क्षेत्र में विकेद्रित संस्थान समाज की पहल होते है, और लोगों के अधिकारों व सामूहिक सम्पत्ति की रक्षा करते है। इनमें जन सगठन और स्वयंसेवी संगठन भी शामिल है जो स्थानीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत वढ़ाने के लिए प्रयास करते है। मोटे तौर पर कहा जाये, तो ये नागरिको द्वारा की गयी पहल और नागरिकों के संगठन होते हैं।

अधिकाश लोग स्थानीय स्तर पर ही (गाँवों, कस्बो और निगमो के वार्डो में) अपना दिन-प्रतिदिन का जीवन बिताते हैं। किसी भी रिहायशी इलाके में लगभग सभी के बीच आमने-सामने का संबंध होता है। जब राज्य इस स्तर पर पहुँचता है, तो वह गहन छानबीन के दायरे में आ जाता है। यहाँ नागरिकों के समूह राज्य से क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं, यहाँ तक कि सरकार से मुठभेड भी करते है तथा व्यक्तियों के साथ-साथ समुदाय का जीवन स्तर बनाये रखने या सुधारने के अपने प्रयास में स्थानीय सरकार के समर्थन की माँग करते हैं।

शुरू में ही यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि अपनी सख्या और कार्यगत पहुँच के कारण स्वयंसेवी एजेसियों की पचायती राज संस्थानों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। बहुत-से गाँवों और छोटे कस्बों में स्वयंसेवी एजेसियाँ हैं ही नहीं। मान्यता-प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रम भी राज्य के सभी जिलों को शायद ही कभी अपने दायर में ले पाते हों। उदाहरण के तौर पर, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए संयुक्त वन प्रबंध समितियाँ, जल उपयोगकर्ता समूहों आदि जैसे मजबूत स्थानीय समूहों की स्थापना हुई है, वहाँ उनका कार्यक्षेत्र कुछ ही पुरवों और गाँवा तक सीमित रहता है।

इसकी तुलना में, देश मे ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतें, ब्लॉक या तालुक

स्तर पर पाँच हजार पंचायत समितियाँ और पाँच सौ से अधिक जिला स्तर की जिला पचायतें मौज़द है। इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि स्थानीय स्वशासन संस्थानो के रूप में पंचायतें तो सर्वत्र है, लेकिन स्वयसवी एजेसियों की व्याप्ति सीमित है।

पंचायतें

वैसे तो भारत के संविधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सघ और राज्य. दो-स्तरीय शासन को ही मान्यता दी गयी है, लेकिन सविधान के अनुच्छेद 40 में 'स्वशासन की इकाइयो' का भी उल्लेख किया गया है, जो जिला स्तर और उससे नीचे की

पचायतो का सुचक है। स्वतत्रता प्राप्ति के बाद के 50 सालों मे प्रशासन, शासन और विकास की समस्याओं के साथ-साथ सत्ता में भागीदारी की जन आकाक्षाओं. जन संगठनों के बढ़ते दायरे और उनकी प्रासिंगकता से सत्ता के विकेदीकरण की

ज़रूरत महसूस हुई है। जिला व उससे निचले स्तरों पर इस विकेंद्रीकरण की विशेष जरूरत समझी गयी है। आज हम सस्थानो और सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो स्वरूप देख रहे है, वह

1950 के बाद के विविध घटनाक्रम का परिणाम है। इस सिलसिले में निम्नलिखित विकास क्रम का विशेष उल्लेख करना होगा : 1. गॉव, जिला, राज्य और केंद्र-इस चार स्तभो पर टिके 'चौखंबा राज' की

अवधारणा मजबत हो रही है।

2. जिला शासन का विचार, विशेषकर 1983 के कर्नाटक पंचायत अधिनियम के प्रभाव से. जोर पकड़ा रहा है।

3. दो सविधान संशोधन (1992 का 73वॉ और 74वॉ), जिनमें जिला व उससे निचले स्तर पर स्थानीय निकायों को स्वशासन सस्थानो के रूप मे परिभाषित किया गया है।

इन बातों के जीन निहिताशय थे। अब तक 'स्थानीय स्वशासन' का जो विचार लॉर्ड रिपन के सरकारी प्रस्ताव (1882) के अनुसार केवल नागरिक सुविधाओं की

देखभाल करनेवाले स्थानीय निकायों तक सीमित था, वह अप्रासंगिक हो गया। दो, जो पंचायतं सीमित कार्यक्षेत्रवाली स्थानीय सस्थाएँ मानी जाती थीं, उनका

स्वरूप अब 'पंचायती राज' को हो गया, जिसका अर्थ अधिक व्यापक ओर अधिक गतिशील था। ये पचायतें अब 'ग्राम सभा से लोक सभा तक' की राजनीतिक प्रक्रिया

(ग्राम विधान सभा से ले कर राष्ट्रीय ससद) का एक अंग वन गयीं। तीन, मौजुदा अर्थ-सधीय ढाँचे में क्रांतिकारी परिवर्नन आने शुरू हो गये, जिसका केंद्र-राज्य सबंधो के साथ-साथ राज्य-पचायत सबधो पर भी प्रभाव पडा। दूसरे शब्दा

में, इस क्षेत्र में काफी अधिक परिवर्तन हो रहे हैं। मंविधान की ग्यारहवी अनुसूची के तहत 29 विषय पचायतों को सौंपे गये हैं। इसका नतीजा यह हुआ हे कि राज्य

विकेदीकरणः सरकार और स्वयसेवी क्षेत्र

के किमी एक स्तर पर सत्ता का केंद्रीकरण अब कठिन होता जा रहा है।

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 243जी मे 'स्वशासन की मस्थाओं का उल्लेख है। इस अवधारणा की व्याख्या पिछले दशक के इस सपूर्ण सकारात्मक घटनाक्रम के मद्देनजर करनी होगी। दरअसल, 'स्वशासन की संस्थाओं' की परिभापा कही भी नहीं दी गयी है। इसलिए व्यवहार के स्तर पर ही इस अवधारणा का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले, इसके लिए स्वायत्तता का होना जरूरी है। स्वायत्तता, जो भारतीय संघ और सरकार के विभिन्न स्तरों के दायरे के भीतर हो। वैसे, स्वायत्तता की अवधारणा का अर्थ अत्यत तचीला होता है। सामान्यतया स्वायत्तता का अर्थ शासन की उस गुजाइश से होता है जो किसी स्तर विशेष पर सबद्ध पक्षों के बीच आपस में तय हो जाती है। लेकिन लचीलेपन का यह दायरा केंद्र द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही होता है। निचले स्तर पर, स्वाभाविक ही है कि, इसकी परिभाषा तय कर दी जाय। राज्यों को पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी पंचायतो को कम से कम कितन और क्या अधिकार तथा कितनी सत्ता प्रदान करनी है, जिसके आधार पर स्वशासन की संस्थाओं के रूप में पंचायतो की पहचान बन तक।

मवैधानिक सशोधनों के बाद 'स्वशासन की सस्थाएँ' बन गयी पंचायतों ओर नगरपालिकाओं के पूरे अर्थ ओर मकसद को सही परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूगे हैं। हालाँकि अनुच्छेद 243डी, 243जी और 243पी(ई) में पचायतों और नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थानों के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन कहीं भी इन सस्थानों के दायरे को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके बावजूद, भारत के संधीय ढाँच में ये मंस्थाएँ दूरगामी परिणामोंवाले क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। सवैधानिक सशोधन के पारित होने के तुरत बाद निर्मल मुखर्जी ने लिखा था: 'संशोधित सविधान के अनुसार राज्यों को न केवल गाँवों के लिए, बल्कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर भी पचायतों को स्वशासन की संस्थाएँ बनाना होगा। परिणामस्वरूप, भविष्य में सरकार अब तीन स्तरों पर होगी—संघ, राज्य और पचायत। इससे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन की कल्पना कठिन है। इसके परिणाम दूरगामी हैं।'

अगर हम पंचायतों की मिसाल तों, तो तीनों स्तरो—ग्राम पंचायत, पंचायत सिमिति और जिला परिपद—की पचायतों उन्हें सीप गये दायित्वों के सदर्भ में अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में स्वशासन की सस्थाएँ है। 'वे सीमित क्षेत्र और सीमित कार्यों के लिए अपने आपमे एक तरह से सन्कारें है...पचायते स्वशासन की प्रनिनिधिक सस्थाएँ

ਵੇਂ ₁ 2

संविधान में 'स्वशासन' की जिस अवधारणा की गारटी दी गयी है, उस पर किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है। पचायतों और नगरपालिकाओं के अधिकारों तथा कार्यों को दो श्रेणियों में बॉटा जा सकता है : (1) मूल कार्य और (2) सौपे गये कार्य। मूल कार्य 'आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तेयार

करने' का है। सौप गय कार्यों में ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल मामलो सहित आर्धिक विकास और सामाजिक न्याय की उन योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है जो पचायतो को सौपी गयी है।

को सौपी गयी है। एक और भी दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार 1992-93 में जो कुछ भी हुआ,

वह 'प्रशासनिक संघवाद' को मजबूत करने के सिवाय और कुछ नहीं था। 73वे संशोधन के प्रावधान राज्यों के कुछ प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार स्थानीय निकायों को सोपे जाने में मदद करने और वढ़ावा देने के लिए 'प्रशासनिक सघवाद' को मजबूत करते है। स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकार व दायित्व तथा इन अधिकारों

के प्रयोग और इन टायित्वों का पूरा करने के लिए वित्तीय ससाधनों का प्रबंध उन कानूनों के जरिये किया जायेगा, जो सबद्ध राज्य सरकारों को पारित करने हांगे। इस विचारधारा के अनुसार, इन निकायों के पास कोई स्पष्ट कार्यकारी, विधायी,

वित्तीय या क्षेत्रीय अधिकार नहीं है, और मात्र सवैधानिक दर्जा हासिल कर लेने या नियमित चुनावो से उन्हे शासन के तीमरे स्तर का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता। इस

विचारधारा के प्रतिपादक एस. गुहन डेनियल इलाजर का हवाला देते हुए प्रतिपादित करते हैं कि विकेंद्रीकरण कोर्ड संघीय गुण नहीं है, क्योंकि विकेद्रीकरण से तात्पर्य एक केंद्रीय प्रधिकार का अस्तित्व होना है।

एक केंद्रीय प्राधिकार का अस्तित्व होना है।³

चूँकि इस विचारधारा में हमार राजनीतिक ढाँचे मे शुरू हुई लोकताँत्रिक ओर

राजनीतिक प्रक्रिया के स्वरूप और प्रभाव को सकुचित व सीमित दृष्टिकोण से देखा गया है, इसलिए इसके तर्कों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जिन देशों में स्थानीय निकाय है, वहाँ उन्हें बजट, उपनियमों और विनियमों

जेसे प्रत्यायुक्त (डेलीगेटेड) अधिकार दिये हुए है। उन्हें विनियमों से संबंधित कई अधिकार भी प्राप्त हैं, जो उनकी कामकाजी जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं। इसलिए भारत निश्चित रूप से प्रशासनिक सघवाद से हट कर बहुस्तरीय सघवाद की ओर बढ़ रहा है। 4

भारत में स्वशासन की संस्थाओं के रूप में स्थानीय निकायों के काम करने के लिए कुछ आवश्यक पूर्व-शर्ते ये हैं (क) क्षेत्राधिकार के बारे में निर्धारित स्पष्ट सीमाएँ; (ख) दायित्वों से मेल खाते पर्याप्त अधिकार व सत्ता; (ग) अपना कामकाज करने के लिए आवश्यक कर्मचारी व कित्तीय संसाधन, और (ध) सघीय ढाँचे के भीतर

करने के लिए आवश्यक कर्मचारी व वित्तीय संसाधन, और (घ) सघीय ढाँचे के भीतर कार्यकारी स्वायत्तता। इन सबके लिए संवैधानिक सशोधनों में प्रावधान किया गया है। सशोधनों के साथ-साथ संविधान में जोड़ी गयी ग्यारहवीं और वारहवी अनुस्चित

मे 29 विषय पंचायतों को और 18 विषय नगरपालिकाओं को सौपने का सुझाव दिया गया है। राज्य अनुपालन अधिनियमां मे इन्हें कमोवेश शामिल भी कर लिया गया है। जब इन पर पूरी तरह से अमल होने लगेगा, तव कहा जा सकेगा कि जिला

विकेद्रीकरण, सरकार और स्वयंसेवी क्षेत्र : 111

स्तर तथा उससे निचले स्तरों पर स्थानीय निकाय सही मायनों में भारतीय सधीय ढाँचे का तीसरा स्तर बन गये हैं और इससे भारतीय सध को एक नया अर्थ मिल गया है। नि सदेह इन स्थानीय निकायों को कोई वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, न ही इनके पास कानून-व्यवस्था की मशीनरी (पुलिस) या न्यायिक शक्तियाँ है। कुछ राज्यों ने अपने राज्य अनुपालन अधिनियमों में स्थानीय अदालतों (न्याय पचायतों) की स्थापना की वात जरूर कही है। नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवियों में एक एंसा वर्ग है, जो पचायतों को पुलिस व अदालती शक्तियाँ दिये जाने का जारदार हिमायती है।

स्थानीय शासन के लिए नौकरशाही का भी अत्यत महत्व है। अतर्वर्ती व्यवस्था चाहे जैसी भी की जाय, अततः पचायती राज का कामकाज चलानंवाले एक अलग सवर्ग की जरूरत पड़ेगी ही। इसका म्बरूप क्या होगा? इसकी सरचना क्या होगी? यह आनेवाले वर्षों में क्रमशः विकसित होगा।

मौजूदा राज्य अधिनियमो और अर्ध-सरकारी निकायों के बारे में इस घटनाक्रम के अर्थ महत्वपूर्ण है। लगभग 53 केंद्रीय और राज्य अधिनियम संविधान के 78वे और 74वे सशोधन के अनुपालन की राह में बाधक का काम करेंगे। बिजलो बोर्ड, जल और जल-मल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, विकास निगम जैसे अर्धसरकारी निकायों का ढाँचा केंद्रीकृत है; ये नये विकेंद्रित ढाँचे से कैंसे तालमेल बैठायेंगे, यह एक अहम सवाल है। दूसरे शब्दों में, हमारी नजर में राज्य की जो भूमिका है और उसका हमें जो अनुभव होता है, उनमें आमूल परिवर्तन आ जायेगा।

सामुदायिक प्रयास

नयी पंचायती राज प्रणाली के तहत, नागरिक समाज की अवधारणा को नया अर्थ और स्वरूप देने की काफी अधिक गुजाइश है। राज्य के निरकुश ऐतिहासिक स्वरूप की तुलना में जहाँ उसकी शिक्त काफी कमजोर है, वहाँ भी नागरिक समाज में स्थानीय स्तर पर स्वशासन के लिए आवश्यक प्रयास म्वयसेवी सम्थाओं द्वारा सुनिश्चित किय जाते है। भारत में यह स्थिति खास तौर से मौजूद रही है। किसी भी उदार समाज में जमीनी स्तर पर नागरिक व्यवस्था को नागरिकों की निरतर गतिविधि के विना बनाये नहीं रखा जा सकता। नागरिक समाज एक तरह से सत्तावादी प्रवृत्तियों का तोड़ है, क्योंकि लोकतात्रिक प्रक्रिया के जिस्स जनमत का अनौपचारिक दबाव तानाशाही की नयी व्यवस्थाओं को रोकता है। सभ्य समाजों की बहुलता और विविधता से ही ऐसी विशेषताएँ सुनिश्चित की जा सकती है, जो स्वशासन का प्रतीक है।

लोगों के प्रयास कई नरह से सामने आतं है। नागरिक समूह, पड़ोसियों के संगठन, सामुदायिक हितों और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए बनायी गयी समितियाँ, सस्थाएँ आदि तथा दबाव समूह आम तौर पर लोगों के सामान्य हितां नथा खास तोर पर दुर्बन्न एव सीमांत वर्गो के हितों की रक्षा करनेवाल स्वयसंवी संगठन, मजदूर सघ, सहकारिता सगठन—इनके कुछ उदाहरण है। गैरसरकारी सगठनों और स्वयसंवी सस्थाओं का आधार अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय हो सकता है। स्थानीय सस्थाएँ आम तौर में ममुदाय आधारित होती है। ऐसं भी संस्थाएँ हैं, जो किसी जिला प्राधिकरण के अधीन जिला या राज्य स्तर पर पजीकृत होती है। (उदाहरण के तौर पर जिला अंधता नियत्रण समितियाँ, जल सग्रहण विकास समितियाँ, सयुक्त वन प्रबंध समितियाँ, जल उपयोगकर्ता समितियाँ आदि)। सामान्यतः प्रशासन, पेशंवर व्यक्ति और उपयोगकर्ता इन संगठनों से जुड़े होते है। यहाँ 'स्वयंसेवी संस्थाओं' से हमारा अभिप्राय स्वयसेवी क्षेत्र के प्रयासों के सपूर्ण दायरे से है।

हाल तक सरकार का रवैया स्वयंसेवी क्षेत्र, जन सगठनों और कार्रवाई समूही हारा लोगों के सशक्तीकरण के लिए किये गये प्रयासों के प्रति अनुकूल नहीं था, इस क्षेत्र में सिर्फ परोपकारी संगठनों को सहन किया जाता था। स्वयसेवी संस्थाओं को ले कर नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के मन में काफी सदेह था, क्योंकि इनमें से कई संस्थाओं ने बेहतर ढग से काम किया था और इसके माध्यम से लोगों का विश्वास जीता था। इन्होंने गरीबों या विचत वर्गों को संगठित किया, तािक उन्हें उनके अधिकार दिलाये जाये। इससे स्थानीय स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करनेवाले राजनीतिक वर्ग को असुरक्षा महसूस होने लगी थी. नौकरशाही भी इन स्वार्थों के साथ थी। राजनेताओं और नौकरशाहों के इस गठजोड़ से स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के जन संगठनों के प्रति प्रतिकूल जनमत तैयार किया गया। गैरसण्कारी सगठनों और स्वयसेवी सस्थाओं को भ्रष्ट और राष्ट्रविरोधी करार दे दिया गया, क्योंकि इनमें से कई को अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहायता मिल रही थी।

लेकिन, इसके समानातर ही एक और विचारधारा पनप रही थी, जिसके अनुसार गरीबी हटाने, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने तथा साक्षरता, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय विकास आदि से जुड़े बड़े आकार के कार्यक्रमों में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर काम करने, योजना बनाने और भागीरदारी करने में स्थानीय सा क्षेत्रीय सहत्वपूर्ण भूमिका है। स्वयंसेवी संस्थाएँ जटिल मुद्दों से निपटने के अभिनव तरीके खोज सकती हैं, परियोजनाओं को लागू करने की किफायती योजना बना सकती हैं तथा लोगों की कारगर व सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने में अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। उनके पास अपने कार्य क्षेत्र की विशेषज्ञता और सक्षमता मौजूद है।

जैसा कि बद्योपाध्याय कहते हैं, इन भारी-भरकम राष्ट्रीय कार्यक्रमो में 'स्थानीय पहलो, नर्वान कार्यक्रमो तथा कल्पनाश्रील योजना की काफी गुंजाइश है, जो ठस और यात्रिक क्रियान्वयन निर्देशोंवाली किसी भी केंद्र पायोजित योजना में संभव नहीं हो सकती। अतः प्रशासन द्वारा संचालित सेवा प्रणाली की किमयो के बोध से स्वयंसेवी संस्थाओं की पूरक भूमिका को स्वीकार करने में मदद मिली।'

सातवी योजना के दस्तावेज में स्वयंसेवी क्षेत्र के सकारात्मक योगदान को स्वीकार करते हुए कहा गया था कि भविष्य में 'विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल करने' के गंभीर प्रयास किये जायेंगे। इस दस्तावेज मे निम्नलिखित क्षेत्रो

में स्वयसेवी संस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया गया था :

 ग्रामीण गरीबो को विकल्प और चयन के अवसर उपलब्ध कराने मे सरकारी प्रयासों के परक के रूप में काम करना:

2. ग्राम स्तर पर लोगो के ऑख व कान के रूप मे काम करना, उदाहरण प्रस्तुत करना । स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए ऊपरी खर्चों में कटौती

ओर समाज की अधिकाधिक भागीदारी से अपने सीमित संसाधनों के भीतर अधिक से अधिक लोगो तक पहुँचने के लिए सरल, अभिनव, लचीले और कम खर्चीले उपाय

अपनाना संभव है: 4. जनता को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करनेवाली व्यवस्था को सक्रिय वनाना

और निर्धनतम लोगों द्वारा महसूस की जानेवाली जरूरतो के प्रति इस व्यवस्था को ग्रामीण स्तर पर कारगर बनानाः

5. सूचना का प्रसार करना; 6. समुदायों को यथासंभव आत्मनिर्भर बनाना;

7. यह प्रदर्शित करना कि अपने विकास के लिए ग्रामीण व घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, मानव संसाधनों, ग्रामीण कलाओं और स्थानीय

जा रही है: 8. प्रौद्योगिकी की रहस्यमयता को समाप्त करना और इसे गाँव में रहनेकले गरीबां तक सरल रूप में पहुँचाना;

जानकारियों को कैसे काम में लाया जा सकता है. जिनकी अभी काफी उपेक्षा की

9. उन जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, जो यह मानते हैं कि स्वयंसेवी कार्य पेशेवर स्तर पर किया जा सकता है:

10. समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुदाय के भीतर से ही वित्तीय ससाधन जुटाना;

11. गरीबो को सगठित तथा सक्रिय करना तथा उनमें बढिया सेवाओं की मॉग

करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। गाँव के स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के कामकाज पर जवाबदेही की सामुदायिक प्रणाली को लागू करना।⁶

आठवीं पचवर्षीय योजना (1992-97) के दस्तावेज⁷ में इस अवधारणा को यह कहते हुए और आगे बढाया गया : 'विकास को जनादोलन बनाना जरूरी है. . समाज के प्रति जवाबदेह जन सस्थानो का गठन कर शिक्षा (विशेषकर साक्षरता), स्वास्थ्य,

परिवार नियाजन, भूमि सुघार, कुशल भू-उपयोग, लघु सिंचाई, जलस्रोतो का प्रबध, जसर भूमि का विकास, वन विकास, पशु पालन, डेयरी, मछली पालन, रेशम उत्पादन

भारत में पचायती राज 114

मभावनाओं के इस्तेमाल से सेवा प्रदान प्रणाली को सुधारने के लिए विभिन्न सस्याओं के बीच चुनाव का अवसर उपलब्ध कराने पर था। योजना में ऐसे 'उपयोगकर्ताओं पैसा लगानेवालों, निर्माताओं या लाभार्थियों' को जन संस्थानों के महत्व को रेखाकित किया गया जो स्थानीय समाज के पति जिस्मेदार हो और जितमे स्थानीय प्रणासन के साथ

आदि के क्षेत्र में काफी प्रगति की जा सकती है।' जोर स्वयसेवी क्षेत्र की विशाल

गया, जो स्थानीय समाज के प्रति जिम्मेदार हो और जिनमे स्थानीय प्रशासन के साथ मिल कर जरूरत स्थानीय योजनाएँ बनाने और उन्हें लागू करने की क्षमता हो।

दस्तावेज में जमीनी स्तर पर अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए उन कार्यों के विकेदित स्थानीय-स्तर नियोजन के लिए एक नये परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया गया है, जो बुनियादी तौर पर जन सस्थानों के सहयोग तथा सरकार के समर्थन से स्वयसेवी सस्थाओं तथा गैरसरकारी सगठनो द्वारा किये जाते है। राष्ट्रीय विकास परिषद की 'लघु स्तर पर नियोजन पर समिति' की रिपोर्ट (1994) मे भी इस बात पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'अच्छे कामकाज के रिकॉर्डवाले ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी सगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को अन्यत्र भी दोहराये ओर लोगों मे संस्था निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करे। साथ ही, उनसे लघु स्तर पर नियोजन करनेवाले निकायों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने की अपेक्षा भी की जा सकती है।'

यहाँ यह बता देना जरूरी है कि स्वयंसेवी सस्थाओं तथा गैरसरकारी सगठनों की अपनी कुछ सीमाएँ हैं। उनमें से अधिकांश एक नेता पर आधारित सगठन है और उनका कार्यक्षेत्र सीमित है, जो अकसर कुछ गाँवो, एक ब्लॉक या जिले के एक हिस्से तक ही होता है। कानूनी तौर पर वे स्थानीय लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते। कड़यों में तो अंदरूनी लोकतत्र भी नहीं होता और वे धन के लिए सरकार या अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं।

पंचायतें और स्वयंसेवी संस्थाएँ

पर चर्चा की जानी चाहिए।

1992 के संवैधानिक सशोधनों के बाद पंचायतों और नगरपालिकाओं की नयीं भूमिका को स्वयंसेवी सस्थाओं द्वारा पहचाना जाना चाहिए। चूँिक वे स्वशासन के प्रतिनिधिक सस्थान होते हैं, इसलिए स्वयसेवी सस्थाओं को उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करना होगा। बद्योपाध्याय के अनुसार, 'स्वयंसेवी सस्थाओं को भूल से भी पंचायतों को अपनी स्थिति, सत्ता व शिक्त का प्रतिद्वंद्वी नहीं समझना चाहिए। प्रतिनिधिक शासन प्रणाली के विभिन्न स्तरों के रूप में पचायतों के प्रभुत्व को बिना किसी ना-नुकच के स्वीकार करना ही होगा।' इस बुनियादी पृष्ठभूमि के दायरे के भीतर ही स्वयंसेवी सस्थाओं तथा पंचायतों. नगरपालिकाओं के बीच संबंध की समस्याओं और संभावनाओ

चुनावों के माध्यम से नयी पंचायतों के अस्तित्व में आने के बाद चार तरह

की स्थितिया लक्षित की जा सकती ह

- (क) पचायतों या स्थानीय प्रयासो के अभाव में जो स्थान खाली था, उस कार्यक्षेत्र में जन सगठनों और स्वयसेवी संस्थाओं ने अपनी जड़े जमा ली है। वे पंचायतो को अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण करनेवाले नवोदित सस्थानों के रूप में देखती है।
- (ख) नवगठित पचायतें सामुदायिक प्रयासो और स्वयंसेवी संस्थाओं या गैरसरकारी सगठनो दोनों ही को अपने क्षेत्राधिकार में काम करनेवाले प्रतिद्वंद्वियों के रूप में देखती हैं।
- (ग) तीसरी स्थिति यह है कि पंचायते और स्वयसेवी सगठन दोनो ही अपनी-अपनी भूमिकाओं को समझते हैं तथा एक-दूसरे के काम में पूरक बनने के लिए आपसी तालमेल और सहयोग से काम करते हैं।
- (घ) कई इलाको में स्वयसेवी सस्थाएँ पंचायत चुनावों में हिस्सा लेती हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं। स्वयसेवी क्षेत्र के उम्मीदवारों को या तो राजनीतिक दलों से टिकट मिल जाता है या वे निर्दिलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते है। निचले स्तर पर ये उम्मीदवार अधिक सफल होते हैं तथा देखा गया है कि स्थानीय निकायो मे उन लोगो का कार्य निप्पादन बेहतर होता है, जिन्होंने या तो स्वयंसेवी सगठनो के साथ काम किया है या उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

स्वयसेवी संस्थाओं और पंचायतो का एक-दूसरे के प्रति रवैया कैसा है? कई राज्यों में पचायतों के प्रति स्वयसेवी सस्थाओं का रवैया 'परवाह नहीं' करने का है। पचायतों के प्रति जन सगठनों का दृष्टिकोण अवहेलनापूर्ण होता है और वे पंचायतों को अप्रासंगिक और निष्प्रभावी मानते है। इसलिए वे पचायतों के साथ किसी तरह के आदान-प्रदान या अंतर्क्रिया की जरूरत महसूस नहीं करते।

चूँकि कई इलाको में पंचायतें काम नहीं कर रही होतीं और उनकी नियमित बैठके नहीं होती, इसलिए स्वयंसेवी संस्थाएँ उन्हें गभीरता से नहीं लेती। वे समझती है कि पंचायतें क्षुट्र राजनीति के अखाड़े हैं और इसलिए उनके साथ जितनी दूरी बनाये रखी जाये. उतना ही बेहतर है।

अधिकाश मामलों में, पंचायते लोगो में स्वशासन की संस्थाओं के रूप मे विश्वास नहीं जमा पाती है। अकसर तो पंचायत सदस्यों को अपनी शक्तियों व दायित्वों का ही पता नहीं होता। जाति तथा वर्ग की दृष्टि से हीन स्थिति, अल्प शिक्षा और वित्तीय शक्तियों के अभाव की वजह से भी उन्हें तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। और फिर, आरक्षण के जिस्ये चुन कर भारी संख्या में आयी महिलाएँ भी अपने तौर पर कामकाज करने में समर्थ नहीं होती। वे परिवार के पुरुष सदस्यों की

'छाया' के रूप में काम करती है। दिन-प्रतिदिन के पचायत कार्यो मे राजनीतिक

दखल स भा पचायतो के विकास में रुकावट आती हे। इसलिए प्रशिक्षण, विचार-विनियम कायक्रमो, सफल पचायतों की यात्राओं तथा जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम

से क्षमता निर्माण बहुत ही जरूरी है। अपनी विशेषज्ञता और विशिष्ट ज्ञान के जरिये

स्वयसेवी संस्थाएँ इस मामले में पंचायतो की मदद कर सकती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ज्ञान और आधुनिकतम प्रौद्योगिक विकास तक पहुँच की दृष्टि से स्वयंसेवी सस्थाओं और गैरसरकारी मगठनों का पलडा पंचायती राज सस्थाओ

की तुलना में भारी है। इनमे से बहुत-से सगठन सूचना के प्रसार और जागरूकता उत्पन्न करने के कामों में लगे हुए है। उदाहरण के लिए कई ऐसे संगठन है, जो ग्रामीण इलाकों के लिए वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के विकास में लगे

है।

कई स्वयसेवी संस्थाओं तथा गैरसरकारी संगठनों ने महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों और भूमि सुधार के कार्यान्वयन जैसे जमीनी मुद्दों में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। इन विषयों के अलावा पचायतं जल प्रबंध, वन प्रबंध, मछली पालन तथा समदाय के सदस्यों की आय बढ़ानेवाली आय अर्जक परियोजनाओं के क्षेत्र

में स्वयंतेवी संस्थाओं का सहयोग ले सकती है। इस चर्चा में स्वसहायता समूहो, पानी पचायतों, जल सभर संस्थाओं, जल उपयोगकर्ताओं की संस्थाओं, सामुदायिक सिचाई समूहों और सयुक्त वन प्रबंध, वन

सरक्षण समितियों और उनके स्थायित्व के मुद्दे का विशेष उल्लेख जरूरी है। स्वसहायता समृह (सेल्फ-हेल्प ग्रूप) लघु बचत, लघु ऋण तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में कार्यरत

है, जो ग्रामीण गरीबों के वित्तीय सहारे का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। यहाँ 'सेल्फ-इप्लायड वीमेन्स एसोसियेशन' (सेवा) की सफलता की चर्चा की जा सकती है। वनो के हास,

भ-क्षरण में वृद्धि, जल स्तर में गिरावट आदि के कारण जल संभर और जल उपयोगकर्ताओं की संस्थाएँ अस्तित्व में आयी है। इन संस्थाओं को जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना की निधियों का 50 प्रतिशत तक प्राप्त करने की अनुमति है। एनआईआरडी के एक अध्ययन के अनुसार जल सभर समितियो

और उपयोगकर्ता समुहों में लाभार्थियों की भागीदारी उत्पादन पैकेजों के चयन और श्रम तक सीमित थी। अत जल सभर समितियो ने नियोजन और क्रियान्वयन प्रक्रियाओ में पिछलग्गू की भॉति काम किया। काम करने के इस तरीके में भागीदारी की गुंजाडश बहत थी।

विश्व बैंक ने इन चार जल संभर परियोजनाओं को समर्थन दिया है हिमालय जल संभर प्रबंध परियोजना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए जल सभर विकास, समन्वित जल संभर विकास परियोजनाएँ (मैदानी) और समन्वित जल सभर विकास परियोजनाएँ (पर्वतीय) । इन परियोजनाओं की समीक्षा से पता चलता है कि ये परियोजनाएँ लबी

अवधि तक नहीं चल सकर्ती।

विकेदीकरण सरकार और स्वयंसेवी क्षेत्र : 117

आध्र प्रदेश में लगभग 10 हजार जल उपयोगकर्ता संस्थाओं और वितरक समितियों का गठन किया गया, ताकि कारगर व भरोसेमंद जलापूर्ति और वितरण

के लिए सिंचाई प्रणाली के प्रबंध व रख-रखाव में किसानों की भागीदारी हासिल की जा सके। पानी पंचायतें देश के विभिन्न हिस्सो में खेती के लिए पानी की गंभीर

की जा सके। पानी पंचायतें देश के विभिन्न हिस्सों में खेती के लिए पानी की गंभीर कमी को देखते हुए गठित की गयी है। महाराष्ट्र में नवगॉव प्रयोग पानी पचायत का एक शानदार उदाहरण है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वनो को फिर से लगाने

मे वन सरक्षण सिमितियों की सफलता के साथ ही सामुदायिक भागीदारी से वन भूमियों के संरक्षण व प्रबंध पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित हुआ है। इस उद्देश्य को ध्यान

में रखते हुए भारत सरकार ने जून 1990 में एक अधिसूचना जारी की, जिसके जिरये वन भूमि को बहाल करने में ग्राम समितियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी को बढावा दिया गया। संयुक्त वन प्रबंध का उद्देश्य समुदाय-आधारित निर्णय प्रक्रिया

और आम सहमित द्वारा पारंपरिक वन प्रबंध प्रणाली को फिर से वापस लाना है। इन सभी प्रयासों में महत्वपूर्ण मुद्दा उनके स्थायित्व का है। इस बात के पर्याप्त

प्रमाण है कि जब तक इन्हें पंचायतों, जो स्थायी होती हैं, की पूर्ण निगरानी व भागीदारी में लाया नहीं जाता, वे कारगर ढग से काम नहीं करतीं। पंचायतों के अलावा और

कोई भी स्थानीय निकाय ऐसा नहीं है जो उनका स्थायित्व सुनिश्चित कर सके। जल संभर समितियों के बारे में एनआईआरडी के एक अध्ययन से पता चला है

कि जल विकास दलों का गठन पंचायत समिति और ग्राम पंचायत सतरों पर जरूरी है, क्योंकि तभी इनकी कार्यकुशलता व निरतरता सुनिश्चित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंध को पंचायतों के दायरे में लाने के बारे में एक विधेयक पारित

हुआ हैं। इस बारे में एक और सफल उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1985-86 में कुएँ खोदने, उथले और गहरे नलकूप लगाने और नदी लिफ्ट सिचाई के लिए विश्व बैंक की मदद से एक व्यापक योजना शुरू कीं, जो मार्च 1994 मैं पूरी हुई। लघु कमान क्षेत्र और आसान प्रबंध की वजह से सभी उथले और निम्न

कार्यक्षमतावालें नलकूप पंचायत समितियों को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया। प्रत्येक जिला परिषद के सभाधिषति ने स्थल चयन समिति से विचार-विमर्श कर विभिन्न पंचायत समितियों को ये नल कूप हस्तांतरित कर दिये। पंचायत समिति स्तर पर कृषि, सिंचाई और सहयोग की स्थायी समिति ने नल कूप ग्राम पंचायतों को आवटित

कर दिये। कमान क्षेत्र में आनेवालें सभी किसानों से यह क्चन लिया गया कि वे पचायत नल क्षों से दिया जानैवाला पानी खरीदेंगे। नल क्षों की रोजमर्रा की देखभाल

का काम लाभार्थी समिति द्वास किया जा रहा है जो पश्चिम बंगाल के पंचायती राज की एक अनूठी विशेषता है। सभी नल कूप ऑपरेटर इस समिति के सदस्य भी है। अपने नियामक कार्यों और नीतिगत मामलो पर जोर के साथ-साथ पंचायते

अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन का काम जन संगठनों को सौप सकती

118 : भारत में पचायती राज

हे। इस संदर्भ में, कई ऐसे कार्य, जो अब तक राज्य द्वारा किये जाते थे, जन संगठनो द्वारा बेहतर ढग से किये जा सकते हैं—ये कार्य चाहे ऋण के क्षेत्र मे हो या कृषि

विपणन अथवा विभिन्न विकास गतिविधियो के क्षेत्र में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

की डेयरी सहकारी सस्थाएँ इस दिशा में एक ठोस उदहारण हैं। स्व-सहायता के आधार पर काम करनेवाली पंजीकृत सोसायटियो को और भी काम सौंपे जा सकते है, जिसका

एक ज्वलंत उदाहरण पश्चिम बंगाल के बॉकुरा जिले में स्थित झिलमिली में ग्रामीण महिला श्रमिक उन्नयन समिति है। यही नहीं, लाभार्थियों की अनीपचारिक संस्थाओं को भी नल कूपों को चलाने और उनके रख-रखाव का जिम्मा सौपा जा सकता है,

जिससे विभागीय कार्यकर्ताओं की जरूरत से बचा जा सकता है। निया स्थानीय शासन प्रणाली के तहत स्वयंसेवी क्षेत्र और जन सगठनों की भूमिका को वढाने की दिशा

मे यह एक निश्चित प्रयास होगा। कई स्वयंसेवी संस्थाएँ स्थानीय जैविक ससाधनो पर जनजातियो तथा अन्य

स्थानीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण तथा जड़ी-बूटियों आदि के बार में उनके ज्ञान को संरक्षित करने के लिए भी कार्य कर रही हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनम

स्वयंसेवी संस्थाओं ने शानदार काम किया है। पंचायती राज सस्थाएँ अब जनजातीय इलाकों मे भी काम करने लगी हैं। ये संस्थाएँ इन मुद्दों पर काम करने के लिए स्वयसंबी सस्थाओं को आमत्रित कर सकती हैं, जिससे जनजातियों और वनवासियों की बेहनरी

के लिए पंचायतें इनके अनुभवों से सीख सकेगी तथा उनकी विशेषज्ञता का फायदा उठा सकेंगी।

लोकतात्रिक संस्थाओं के निर्माण की राजनीतिक प्रक्रिया में सामाजिक वदलाव

लाने के लिए जन संगठन उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। ये संगठन भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदी होते हैं और संकट प्रबधन में अधिक कुशल होते

है। नागरिक समाज का स्वास्थ्य कारगर जन संगठनो के अस्तित्व को भी तय करता है और उनके प्रति संवेदनशीलता भी विकसित करता है। मौजुदा संविधान मे ग्राम सभा को कार्यकारी निकाय का दर्जा प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा गाँव या वार्ड के सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसे मुद्दे उठाने, स्पष्टीकरण माँगने और क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम सुझाने के अधिकार

है। ग्राम सभा, ज्यादा से ज्यादा, सामाजिक निगरानी की भूमिका अदा कर सकती है। स्वयंसेवी क्षेत्र के साथ अपने अनुभव के आधार पर, ग्राम सभाएँ स्वयंसेवी संस्थाओं मे से अच्छी संस्थाओं और कम अच्छी संस्थाओं की पहचान करने की भूमिका अदा

कर सकती हैं। स्वयंसेवी संस्थाएँ पंचायतों की सदस्यता के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वे चुनावो में निर्दलीय उम्मीदवार खडे कर सकती हैं। लेकिन जिला नियोजन समितियों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने कार्य

विकेंद्रीकरण सरकार और स्वयसेवी क्षेत्र : 119

निष्पादन के आधार पर य इन सिमितियों में नामजद की जा सकती है। ग्राम नियोजन, संसाधनों की पहचान, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वयसेवी तकनीकी दल गठित करने में उनका स्थान महत्वपूर्ण हो सकता है। वे बेहतर सहयोग और

समन्वय सुनिश्चित कर सकती हैं। इस प्रकार पचायते एव स्वयंसेवी संस्थाएँ आवश्यकता होने पर, विशेषकर तब जब वे एक-दूसरे को विकेद्रीकरण और विकास की प्रक्रिया मे प्रतिद्वद्वी न समझ कर साझेदार समझें, आपस में मिल कर कारगर ढंग से काम

म प्रातद्वद्धा न समझ कर साझदार समझ, आपत्त म ामल कर कारगर ढंग स काम कर सकती हैं। इस संदर्भ में, हमें राजनीतिक दलो की भूमिका पर भी गौर करना होगा। भारत ने बहुदलीय ससदीय प्रणाली अपनायी है और लोकतात्रिक सस्थानो की सबसे निचली

इकाइयों में भी बहुदलीय प्रणाली की झलक देखने को मिलती है। इसलिए राजनीतिक

पार्टियां गाँवां, वार्डो और कस्बो मे अपनी जड़े जमाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करती है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जान लड़ा देती हैं। वे अपने जन सगठनो या पार्टी मचों से जन समस्याओं को उठाती है। जहाँ भी यह मशीनरी मजबूत होती है, वहाँ देखने मे आता है कि जन संगठन अधिक मजबूत नहीं होते

और न ही बड़ी संख्या में होते है और अगर थोड़े-से होते भी हैं, तो उनका स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पश्चिम बंगाल है।

जिन राज्यों में जन सगठनों का आधार मजबूत है, उनके पास समर्पित कार्यकर्ता है, प्रासंगिक कार्यक्रम हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और काम करने पर जोर है, वे स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते है। विचार

और काम, दोनों ही के जरिये ये सस्थान मार्ग प्रदर्शन कर सकते है और स्थानीय निकायों की मदद भी कर सकते है। नियोजन प्रक्रिया के लिए जन अभियानों के माध्यम से पद्मायतों को नया रास्ता दिखाने में केरल शास्त्र साहित्य परिषद की भूमिका इसका बेहतरीन उदाहरण है। महाराष्ट्र में, जहाँ सहकारी आदोलन काफी मजबूती

से चल रहा है, ये संस्थाएँ राज्य में पंचायती राज को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विकेंद्रित संस्थाओं को मजबूत करने (या कमजोर बनाने) मे विधायको, राज्य स्तर के राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों का बड़ा हाथ रहता है। स्वतंत्रता

प्राप्ति के बाद से प्रशासन और सरकार की प्रवृत्ति केद्रीकरण के पक्ष मे रही है। 1990 के दशक के आरभ से विकेद्रित सस्थाओं के प्रति उनके रुख में सकारात्मक परिवर्तन आया है। लेकिन अभी उन्हें शासन और प्रशासन के नये स्वरूप के बारे में उभरते सोच के अनुरूप अपने को ढालने में समय लगेगा।

औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों ही क्षेत्रों में गतिशील विकेंद्रित सस्थान किसी भी नागरिक समाज की नींव होते हैं। केवल वास्तविक लोकतांत्रिक माहौल में ही, समाज अपनी भूमिका अदा कर सकता है और नागरिको को पहल करने के

120 भारत में पचायती राज

लिए प्रेरित कर सकता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि पड़ांस के स्तर से गॉव कस्वा, ब्लॉक और जिले के स्तर तक जिम्मेदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और कुशल स्थानीय स्व-शासन प्रणाली के लिए सिक्रय नागरिक समाज का होना अति आवश्यक है।

संदर्भ

- 1 निर्मल मुखर्जी, तीसरा पाया, इकॉनॉमिक एड पॉलिटिकल वीकली, 1 मई 1993, पृष्ट 856-62
- 2 डी बंदुपोपाध्याय, स्वयसेवी संगठन और पन्नायत. मेनस्ट्रीय, 29 मार्च 1997
- उ एस गुहन, सघवाद तथा तिहत्तरवाँ सशोधन कुछ विचार, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज, नयी दिल्ली की दसवीं वर्घगाँठ पर सितवर 1995 में प्रस्तुत परचा। गुहन हालांकि यह म्वीकार करते है कि नयी घटनाएँ सघवाद को मजबूत कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि सीमित स्तर पर, क्योंकि ससाधन, उत्तरदायिख, शक्तियां जेसी इसकी अधिकाश विषय सामग्री राज्य की इच्छा पर है।
- 4 जॉर्ज मेच्यू, भारत मं स्वशासन की सस्थाएँ बहुस्तरीय सधवाट की ओर, डेवलपमेट एड चेज, खड 2 स. 2, जुलाई-दिसबर 1997, मदास इस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेट स्टडीज, पृष्ठ 276-93
- 5. उपर्युक्त (2)
- 6 भारत सरकार, सातवीं पचवर्षीय योजना 1985-90, खंड 2, योजना आयोग, पृष्ठ 66
- 7 भारत सरकार, आठवी पचवर्षीय योजना, 1992-97, खंड 1, योजना आयोग, पृष्ठ 17
- के जयलक्ष्मी और वी. अलामलाई, डीसेंट्रलाइण्ड इस्टीट्यूशन्स इन द फॉर्मल एड इनफॉर्मल सेक्टर्स, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
- 9. उपर्युक्त (1)

पंचायतों के लिए स्वयंसेवक

क्या पचायतें गॉवों में छुपी प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकती हैं? क्या स्थानीय निकाय इस विशाल देश के कोने-कोने में उपलब्ध मानव संसाधनो का उपयोग करने मे समर्थ हैं?

हाँ, वे कर सकती है। केरल के प्रयोग से ताँ यही इशारा मिलता है। विकंद्रित नियोजन के लिए जन अभियान की सफलता के बाद केरल ने वॉलटरी टेक्नीकल कोर (वीटीसी) के नाम से एकदम नया प्रयोग शुरू किया है। कोर में हर एक ब्लॉक एव नगरपालिका के अतर्गत 50 से 60 विशेषज्ञों की टीम बनायी गयी है। यह टीम स्थानीय निकायों के लिए नौवीं योजना मे तैयार परियोजनाओं के मूल्यांकन में मदद करेगी। स्थानीय प्रशासन प्रणाली को मजबूत बनाने की राह पर यह मील का पत्थर है।

वॉलटरी टेक्नीकल कोर की उत्पत्ति एवं महत्व को समझने के लिए उसे विकंद्रित नियोजन के लिए जन अभियान के साथ जोड़ कर देखना होगा। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ है। जन अभियान के जिरये सबसे कम समय में गाँव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर नियोजन क्षमता बटोरने में सफलता मिली है। केरल में नोवी योजना का 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों में लोगों द्वारा स्वयं बनायी गयी योजनाओं का है।

अभियान का पहला चरण लोगों की आवश्यकताओ एव स्थानीय विकास की किमयों को चिहित करने के लिए चलाया गया था। इस मकसद के लिए ग्राम सभा तथा नगरपालिका वार्ड स्तर पर सम्मेलनो एवं परिचर्चाओं का आयोजन किया गया था। केरल में 990 ग्राम पंचायतो तथा 58 नगरपालिकाओं में 14,000 वार्ड है। एक अनुमान के अनुसार इस अभियान में 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरे चरण में सभी पचायतों एवं नगरपालिकाओं में विकास संगोष्टियाँ आयोजित की गयी थो, जिनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने

ग्रम सभाओं तथा वार्ड स्तरीय सम्मेननों म वनी गर्क सम्बन्ध का है निया, समेकित इन भी हुँहै।

पहली बार ससाधनों का नक्शा (विकास से स्वापन प्राणिक एवं सानव ससाधनों का निष्णक्ष आकलन) भी बनाया गया। या नविक सन्दर्श अधिक हो, त्यारित मूल्याकन तकनीकों तथा चालू कार्यक्रमों की अधनगढारों सर्वाचा के प्रतियं बनाया गया था। इन विकास रिपोर्टी में एक लाख ने स्वाप्त की है कि कि कि निम्में स्थानीय इतिहास, समाधन, विकास की समस्याएं एवं संगानक वर्ष है नहा के और ये अव सभी पंचायतों में उपलब्ध हैं।

अभियान के तीसरे चरण के अनर्गत योजना न मानिक करने के नित्र समाधानों के समेकित ज्ञापनों को परियोजनाओं अध्या यो क्या न यदना गया था। पचायत/नगरपालिका स्तर पर इस काय के निर्ण स्थानक विद्या निधा कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयो पर कार्यवल बनाये गये थे। पणायक नगरपाणिका को की योजनाएँ बनाते समय कार्यवल दारा तैयार परियोजनाओं म न क्यानिक अपने योजनाएँ छाँटी जा रही है। अगले चरण मे ब्लॉक एव जिला नगर के व्यानना को में न्यानीय योजनाओं को मिलाने के लिए जिला और ब्लॉक नगर पर विकास नगरिक जो का आयोजना किया जायेगा। वॉलंटरी टेक्नीकल कोर की भूमिका हमी नरका, नार पर कार्यो है। उन्लेखनीय है कि नौवीं योजना के लिए जन अभियान का ममादन के न्या कार्यां ना की 40वीं जयती के अवसर पर राज्यस्तरीय महासम्मेशन में किया कार्यां मा

करल में तरकारी अधिकारियों ने जन ऑप्यासन पर जुक में तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आम जनता का उन्साह मामने आआ और उसे आगे बढ़ाने में पचायतों में आत्मिवश्वास दिखा तो उन्हें "मका नंता मानना पड़ा। इसी बीच इस अभियान को शुरू करनेवाली 'राज्य नियोजन पांज्यद' ने अधिकारियों के लिए व्यवस्थित आचार एव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजिन किये आग. धीरे-धीरे ही सही, उनका रयेया बदलने लगा। इतना जरूर या कि ऐसे नीकाचार में भी हर एक जिले में अधिकारियों के शामिल होने का फैसला जिला ऑधकारी को ही करना था। कुछ स्थानों पर बैंक कर्मचारियों एव अफसर के सगडनों ने पशस्यनों के लिए परियोजनाएं बनाने के लिए अपने सदस्यों के प्रशिक्षण के अग्ये अकावनों के लिए परियोजनाएं बनाने के लिए अपने सदस्यों के प्रशिक्षण के अग्ये अकावनिक केंद्र अभी तक इससे दूरी बनाये हुए हैं। उनकी तरफ से सामाजिक हिस्सोदारी की कमी इस उच्च साक्षरतावाले राज्य में उच्च अध्ययन के केंद्रों के रवैये को परिनाहित करनी है।

जन अभियान के प्रति जनता का रुख शृष्ट में असम्मान था। कई क्षेत्रो में प्राम सभाओं में जहाँ हजारों लोग इकड़ा हो रहे थे, वहीं कुछ अन्य जगहों पर कोरम पूरा करना भी भारी पड़ जाता था। शहरीकृत गाँवों में ज्यादा लोग अभियान की सभाओं में नहीं आते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। सार्वजनिक जीवन में जहाँ-जहाँ महिलाएँ आगे आ रही थी, उन ग्राम संभाओं में भीड़ ज्यादा होती थी। इसके साथ ही पहले से ही चलाये गये प्रचार एवं जागरूकता अभियानों से भी कार्यक्रम में भागीदारी अच्छी रहती थी। पंचायतों में अभियान की वेहतर सफलता का सबक यह है कि प्रत्येक गाँव में राजनीतिक वफादारी और दलगत मतभेद तो रहेगे, मगर विकास की गतिविधियों के संवर्धन के लिए लोग सामुदायिक स्तर पर अपने मतभेद भूल कर एकजुट होने को तैयार है।

जन अभियान की प्रक्रिया के जिरये केरल में पंचायतों द्वारा करीब 1.5 लाख परियोजनाएँ सुझायी जा चुकी है। इन परियोजनाओं के दो वर्ग थे (1) वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना में शामिल करने के लिए सुझायी गयी परियोजनाएँ और (2) नौवीं योजना की वाकी अवधि के लिए सुझायी गयी योजनाएँ। इन योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने चालू वर्ष के बजट में 1025 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नौवीं योजना में स्थानीय निकायों का हिस्सा 40 प्रतिशत है, जो 4400 करोड़ रुपये बैठता है। इस पूरे कार्य व्यापार में एक बड़ा मुद्दा यह था कि स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित सैकडों परियोजनाओं की तकनीकी संभाव्यता, वित्तीय क्षमता तथा सामाजिक स्वीकार्यता का परीक्षण कौन करेगा, ताकि उनके लिए समुचित तकनीकी एव अन्य स्वीकृतियाँ आसानी से हासिल की जा सके?

इसी बिंदु पर 'वॉलंटरी टेक्नीकल कोर' (वीटीसी) का विचार उत्पन्न हुआ। वीटीसी के अंतर्गत केरल भर में करीब 10,000 विशेषज्ञ छाँटे जायेंगे। उन्हें केरल के सभी गाँवो एवं ब्लॉको में बड़ी संख्या में उपलब्ध सेवानिवृत्त एवं गैरसरकारी विशेषज्ञों में से चुना जायेगा। उसके पास स्नातकोत्तर अथवा व्यावसायिक उपाधि के साथ ही साथ विकास के क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव आदि निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है। अनुभवी लोगों को शैक्षिक योग्यता की शर्त में ढील मिल सकती है। पंचायतों को स्वैच्छिक सहायता देने के लिए उन्हें हफ्ते में कम से कम एक दिन कार्य करना होगा। ब्लॉक में काम करने से पहले प्रत्येक जिले में उन्हें परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा है। ये स्वयंसेवी विशेषज्ञ ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं के जरियं परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे।

इस नयी पहल के प्रति व्यावसायिक विशेषज्ञों का रुख काफी उत्साहजनक है। राज्य योजना परिषद द्वारा वॉलंटरी टेक्नीकल कोर में शामिल होने के आह्वान से प्रभावित हो कर तिरुवनंतपुरम में हाल में करीब 200 सेवानिवृत्त विशेषज्ञों ने बैठक की थी। उनमें इजीनियर, डॉक्टर, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के प्रोफेसर, तकनीशियन, बीडीओ, सैनिक, नक्शानवीस, वैज्ञानिक आदि कई सेवानिवृत्त विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक में आम सहमति यह बनी कि इस क्रांतिकारी व्यवस्था के जरिये पंचायतों के लिए तकनीकी, वित्तीय तथा सामाजिक दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाएँ बनाने में इतनी बड़ी सख्या में जमा विशेषज्ञों से मुफ्त तकनीकी सलाह लेने में सहायता मिलेगी। पचायत क्षेत्रा में स्वास्थ्य निरोधक कायक्रमा का लागू करने म सेवानिवृत्त डाक्टर ओर स्वास्थ्य कार्यकर्ता काफी बडी भूमिका निभा सकते हैं। वीटीसी के रूप में हुई इस पहल को पंचायतों और नगरपालिकाओ की परियोजनाओ एव योजनाओ के

क्रियान्ययन के समय भी जारी रखा जा सकता है। पंचायती राज के अंतर्गत विकास

योजनाओ एवं कार्यक्रमो मे सेवानिवृत्त व्यावसायिक विशेषज्ञो की भागीदारी के कई अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। भारत की आबादी मे वृद्धो (60 वर्ष से अधिक) का अनुपात धीरे-धीरे बढ

रहा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात 6.3 प्रतिशत था, जबकि 60 के दशक में यह 5.7 प्रतिशत था। केरल में यह अनुपात अप्रत्याशित रूप सं ज्यादा है। वर्ष 1961 में यह अनुपात जहाँ 5.8 प्रतिशत था, वहीं 1991 में बढ़ कर

8.10 प्रतिशत (देश में सबसे ज्यादा) एवं 1996 में और भी बढ़ कर 9.5 प्रतिशत हो गया था। शताब्दी के अंत तक इस अनुपात के 10.2 प्रतिशत तथा 2021 तक

कुल आबादी में वृद्धों का प्रतिशत बढ़ कर 16 प्रतिशत हो जाने के आसार हैं। केरल के गॉवो में अनुभव एवं योग्यता से भरपूर लोगो की भरमार है। इसका कारण शिक्षा

का ऊँचा स्तर, लबी जीवन अवधि तथा विदेशो अथवा राज्य से बाहर काम कर रहे लोगो में सेवानिवृत्ति के बाद बसने के लिए अपनी मातृभूमि में वापस लौटने की

प्रवृत्ति है। इसके बावजूद इनकी योग्यता का शायद धार्मिक संगठनो के अलावा कोड भी उपयोग नही कर रहा। पचायती राज संस्थाओं को सुदृढ करने के लिए मानव

ससाधन की इस विराट सपदा के सदुपयोग की यह सचमुच नयी शुरुआत है। इसका एक अर्थ स्थानीय प्रशासन के दक्ष संचालन मे नागरिक समाज द्वारा

सहायता किया जाना भी है। जनता एवं नागरिक समूहों के बड़े पैमाने पर शामिल होने अथवा उनके समर्थन के बिना न तो पंचायतें और न ही नगरपालिकाएँ स्वशासन की सस्थाएँ बन सकती हैं। विकास मे जनता की भागीदारी एस.के. दे सामुदायिक विकास के समय से ही महत्वपूर्ण जुमला बना हुआ है, लेकिन आज तक यह सपना

साकार नहीं हो पाया। केरल का यह अभिनव प्रयोग अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण है। पचायत कार्यक्रमों के तकनीकी पहलुओं में तकनीकी पकड़वालें लोगों को

शामिल करने से इन स्थानीय निकायों के काम-काज में सिक्रिय खप से भाग लेने के लिए समाज के दूसरे लोगों को भी आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छे शासन की यह पक्की राह है। इस प्रकार वॉलटरी टेक्नीकल कोर के सुधी-प्रबुद्ध लोगों, विशेषज्ञों

यह पक्की राह है। इस प्रकार वॉलटरी टेक्नीकल कोर के सुधी-प्रबुद्ध लोगी, विशेषज्ञी तथा नागरिकों का एक अनूठा अभियान बन जाने की खासी अच्छी सभावना है। केरल मे यह सब राज्य योजना परिपद तथा सत्तारूढ़ दला द्वारा शुरू से ही

नीचे से ऊपर की ओर नियोजन को पूरी गंभीरता से अपनाय जाने के कारण सभव हो पाया है। इससे लोगों के लिए योजना भवन अथवा राज्य योजना परिपदों द्वारा

पचायतों के लिए स्वयसेवक : 125

योजनाएँ तैयार किये जाने के रिवाज से अलग हट कर नियोजन के नये अध्याय की शुरुआत हुई है। इस नयी पहल से लोगों मे अपनी पंचायतो तथा नगरपालिकाओं से खुद योजनाएँ वनाने की क्षमता पैदा हुई है। अब राज्य के सरकारी नियोजकों को सिर्फ उन पर विचार करके उन्हें स्वीकृति देनी होती है। अधिकारियों द्वारा बनायों गयों योजनाओं तथा जनता द्वारा तैयार योजनाओं में आज जबरदस्त अंतर परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए केरल में पहले योजना राशि में से सबसे ज्यादा पैसा लोक निर्माण तथा प्रशासन पर खर्च होता था। आज जनता द्वारा तैयार योजना में सबसे ज्यादा यानी 40 से 50 प्रतिशत राशि कृषि एवं उत्पादन क्षेत्रों, 30 प्रतिशत तेवा क्षेत्र तथा बाकी 30 प्रतिशत सडको एवं प्राथमिक सेवाओं के लिए मॉगी जा रही है। इसके साथ ही स्वैच्छिक योगदान एवं श्रमदान के रूप में गाँवों में योजनाओं के लिए काफी हद तक ससाधन भी खुद ही जुटाये जा रहे है। लेकिन दुर्भाग्य से केरल में पंचायतों द्वारा तैयार परियोजनाओं की आर्थिक संभाव्यता के प्रति बैकों द्वारा 45 16 के नीचे ऋण वसूली अनुपात के कारण (दिसंबर 1996 में केरल में बैको जमा राशि 21,340 करोड़ रुपये थी, जबिक बैको ने ऋण कुल 9,636 करोड़ रुपये का ही दिया हुआ था) उपेक्षा का रुख अपनाया जा रहा है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह है: यदि केरल यह कर सकता है, तो अन्य राज्य क्यों नहीं कर सकते? यदि पंचायतों को निर्धारित अधिकारों के साथ उनका मुनासिब संवैधानिक दर्जा दे दिया जाये और दूरदृष्टि-सपन्न लोग हाथ बॅटाने को आगे आयें तो यह जरूर हो सकता है। केरल के इस प्रयोग का असर अन्य राज्यों में भी फैलना चाहिए और पंचायतों में स्वयंसेवी समूहो की भागीदारी बड़े पैमाने पर बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य से ज्यादातर राज्यों में पचायतों का गठन, उन्हे गाँवों मे परिवर्तन अथवा लोगों के जीवन की गुणवना सुधारने या लोकतात्रिक आधार को सुदृढ करने का औजार बनाने के बजाय, महज 73वें सविधान संशोधन की इंबारत पर अमल करने के लिए किया गया है। इसके लिए सभी राज्यों में जनहित की भावनावाले नागरिको, अधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को आगे आ कर अभिनव कार्यक्रमों के जरिये पचायतो तथा नगरपालिकाओं को आवश्यक आधार देने की आवश्यकता है।

मानवाधिकारों के रू-ब-रू

भारत ने प्राचीन काल से ही स्थानीय मसलों के समाज-आधारित प्रबंधन के लिए अनेक पद्धतियों का विकास किया था। देश के अधिकांश हिस्सों में इन सस्याओं को 'पचायत' के रूप में जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है—पाँच व्यक्तियों

की परिषद । इनका काम कृषि चरण के दौरान अन्य देशो में विकसित स्थानीय शासन की तरह था—चाहे वह रूसी 'मीर' हो, जर्मन 'मार्क' हो या इंग्लैंड का मध्यकालीन

'मेनॉर'। भारत के अधिकाश भागों में पचायत व्यवस्था युगों से चली आ रही जाति व्यवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार पर आधारित थी। भारत में ब्रिटिश शासन

के दौरान उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा पहले शहरी क्षेत्र में और बाद में गाँवों में लागू की गयी। तब से स्थानीय स्वशासन निकायो

को भारतीय सविधान का अग बनने में सौ साल से भी अधिक का समय लग गया। इन निकायों को 'पचायत' कहा गया, लेकिन अब ये नये सास्तत्व के साथ लोकतांत्रिक

सस्थाएँ हैं। 90 के शुरू में पचायतों की नयी पीढी के आने के साथ ही व्यापक रूप से ऐसा माना जाने लगा है कि इससे विकेदीकरण, विकास, सामाजिक न्याय,

जन सहभागिता और जमीनी लोकतंत्र की संभावनाओं के द्वार खुल गये है। प्रश्न यह है कि विकेद्रीकरण का नया दौर भास्त में मानवाधिकारों की स्थिति को किस

तरह प्रभावित करता है?

मानवाधिकार एक व्यापक विचार और अवधारणा है, जिसकी जड़े पश्चिमी राजनीतिक चितन में हैं। ऐसे कई चार्टर और समझौते है, जिन पर सरकारो ने अपन-अपने देश में नागरिको के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दस्तखत किये हैं।

मानवधिकारों की वैश्विक घोषणा के मुताबिक, मानवधिकारों में नागरिक ओर राजनीतिक दोनों ही अधिकार (अनुच्छेद 1 से 21) तथा आर्थिक, सामाजिक ओर साम्कृतिक अशिकार (अनुच्छेद 22 से 28) समाहित है। असल में यह वैश्विक घोषणा

सास्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 22 से 28) समाहित है। असल में, यह वैश्विक घोपणा युद्ध के तुरत बाद मानवाधिकारों को ले कर वनी सहमति को प्रदर्शित करती हे, जो राष्ट्रपति रुजवेल्ट की 'चार स्वतत्रताओं' सबधी व्याख्या पर आधारित थी। इनम् अभाव से स्वतत्रता भी शामिल थी। रूजवेल्ट इन्हें अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र में शामिल करना चाहते थे। मानवाधिकारो पर 1993 में वियेना में हुए दूसरे राष्ट्र सघ सम्मेलन में एक व्यापकतर सहमति बनी थी, जहाँ विकास के अधिकार को सार्वभौमिक और अविच्छंद्य अधिकार तथा मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना गया। के लेकिन कुछ समय के लिए भारतीय राज्यों के चरित्र पर इनका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पडा।

भारत में मानवाधिकारों का अध्ययन तीन स्तरों पर किया जाना चाहिए—पहला, शासन द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, दूसरा, लोगों के अधिकारों पर आधात करनेवाले सामाजिक-आर्थिक कारण; और तीसरा, जीविका तथा बेहतर जीवन स्तर के अधिकार की अवहेलना से बड़ी सख्या में लोगों का अनादर तथा उनकी प्रतिष्ठा में कमी। एक से ज्यादा अर्थों में भारत में ग्राम पचायतों का यह नया चरण है, जिसमें मानवाधिकार के प्रश्नों को उपर्युक्त तीनों स्तरों पर एक से ज्यादा अर्थों में उठाया गया है। इस अध्ययन में उपलब्ध आँकड़ों तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विकेदीकरण एव पंचायन अध्ययन के विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करने की कोशिश की गयी है।

1992 के संविधान संशोधन का महत्व

यद्यपि गाँव तथा उनकी स्वशासन प्रणाली महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गये भारतीय स्वतंत्रता सग्राम के केंद्र मे थी, लेकिन जब स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा गया तो उसके मुख्य भाग मे इन्हें जगह नहीं मिली—सिर्फ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इनकी चर्चा भर की गयी। इसिलए राज्यों ने शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को गंभीरता से नहीं लिया। भारतीय शासन सिर्फ दो स्तरों पर संघीय शासन के रूप में काम कर रहा था—संघ और राज्य। कई साल बाद यह महसूस किया गया कि स्थानीय समुदायों को गंभीरता से लिए बिना और उन्हें शिक्तशाली बनाये बिना न तो लोगों का विकास हो सकता है और न ही उनका शासन संभव है। नागरिक समाज संगठनों, बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील राजनेताओं के प्रयासों से संसद ने 22 और 23 दिसबर 1992 को दो सविधान संशोधन—ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायत) के लिए 73वाँ संविधान संशोधन और शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका) के लिए 74वाँ संविधान संशोधन—पारित कर इन्हें 'स्वशासन की संस्थाएँ' बना दिया। एक साल के भीतर सभी राज्यों ने संशोधित सवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल अपने-अपने कान्न पारित कर दिये।

संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये इन सवैधानिक कदमों के परिणामस्वरूप भारत 'बहुस्तरीय संघवाद' की ओर अग्रसर हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इससे

128 : भारत में पंचायती राज

भारतीय राजनीति के लोकतात्रिक आधार का विस्तान हुआ। हान स्थायना स पहल, भारत का लोकतात्रिक ढाँचा निर्वाचित प्रतिनिधियों के ^{गृत्ये} संसद के वा सदना, 25 राज्य विधान सभाओं और दो सघ-शासित क्षेत्रो किनी ओर पाडिचेंगी तक ही सीमित था। इनमें सिर्फ 4963 निर्वाचित प्रतिनिधि ^{है।} अब ग्रामीण भारत मे लगभग 600 जिला पंचायतें, 6000 ब्लॉक पंचायते तथा रे⁵⁰ 000 ग्राम पन्त्रयनें है. जहाँ भारत की 72.2 फीसदी आवादी रहती है। शहरी ^{भार}न में 96 नगर निराम, 1700 नगरपालिकाएँ और 1900 नगर पचायतें है तथा भारत की 27.8 प्रतिशह जनसंख्या यहाँ रहती है। आज हर पाँच साल पर लोग लाकि मिनिक प्रक्रिया के नाम करीब 34 लाख स्थानीय प्रतिनिधि चुनते है, जिनमें क^{ीव} 10 लाख महिलाएं है। लगभग 175 जिला पंचायतो, 2000 से अधिक ब्लॉक पंचायती और लगभग 85,000 ग्राम पचायतों का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। इसके अनावा, महिलाए 30 नगर निगमो और करीब 600 नगरपालिकाओं की अध्यक्ष है। बैंबित समुहो और समुदानी को एक बड़ी सख्या अब इन फैसला लेनेवाली संस्थाओं में आमिल है। भारत की कुल आवादी मे 14.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 8 प्रतिशन जनगानिया है नथा लगभग 6,60,000 निर्वाचित सदस्य इन्ही जातियों का प्रतिनिधिन्ध करने हैं। यह सरना ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों की कुल संख्या का १२.5 प्रतिशत है।

नयी स्थानीय सरकारों के मुख्य लक्षण

स्थानीय शासन के संस्थानों को जरूरी यद और प्रतिष्ठा देने के निए मी स्थान में कुछ बुनियादी और जरूरी प्रावधान किये गये। उनमें नियमित युनाय, अनुस्थित जानियों और जनजातियों, महिलाओं जैसे समाज के कमजोर वर्गों को प्रातनिविच्य तथा इन सस्थानों को मजबूत बनाने के लिए सत्ता और वित्तीय ससाध्या की नियमित एवं निश्चित उपलब्धता शामिल है। इस नयी व्यवस्था के मुख्य लक्षण है। प्रत्यक्त गांच या गाँवों के समूह के लिए एक 'ग्राम सभा' का प्रावधान, जिन्ममें सभी व्यवस्क्री की मतदाता के रूप में शामिल किया जायेगा, कुल सीटो तथा अप्यक्ष पदी हा एक्तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। अनुस्योचन नानियों आए जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटो और अध्यक्ष गरी का अस्प्राप्य होना चाहिए (इनमें एक-तिहाई स्थान इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आर्थाप होना चाहिए (इनमें एक-तिहाई स्थान इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आर्थाप होगा।); पिछडे वर्गों के हित में सीटों और अध्यक्ष पदी के आर्थाप में निग साथ होगा।); पिछडे वर्गों के हित में सीटों और अध्यक्ष पदी के आर्थाप में निग साथ होगा।) को स्वतंत्रता, 11वी अनुसूची में वर्गित विषयों में आंथेक विकास विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के निर्माण के लिए विकास निर्माण कर निर्माण के लिए विकास निर्माण और राज्य निर्माण आर्थ साधानों और चुनावों के लिए कमज गण्य विन आयोगों आर राज्य निर्माण आयोगों का गठन। पंचायत का कार्य काल पाँच साल का होना है।

नयी पीढी की पंचायतों द्वारा कार्य प्रारभ किये जाने के बाद ऐसे अनेक महे सामने आये है जिनका संबंध मानवाधिकारों से है। पचायती व्यवस्था के रू-ब-रू मानवाधिकारो की स्थिति के महत्वपूर्ण कारक के रूप में निर्णायक योगदान भारतीय समाज की प्रकृति का है, जो स्वभाविक रूप से राज्य के स्वरूप को भी तय करनी है। भारतीय समाज अपनी विषमता, सामाजिक पदानुक्रम तथा अमीर एव गरीब मे भेद के लिए जाना जाता है। सामाजिक पदानुक्रम जाति व्यवस्था का ही परिणाम है, जो भारत के वाहर कहीं नहीं पायी जाती। इस प्रकार जाति एवं वर्ग दो कारक हैं जो इस सदर्भ में ध्यान आकर्षित करते है। एक अन्य स्तर पर इन सवालों को देखना जरूरी हे कि सामाजिक व्यवस्था के शिकार कौन लोग हैं? राज्य की प्रकृति एवं चरित्र के शिकार कौन है? ये लोग हैं पहले के अछ्त (ये अब अपने को दलित कहते है, जिसका अर्थ है 'दबाया गया'), जनजातियाँ, स्त्रियाँ एव गरीब। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गयी स्थानीय संस्थाओं को मजबूत कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार मानवाधिकार के उपर्युक्त सवालों को हल करेगी? क्या विकेदीकरण की प्रक्रिया एव विकेंद्रीकृत संस्थाएँ मानवाधिकारों के उल्लंघन में वृद्धि करेंगी या मानवाधिकारों के पालन एव सम्मान की सभावनाओं को बढायेंगी? इस परचे मे प्रथमतः सामाजिक कारको एव हाशिये पर स्थित लोगों के जीवन यापन के अधिकार की उपेक्षा की और अततः राज्य की प्रतिक्रिया की जॉब की गयी है। भारत की विशेष स्थिति मे जाति एवं वर्ग, इन दो कारको को विशेष रूप से चर्चा के लिए चुना गया है। परचे का उपसहार विकेंद्रीकरण के सदर्भ मे मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण से हुआ है। इसके साथ ही इस पर भी विचार किया गया है कि भविष्य का स्वरूप क्या हो सकता है।

जाति

जाति भारत की एक सामाजिक घटना है, जिसे परिभाषित करना असाधारण रूप से कठिन है, क्योंकि इसकी प्रकृति में भिन्नता पायी जाती है। गॉवों में जाति व्यवस्था की जड़े गहरी हैं एवं जीवन इससे व्यापक रूप से प्रभावित है, क्योंकि जाति की जड़ें धार्मिक व्यवस्था में हैं एव इसे आनुवाशिक पदानुक्रम, जाति-सीमित वैवाहिक सबध एवं पेशागत समूहों, जिनके स्थान निश्चित है एव जिनकी गतिशीलता विभिन्न जातियों के बीच अनुपालित धार्मिक क्रियाओं के अतर द्वारा बाधित रहती है, के पदानुक्रम के रूप में भी समझा जाता है। उन इस परचे के लिए हम जाति व्यवस्था पर इमोन्ट द्वारा विकसित दृष्टिकोण को अपनायेंगे। इमोन्ट जाति को हिंदुत्व से आंतरिक रूप से संवद्ध मानते हैं। उनके अनुसार यह हिन्द संदर्भ के बिना अकल्पनीय

शिक्षा से भी वंचित करती है। यह प्राचीन परपरा युगों से चलती आ रही है एव इसका प्रामीण लोगो के जीवन पर आज भी बहुत असर है। निम्न जाित के लोगों को उच्च जाितयों की रिहायश से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता है—अधिकांशत. गाँवों के सीमात पर। कई बार उन्हें मतािधकार से वंचित रखा जाता है एवं उन्हें बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना पडता है; उनके साथ बॅधुआ मजदूर की तरह व्यवहार होता है। व इस प्रकार कोई भी यह देख सकता है कि एक तरफ युगों पुरानी जाित व्यवस्था है जिसका आज भी अपमानजनक रूप में अनुपालन होता है एवं दूसरी ओर भारतीय सविधान है जो लोकताित्रक सिद्धातों के अनुसार कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। मानवािधकार कार्यकर्ता एवं विद्यान, रामेंद्र मानते हैं कि यथार्थ इन दोनों अतिवादों के बीच कही स्थित है एव इस बात की पुष्टि करते हैं कि समाज में मानवािधकारों के उल्लंबन का सबसे वडा स्रोत जाित व्यवस्था ही है।

हे, जिससे इसकी समझ के लिए वैचारिक आधार प्राप्त होता है। डूमोन्ट के लिए जाति स्थायी एवं शक्तिशाली सामाजिक व्यवस्था है जो एक मूल्य प्रणाली प्रस्तुत करती है, जो पदानुक्रम एवं धार्मिक रूप से स्वीकृत शुद्धता तथा अशुद्धता के विचार

जाति किस प्रकार मानवाधिकारों को प्रभावित करती है? मानवाधिकार कार्यकर्ता एव विद्वान आर.एम. पाल मानते हैं कि जाति व्यवस्था ने मानव समूहो के बीच दुर्गम दीवारे खडी कर दी है, जहाँ किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करनेवाला एकमात्र कारक जन्म है। इस सामाजिक स्थिति का तर्क यह है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही किसी खास जाति में जन्म लेता है। उनके दृष्टिकोण से भारत मे आज भी मानवाधिकारों के सामाजिक उल्लंघन का निकृष्टतम रूप जाति व्यवस्था ही है। पाल का तर्क है कि 'मनुस्मृति' नामक ग्रथ, जहाँ से जाति व्यवस्था की जड़ें निकलती हैं, भारतीय परपरा का सर्वाधिक विकृत रूप है। इस ग्रथ के अनुसार, समाज मे स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के अधीन ही रहनी चाहिए। इससे भी अधिक, जाति व्यवस्था निम्न जातियों एव स्त्रियों को प्राथमिक

पर आधारित है।"

जाित व्यवस्था है जिसका आज भी अपमानजनक रूप में अनुपालन होता है एवं दूसरी ओर भारतीय सविधान है जो लोकताित्रक सिद्धातों के अनुसार कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। मानवािधकार कार्यकर्ता एवं विद्धान, रामेंद्र मानते हैं कि यथार्थ इन दोनों अतिवादों के बीच कही स्थित है एव इस बात की पुष्टि करते है कि समाज में मानवािधकारों के उल्लंधन का सबसे वडा स्रोत जाित व्यवस्था ही है। अज जब से सविधानिक संशोधनों द्धारा स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूती मिली है, स्थानीय समुदायों में जाितवाद की उग्र अभिव्यक्ति में तीव्र वृद्धि हुई है। जब उच्च जाितयों ने पचायती राज्य सस्थाओं को उस औजार के रूप में देखा जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक राज्य तंत्र में रह रहे निम्न जाितयों के लोगों द्धारा व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों का दावा किया जाता है तो ये लोग जाितगत भेदभाव एवं हिसा का निशाना बनने लगे। स्थानीय स्तर पर यह बढती हुई अशाित सामान्य पटना हो गयी है।

यह प्रकट ही है कि उच्च वर्ग जो अब तक गाँव एव समाज के मामलों एव

जा रहे बदलावों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसी कारण पंचायती व्यवस्था के क्रियान्यवन की शुरुआत से ही बदलाव को रोकने के लिए तनाव, हिंसा एव हत्याएँ होने लगी।

स्थानीय शासन निकायों के चुनाव जातिवादी समूहों के वार के पहले एवं सबसे महत्वपूर्ण निशाने रहे है। नयी व्यवस्था के अंतर्गत हुए पहले चुनाव से ही निम्न जातिया द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया मे भागीदारी एवं पद ग्रहण करने पर उच्च जातियो द्वारा सवाल उठाया जाता रहा है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण भारत के एक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के मद्रै जिले के एक गाँव मेलावलाव् का है। मेलावलाव् मे इस क्षेत्र के प्रभावी जातियों के लोगों ने नीची जातियों के दो लोगों, पचायत अध्यक्ष एवं पचायत उपाध्यक्ष, की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया था। अक्टूबर 1996 के स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए जब मेलावलाव को नीची जातियों के लिए सुरक्षित पचायत घोषित किया गया तो ऊँची जातियों ने इसका विरोध किया; परिणामस्वरूप चुनाव नहीं हो सके। चुनाव कराने का दूसरा प्रयास भी हिंसा एवं ब्रथ-कब्जे के कारण विफल हो गया। आखिरकार जब 30 दिसंबर 1996 को चुनाव हुए, तो ऊँची जातियों ने उसका बहिष्कार किया। उनके विरोध के बावजूद नीची जातियों के सदस्य पचायत के अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन ऊँची जातियों ने उन्हें कभी भी नये पचायत कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अनतः 30 जून 1997 को अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष की अन्य तीन व्यक्तियों के साथ दिन-दिहाडे हत्या कर दी गयी। उनका एकमात्र अपराध यही था कि वे लोकतात्रिक प्रक्रिया से चुने गये थे।16

इस प्रकार के उल्लंघन आज भी निर्बाध रूप से जारी हैं। इसी राज्य में हाल ही में हुए स्थानीय निकायों के चुनावो में देखा गया कि ऊँची जातियाँ अब भी नीची जातियों के मताधिकार को दबा रही हैं। अधिकांश राज्यों में इसी प्रकार की घटनाएँ हुई हैं। उत्तरी राज्यों में, जो जातीय सघर्षों की ओर बढ रहे है, नये चरण की पचायतों की शुरुआत के बाद मानवाधिकार उल्लंघन की अनेक घटनाएँ देखी गयी है। ऐसे अनेक उदाहरण हे, जिनसे पता चलता है कि शक्तिशाली जातियों का उच्च वर्ग गाँवों में सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रयासों को लगातार विफल कर रहा है। है। जीची जातियों के पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों की हत्याओं की लगातार रिपोर्ट केवल पिछडे राज्यों तक सीमित नहीं है, जहाँ सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया निचले स्तर पर शुरू ही नहीं हो पायी है। जातीय हिंसा अन्य राज्यों में भी सामाजिक यथार्थ का हिस्सा है—पश्चिम बगाल, त्रिपुरा एवं केरल के अलावा, जहाँ राजनीतिक जागरूकता अधिक है।

विहार में संपन्न हुए पिछले पचायत चुनावों मे एक मजिस्ट्रेट एवं अनेक उम्मीदवारो सहित 96 से अधिक व्यक्ति मतदान के दौरान मारे गये एव विभिन्न जिला में 40 स अधिक उम्मीदवार चुनावा का अधिसूचना जारी होने एव नामाकन दाखिल करने के बीच मारे गये। अध्ययन बताते हैं कि इनमे से अधिकांश हत्याएँ

जाति युद्ध के कारण हुई।¹⁹

विधि-सम्मत रूप से चुने जाने के बावजूद निचली जातियाँ वह उचित अधिकार एव दर्जा नहीं प्राप्त कर पा रही है, जिसकी वे अधिकारी है। उन्हें पचायत कार्यालय

के वाहर जमीन पर बिठाया जाता है जब कि गाँव के परंपरागत प्रभुत्वशाली व्यक्ति कुर्सी पर बैठते हैं। यहाँ तक कि जब निचली जातियों पर ऊँची जातियों के समूह

अत्याचार करते हैं, जो न्याय दिलाने का कोई ऐसा तंत्र नहीं होता जो उनकी सहायता कर सके। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पुलिस (कानून एव व्यवस्था की मशीनरी)

कर सके। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पुलिस (कानून एव व्यवस्था की मशीनरी) पचायतो के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राज्य सरकार एवं पुलिस की साँठ-गाँठ एव

पंचायता के जायजार क्षेत्र ते बाहर है। राज्य तरकार एवं जुलित की ताउँनाठ एवं साजिश के कारण निम्न जातियों के व्यक्तियों को निरतर अत्याचारों का शिकार बनाया जाता है। अनेक उदाहरणों में अत्याचारियों (जो ज्यादातर उच्च जातियों के होते हैं)

के विरुद्ध मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि पुलिस पर उच्च जातियों का

प्रभाव एवं नियत्रण होता है। 20 इसी कारण 1997 के कामराजनगर जिले के राजापालयम क्षेत्र में हुए जातीय दंगों पर तमिलनाडु के लेखकों एवं विद्वानों के समूह द्वारा प्रस्तुत

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राजस्व एव पुलिस विभाग के अधिकारियों के

विभिन्न स्तरों पर कम से कम एक-तिहाई अधिकारी प्रभावित वर्गो के हो। विकेंद्रीकरण का नया दौर अब भी जातीय तनावों से जूझ रहा है, जो ग्रामीण

क्षेत्रों में वीभत्स ढंग से मौजूद है। निचली जातियों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों एवं मानवाधिकार हनन को आदमी और आदमी के बीच बराबरी की तंस्कृति विकसित करके ही नियंत्रित किया जा सकता है। इस संस्कृति का विकास मानवाधिकारों की शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन द्वारा किया जा सकता है। इसमें पंचायतों की महत्वपूर्ण

भूमिका होगी। आर्थिक कारक

गरीबी मानव अस्मिता का हनन एवं लोप है।²¹ भारत मे लगभग तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे दयनीय स्थितियों मे घोर अभाव का जीवन जीते है। भारत मे व्यापक तौर पर उपस्थित गरीबी भारतीय संविधान मे वर्णित एकजुटता, सामाजिक

न्याय एव समानता के उद्देश्यों के ठीक विपरीत है। ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं के होने के बावजूद वर्षों से गरीबी के स्तर में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार 26.1 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी

रेखा के नीचे रहते हैं—ग्रामीण क्षेत्रों मे 27.1 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों मे 23.6 प्रतिशत लोग। ग्रामीण आबादी का लगभग आधा हिस्सा (50.56 प्रतिशत) अब भी निरक्षर है। ग्रामीण स्त्रियों में निरक्षरता की दर 60 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की

मानवाधिकारों के रू-ब-रू : 133

स्त्रियों में साक्षरता की दर 24 प्रतिशत है, जो स्त्रियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 45.72 प्रतिशत (जनगणना 2001) से काफी कम है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर स्थिति और भी खराब है। नवजात मृत्यु दर 63.19 प्रति हजार है, जब कि 5 वर्ष से कम की शिशु मृत्यु दर 98 प्रति हजार है। 53 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं। स्वच्छता हासिल कर सकनेवालों की जनसंख्या कंवल 31 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक से पाँच वर्ष के आधे से अधिक बच्चे कुपोषित होते है एवं 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है।

एलन.जी. स्मिथ के अनुसार, 'ग्रामीण गरीब गाँव स्तर पर चयन के कानूनो का कष्ट भोगते हैं। जहाँ न्यूनतम भोजन या स्वास्थ्य हासिल करना अनिश्चित है. वहाँ जरूरी चयन से भी वंचित रहना पड़ता है। लेकिन यह समेकित मानवाधिकारो के निर्धारण के मुद्दों में शामिल नहीं है। 22 यह किसी भी अन्य लोकतात्रिक देश की तुलना में भारत के संदर्भ में ज्यादा सही है, यद्यपि भारत ने 1950 में लोकतात्रिक उद्देश्यो की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम 'सामाजिक अवसरों की विस्तृत श्रेणियो को बढावा देने की आवश्यकता²³ के अनुसार कार्य करने के लक्ष्य के साथ-साथ उठाया था। अमर्त्य सेन और जॉन ड्रेज के अनुसार, वास्तव में 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कड़े कानूनों के पूरक हैं, कानूनी प्रावधानों से कहीं आगे बढ़ जाते है। उदाहरण के लिए वे राज्य से कहते हैं कि वह 'जनता के कल्याण को बढ़ावा देनेवाली सामाजिक व्यवस्था हासिल' करे। इसके साथ ही, वे और भी अधिक स्पष्ट अधिकारी की श्रेणियों को भी मान्य करते है-'जीवन यापन के पर्याप्त साधनों का अधिकार' एव 'मुफ्त कानूनी सहायता' से 'सभी बच्चो के लिए मुफ्त एव अनिवार्य शिक्षा' एव 'काम का अधिकार' तक। 24 स्थानीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य संवैधानिक प्रावधानों एवं आर्थिक यथार्थ के बीच के अंतर को पाटना था। लेकिन इस दिशा मे प्रगति की रफ्तार तेज नहीं है।

नयी पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के शुरुआती वर्षी में ही भारत में गरीब हिसा एव शोषण का शिकार होने लगे। इसके अपवाद भी हैं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं केरल जैसे कुछ राज्यों मे गरीबी को मानवाधिकारों के मुद्दे के रूप में देखा जाने लगा एवं विकेंद्रीकरण की इसके उपचार के प्रभावी औजार के रूप में।

ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को प्रदत्त विषयों की सूची में शामिल 29 विषयों में से अधिकांश आर्थिक विकास से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए कृषि, भूमि उन्नयन, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, डेयरी, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु उद्योग, ग्रामीण भवन निर्माण, ईंधन एवं चारा, सड़के, जल परिवहन एवं फेरी, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी निवारण कार्यक्रम एवं अन्य ऐसे ही विषय।

भारतीय सदर्भ में मोटे तौर पर जाति का संबंध वर्ग से है। निम्न जातियाँ

134 : भारत में पचायती राज

एव जाति व्यवस्था से बहिष्कृत समूह अत्यत गरीब है चूिक निचले पायदानो पर सामाजिक एवं आर्थिक कारक सामुदायिक जीवन के साथ घुले-मिले होते हैं, उन्हे अपने अधिकारो पर चौतरफा वार झेलना पड़ता है।

अपन आवकारा पर पातरका पार जालना पड़ता है। यह अब सर्वविदित है कि स्थानीय शासन द्वारा सचालित कार्यक्रम एवं विकास के उपादान गरीबों तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि धनी एवं शक्तिशाली व्यक्ति उनका

अधिकांश हिस्सा हथिया लेते हैं। विकेंद्रीकृत संस्थाओं में भ्रष्टाचार ने सामाजिक सगठनों एवं राज्य का ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि जॉच एवं संतुलन की एक

पद्धित एवं सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था मौजूद है, फिर भी धनी लोग लाभ हथिया लेते हैं एवं गरीब जस के तस रह जाते हैं। हालाँकि उच्च स्तरो पर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है. लेकिन जो निचले स्तरो पर होता है, उसका सीधा असर गरीबो एवं उनकी

जीविका पर पड़ता है। उदाहरण के लिए पंचायतों के अध्यक्षों को विकास निधि में गडवडी के लिए दंड देना (आंध्र प्रदेश), विभिन्न विकास कार्यक्रमों (कृषि क्षेत्र में)

के मद में अधिक व्यय दशनिवाले अधिकारियों को सजा, क्योंकि चयनित लाभार्थियों को राशि प्राप्त ही नही हुई (असम), आर्थिक गड़बडियों के लिए अध्यक्ष का निलंबन,

को राशि प्राप्त ही नहीं हुई (असम), आर्थिक गड़बर्डियों के लिए अध्यक्ष का निलंबन, क्योंकि बिना सही तरीका अपनाये खरीद पर भारी खर्च किया गया (हरियाणा), नागरिक निकायों में निर्माण के ठेके देने में घूसखोरी का मामला (कर्नाटक) आदि सन 2001

मे रिपोर्ट किये गये मामलों में से हैं। 25 विकसित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में किये गये क्षेत्र सर्वेक्षण दिखाते हैं कि गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास हेतु आवटित धन का बड़ा हिस्सा अधिकारियों एवं शक्तिशाली राजनेताओं ने हड़प लिया। 26 इस

तरह गरीब वैसे ही रह गये जैसे वे पहले थे, बल्कि कुछ मामलों में तो उनकी स्थिति और भी बिगड़ गयी एव वे मानवाधिकारों के हनन के सहज शिकार बन गये।

दलित

पूर्व-उल्लिखित परंपरागत वर्ण व्यवस्था मे पाँचवीं श्रेणी अछूत या अत्यज की है। महात्मा गाधी ने उन्हें 'हरिजन' नाम दिया, जिसका अर्थ 'ईश्वर के लोग' होता है। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इस समूह के सदस्य अपने को 'दलित' कहना पसंद करते है, जिसका अर्थ होता है 'दबाया गया'। सवैधानिक रूप से उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त

हे तथा उन्हें 'अनुसूचित जातियों' के रूप में जाना जाता है।²⁷ संवैधानिक संशोधनों द्वारा हुए विकेंद्रीकरण के पश्चात भी वे वास्तव मे किसी भी अन्य समूह की तुलना मे अधिक दीन अवस्था मे है। भारतीय सविधान के निर्माता बी.आर. आंबेडकर,

जो स्वयं एक अछूत जाति के थे, ने कहा था कि गाँव भारत के विनाशक हैं, क्योंकि वे अज्ञान, साप्रदायिकता एव भ्रष्टाचार के गढ़ हैं। उन्होंने पचास वर्ष पूर्व जो कहा

था, वह आज भी सच है—नयी पंचायती व्यवस्था लागू होने के बावजूद। चुनावो के पश्चात, राज्यों की रिपोर्टे बताती हैं, कि स्थानीय निकायों के शक्तीकरण के पश्चात

मानवाधिकारों के रू-ब-रू : 135

भी दलितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन अनेक तरीकों से हुआ है। गाँव स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने अनेक मामलों में भागीदारी करनेवालों को शक्ति एवं बल प्रदान नहीं किया है—मुख्यतः विचत जातियों को। मध्य प्रदेश में 1993 के चुनावों के पश्चात पुलिस द्वारा एक दलित पंचायत सदस्य की पिटाई के मामले के अध्ययन से पता चलता है कि घटना जिले के मुख्य कार्य अधिकारी के समक्ष हुई थी एवं घटना के बाद मानवाधिकार आयोग के पास मुकदमा दर्ज होने पर इस अधिकारी ने गाँव का दौरा किया। बताया जाता है कि उक्त अधिकारी ने लोगों से कहा कि वे दलित सदस्य के पक्ष में गवाही दें। लोग इस मुद्दे पर वोलने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें प्रशासन द्वारा सताये जाने का भय था। 28

दिलतों के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव दु स्वप्न की तरह थे। तिमलनाडु के कुछ जिलों की चार ग्राम पचायतों में, जो दिलतों के लिए आरक्षित थीं, चुनाव नहीं हो सके—क्योंकि उच्च जातियों द्वारा धमकी देने के कारण एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हो पाया। अनेक क्षेत्रों में दिलत उम्मीदवार अब भी भय में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभुत्वशाली जातियों की अवहेलना करते हुए ग्राम पचायतों के विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किया था। अनेक पचायतों में दिलत सदस्यों को वोट देने से रोका गया। उन्हें डराने के लिए बहुत-से घरों एव बस्तियों पर हमला किया गया।

यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि विकेद्रीकृत प्रणाली में भागीदारी द्वारा दिलतों एव उपेक्षितों का सशक्तीकरण इस केंद्रीय कानून के उद्देश्यों में से एक था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर इशारा करती है। यह देखा गया है कि हिंदू उच्च जातियों अनेक उपायो का सहारा ले कर वंचित लोगो, खासकर दिलतों, के सशक्तीकरण के प्रयासो को कमजोर या ध्वस्त करने का प्रयास करती हैं। ऐसे उदाहरण हैं कि ऊँची जातियों ने अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए किये गये आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी एवं यह प्रयास विफल होने पर चुनावो के बहिष्कार की घोषणा की। दिलतो को चुनाव लड़ने से रोकने या उन्हें किसी अन्य को समर्थन देने के लिए दबाव डालने के लिए हिंसा के अनेक मामले सामने आये है। अगर ये प्रयास भी विफल हो जाते हैं और चुनाव होना निश्चित हो जाता है, तो वे ऐसे उम्मीदवार खोजते हैं, जो प्रभुत्वशाली जातियों की इच्छा-आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी हों। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति प्रभुत्वशाली जातियों की मदद के बिना भी चुना गया, तो वे उस व्यक्ति से सहयोग नहीं करते। 29

सत्ता में आने के बाद भी निर्वाचित दलित प्रतिनिधि नेतृत्व क्षमता का प्रभावी उपयोग करने से वचित किये जाते है। यह घटना दलित स्त्री सदस्यों के साथ ज्यादा होती है, जिन्हे दुहरे दमन का शिकार होना पड़ता है। ऐसी घटनाएँ आम हैं जब स्त्री दलित सत्पच को पचायत की कार्यवाही के दौरान जमीन पर बैठना पड़ता है

एव ऊँची जातियों के सटस्य कुर्सी पर बैठते हैं। समस्या तब भी होती है जब ग्राम मचिव ऊँची जाति का होता है। सकारात्मक पक्ष यह देखा गया है कि दिलत सरपच या सदस्य की उपस्थिति के कारण ग्राम सभा की बैठकों में दिलतों की भागीदारी अधिक होती है। मोह भंग तब होता है, जब दिलत सरपचों को मजबूर किया जाता है कि वे ऊँची जातियों से सबंधित कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करे।

अनुसूचित जनजातियाँ,³⁰ या आदिवासी, जिनमे लगभग 400 प्राचीनतम समुदाय शामिल हैं, भारत के सुदूर एवं जंगली क्षेत्रों में रहते है। ये भारत की जनसंख्या का 7 8 प्रतिशत भाग हैं। 73वें सवैधानिक संशोधन की विशेषता यह है कि इसने जमीनी लोकतत्र को प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियो/जनजातियो एवं स्त्रियों जैसे

जनजातियाँ

वचित समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की है। पर 73वॉ संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों (वे भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ आदिवासी घने रूप से रहते हैं) में स्वतः लागू नहीं होता था क्योंकि इनकी विशिष्ट चारित्रिक विशेषताएँ एव विशेष जरूरतें होती है, अत

एक पूरक संवैधानिक संशोधन 1996 दिसबर मे लागू किया गया जिसका शीर्षक था—'पंचायत अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) के प्रावधान, 1996'। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों को भारतीय सविधान अनुख्डेद 244 एवं अनुसूची 5

एवं 6 के प्रावधानों के सदर्भ मे निर्दिप्ट किया गया है। यह विस्तार अधिनियम

वर्तमान समय में सबसे प्रभावी वैधानिक उपाय है, जो जनजातीय लोगों के जीने के तरीकों, आकाक्षाओं, उनकी संस्कृति एवं परपरा को स्वीकृति देता है। बहरहाल, विस्तार अधिनियम के क्रियान्यन एव प्रभाव को जॉचने के लिए किया गया अध्ययन, कि क्या जमीनी लोकतंत्र जनजातीय लोगों की भावनाओं के अनुरूप लागू हो पा

रहा है, यह बताता है कि इन क्षेत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उल्लेखनीय हो एवं जनजातीय लोगों की स्थिति कमोबेश पहले जैसी ही है। राज्यों के नेतृत्व की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर यह एक दु खद टिप्पणी हे कि अनेक राज्यों, जैसे राजस्थान, ने 1996 के संशोधन के अनुरूप अपने कानूनों

कि अनेक राज्यो, जैसे राजस्थान, ने 1996 के सशोधन के अनुरूप अपने कानूनों मे निर्धारित अवधि के बाद भी सुधार नहीं किया। राज्यों के कानूनों के एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्यों ने संवैधानिक निर्देशों का आधे-अधूरे मन से ही पालन का प्रयत्न किया, सच्ची भावना से नहीं।³² कुछ राज्यों के कानून विस्तार अधिनियम के महत्वपूर्ण

प्रावधानों को उचित ढंग से लागू नहीं करते, जैसे—लघु वन उत्पादो का स्वामित्व, भूमि हस्तातरण पर रोक, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण आदि। यह जनजातीय क्षेत्रों के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता दर्शाता है एवं जनजातियों को अधिकार प्रदान

करने के प्रति उनके प्रतिरोध को भी। दूसरी ओर, जनजातियों के अधिकारों का उल्लंधन

मानवाधिकारो के रू-ब-रू : 137

नियमित अंतराल पर होता रहता है। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2001 में एक जनजाति के लोगों ने, जो अपनी जीविका के लिए एक जलाशय पर निर्भर हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध आवाज उठायी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सरकार उनके उत्पाद बेचने के अधिकार को समाप्त कर रही है। 3 गुजरात में अधिक गंभीर उल्लंघन हुआ, जब सरकार ने ग्राम पंचायतों के चुनावों की घोषणा के केवल 48 घटे पूर्व जनजातियों को आरक्षण देने से मना कर दिया। 34

निर्वाचित जनजातीय पुरुषो एव स्त्रियो को स्वशासन के विकेद्रीकृत सस्थानों में कार्य करने नहीं दिया जाता। अनुसूचित जातियों के समान ही जनजातियों के लोग भी पंचायत नौकरशाही से अपेक्षित सम्मान नहीं पाते। जनजातियों के निर्वाचित स्त्री सदस्यों को अधिकारियो एव शक्तिशाली लोगों के अधिकारों को चुनौती देने की सजा हिसा एवं बलात्कार के रूप में मिलती है।

राजस्थान के एक जिले में एक जनजाति की स्त्री सरपच को 15 अगस्त 1998 (स्वतंत्रता दिवस) को राष्ट्रध्वज फहराने के कारण नंगा कर दिया गया। एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश की एक जनजाति की स्त्री सरपंच को एक उच्च जाति के नेता से सलाह नहीं लेने के जुर्म में ग्राम सभा की बैठक मे नगा कर दिया गया। 55 इस प्रकार के मानवाधिकार उल्लंधन की घटनाएँ भारतीय जनजातीय क्षेत्रों मे प्रतिदिन होती है—विकेद्रीकृत शासन के लिए शक्तिशाली कानूनों के होने के बावजूद।

स्त्रियॉ

जब भारत औपनिवेशिक शासन में था, तो कुछ खास शर्तो को पूरा करनेवाले व्यक्ति ही वोट दे सकते थे एवं चुनाव लड़ सकते थे और राजनीतिक दृश्य से स्त्रियाँ गायब थीं। उदाहरण के लिए बंबई ग्राम प्चायत कानून, 1920 में स्पष्ट कहा गया कि कोई भी स्त्री निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकती एवं प्रत्येक गाँव के वयस्क पुरुष निवासी सहायक या उप-कलक्टर की अध्यक्षता में सपन्न बैठक में चुनाव सपन्न कर सकेंगे। कि स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय संविधान में स्त्रियों के लिए विधान मंडलों एवं ससद में आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था या उल्लेख नहीं था। कि स्त्रियों को वैधानिक राजनीतिक संखाओं में प्रतिनिधित्व पाने में लगभग चालीस साल लग गये। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह सभव हुआ 73ये सवैधानिक संशोधन द्वारा, जिसमें स्थानीय निकायों की कुल सीटों का एक-तिहाई भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित करने की क्रांतिकारी व्यवस्था है। इस केंद्रीय कानून द्वारा महिलाओं को वह बहुप्रतिक्षित अवसर मिला जिससे वे राजनीतिक अधिकारों द्वारा अपने आसपास के समुदाय की निर्णय प्रक्रिया में सिक्रेय हिस्सेदारी कर सके। पंचायती राज के इस नये दौर में दस लाख से अधिक निर्वाचित स्त्री प्रतिनिधि पचायत के तीनो स्तरों के लिए चुनी जाती है और स्थानीय

समुदाय का प्रवक्ता बन कर राजनातिक प्रतिानधित्व का जमीनी अथ प्रदान करता

है।

सवैधानिक सशोधनो द्वारा स्त्रियों के राजनीतिक सशक्तीकरण के पिछले नौ वर्षों के अनुभवों ने अनेक मिथकों को तोड़ा है, जैसे वे राजनीतिक संस्थाओं के प्रति नकारात्मक एव उदासीन हैं, केवल सपन्न एव ऊपरी तबके की स्त्रियाँ ही आरक्षण

के माध्यम से सामने आयेगी; केवल शक्तिशाली राजनताओं की रिश्तेदार ही राजनीतिक सबद्धता के कारण पचायत चुनावों में आयेगी, ताकि उनके लिए सीट कायम रखी

जा सके; स्त्रियाँ नाम-मात्र की प्रतिनिधि सदस्य होती हैं एवं पंचायत के काम-काज मे भाग नहीं लेतीं। कुछ महिलाओं द्वारा ऐसा करने के बावजूद, जो पितृसत्तात्मक

ढाँचे का एक अनिवार्य परिणाम है, यह कहा जा सकता है कि ये मिथक अब ध्वस्त हो चुके हैं।³⁸ आज की बात यह है कि स्त्रियाँ कर सकती हैं।

यह व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि स्थानीय निकायों की सत्ता में हिस्सेदारी देने में एवं गॉवो के स्थानीय मामलों के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर स्त्रियो

की भागीदारी ने (कर्नाटक में यह भागीदारी 43 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है एव वह समय दूर नहीं जब स्त्रियाँ 50 प्रतिशत से अधिक सीटों पर कब्जा कर लेगी) इन निकायों के स्तर एवं अधिकारों में वृद्धि की है। अनेक राज्यों में स्त्री संगठनो के कार्यों द्वारा लैगिक समानता एवं स्त्रियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी

है—विशेषकर जहाँ मानवाधिकारों के प्रयासों ने समाज में स्त्रियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने को चुनौती की तरह स्वीकार की है।

यह भी साबित हो चुका है कि जहाँ भी स्थानीय निकायो में स्त्रियाँ पद धारण करती हैं, वहाँ सार्वजनिक मामलो के प्रबंधन में अधिक कुशलता एवं पारदर्शिता मिलती हे। कर्नाटक राज्य के मालगुडी जिले की ग्राम पंचायत अध्यक्ष गंगम्मा जयकर पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की उपज है। वे अनुसूचित जाति की हैं एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। वे शिक्षा के प्रसार में रुचि रखती थीं एवं गाँव में स्त्रियों के

लिए नाक्षरता की कक्षाएँ चलाती रही थीं। बालिकाओं की शिक्षा के बारे में सरकारी कार्यक्रम के बारे में सुन कर उन्होंने योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं जरूरी प्रक्रियाओं का पालन कर गाँव में एक स्कूल खुलवाया।³⁹ राज्य सरकारे और नागरिक सगठन अब पचायतों की विशिष्ट नेताओं के योगदान को मान्यता देने के लिए वार्षिक

पुरस्कारों की स्थापना कर रहे हैं।⁴⁰ महिलाओं की हैसियत बढने के साथ-साथ पुरुष-प्रधान पितृसत्तात्मक भारतीय समाज की ओर से गंभीर प्रतिरोध भी किया जा रहा है। निर्वाचित्र स्त्रियाँ शोयण,

हिसा एवं उत्पीड़न का शिकार हुई है। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद देश भर से उनके अधिकारों के हनन की कहानियाँ पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं। तमिलनाड़ के एक नगर निगम की स्त्री पार्षद का मामला ऐसा ही एक मुद्दा है। विल्लापुरम के लांगा का स्थायी जलापूर्ति की सुविधा नहा था एवं ये निगम के टकरो द्वारा लाय जानेवाले पानी पर निर्भर थे। यह पानी स्थानीय गुंडो द्वारा पैसे ले कर लोगो को बेचा जाता था। एक स्थानीय जल स्रोत से पाइपो द्वारा जलापूर्ति के प्रयास को माफिया तत्वों ने विफल कर दिया, क्योंकि उन्हे पहले की व्यवस्था से अधिक फायदा था। लीलावती ने अपने चुनाव प्रचार में केवल एक मुद्दे, अपने चुनाव क्षेत्र में पीने का पानी लाने को, ले कर प्रचार किया। उनके अनथक प्रयास से स्थानीय नौकरशाही पर दबाव वना एव प्रयास सफल हुआ। लेकिन परीक्षा आपूर्ति के तीन दिनों बाद, सशस्त्र लोगों ने दिन-दिहाडे उनकी हत्या कर दी। लीलावती पानी के लिए लोगों के सवर्ष का प्रतीक बन गयी।

प्रारभ में स्त्रियाँ इस नये राजनीतिक दृश्य मे प्रवेश करने से हिचकती थी। राजनीतिक दलों एवं निहित स्वार्थी तत्वो ने इस स्थिति का लाभ उठाया एव उनका परोक्ष शासन चलने लगा। इस प्रकार सत्ता परंपरागत शक्तिशाली समूहों के पाम ही रही। स्त्री सरपचों के पितयों का नया वर्ग सामने आया, जो पचायत के मसलों को सभालता था एवं पित्नयाँ रबर स्टैम्प का कार्य करती थीं। कर्नाटक राज्य का एक अध्ययन दर्शाता है कि स्थानीय निकायों या पचायतों के लिए निर्वाचित स्त्रियों में से अनेक अपने पिता या पित का स्थानापन्न थी, क्योंकि आरक्षण के कारण वे चुनाव नहीं लड सके। कुछ को धनी एवं शक्तिशाली लोगों ने स्थान दिलवाया—क्योंकि उन्हें अपनी जरूरत के मुताविक झुकाया जा सकता था, तािक वे रहें तो निर्वाचित प्रतिनिधि, पर एक गुडिया की तरह उनके हितों की पूर्ति कर सकें। 42

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक मुख्य चिता चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के नियम का, विशेषकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एव हिमाचल प्रदेश में जहाँ यह लागू किया जा चुका है, चुनाव लड़ने की अनिवार्य अर्हता के रूप होना है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण भारत में जल्दी बच्चे पैदा करने का चलन है, जिसके परिणामस्वरूप पुनरुत्पादन दर भी अधिक है। यह बहुत-सी स्त्रियों को राजनीति के मैदान में उतरने से रोकता है।

लोकतात्रिक प्रक्रिया में स्थान पाने के बाद भी परंपरागत रूप से उपेक्षित समूहों की स्त्रियाँ उच्च जातियों के अत्याचारों का शिकार रही है। मध्य प्रदेश में पचायत चुनावों के एक वर्ष के बाद ही रायगढ, छतरपुर, रायसेन एवं पूर्वी निमाड़—इन चार जिलो से रिपोर्ट आयी कि एक स्त्री सरपच को नंगा किया गया, एक अन्य स्त्री सरपच के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, एक उप-सरपंच का उत्पीडन हुआ एव एक दलित पंचायत सदस्य को पीटा गया। 133

राज्य की प्रतिक्रिया

किसी भी समाज की प्रकृति राज्य के चरित्र में दिखाई देती है। यद्यपि भारत क

सविधान में बराबरी एवं सामाजिक न्याय के आदर्श निहित है, लेकिन जमीनी यथाय इससे एकदम भिन्न है। सत्ताधारी पार्टी एवं गठवधन की प्रकृति भी विकेदीकरण

एव ग्रामीण स्तर पर जनता को सत्ता के हस्तांतरण की नीतियाँ तय करती है। अनुभव बताते है कि संवैधानिक प्रावधानों को सही अर्थों में लागू नहीं किया गया है, विशेषकर

पचायतो एव नगरपालिकाओ के सदर्भ मे। प्रथम दृष्टांत एक या दूसरे कारण से पचायत चुनावो को स्थगित करने का

है। अनेक राज्य सरकारों ने पाँच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर चुनाव कराने

के संवैधानिक प्रावधान को गंभीरता से नही लिया है। भारतीय सविधान का अनुच्छेट 248बी स्पष्ट करता है कि प्रत्यंक राज्य में गाँव, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पचायते

होगी एवं (1) प्रत्येक पंचायत अपनी बैठक के लिए गठित होने की तिथि से पाँच वर्षो तक चलेगी-इससे अधिक नहीं (2) पचायत के गठन हेतु चुनाव उसके पाँच

वष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व या उसके भग होने के 6 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए (अनुच्छेद 243ई (1) एवं (3))। राजनीतिक पार्टियाँ गाँव स्तर से ही पंचायतो पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत रहती हैं एव सत्ताधारी पार्टी राज्य

की जनता का अपने कार्यकाल के मध्य या अतिम चरण मे सामना करने से घबराती है। लेकिन भारत के परिपक्व लोकतंत्र को यह श्रेय जरूर जाता है कि प्रत्येक चुनाव का नतीजा अप्रत्याशित होता है एवं राजनीतिक पार्टियाँ यह मान कर नहीं चल सकती

कि जनता उन्हें ही वोट देगी। ज्यादातर मामलो मे विपक्षी दल भी चुनाव स्थागित करने के लिए सत्ताधारी टल से हाथ मिला लेते है, क्योंकि वे भी पंचायतों के मतदाताओं का सामना करने

से डरते है। विपक्षी दलो के राजनेता स्थानीय निकायों को अधिकार देने की वकालत करते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि सत्ता मे आने के बाद वे भी रंग बदल लेते है। कुछ मामलों में वे अप्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालयो मे याचिका डलवाते हैं, ताकि

चुनावों पर स्थगन आदेश मिल जाये। यह सरकार जैसी विधिक संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो स्वय ही जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने के अवसर से विचत

सभी राज्यों में पचायत चुनाव पूरे हो चुके हैं-अपवाद केवल झारखड, अरुणाचल प्रदेश, एवं पांडिचेरी है। लेकिन यह हुआ है लवे न्यायिक संघर्ष के बाद तथा नागरिक

सगठनो के सफल हस्तक्षेप से। समस्या यह है कि राज्यों के राज्य चुनाव आयोग इस संदर्भ मे राज्य सरकार के दबाव कं आगे झुक जाते है—यद्यपि कुछ अपवाद

भी हैं, जैसे उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में राज्य चुनाव आयोगो ने अनावश्यक दबाव का सामना करते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। पंचायतों के अधिकारों को कम करने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासा का दूसरा दृष्टात है पचायती राज संस्थाओं के समानांतर चलनेवाले निकायो का गठन।

इस स्तर पर केंद्र एव राज्य सरकारें दोनों ही समानांतर निकायों का गठन करने या उन्हें बढावा देने में एक-दूसरे से होड़ करती हैं। मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा इन पजीकृत निकायों को व्यय हेतु कोष दिया जाता है। केंद्र एव राज्य के विभिन्न मंत्रालयों एव विभागों द्वारा पचायतों को नजरअंदाज करते हुए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करने का एक नमूना गुजरात सरकार की 'समरस ग्राम योजना' में दिखता है, जिसके तहत उन ग्राम पचायतों को एक लाख रुपये दिये जाते हैं जिनके सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। दूसरा नमूना सीटों की नीलामी का है, जिसमें सबसे ऊँची बोली लगानेवाला व्यक्ति ही सीट पाता है। सीट पर उसका स्वामित्व तय हो जाने के बाद कोई भी उसके विरुद्ध चुनाव नही लड़ सकता। यदि कोई इसका उल्लंधन करता है तो उसे शारीरिक यातना या सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ सकता है। तिमलनाडु के मदुरै जिले के एक गाँव में एक उम्मीदवार ने 5,60,000 रुपये की बोली लगा कर पंचायत अध्यक्ष का पद प्राप्त किया। वार्ड सदस्य के पद की बोली 10,000 रुपये से शुरू हुई। नीलामी की राशि का उपयोग स्थानीय उत्सवों एवं ऐसे अन्य अवसरो पर होता है।

राज्य सरकारों के ऐसे प्रयास लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं या पूरी प्रक्रिया का मजाक बनाते हैं। वे एक तरफ प्रभुत्वशाली वर्गों या समुदायों को गाँव के समूचे मामले का अधिकार लेने का अवसर देते हैं तो दूसरी ओर स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में स्त्रियों, दलितों, जनजातियों एवं अन्य उपेक्षित समूहों की सक्रिय भागीदारी के अवसर को छीनते है।

ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के अधिकार को 73वे संवैधानिक संशोधन द्वारा कानूनी मान्यता मिली है। ग्राम सभा स्थानीय जनता का स्थानीय विकास की अपनी जरूरतो एवं समस्याओ पर चर्चा करने का मच है एव योजना प्रक्रिया का अंग बनने का भी। दूसरी ओर, यह जनता को अपने उन प्रतिनिधियों के कामकाज पर नजर रखने का साधन भी प्रदान करता है, जिन्हे उसने पंचायतों हेतु चुना है। इस प्रकार ग्राम सभा पंचायत के कार्यों में उत्तरदायित्व एव पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। इसमें एक बड़ी कमी यह है कि 73वॉ सविधान संशोधन जहाँ ग्राम सभा के गठन का प्रावधान करता है, वही ग्राम सभा के अधिकार एव कार्य तय नहीं करता। यह सबधित राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है। अतः इस प्रावधान से ग्राम सभा को वास्तविक शक्ति नहीं मिलती, तािक वे कार्यक्षम और निर्णायक हो सकें। इस संदर्भ में यह याद दिलाने की जरूरत है कि मानवाधिकारों के आधार पर बनी नीतियाँ गरीबों की हिस्सेदारी एव सशक्तीकरण को प्राथमिकता देती हैं।

मानवाधिकार बरक्स पचायते

असर भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर पड़ा है। यह विशेष रूप से ग्रामीण भारत के गाँवों में घटित हुआ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने गाँव के लोगों को एक-दूसरे के निकट ला दिया है एवं वे अब प्रत्येक पाँच वर्ष बाद स्थानीय चुनावों में भाग ले सकते हैं तथा वोट देने के अधिकार का उपयोग कर सकते है। भारत में चुनाव जन शिक्षण की एक बड़ी प्रक्रिया है। सामदायिक स्तर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था

विल्ले एक दशक से भारत में गित पकड़ रही विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का गहरा

की कमी से बहिष्कृत लोगों के अधिकारों का हनन वर्षों से होता रहा है, जिसके फलस्वरूप वे समुदाय के मामलों में सिक्रिय भागीदारी नहीं कर सके। पंचायती राज सस्थाओं में अभिव्यक्त स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ने गाँव के स्तर पर नागरिकों के गौरवपूर्ण जीवन एवं सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लैंगिक समानता एवं स्वाधीनता पर आधारित सामाजिक न्याय के आदर्शों को

स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। औपचारिक ढग से सभी राज्यों ने संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है, ताकि पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों, दिलतों एवं आदिवासियों जैसे विचत समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। गरीबों की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ गरीबी उन्मूलन एवं विकास कार्यक्रमों को पचायतों को हस्तातरित कर

सवैधानिक निर्देशों का भी सम्मान किया गया है। एक-तिहाई सीटों के आरक्षण द्वारा स्त्रियों ने पंचायतों में मोटे तौर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है। दलितों एव आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप हुआ है। प्रकटत यह जरूरी नहीं है कि औपचारिक प्रतिनिधित्व भागीदारी का सकेत

भी हो। विकेद्रीकरण के नये दौर से यह बात सामने आयी है कि भारत के ग्रामीण समाज में व्याप्त निष्कासन तथा बहिष्कार के कुछ निकृष्टतम तरीके अब अनेक राज्यों में व्यवहार में नहीं हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों में निर्वाचित सदस्य एक साथ बैठ कर विचार-विमर्श करते हैं। दिलतों, आदिवासियों एवं स्त्रियों सहित गाँव के सभी सदस्यों की प्रतीकात्मक भागीदारी, सवैधानिक जरूरतों के लिए ही सही. कितु होती है। यह भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे धीमे, मगर निश्चित बदलावों का एक नतीजा है।

भारत में लोकतात्रिक प्रक्रिया द्वारा सामाजिक बदलाव शातिपूर्ण नहीं है। अत जब से भारत ने विकेंद्रकीरण एवं स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने का गभीर प्रयत्न किया है, सभी स्तरो पर मानवाधिकारो का उल्लंघन हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि अब तक जो लोग सत्ता एव विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे थे, वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संवैधानिक निर्देशों के साथ मितरवात करना चाहते है। इसे दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है। परंपरागत समाज मे कोई भी वदलाव, जिसका ढाँचागत प्रभाव हो, सघर्षपूर्ण होता है। हितों का टकराव इतना शक्तिशाली होता है कि उसमे हिसा, रक्तपात एवं जान का नुकसान होता है। जब से भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई है, यह होता रहा है। लेकिन इसका खूनी चरित्र लंबा नहीं रहा है, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास होता रहा है।

1993 के बाद से पचायतों के नये दौर मे, कुछ राज्यों को छोड़ कर, चुनावों के दो दौर हो चुके हैं। यह विडवनापूर्ण हैं कि भारत में चुनावों के समय गभीर रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। चुनाव के समय अमीर यह प्रयास करते हे कि गरीबों का वोट खरीद लें या वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करे। अनेक मामलों में ऊँची जातियाँ नीची जातियों को बोट देने से रोकती है—जब उन्हे यह पता चलता है कि गरीब एव वंचित लोग स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करनेवाले हैं। इस प्रक्रिया में हिंसक वारदाते होती है एव अनेक लोग जान गवा देते हैं। यद्यपि राज्यो एवं ससद के चुनावों में भी हिसा होती है, लेकिन स्थानीय चुनावों में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनमें मतदान का प्रतिशत भी ऊँचा होता है।

गॉव स्तर पर हिसा इसलिए भी अधिक होती है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सत्ता सबसे महत्वपूर्ण औजार है एव सभी इसे हथियाना चाहते है। अतः पहले से मौजूद तनाव तब और वढ जाता है जब सत्ता की इच्छा रखनेवाले वचित लोग उन वर्गों के विरुद्ध खड़े होते हैं जो इसे छोड़ना नहीं चाहते। बाहुबल तथा धन एव जाति की शक्ति का वीभत्म रूप स्थानीय निकायी के चुनावों में सामने आता है। इस हिसा का एक विश्लेपण यह दर्शाता है कि जहाँ भी राजनीतिक चेतना कम होती है एव विकास की गति सापेक्ष रूप से विपरीत है, उस क्षेत्र के लोग हिंसा में अधिक संलग्न होते है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जातिवाद खत्म करने के लिए दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ ठोस व्यवस्थित प्रयास नहीं हो रहे है। कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन भी काफी मामूली तथा अपर्याप्त रहा है तथा कानून का उल्लंघन करनेवालो को सजा तक नहीं मिलती। अनुसूचित जनजातियों के सासद सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर चुके है कि भारत सरकार जातिवाद तथा निचली जाति के लोगो के लगातार अपमान के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को लागू करना नहीं चाहती। उनके अनुसार, 'यह अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों का दुर्भाग्य और एक शर्मनाक ट्रेजडी हैं कि उन्हें अपने ही देशवासियों के हाथो अमानवीय और बर्बर तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है।' कई वार उनकी औरतो को गलियों मे नगा घुमाया जाता है तथा उनके बच्चों को जानवरों की तरह काट डाला जाता है; उनके घरो को जला दिया जाता है तथा उनकी जीविका के साधन नष्ट कर दिये जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सरकार और उसका तंत्र असहाय मूक दर्शक या उदासीन विश्लेषक की भूमिका में नजर आते हैं।44

राज्य अनुसूचित जाति आर जनजाति आयोगा का गठन अनुसूचित जाति आर जनजाति (अत्याचार विरोधी) कानून, 1989 के तहत किया गया है. लेकिन जातिगत

अत्याचार से पीडित व्यक्ति या समूह वदले के डर से रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराते हे, हालाँकि आयोग सुरक्षा और आर्थिक मुजावजा देने का वादा करता है।

इन सबके बीच पंचायतों ने उन सभी मामलो को सामने लाये जाने की उम्मीद

पैदा की है जिन्हे पहले कालीन के नीचे दबाये रखा जाता था। अव ये मामले गुप्त या छिपं हुए नहीं रहे। यद्यपि ग्राम सभा ओर ग्राम पचायत जोड-तोड की राजनीति के केंद्र हैं, फिर भी उन्होने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुली लड़ाई का

एक मच मुहैया कराया है। 45 सर्विधानिक समर्थन के साथ ऐसा मच अब पहली वार उपलब्ध है। यहाँ राजनीतिक दलो की भूमिका महत्वपूर्ण है। आम सहमति की जो पूर्ववर्ती

अवधारणा (जो असल में ताकतवर जो कुछ कहता या करता है, उस पर सहमति का पर्याय है) कमजोर हो रही है। लोग पार्टी लाइन पर एकजुट हो रहे हैं, तािक जिस मामले मे भी पारदर्शिता नहीं हैं, उस पर प्रश्न किया जा सके। अगर एक दल किसी कारणवश दलित का साथ देता है तो दूसरा दल दमनकारी का संरक्षक बन कर खड़ा हो जाता है। स्थानीय मामलों मे राज्य स्तर की राजनीति या राष्ट्रीय स्तर

की विचारधारा का काफी कम असर होता है। फिलहाल तो पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलो की भागीदारी वर्षी पुरानी जातीय या पारिवारिक निरक्शता की चुनोती

का सामना करने का सर्वोत्तम तरीका है। जन संचार, सूचना तकनीक और भौगोलिक संचरण ने गाँवा के एकाकीपन

को तोड़ा है। यहाँ तक कि दूर-दराज की पंचायतों में होनेवाली घटनाओ की चर्चा अव राज्य और राप्ट्रीय स्तर पर तत्काल होने नगी है। नयी पंचायत व्यवस्था ने, अपनी सभी मौजूदा कमजोरियों के वावजूद, गाँवों में व्यापक सामाजिक सरोकार पेदा करने में मदद की है। स्थानीय स्तर पर दबे-कुचले लोगो के मानवाधिकारों के मामले में न्यायपालिका

का सकारात्मक हस्तक्षेप ॲधेरे में आशा की एक किरण की तरह है। यद्यपि भारतीय न्यायपालिका अपनी धीमी चाल के लिए कुख्यात है, जन हित याचिकाएँ स्थानीय

निकायों के विधानों को अर्थ देने मे एक सफल हथियार के रूप मे काम कर रही है। उदाहरण के लिए दलित समुदाय की एक महिला को पचायत का प्रमुख वनने पर हारे हुए ऊँची जाति के उम्मीटवार का कोपभाजन बनना पड़ा। दक्षित महिला

अध्यक्ष द्वारा थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी मे कहा गया कि उपद्रवियो ने उनका घर लुट लिया तथा अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ गाली-मलीच की। मामला अदालत मे गया। उच्च न्यायानय ने प्राथमिकी रह करने से इनकार करते हुए यह माना कि 'सामंती और पेशागत श्रम विभाजन के आधार पर बनी

मानवाधिकारों के रू-ब-रू : 145

के विकास में एक बड़ी बाधा है। इसमें कोई सदेह नहीं कि 'चमार' शब्द एक खास जाति की ओर इशारा करता है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग तथाकथित ऊँची जातियों के लोग ऐसे लोगों के खिलाफ भी करते हैं जिन्हें वे अपने से नीचा समझते है। अत[,] इसका प्रयोग तथाकथित ऊँची जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दलितों की भावनाएँ आहत होती है।'⁴⁶

भारत की प्राचीन जाति व्यवस्था आज पूरी तरह से अप्रासंगिक है तथा यह राष्ट्र

वास्तिवक लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी के लिए स्थानीय निकायो के चुनाव के कई दौर जरूरी है। इसमे कोई सदेह नहीं कि जीवंत लोकतंत्र पर आधारित स्थानीय सरकारें नागरिक संगठनों की मदद से सभी स्तरों पर लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करेंगी। लेकिन भारत जैसे परंपरागत समाज में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जिर्चे ऐसा होने में समय लगेगा।

(यह परचा 'विकेद्रीकरण, स्थानीय सरकार और मानवाधिकार—मुद्दों का एक सर्वेक्षण' विषय पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नीति परिषद, जिनेवा के एक व्यापक अध्ययन का एक हिस्सा है। डेविड पेट्रासेक की टिप्पणियो और इस विषय पर काम करने के लिए उनके प्रोत्साहन का मैं शुक्रगुजार हूँ। पेट्रासेक इस अतरमष्ट्रीय अध्ययन के समन्वयक है, जिसमें भारत, फिलीपीस, वुर्किना फासो, माली, चिली, रूसी सघ और युगाडा को शामिल किया गया है।)

संदर्भ

- शिटिश शासको ने 1687 में व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर निगमों की स्थापना की तथा 1870 में लॉर्ड मेयों ने प्रशासनिक कुशलना लाने के लिए सत्ता के विकेदीकरण से सर्वाधित एक प्रस्ताय अपनी परिपद द्वारा पारित कराया। 1882 में लॉर्ड रिपन के वायसराय बनने पर चुन हुए प्रतिनिधियोवाले स्थानीय बोर्डा के लिए मरकारी प्रस्ताव आया, जो स्थानीय स्वशासन की विशा में एक प्रस्थान विदु साबित हुआ।
- 2 22-23 दिसबर 1992 को भारतीय संसद ने दो संविधानिक संशोधन (75वॉ और 74वॉ) पारित किये तथा 24 अप्रैल 1993 को उन्हें पचायतों के लिए भाग नी तथा नगरपालिकाओं के लिए भाग नी-ए के रूप में जोडा गया। दिसंबर 1996 में संसद ने 73वे संशोधन को अनुसूची पाँच के इलाकों पर लागू किया। तीन-स्तगिय स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में ग्राम पचायत सबमें निचला स्तर होती है। उत्तर भारत में पचायत 2000 से 5000 की आबादी पर होती है, जब कि दक्षिण भारत में 10,000 से 15,000 की आबादी पर। अगल स्तर की पचायत ब्लॉक नहसील या मडल स्तर पर होती है। उप-जिला स्तर पर यह पचायत 40 से 45 ग्राम पचायता पर होती है। सर्वोच्य स्तर पर जिला पचायत होती है।
 - अर्जुन मेनगुप्त, मानव अधिकार के रूप में विकास का अधिकार, इकॉनॉमिक एड पॉलिटिकल वीकली, 7 जुलाई 2001, पृष्ट 2527
 - 4 भारतीय सर्विधान के अनुस्केद 40 के अनुसार, राज्य ग्राम पचायतो का सगटन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार करेगा जो उन्हे स्वायत्त शासन की

इफाइया के रूप में कार्य करने याग्य बनान के लिए आवश्यक हो। भारतीय सर्विधान के मृताविक भारत राज्यों का सघ है। 26 नवबर 1949 का सर्विधान सभा

द्वारा अपनाय गये सर्विधान में सशक्त कड़ की परिकल्पना की गयी थी।

अनुच्छेद २४३ के तहत, 'पचायन स्वापत्त सरकार का सस्यान है।' अनुच्छेद २४३औ पदायतों को ऐसे अधिकार देता है, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे कानून में अधिकारों के विकेदीकरण और पचायतो को जिम्मेदारियाँ सोपने का प्रावधान हो सकता हे, नाकि ऐसी योजनाएँ तेयार की जा मफे, जिनसे आर्थिक विकास

ओर सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त हो। अक्टूबर 2000 म तीन नये राज्य बनाये गये और आज देश में कुल 28 राज्य है। य नये राज्य झारखंड, उत्तराचल ओर छत्तीसगढ।

भारतीय सविधान के खड मी ओर मी-ए के तहत अनुच्छेट 243ए से 243ओ ओर 243र्पा स

243जेडएफ तक देखे। ग्यारहर्वी अनुसूची में पचायतों के लिए 29 विषय हैं और बारहर्वी अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय है। इनमें शिक्षा, कृषि, पेय जल, ग्रामीण गृह निर्माण, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम, पारिवारिक कल्याण तथा लघु उद्योग जेसे विषय शामिल हैं।

जी डकन मिशेल, 1979, ए न्यू *डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी*, गउटलज ओर केगन पाल, लटन ओर हेनले

देखं डकन वी फोरेस्टर, *काम्ट एड क्रिश्चनिटी*, कर्जन प्रेस, लदन, 1980, पृष्ठ 1-4। दूसरी ओर एफ जी बेली जाति को सामाजिक सोपानीकरण का अतिवादी और कड़ा स्वरूप कहते है। बेली कोड आदर्शवादी पहलू जोड बिना जाति की व्याख्या करते है और हिंदुत्व से उसका कोई आवश्यक सबध नहीं देखते।

आर एम पाल, जाति प्रथा और मानव अधिकारों का उल्लंघन, पीयुसीएल बुलेटिन, 12, 10 2-4 1992

पोराणिक मान्यताओं के मुताबिक मन् को विधि निर्माता माना जाता है। उनका समय तीन हजार साल पहले का है। मन्स्मृति में बेगार (निचली जाति का श्रीमक, जो बिना पारिश्रमिक के काम करता है) को मजूरी दी गयी है।

रामंद्र, मानव अधिकार तथा जाति प्रथा, पीयुसीएल वुलेटिन, जनवरी 1993, पृष्ठ 8-10 जॉर्ज मेथ्यू, मेलावलाव् के मायने, हिंदू, 30 सितंबर 1997

पचायती राज अपडेट, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज, भाग 8, न. 10, अक्टूबर 2001, पृष्ठ 3 जी के लीटेन और रवि श्रीवास्तव, अनङ्क्वल पार्टनर्स पावर रिलेशस, डियॉल्यूशन एड डेवलपमट

इन उत्तर प्रदेश सेज पिनकेशस 1999, पृष्ठ 105-141 पचायती राज अपडेट, खंड 8 अप्रेल 2001

ह्युमन गइट्स वाच, ब्रोकन पीपल कास्ट वायलेस अगेंस्ट झॅंडेया'ज अनटचेबत्स, 1999 ह्यूमन राइट्स एड पावर्टी इरेडिक्रेशन ए टालिसमेन फॉर द कॉमनवेल्थ, ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव, नयी दिल्ली, 2001 पृष्ठ 6

एलन जी. स्मिथ, ह्यूमन राइट्स एड च्वायस इन पावर्टी ' फूड सिक्यूरिटी, डिपेडेसी एड ह्यूमन राइट्स-बेस्ड डेवलपमेंट एड फॉर द धर्ड वर्ल्ड खग्न पुअर, प्रेजर पब्लिशर्स, 1997

जॉन ड्रेज और अमर्त्य सेन, *डेमोफ्रेटिक प्रैक्टिसेस एड सोशल इनडक्वलिटी,* इन्टीट्यूट ऑफ साशल साइसेज, ऑकेजनल पेपर्स सीरीज, नयी दिल्ली, 2002

147

- उपर्यक्त 24
 - पचायती राज अपडेट, जनवरी-दिसंबर, 2001

जनजाति कहा जाता है।

- जॉर्ज मेथ्यू, महाराष्ट्र का ग्राम सेवक राज, द हिंदू, 13 अग्रस्त 2001
- भारत के राष्ट्रपति को विशेष प्रावधानों के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार 27
- है, ताकि उनके हितो की रक्षा की जा सके। उन्हें अनुसूचित जानि कहा जाता है।
- 28. जॉज मेथ्यू ओर रमेश सी नायक, *पंचायते व्यवहार में क्या लाभ है इनसे शोषित वर्गो को*र इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, मुबर्ड, 6 जुलाई 1996 पृष्ठ 1765-1771
- 29. क्रटलाइन, 26 अक्टूबर 2001, पूछ 34-35
- 30. भारत के राष्ट्रपति को निचली जातियों की तरह की आदिवासिया के लिए भी उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए एक सूची बनाने का अधिकार है। उन्हें अनुसचित
- अनुस्चित क्षेत्रो को आम तौर पर इस आधार पर तथ किया जाता है अनुसूचित जातिया की अधिकता, भौगोलिक अलगाव और सामान्य पिछडापन । अनुसूचित क्षेत्र माने गर्य 10 राज्य हे-आध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उडीसा और गजस्थान।
- असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र माने गये हैं। 32 विस्तार अधिनियम में किये गये कुछ अनिवार्य प्रावधान आध्र प्रदेश अधिनियम मे शामिल नही
- किये गये हैं।
- 33. *हिंदु*, 14 दिसंबर 2001
 - 34. गुजरात सरकार ने गुजरात पचायत अधिनियम, 1993 में संशोधन के लिए 23 नवबर 2000 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमे यह कहा गया कि पंचायत अधिनियम के खड़ नौ के उपखंड पॉच की उपधारा (ए) के प्रावधान पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र के तहन आनेवाली ग्राम पचायतो पर लागू नहीं होंगे, जहाँ अनुसूचित जनजातियों की आबादी ग्राम पचायत की आबादी के 25 प्रतिशत से कम है। मूल उपधारा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए गाँव मे उनकी
 - आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। इस नयी अधिसूचना के लागू होने के साथ ही उन ग्राम पचायतो मे, जहाँ अनुसूचित जनजातियों की आबादी 25 प्रतिशत से कम है, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में कटौती हो गयी।
 - 35. पचायती राज अपडेट, जून और अगस्त 1998 निर्मला बुच स्टेटस ऑफ पचायत्स इन द स्टेट्स एड यूनियन टेरिटरीज 2000 में शामिल 'पचायत और स्त्रियाँ' में, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नयी दिल्ली, 2000, पृष्ठ 34
 - गोरतलब है कि राज्य विधान सभाओं और भारत की ससद में महिलाओं का प्रतिशत काफी कम है। ससद में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ आठ प्रतिशत है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि यह ऑकड़ा संपूर्ण महिला समाज का प्रतिनिधित्व करता है।
 - 38 निर्मला ब्च, पूर्व-उल्लखित, पृष्ठ 34-35
 - 39. विनोद व्यासुल् और पूर्णिमा, वीमेन इन पंचायती राज, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया, मालगुडी का अनुभव, मार्च 1999
 - कुछ पुरस्कार विजेता महिलाओं ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने, बाल विवाह तथा बाल
 - मजदूरी के विरुद्ध अभियान चलाने, पाइप द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था करने, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण तथा प्राथमिक विद्यालयो को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट योगदान किया है।
 - 41 मैथिली श्रिवरमण, अच्छाई को आघात, हिन्दू, 18 मई 1997 42 विनोद व्यासुलु और पूर्णिमा, पूर्व-उल्लिखित
 - भारत में पचायती राज 148

- 43 जॉर्ज मेथ्यू ओर स्मेश सी नायक, पूव-उल्लिखित
- 44 साउथ एशिया ह्यमन राइटस डक्यूमेटेशन संटर, रेशियल डिस्किमिनेशन व रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, सितंबर 2001, पृष्ठ 36-37
- 45 विस्तृत जानकारी क लिए देखे जॉर्ज मेथ्यू और ग्मेश सी नायक, पूर्व-उल्लिखित
- 46 पद्मायती राज अपडेट, फाबरी 2001

एक कदम आगे, दो कदम पीछे

राजनेताओं की जयंतियाँ मनाना और राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए स्त्री-पुरुषों का सम्मान करना हमारे राजनीतिक वर्ग का प्रिय शगल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ पुरानी फाइलों की धूल झाड़ कर नये नायकों का आविष्कार किया है, जिनका सम्मान किया जा सके। लेकिन यही सरकार उस वक्त स्मृति-भंश का शिकार हो जाती है जब मामला स्वतंत्र भारत की एक युगांतरकारी घटना—पंचायतों को भारतीय संविधान के भाग नौ में शामिल किया जाना—की दसवी वर्षगाँठ मनाने में होता है। 1993 के 24 अप्रैल को, एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद, पंचायतों को 'स्वशासन की संस्थाओं' के रूप में सवैधानिक मान्यता मिली। भाजपा और उसके माध्यम से केंद्रीय सरकार इस घटना के ऐतिहासिक महत्व की उपेक्षा कर रही है। निश्चय ही, पंचायत राज्य सरकारों का विषय है, लेकिन केंद्रीय सरकार जिस तरह के संकेत भेज रही है, उससे राज्य सरकारों को यह निष्कर्ष निकालने में सुविधा हो सकती है कि पचायतों की कोई वकत नहीं है और विकेदीकरण तथा स्थानीय स्वशासन के सशक्तीकरण का काम भविष्य में होता रहेगा।

वर्तमान सरकार की अवधारणा यह प्रतीत होती है कि पचायतों और नगरपालिकाओं को कुछ सामाजिक और राजनीतिक शिक्तियों के प्रभाव से सिवधान में स्थान मिल गया—इस मामले को आगे बढाने की जरूरत नहीं है। सो पंचायतों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस अवधारणा पर चलते हुए भाजपा सरकार ने अब तक यही किया है: कुछ पंचायत उत्साहियों को सतुष्ट करने के लिए एक कदम आगे बढना और फिर इस सस्था का महत्व कम करने के लिए दो कदम पीछे की ओर लौटना। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर भाजपा के सत्ता में आने के बाद, केंद्रीय सरकार के कुछ निर्णयों को और किस रोशनी में देखा जा सकता है?

73वॉ संविधान संशोधन पारित होने के दसवें वर्ष के ठीक पहले, 21 दिसंबर 2002 को, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तीकरण के लिए एक उच्च शक्ति-सपन्न उपसमिति का गठन किया था। यद्यपि इस उपसमिति को कार्यशील बनाने का आदेश जारी करने में योजना आयोग को तीन महीने लग गये, इसके वावजूद हर दृष्टि से यह आगे की ओर उठाया गया एक निर्णायक कदम है।

उच्च शक्ति-संपन्न उपसमिति के अध्यक्ष है ग्रामीण विकास मंत्री। वित्त तथा कपनी मामलो के मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण

मत्री, जनजाति मामलों के मत्री तथा असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्री इसके सदस्य है। योजना आयोग के सचिव इस

उपसमिति के सयोजक और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सह-संयोजक हैं। समिति के कद-काठी के बडे होने में क्या सदेह हैं।

सिनित को जो निर्देश दिये गये हैं, उनमें ये विषय शामिल हैं: 78वें सिवधान सशाधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए—ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावशाली सस्थाओं के रूप मे काम कर सके—राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों का पुनरीक्षण, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ससाधनों के

हस्तातरण के माध्यम से पचायती राज संस्थाओं के कार्य क्षेत्र को सुदृढ करने के लिए वाछनीय उपाय निर्धारित करना और पचायतों द्वारा अपने ससाधन विकसित करने की श्रमता का मुलाकन तथा हम दिशा में एक कार्य शोजना का विकास ।

करने की क्षमता का मूल्याकन तथा इस दिशा में एक कार्य योजना का विकास। समिति को विभिन्न स्तरों की पचायतों को विभिन्न योजनाओं के तहत किये गये वित्तीय आवटनों को जज्ब करने की उनकी क्षमता का मूल्याकन और विभिन्न

स्तरों पर राजकोषीय अनुशासन तथा विनीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक कारगर ढॉचे का विकास करना भी था। समिति के जिम्मे अन्य कार्य थे: सविधान की ग्यारहवी अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के क्षेत्र में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियो पर पंचायतो का प्रशासनिक नियत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कटम सुझाना, विकास की प्रक्रिया को जनादोलन में बदलने के लिए लोगों की अनुभूत

आवश्यकताओं और अभिलाषाओं को अभिव्यक्त कर सकें, ऐसी स्थानीय योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें परियोजनाओं का स्वरूप देने के लिए एक सुसंगत ढॉचा निर्मित करना, निर्वाचित पचायत सदस्यों के प्रशिक्षण की जरूरतों का मूल्याकन करना करा हम प्रशिक्षण के मॉड्यल सुनिष्नित करना, केटीय मुझ्यता को राज्यों के साथ

तथा इस प्रशिक्षण के मॉड्यूल सुनिश्चित करना, केद्रीय सहायता को राज्यो के साथ इस तरह जोड़ना कि वह पंचायतों के सशक्तीकरण की प्रगति के साथ जुड सके; एव देश भर में पंचायतों को सुदृढ़ और सशक्त बनाने से संबंधित अन्य प्रासंगिक

मुद्दो पर विचार करना। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य

इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करने के लिए बनायी गयी इस समिति की पहली बैठक अभी भी होनी है और विकेदीकरण तथा पचायती राज के सभी हिमायती उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे है कि समिति की बैठक से क्या नतीजा निकलता है।

ऐसा लगता है कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को एक हाथ से जो दे रही है, वह दूसरे हाथ से वापस ले ले रही है। इस द्वद्वात्मकना ने दंश मे स्थानीय स्वशासन प्रणाली की नीव को ही आघात पहुँचाया है। वस्तुत इस प्रक्रिया की शरुआत 1999 में ही हो चुकी थी। तब वरिष्ठ भाजपा नेता सुदरलाल पटवा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। 15 दिसंबर 1999 को सभी मुख्य मित्रयों को भेज गये एक पन्न में पटवा ने अपनी इस उपलब्धि की प्रशंसा यह कर की थी कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणो को सुदृढ करने के लिए उन्होंने किम तरह 'डीआरडीए प्रशासन' नाम की एक नयी योजना का श्रीगणेश किया है। पटवा के अनुसार, डीआरडीए जिला स्तर पर ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने वाली सस्थाओं में अग्रणी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पटवा ने-और उन्होंने भी जिन्होंने उनके बाद इस मंत्रालय का नेतृत्व किया-नये पचायती राज की आत्मा को कभी समझा ही नही। अन्यथा वे इस तरह का दावा कैसे कर सकते थे, जब कि सविधान ने साफ तौर पर पचायतों को ही यह अधिकार दे रखा है कि वे अपने-अपने स्तर पर आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजना तैयार करेगी और आर्थिक विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगी। जिला स्तर पर लोकतात्रिक रूप से निर्वाचित पंचायत संस्था-जिला परिषद-पर मजबूत डीआरडीए प्रशासन को वरीयता देना लोकतंत्र का मजाक उडाना है।

पटवा ने उन राज्य सरकारों को प्रशंसा की निगाह से नहीं देखा, जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों की शब्दावली और आत्मा कर आदर करते हुए डीआरडीए को भग कर दिया था और उसके कार्य जिला पचायत को सीप दिये थे। पटवा ने लिखा 'यह लिक्षित किया गया है कि कुछ राज्यों में डीआरडीए को भंग कर दिया गया है और उसके कार्य जिला पंचायत को सींप दिये गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ डीआरडीए का स्वतंत्र अस्तित्व अत्यंत वाछनीय है। अतः मेग सुझाव है कि जहाँ भी डीआरडीए का पृथक अस्तित्व नहीं है, आप उनका पुनर्गठन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे।'

डीआरडीए के प्रति सुंदरलाल पटवा का इतना प्यार क्यों उमड़ रहा था, यह कोई रहस्य की बात नही है। यह एक वह एजेसी है जो पैसे से लबालब भरी रहती है (साल में लगभग 15,000 करोड़ रुपये) और जहाँ जिसके आवटन तथा उपयोग में सांसदो, विधायकों और अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है। यह वही जगह है जहाँ राजनेता, नौकरशाह और ठेकेदार की तिगडी सबसे ज्यादा असरदार होती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस निर्णय की आलोचना कई क्षेत्रों से आयी। उदाहरण के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय पर ससद की स्थायी समिति ने अपनी 2000-2001 की रिपोर्ट में कहा, 'यह समिति जानना चाहेगी कि विकास की विभिन्न गितिविधियो पर डीआरडीए प्रशासन के सुदृद्धीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। विशेषत यह सिमिति चाहती है कि संविधान के अनुच्छेद 243 जी को ध्यान में रखते हुए डीआरडीए संस्थाओं के नौकरशाही-भाराधिक्य पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार किया जाये तथा पचायती गज को सिविधान के भाग नौ में डाले जाने के पूर्व की प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में डीआरडीए सस्थाओं के प्रकार्यों का विलय सविधान के भाग नौ को प्रभावी बनाते हुए किया जाये; डीआरडीए का लोकतत्रीकरण तथा पचायती राज प्रणाली में उसे समन्वित करने की जरूरत है।

तब तक वेंकैया नायडू ग्राम विकास मंत्री का पद सँभाल चुके थे। पंचायती राज संस्थाओं के प्रति उनकी दृष्टि और ज्यादा तथा विनाशकारी थी। उन्होंने स्थायी सिमिति के सुझावों की बिलकुल ही उपेक्षा कर दी। इस पर 2001-2002 की मसंदीय सिमिति ने उनके मंत्रालय की आलोचना इन शब्दों में की - 'डीआरडीए संस्थाओं के प्रकायों का बिलय जिला पंचायतों के साथ करने की अपनी पूर्व सिफारिश के प्रन्युत्तर में सरकार के जवाब को नोट कर यह सिमिति चितित है। मुद्दे पर विचार करने और सुस्पष्ट उत्तर देने के वजाय, वर्तमान दिशा निर्देशों को ही फिर से जारी किया जा रहा है, जिनके अनुसार डीआरडीए संस्थाओं से आशा की जाती है कि व पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावशाली समन्वयन का काम करेंगी। इसे देखते हुए,

यह कंद्रीय सरकार पर एक दुखद टिप्पणी है कि उसने सवैधानिक हैसियत प्राप्त नोकतात्रिक सस्थाओं को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में निर्णायक ढग से काम नहीं किया।

यह समिति अपनी सिफारिशों को और भी शक्ति के साथ दुहराती है।' इसके बाद

भी, वाछनीय दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दो

ग्रामीण विकास मत्रलाय को मिलने वाले बजदीय आवटन प्रतिरक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा होते है। यह मत्रालय देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और अधिरचना, निवास स्थितियों एव भूमि ससाधनों के विकास पर प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। संसद सदस्य भी इन राशियों के उपयोग में हाथ बॅटाना चाहते हैं। इसलिए वे 'ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और बडी भूमिका' की माँग करते हैं।

सरकार ने सासदों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। अब ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर सिमितियाँ बनाने की मुहिम चल रही है। इन सिमितियों की अध्यक्षता सासदों को सौपी जायेगी। यह पचायतों की संवैधानिक हैसियत और स्वायक्तता पर संभवतः सबसे बडा आधात है। इस मुहिम की शुरुआत राजग सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तीसरे मंत्री, शांता कुमार, के कायकाल में हुई। वे भी भाजपा के वरिष्ठ नेता है और अब मत्री पद से इस्तीफा दे चुके है।

20 दिसंबर 2002 का शाता कुमार ने संसद सदस्यों को जिला निगरानी समितियों का अध्यक्ष पद सौपते हुए इसका औचित्य इस प्रकार प्रतिपादित किया : 'ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को, प्रभावशाली और कार्यक्रशलता दोनों ही दृष्टियों से, सुधारने की गुंजाइश है, जो आज हमारे सामने उपस्थित सबसे बड़ी चुनौती है, और जिसमें 'संसद सदस्यों को बृहत्तर भूमिका निभानी होगी।' मंत्री महोदय के अनुसार, सरकार मानती है कि ससद सदस्य इस भूमिका का प्रभावशाली ढग से निर्वाह करने की स्थिति में हैं, अतः निगरानी समिति के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को शींब ही लागू किये जाने की आशा की जाती है।

जिला निगरानी समिति के संगठन की चर्चा इसलिए जरूरी है कि इसके माध्यम से सरकारी चितन की दिशा प्रतिबिंबित होती है। समिति का सदस्य-सचिव जिला कलक्टर है और लगभग बीस सदस्यों की इस समिति में जिला पंचायत का अध्यक्ष भी विभिन्न प्रशासनिक विभागों के पीठासीन अधिकारियों के साथ मात्र एक सदस्य है। जो मत्री महोदय के पत्र और समिति के लिए जारी मार्ग निर्देशों का पढ़ेगा, उस पर यही प्रभाव पड़ेगा कि मत्री महोदय की योजना में जैसे पंचायतों का कोई अस्तिल ही नहीं है। उन्होंने बहुत ही सुविधा से यह तथ्य भुला दिया कि प्रधान मत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वहुत ही स्पष्टता से कहा था कि पचायते भारत की संघीय व्यवस्था में शासन का तीसरा सस्तर हैं।

इस सदर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बुलायी गयी राज्य मचिदों की एक बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और लगभग सभी सचिवों ने एकमत से सांसदों को जिला निगरानी समितियों का अध्यक्ष बनाने का विरोध किया था।

केंद्रीय सरकार की इस मुहिम का विरोध करने वाले पहले मुख्य मंत्री थे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि जिला निगरानी समितियों की अवधारण संघवाद की आत्मा के विरुद्ध और ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय सरकारों की ईमानदारी और योग्यता के प्रति मंत्रालय के अविश्वास की अभिव्यक्ति है। दिग्विजय सिंह के अनुसार, यह विडबना ही है कि मत्रालय एक ऐसा अनुचित प्रस्ताव ले कर हाजिर हुआ है जो 73वे सविधान की आत्मा का हनन करनेवाला है। सरकार के इस आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश के तर्क विचारणीय हैं।

दिग्विजय सिंह द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण नुक्ता हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सिद्धांत और व्यवहार है। जिला निगरानी समितियों के जो काम बताये गये हैं, वे जिला पंचायतों के प्रकार्यों और दायित्वों से मिलते-जुलते है। एक निर्वाचित बनाना क्या अनुचित नहीं है? इसके अलावा, सांसद और विधायक जिला पचायन के सदस्य होते है। जिला परिपद का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है, जिसे जिले के लोगों ने अपने मामलों की देखरेख के लिए निर्वाचित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का प्रश्न है - ऐसी स्थिति में जिले के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी क लिए किसी सासद को लाना क्या जिला पचायत के संवैधानिक प्राधिकार का क्षरण करने का ऐच्छिक प्रयास नहीं है?

निकाय-जिला पचायत-के रू -द-रू एक नामांकित निकाय का ज्यादा शाक्तशाला

स्पप्टत सरकार की अपेक्षा इस देश की जनता का ज्यादा सरोकार इस वात से हे कि विकास कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन और प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का ठीक से उपयोग हो। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जनसाधारण का विश्वास सासदों के बजाय पचायत प्रतिनिधियों में ज्यादा हैं ओर इसका सीधा-सा कारण यह है कि सांसद तक अकसर उसकी पहुँच नहीं होती। इसके विपरीत, पंचायत प्रतिनिधि उसके बिलकुल करीव होते हैं, उनके साथ रोजाना का व्यवहार रहता है और जनता उनकी दैनदिन गतिविधियों पर नजर रख सकती है।

यही कारण है कि देश में संसदीय चुनावों की तुलना में पचायन चुनावों में मतदान का प्रतिशत हमेशा बहुत अधिक हाता है। सांसदों को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौपना एक ऐसी चीज है, जिसे देश स्वीकार नहीं कर सकता। 1993 में शुरू की गयी सांसट स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को ही लीजिए। इस कार्यक्रम के तहत, स्थानीय सासदों को परियोजना के चयन और कोप का आवंटन का एकल अधिकार होता है और इस अधिकार का प्रयोग करते समय वे पंचायतों की प्राथमिकताओं की उपेक्षा कर सकते हैं। राज्यां मे जारी विधायक क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत आवंटित राशि को सासद क्षेत्र विकास योजना के तहत दी जाने वाली राशि को मिला दिया जाये, तो लगभग 3000 करोड़ रुपये की राशि बनती है, जो पंचायतों की भूमिका को परिमित करता है। हाल के वर्षों में सासद क्षेत्र विकास योजना का बजट बनाने की मॉग निरतर बनी रही है, जब कि पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता की उपेक्षा की जा रही है। साल-दर-साल लोग इन आशय के किस्से स्नते रहते हैं कि सांसद कोष का पैसा खर्च नहीं हो पाता और 'खर्च' होता भी है, तो जनता के मन में खर्च के प्रकार के प्रति गभीर सशय बने रहते है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती के कुख्यात वीडियो-टेप ग्रामीण विकास में सासदों की 'ईमानदार' दिलचस्पी की कहानी का दूसरा ही

के हिमायती है। विकेंद्रीकरण के वे विरोधी है। सार्वजनिक कोपो के कुशल इस्तेमाल और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए

पक्ष प्रकट करते है। सुंदरलाल पटवा से शुरू कर मायावती तक चलनेवाले किस्से का सदेश यही जान पडता है कि सासद ऊपर से नियंत्रण करना चाहते हैं। वे केंद्रीकरण केंद्र और राज्य के स्तर पर अनेकानेक विस्तृत व्यवस्थाएँ हैं। अंकेक्षण का सास्थानिक तत्र है, जो समय की कसौटी पर खरा उतर चुका है। इसी तरह, सरकार द्वारा प्रायोजित और नागरिक सगठनो द्वारा समर्थित सतर्कता सिमितियाँ है। दूसरे स्तर पर, भारत एक अढितीय देश है जिसने प्रत्यक्ष लोकतत्र का अनूठा संवैधानिक मच मृजित किया है—ग्राम सभा, जिसे स्थानीय विकास और व्यय की निगरानी करने के विशेष अधिकार मिले हुए है। नवाचार के इन प्रयोगों से 'सामाजिक अंकेक्षण' की अवधारणा का विकास हुआ है।

ये सभी तत्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यह स्वीकार करने में हिचक नही होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है, तो निगरानी के मौजूदा ताने-बाने को मजबूत करना, ताकि वह सचमुच असरदार हो सके, क्या ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा? उदाहरेंण के लिए, संविधान समीक्षा समिति ने सार्वजनिक निकायों के खातों के अंकेक्षण से संबंधित अपर्याप्त कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया है, जिनके कारण कोष का दुरुपयोग होता है, परियोजनाओं का शिथिल और विलंबग्रस्त क्रियान्वयन होता है और पूरी प्रणाली ही अंततः कमजोर होती है। समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि पचायतो के खातों के अंकेक्षण के लिए आवश्यक प्रावधान किये जाएँ, ताकि अंकेक्षण से संबंधित सारा कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर पूरा हो सके। साथ ही, भारत के नियत्रण एवं लेखा महापरीक्षक को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे पंचायतों के खातों का अंकेक्षण करवा सकें अथवा इसके लिए लेखा प्रतिमान निर्धारित कर सके। अगर मंत्रालय ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया होता और तब भी स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं होता, तब कहीं सांसदो को ऊपर से उतारने के पक्ष मे दिये जा रहे तर्कों का कुछ औचित्य हो सकता था। लेकिन अपनी दोपी से सांसदो को जमीन पर उतार कर सरकार पंचायती राज संस्थाओं की अवमानना की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ा रही है।

बहुत सारी बाधाओं और पंचायतों को महत्वहीन करने के तमाम सरकारी प्रयत्नों के बावजूद त्रि-स्तरीय पचायतों का बैलेंस शीट सकारात्मक है। पंचायतों की भूमिका के बारे में अंतिम निर्णय देने के लिए दस वर्षों की अविध बहुत छोटी है। तथ्य यह है कि ग्रामीण भारत एक मीन क्रांति से गुजर रहा है। वहाँ एक नये ढग का नेतृत्व उभर रहा है। अभी तक बहिष्कृत समूह और समाज के सीमात पर स्थित वर्ग अब राष्ट्रीय ससाधनों में अपने हिस्से की मॉग कर रहे हैं। साधारण पुरुष और महिलाएँ अब सिस्टम का अंग हो गयी हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति का व्याकरण ही बदलने की प्रक्रिया में है। पचायतों को भारत के संघीय ढाँचे का तीसरा सस्तर बनाये जाने की दसवी वर्षगाँठ पर, ऐसा लगता है, जनसाधारण के पास जश्न मनाने के कारण मौजूद हैं।

मीडिया की नजर

इन दिनों समाचार देखते हुए कुछ परेशान करनेवाले खयाल मेरे मन मे आते है। आध्र प्रदेश में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी जो खबर मेरे हिसाब से वहुत महत्वपूर्ण, सदमे में डालनेवाली और त्रासद थी, उसे दिन की चौथी या पॉचवी खबर के रूप मे धकेल दिया गया था, जबिक उस दिन की अन्य घटनाओं को प्राथमिकता ओर व्यापक चर्चा मिली थी। इस खबर को कम महत्वपूर्ण बनानेवाला जो एकमात्र दृष्टव्य तत्व लग रहा था, वह था इसका तीखा और विशिष्ट 'ग्रामीण' चरित्र।

आज यह लगभग अनकहा तथ्य है कि ग्रामीण भारत के लांग और उनके सकट अब हमारे मीडिया की मुख्य धारा की प्राथमिकता-सूची में नहीं रह गये है। इस समूचे मुद्दे का एक डरावना पहलू यह है कि यह प्रवृत्ति बड़ी तेजी से और बिना

किसी प्रश्न के स्वीकार्य होती जा रही है। पीछे मुझ कर देखें तो हम पाते हैं कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान और 1947

के बाद के वर्षों में प्रिंट मीडिया ने खुद को मूलतः एक सार्वजनिक उपयोग की सेवा के रूप में प्रस्तुत किया। इसने आम लोगों के कई अभियानों में सिक्रिय सहयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और सामाजिक बदलाव के पक्ष में तार्किक आवाजों को अभिव्यक्ति की जगह सुलभ करायी, भारत के विकास के लिए जनमत बनाया। 1946 में दिल्ली में हुए एशियाई सम्मेलन में गाधी जी ने जो कहा था—'यह (दिल्ली) भारत नहीं है, गाँवों में जाइए, वहीं भारत है, वहाँ भारत

जो कहा था—'यह (दिल्ली) भारत नहीं है. गांवों मे जाइए, वही भारत है, वहाँ भारत की आत्मा बसती है।' वह काफी समय तक भारतीय पत्रकारिता के लिए वेद-वाक्य रहा। भाषाई प्रेस ने एक उत्पेरक की महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिसके जरिये हाशिये के जनमत के निर्माण, अभिव्यक्ति और प्रसार की गुंजाइश बनी।

धीरे-धीरे, कुछ दशको में, स्थितियाँ बदल चुकी है। आर्थिक पूर्वाग्रहों ने जनपक्षीय वैचारिक संवेदनशीलता को बेदखल कर दिया है। ऐसा लगता है कि मार्केटिंग टीमें सपादकीय विभागों से ऊपर हो गयी हैं। इसका एक कारण यह लगता है कि समाचारपत्र मालिकों के रांजाना दखल ने अखबारों के सपादकों और सवाददाताओं के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया है। वस्तुतः समाचारपत्र कारपोरेट या राजनैतिक तंत्र से मोल-तोल करने लगे है। इसका शिकार ग्राम आधारित विकास की खबरें हुई हैं। आज अखबारों का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा आय बढाना है। इसके लिए जनता की जरूरतों को नहीं, बल्कि विज्ञापन को ध्यान में रख कर की गयी खबर अहम है। इसका यह भी मतलब है कि अखबारों को अब उन्हीं लोगों तक पहुँचना है जिनके पास खरचने के लिए पैसा है। दूसरे शब्दों में, उनका लक्ष्य शहरी अमीर है।

भूमंडलीकरण के आगमन के साथ स्थितियाँ और बदत्तर हुई है। उपभोक्तावाद के इस दौर में मीडिया बुरी तरह 'इमेज-कॉन्शस' है और सिर्फ वही छापता है जो बिकता है। ग्रामीण विकास से जुड़े गम्भीर मुद्दे उबाऊ, शैक्षणिक और कुछ ऐसी चीज माने जाते हैं जो बिकती नहीं है। इसलिए यह बाजार तय करता है कि क्या खबर बनने लायक है और किस मुद्दे को कितनी जगह मिलनी चाहिए। यह विडंबनापूर्ण हे कि भारत में 70 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण आबादी रहते हुए भी हमारे तथाकथित राष्ट्रीय अखबार बुरी तरह नगर-केंद्रित बने रहते हैं। लगभग सभी मुद्दो, संकटो, विश्लेषणों और खबरों को उच्च और मध्य वर्ग-केद्रित 'नगर दृष्टि' झेलनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रो से जुड़े विकास के मुद्दे ज्यादातर किनारे कर दिये जाते हैं या फिर इन्हें नगण्य-सी जगह दी जाती है—खबर के लिहाज से उनकी चाहे कितनी भी अहमियत क्यों न हो। आदर्श रूप में मीडिया को प्रारंभिक चेतावनी का स्रोत होना चाहिए, जिससे आनेवाली किसी खतरनाक तबाही की पूर्ण सूचना मिले। दुर्भाग्य से वे सूखा, अकाल, बाढ़ और अन्य तबाहियों के निरपेक्ष सदेशवाहक रह गये हैं-वह भी तब जब वे 'सदी की बदतरीन घटनाएँ' हो जाती हो। हालाँकि सभी अखबारो में राजनीति, खेल, व्यवसाय, फुरसत, जीवन शैली और नगर चर्चा के लिए निर्धारित पृष्ठ होते हें, लेकिन किसी मे भी जमीनी मुद्दो या आजमाये जा रहे विकास के वैकल्पिक मॉडलो पर कोई परिशिष्ट नही होता। शख्सियतो-फिल्मी सितारों या राजनीतिज्ञों-के पीछे भागना रोजमर्रा का काम हो गया है। 'पेज तीन' प्रवृत्ति हर तरफ है। कौन-सी शख्सियत कौन-सी किताव पढ़ रही है, इस पर पूरे-पूरे परिशिष्ट आते है, मगर यह बात खबर वनने लायक नहीं है कि हमारे गाँवों में स्कूल या सडक जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी है या नहीं।

इस प्रवृत्ति का खतरा यह है कि इससे शहरी लोगों और गॉववालों के वीच पहले से ही मौजूद खार्ड को और चौडा करने मे मदद मिलती है। शहर मे रहनेवाला व्यक्तित्व ग्रामीण क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति से अनजान और जमीनी आंदोलनों के प्रति संवेदनहीन होता जाता है। शहरी समाज के लिए 'भारत' शहर की सरहदों तक सीमित है। दूसरी ओर, गाँववाला खुद को 'बाकी देश' से ज्यादा-से-ज्यादा कटा हुआ और अलग-चलग महसूस करता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद को गर्व के साथ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बताने के बावजूद हम ग्रामीण क्षेत्रों के हालात से जुडी समस्याओं को कभी महत्व नहीं

देते। मीडिया को इसका ध्यान सिर्फ तभी आता है जब राजेद्र सिंह जैसे किसी 'पानी बाबा' को किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान का कोई पुरस्कार मिलता है। यही हाल जमीन

से जुड़ी राजनीति का है। राष्ट्रीय राजनीति को अखबारों में महत्वपूर्ण जगह मिलती है, जविक ग्रामीण राजनीति की कोई खबर ही नहीं होती।

इसका एक उदाहरण प्रिट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाली पचायत की

खबरें हैं। 73वें सविधान सशोधन के साथ इस बात को व्यापक मान्यता मिली हे कि जिला और उसके नीचे की पचायतें प्रशासन का नीसरा स्तर हो गयी है ओर

कि जिला और उसके नीचे की पंचायते प्रशासन का नीसरा स्तर हो गयी है ओर इस तरह पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुने हुए करीब तीस लाख सदस्य होते है। जिला स्तर पर 504 पंचायते हैं, करीब छह हजार पंचायते उससे नीचे के स्तर

पर और ढाई लाख से ज्यादा गाँव के स्तर पर हैं। ग्यारहवी अनुसूची के अंतर्गत इन्हें 29 विषय मिले हुए है। 73वे संविधान सशोधन के पारित होने के बाद के नौ

वर्षों में पंचायतो से जुड़े कामकाज और मुद्दों को हमारे जन संचार के साधनो ने कितनी जगह दी है? करीब पाँच प्रतिशत? यह भी एक उदार अनुमान ही होगा।

पिछले दिनों जब इस सविधान संशोधन का दसवाँ साल शुरू होनेवाला था, नयी दिल्ली मे देश भर से पचायतो के 1500 चुने हुए प्रतिनिधियो का राष्ट्रीय सम्मेलन इआ। यह एक अनुठा अवसर था—जीवत और अर्थवान, मगर कुछ हिंदी और भाषाई

हुआ। यह एक अनूठा अवसर था—जीवत और अर्थवान, मगर कुछ हिंदी और भाषाई अखबारों को छोड़ कर बाकी मीडिया के लिए यह मानो कोई खबर ही नहीं थी। हमारे कितने राष्ट्रीय नेता भाषाई अखबारों में छपी खबरों से अवगत रहते

है? अगर अग्रेजी के राष्ट्रीय अखबार विकास के मुद्दों को नजरअवाज कर दें, तो उस बेचैनी के बारे में किसे पता चलेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में आकार ले रही हैं? अपनी दुर्दशा सामने लाने के लिए इन क्षेत्रों के लोग किसके पास जायेंगे? आज के मीडिया की यह अल्पदृष्टि बहुत खतरनाक है।

हमारे देश में समस्याएँ कई है और विविध किस्म की हैं, और अगर अखबार उनकी खबर न दे तो यह एक खतरनाक स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ ग्रामीण मुद्दों को ही उजागर करने की जरूरत है, लेकिन खबर

यह नहीं कि सिर्फ ग्रामीण मुद्दों को ही उजागर करने की जरूरत है, लेकिन खबर देने के मामले में सतुलन बनाने की कोशिश अवश्य होनी चाहिए। प्रारंभिक काल के अखबारों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का एक एहसास हुआ

करता था। उन लोगो को राष्ट्र-निर्माताओं की तरह देखा जाता था जो अपने अखबारों में लेखों के जरिये एक सार्वजनिक वहस खड़ी करते थे और नीति-निर्माताओं पर दबाव बनाते थे। वे प्रमुख लेखकों के आलेख मेंगवाते थे, अपने संपादकीय में विकास के विभिन्न मुद्दो पर बहस चलाते हुए और लोगों का नजरिया बदलते हुए राष्ट्र-निर्माण में योगदान देते थे। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान वेटखल हुए लोगों को मीडिया द्वारा उनकी दुर्दशा उजागर किये बिना उचित मुआवजा मिल सकता है?

समकालीन परिस्थिति बहुत ही कटु है। कुछ खास उद्देश्यों को ध्यान मे रख कर ही मुद्दों को सामने लाया जाता है। उनमें से एक है शहरों की व्यवस्था ओर यह कि किस मुद्दे से कौन जुड़ा है। चाहे कोई मामला अपने आपमें कितना भी गभीर हो, वह तभी उठाया जायेगा जब कोई शिख्सियत उससे जुड़ी हो। यही बक्त है जब मुख्य धारा का मीडिया ग्रामीण विकास और जमीनी समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उचित जगह देने के बारे में सोचना शुरू करे और जो बात गांधी जी ने भारत की स्वाधीनता की पूर्व-सध्या पर कही थी, उसे संजीदगी से तें—'गॉवों में जाइए, वही भारत है।'

भविष्य पर मँडराते ग्रह

दस वर्ष पहले 22 और 23 दिसंबर 1992 को जब लोक सभा और राज्य सभा ने सिवधान का तिहत्तरवाँ और चौहत्तरवाँ संशोधन पारित किया, जिनमे पचायतां ओर नगरपालिकाओं को 'स्वशासन की इकाइयाँ' बनाने की व्यवस्था की गयी थी, तो इसे एक ऐतिहासिक घटना और एक मौन कित का प्रारभ माना गया था। किसी भी दृष्टि से देखा जाये, रूप और वस्तु दोनों के लिहाज से यह एक रेडिकल संवैधानिक कदम था। दस वर्ष की यात्रा के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं?

पहली वात तो यह है िक पहले दस वर्षों की यह अवधि पूरी तरह से निराशाजनक नहीं रही है। स्वशासन की इस नयी व्यवस्था को जिन कठिन सामाजिक और राजनीतिक दबावों के बीच—सामाजिक विषमता, जाति प्रथा, पितृसत्तात्मकता, सामंती ढाँचा, निरक्षरता, असमान विकास—काम करना पड़ा है, उन्हें देखने हुए हम कई चीजो पर गर्व कर सकते है।

उदाहरण के लिए, आज प्रत्येक पाँच वर्ष पर स्थानीय स्वशासन की सस्थाओं का नियमित चुनाव एक प्रतिमान बन गया है, यद्यपि शुरू के वर्षों में प्रायः सभी राज्यों ने—उनमें चाहे जिस पार्टी की सत्ता हो—अपनी पूरी ताकत से इस संवैधानिक उपबध की अवहेलना की। स्थानीय लोकतत्र को यह पुख्ता आधार देने में जहाँ एक ओर नागरिक समाज के सगठनों की जबरदस्त भूमिका रही, जिन्होंने जन हित याचिकाएँ

दायर कर राज्यों के इस संविधान-विरोधी रवैये का विरोध करने की पहल की, वहीं न्यायपालिका ने भी विभिन्न स्तरों पर प्रभावशाली ढग से हस्तक्षेप किया।

अपने आपमें यह भी कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएँ सभी राज्यों में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोगों ने पंचायत चुनावों को गंभीरता से लिया है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख बनी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में तो राज्य चुनाव आयोगों ने अतिरिक्त सिक्रयता भी दिखायी है। 3 मई 2002 की उच्चतम न्यायालय ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानने के लिए मतदाता के अधिकार के बारे में जो निर्णय दिया था, उसके आधार पर राज्य चुनाव आयोगों ने पचायत एवं नगरपालिका चुनावों के लिए भी ऐसे ही निर्देश जारी किये है। आखिर पंचायतों और नगरपालिकाओं के मतदाताओं को भी अपने उम्मीदवारों के बारे में जरूरी सूचनाएं हासिल करने का अधिकार है।

पिछले दस वर्ष इस तथ्य के भी गवाह रहे हैं कि जहाँ तक ग्राम स्तर से जिला स्तर तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में वंचित तबको को शामिल करने का सवाल है, इस क्षेत्र में क्रिमिक प्रगति हुई है। इसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। आज दस लाख से ज्यादा महिलाएँ हर पाँच वर्ष पर स्थानीय निकायो के सदस्यो और अध्यक्षों के पदो पर निर्वाचित होती हैं और 30 लाख से ज्यादा महिलाएँ इन पदों के लिए चुनाव लड़ती हैं। हमारे जैसे सोपानीकृत और पुरुष वर्चस्वयाले समाज के लिए यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह आम शिकायत कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवारों के पुरुष ही उनकी लोकतात्रिक सत्ता का सचालन करते हैं, आशिक रूप से सही हो सकती है। लेकिन विभिन्न अध्ययनों से यह बात सामने आयी है कि अब स्थिति मे तेजी से परिवर्तन आ रहा है। विभिन्न स्तरों की सभी पचायतों और नगरपालिकाओं मे से एक-तिहाई के अध्यक्ष पद पर महिलाएँ हैं। समय बीतने के साथ-साथ सामान्य यानी अनारिक्षत सीटों से चुन कर आनेवाली महिलाओं की सख्या बढ़ती जा रही है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ भी स्थानीय निकारों में अपना वाजिब हक पा रही है।

देश भर में स्वशासन की संस्थाओं के अस्तिन्व में आ जाने के कारण उनके काम-काज पर निगाह रखी जा रही है और इस पर चर्चा भी होने लगी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि शासन को लोगों के दरवाजों तक ले जाने के पक्ष में सकारात्मक माहौल धीरे-धीरे ही सही, पर तैयार हो रहा है। इस प्रक्रिया की एक प्रमुख उपलब्धि यह है कि सरक्षण देने और पृष्ठिपोधक बनने की जो भूमिका परंपरागत जातियों और प्रभावशाली परिवारों के हाथ में रही है, वह राजनीतिक पार्टियों और विचारधाराओं को स्थानांतरित हो रही है।

लोकतात्रिक प्रक्रिया के इस क्षैतिज विस्तार का लाभ उठाते हुए बहुत-से राज्यों ने स्थानीय शासन, योजना प्रक्रिया तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक नवाचार तथा रचनात्मक प्रयोग किये हैं। केरल का जन योजना अभियान इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है।

वहरहाल, दस वर्षों का आंतिम लेखा-जोखा देखा जाये, तो निराशा-सी होती है। यह विडंबना ही है कि जिन हाथों ने नयी पचायत और नगरपालिका व्यवस्था की नींव रखी, वे हाथ ही इसे निष्प्रभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी तो लगता है कि इरादा इनकी हत्या करने का ही है। परिणामस्वरूप, देश के अनेक हिस्सों में मौन क्रांति खूनी क्रांति में परिणत हो चुकी है।

पंचायतों और नगरणिलको को उनका प्राप्य न तो मंसद के सदस्य दे रहे है न ही विधान सभाओं के सदस्य। सच तो यह है कि सांसद और विधायक स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के वैध स्थान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं तथा विधायक कोषों का अस्तित्व, जिनकी राशि करोड़ों रुपयों में है, स्थानीय निकायों के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है? 'आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय' के लिए योजनाएँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पंचायत व्यवस्था की मृष्टि करने के बाद हमारे सांसदों और विधायकों को स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए राज कोष से करोड़ों रुपये क्यो मिलने चाहिए? निश्चय ही पचायतों की हैसियत को कमजोर करने और उन्हें हाशिये पर लाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है।

इसी तरह का दूसरा गंभीर उदाहरण सांसदों, विधायको और नौकरशाही की वह उत्सुकता है कि सभी केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के बजट को पंचायतों के दायरे के बाहर खर्च किया जाये और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) नामक संस्था को जीवित और सक्रिय रखा जाये। योजना आयोग द्वारा गठित 'पचायती राज संस्थाओं पर कार्य दल' (दिसंबर 2001) ने टिप्पणी की है कि राज्य सरकारो और केंद्रीय मंत्रालयो ने केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्यक्रम तथा उसकी रणनीति बनाने में पवायती राज सस्थाओं को शामिल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है तथा ये योजनाएँ अनिवार्यतः नौकरशाही के सोपानीकृत संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। राजनेता, नौकरशाह और ठेकेदार-इन तीन तत्वो का अपवित्र गठबंधन सारा मलीदा खा जा रहा है। (केंद्र-प्रायोजित कार्यक्रमो के लिए 2000-01 के केंद्रीय बजट में 31,575.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।) पचायतों को सुदृढ करने के स्थान पर उन पर उँगली उठायी जा रही है और कहा जा रहा है कि वे भ्रष्टाचार से सराबोर है। लेकिन हमारी नेता-नौकरशाह जोड़ी यह भूल जाती है कि पचायतों के लिए यह 'आदर्श मॉडल' उन्होंने ही तैयार किया है। भ्रप्टाचार और छदम के विशाल महासागर में हम ईमानदारी और निष्ठा के द्वीप कैसे गढ़ सकते है?

पंचायतों की अक्षमता और अकुशलता का ढिंढोरा पीटनेवाले बढ़ते जा रहे है। लेकिन उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए किया क्या गया है? नहीं के बरावर। इसका कारण क्या है? क्या धन की कमी? नहीं। न केवल हमार पास पर्याप्त संसाधन हे, बल्कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियाँ भी मानव पूँजी के विकास मे विनियोग करने के लिए तैयार है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें कोई रुचि नहीं है। प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण विकास राज्य संस्थान है, जिसे कायदे से पचायतो के सदस्यों और कार्यपालकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण का कंद्र होना चाहिए था। लेकिन ये राज्य संस्थान निहायत उपेक्षित है और इस महत्वपूर्ण काम को अजाम देने के आवश्यक साधन भी उनके पास नहीं है। लेकिन इसकी परवाह किसे है?

केद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय पचायती राज के साथ जो सलुक कर रहा है, वह किसी फूहड मजाक से कम नहीं है। जब कि ढाई लाख ग्राम पचायतो. 6000 पचायत समितियो और 600 जिला पंचायतो को मार्ग दर्शन देने और उनके काम-काज पर निगरानी रखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय मे एक सपूर्ण संभाग की सख्त जरूरत है, पचायती राज के लिए सचिव स्तर का कोई अधिकारी तक नहीं है। यह कार्य संयुक्त सचियो को अतिरिक्त दायित्व के रूप में सौंप दिया गया है। मत्रालय के जिन अधिकारियों को पंचायती राज की कुछ जिम्मेदारी सौपी गयी है, उनके काम-काज का कुछ अता-पता नहीं है। प्रधान मन्नी ने हाल ही मे कहा कि संविधान का पुनर्वीक्षण करने के लिए गठित न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग की सिफारिशो के आलोक मे अनुच्छेद 243 को, जिसका सबंध पचायतो से है, धारदार और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। लेकिन जिसकी कुछ चलती है, ऐसे किसी भी व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया है। कोई भी राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशो को वह महत्व नहीं देती जो उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी तरफ, राज्य चुनाव आयोग, जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएँ है, कठिन सीमाओं के तहत काम कर रहे हैं। चाहे पचायतो और नगरपालिकाओं के पुनर्सीमन का मामला हो या चुनाव की तारीखें घोषित करने का या कोई अन्य सबंधित मुद्दा, राज्य सरकारे राज्य चुनाव आयोगों को अपनी इच्छानुसार चलाने की कोशिश करती हैं। जिला योजना समितियाँ, जो भारत के योजना इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्व की घटना है, या तो गठित ही नहीं की गयी है या गठित की गयी है तो सिफ नाम के वास्ते। राज्यों में पचायत काडर नाम का कोई तत्र नहीं है न ही इसका गठन करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है। स्पष्टता अथवा वैचारिकता के अभाव मे विभिन्न विभागों के बीच इस मुद्दे पर फालतू कलह जारी रहता है कि विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारियो और कर्मचारियो का निर्वाचित स्थानीय निकायों से रिश्ता क्या हो।

यह सब देख कर दिमाग चकरा जाता है कि जब मंत्रियों और विधायको ने तिहत्तरवाँ और चौहत्तरवाँ संविधान संशोधन पारित किया, तो क्या वे समझ भी रहे थे कि इस नयी पंचायत प्रणाली से देश के राजनीतिक तत्र मे कितने गभीर परिवर्तन आ सकते हैं। अब जा कर उनकी समझ में आया है कि यह तो जनता के हाथ में सत्ता देने का एक सक्षम औजार है और यह औजार ठीक से काम करे, तो आजादी के बाद से वे जो ताकतें अपने पास जमा करते रहे है, उनका एक बड़ा अंश उनसे छिन जायेगा, तो इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि पंचायतो के 'स्वशासन

की संस्थाएँ' तथा शासन का तीसरा पाया बनने की प्रक्रिया को रांका जाये।

दस वर्षों की यात्रा बहुत लंबी यात्रा नहीं है। पचायतों ने कोई जादू नहीं किया है, पर एक छोटी-सी शुरुआत जरूर हुई है—बावजूद इसके कि सासदों और विधायकों ने उनका अवमूल्यन करने की जी तोड़ कोशिश की है। सभव है, उन्हें वीडीओ राज और पटवारी/ग्राम सेवक राज के बने रहने में अपना फायदा नजर आता हो। लेकिन अगर हम राजनेताओं और नौकरशाहों पर निर्भर रह जाते हैं, तो सचमुच का पंचायती राज दिवास्वप्न ही बना रहेगा। इस निराशाजनक परिदृश्य को बदलने के लिए लोगों को स्वय आगे आना होगा।

λ ŧ . 1

दो पंचायतों की कहानी

जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में देश की पहली पचायत समिति का उद्याटन किया था। इस प्रचायत का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा

बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशो को स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप हुआ था। महता समिति ने सिफारिश की थी कि 'सामुदायिक कार्यों में जनता की भागीदारी को वैधानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के जरिये सुनिश्चित किया जाना चाहिए।' इसके

नौ दिन बाद नेहरू आंध्र प्रदेश गये और उन्होने वहाँ शादनगर मे 11 अक्टबर 1959 को दसरी पंचायत समिति का उद्घाटन किया। स्वतत्र भारत में पंचायती राज के उद्घाटन के लिए नेहरू इन्ही दो स्थानो पर क्यों गये थे? पंचायती राज संस्थाओ

की स्थापना के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बुनियाद डालने में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा गहरी दिलचस्पी लेने के 42 वर्ष के बाद इन दो पंचायतों का हाल

कैसा है? इन प्रश्नों तथा अन्य संबंधित प्रश्नों के जवाब ढूढने के लिए इस लेखक ने नागौर और शादनगर जा कर स्थिति का निकट से अध्ययन किया। पंचायती राज

को एक नये उत्साह के साथ लागू करने के इस दौर मे उस अध्ययन के नतीजे काफी पासंगिक हैं।

नागीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित ऊँघता हुआ-सा जिला मुख्यालय है। लोग इसके शानदार इतिहास के बारे में बाते करते हैं। यह कस्बा 850 वर्ष पुराना है। यह चौहानों की सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र

था, जिन्हे मुसलमान सम्राटो ने अतत हरा दिया और सभी संधियाँ नागौर में हुई थीं। किसी जमाने में यह मरुस्थलीय काफिलो का भी महत्वपूर्ण पड़ाव था।

नागौर जाट-बहुल इलाका है। यहाँ की आबादी में जाटों की संख्या 60 प्रतिशत है। उनके अलावा यहाँ 10 प्रतिशत राजपूत, 23 प्रतिशत मेघवाल (अनुसूचित जाति) तथा 10 प्रतिशत मुसलमान है। नागौर में साल में सिर्फ एक फसल होती है। किसान बाजरा, जीरा तथा सरसो उगाते हैं।

दो पंचायतों की कहानी : 169

नेहरू जब नागौर आये थे, तब नागौर पचायत सिमिति के अध्यक्ष हिराम बागड़िया (65) थे। उस समय वह सिर्फ 29 वर्ष के थे और वकालन कर रहे थे। वे अब भी वकालत कर रहे है और उनके पास बी. कॉम. और एलएल. बी की डिग्री है। श्री बागड़िया उन दिनों की यादों में डूवते हुए बताते है कि नेहरू जी के हवाई जहाज को उतारने के लिए मारवाड के राजा द्वारा बनायी गयी हवाई पट्टी का नवीनीकरण किया गया था। नेहरू दोपहर दो बजे वहाँ पहुँचे थे। अन्य लोगों के साथ श्री बागड़िया ने भी प्रधान मत्री को माला पहना कर उनका स्वागत किया था। उनके ड्राइग रूम मे हवाई पट्टी पर नेहरू जी का स्वागत करते हुए उनकी वडी-सी तस्वीर टॅगी हुई है। उन्हें 15 सितम्बर को 30 सरपंचों ने सिमिति का प्रधान चुना था। सरपंच पद के लिए सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही उम्मीदवार बन सकते थे। अनुसूचित जाति और महिलाओं के दो-दो प्रतिनिधियों को नामांकित किया गया था।

श्री बागडिया के अनुसार नेहरू जी एस.के दे के कारण नागौर आये थे। श्री दे जनवरी 1958 में नागौर के पशु मेले में आये थे और वहाँ से 1962 का संतदीय चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन समाजवादी नेता बंसीलाल सारस्वत (अब भाजपा में) कुछ अलग ही किस्सा सुनाते हैं। उनके मुताबिक नेहरू जयनारायण व्यास के रसूख के कारण नागौर आये थे। श्री व्यास स्वतंत्रता आदोलन में राजस्थान के अग्रणी नेताओं में थे और वे स्वय भी समाजवादी थे। राजस्थान के मुख्य मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने 1958 में सामतशाही खत्म की थी तथा चूँिक मारवाड मे राजपूत बड़े-बड़े जमीदार थे, इसलिए इस इलाके में उनके कामों को जनता के बीच काफी प्रसिद्धि मिली थी। इस क्षेत्र मे नागौर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था और श्री व्यास द्वारा उठाये गये कदमों से जाटो को काफी लाभ हुआ था।

सभा स्थल पर नेहरू जी को एक जुलूस के साथ ले जाया गया। मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने श्री नेहरू का स्वागत किया। मंच पर पचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा, लोक सभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा एवं एस.के. दे भी नेहरू जी के साथ विराजमान थे। नेहरू जी ने हिंदी में एक घटे तक भाषण दिया था। करीब 20 हजार लोगों ने बहुत ध्यान से उन्हें सुना। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसार ने भी उस मौके के लिए संदेश भेजा था। राष्ट्रपति ने कहा था, 'जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारतीय गणतंत्र के किसी भी सदस्य राज्य ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर विकेदीकरण का प्रयोग करने की ठानी है।' सभा के बाद नेहरू जी ने किले में रात का खाना खाया था। श्री बागड़िया के अनुसार तीन से चार हजार प्रधान और प्रमुख तथा अन्य लोग सामूहिक भोजन के इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे।

नागौर पंचायत समिति ने 1959 के अपने एजेंडे में प्राथमिक शिक्षा, सहकारी सस्थाओं तथा पंचायत घरों के निर्माण को प्राथमिकता दी थी। नागौर में 1959 में बालिकाओं के लिए सिर्फ तीन प्राथमिक पाठशालाएँ थी, जब कि लड़कों के लिए ्रिसी शालाओं की संख्या 20 से अधिक थी। पिछले 36 वर्षों में और सिर्फ एक ाथिमक शाला खोली गयी है। शायद इसीलिए नागौर में महिला साक्षरता दर आज भी सिर्फ 7 08 प्रतिशत है। पहली और दूसरी सिमितियों (1959 और 1961) के कार्यकाल में शिक्षक नियमित रूप से कक्षाओं में आते थे एव उनके कामकाज के निरीक्षण के लिए अध्यक्ष एवं सदस्य स्कूल आते-जाते रहते थे। लेकिन पचायत सिमितियों के पास संसाधनों की कमी थी, क्योंकि उन्हें प्रति एक रुपया भू राजस्व पर शिक्षा के लिए सिर्फ पाँच पैसे की चुगी मिलती थी। इसके साथ ही सिमितियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से समुचित परिवर्तन करने की भी आजादी नहीं थी। उदाहरण के लिए, नागौर सिमिति विद्यालयों को गर्मियों में खुला रख कर दशहरा व दीवाली (अक्टूबर-नवम्बर) के दिनों में बंद रखना चाहती थी, क्योंकि उन दिनों खेतां का कामकाज जोरो पर होने के कारण उसमें हाथ बँटाने के लिए बच्चों की जरूरत पडती थी। सिमिति के इस सुझाव को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने ठुकरा दिया था, हालाँकि श्री बागडिया के मुताबिक वे अपने स्तर पर अनौपचारिक इग से गर्मियों में भी कक्षाएँ चलाते रहे।

शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता होने पर भी उन्हें नियुक्त करने का अधिकार सिमितियों के पास नहीं था। हमारी बातचीत के दौरान वहाँ उपस्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'ब्लॉक में 112 शिक्षकों के पद खाली हैं और बार-बार पत्र लिखने के बावजूद नये शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। जिला पदाधिकार-सस्थापन सिमिति एक तो वैसे ही चयनित शिक्षकों को नहीं भेजती; दूसरे चयनित शिक्षक भी गॉवों में काम करने को तैयार नहीं हैं। इस स्तर पर पचायत सिमित निरुपाय है।' हमारी बात सुन रहे एक युवा अफसर ने बाद में कहा, 'इस क्षेत्र में सभी की शिक्षा के लिए कोई प्रतिबद्ध प्रयास किया ही नहीं गया। ऐसा जानबूझ कर किया गया था। शिक्षित हो जाने पर वे पारपरिक नेतृत्व को चुनौती देने लगेगे।' बसीलाल सारस्वत का मानना है कि शिक्षा के निम्न स्तर के लिए पारिवारिक पूर्वाग्रह और अनिच्छुक शिक्षकों का (उनमें से ज्यादातर के पास आजकल ट्रैक्टर है और वे खेती के धंधों में लगे रहते हैं) रवैया मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

लगातार 18 वर्ष (1959 से 1977) तक जिला परिषद के प्रमुख रहे लिकोमाराम ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वे प्रमुख बने थे, तब परिषद का बजट 36 हजार रुपये का था। वे किले में किराये के एक दफ्तर में बैठते थे। उसके बाद जल्दी ही प्रधानो ने अपने-अपने कोष से चंदा दे कर जिला परिषद कार्यालय की इमारत का निर्माण कराया और नागौर की जिला परिषद देश की ऐसी पहली परिषद बन गयी. जिसका अपना कार्यालय भवन था।

समिति में 1959 में दो महिलाएँ थीं, मगर केवल नाम के लिए। दोनो जाट थी। उनमे से एक का नाम श्रीमती सोनी था। श्री बागड़िया के अनुसार वे विधवा थी आर अकत्तर तीर्थ यात्रा पर रहती थी और उन्ह 1961 तथा 1965 मे भी नामांकित किया गया। वे समिति की बैठकों में शामिल तो होती थी, लेकिन उनका योगदान कुछ नहीं था। किसी भी महिला ने चुनाव नहीं लंडा था।

देश के पहले प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटित पंचायत समिति नागौर के जीवन पर कोई छाप नहीं छोड पायी थी। आज, 35 साल बाद, वह विफलता का प्रतीक है। संपूर्ण तत्र की विफलता के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में आम तौर पर बताये जानेवाले कारण यहाँ भी वरिष्ठ नेताओ द्वारा दोहराये गये—पचायत के सीमित अधिकार, निरक्षरता, शिक्षा की कमी, पैसे की भारी किल्लत, अनियमित चुनाव, बेपरवाह नौकरशाही, सर्वसत्तासंपन्न सरपंच, जिसके हाथ में सारे वित्तीय अधिकार केंद्रित थे और जबरदस्त भ्रष्टाचार। मोहनलाल सुखाडिया द्वारा प्रधानों को महत्व देने के बावजूट विधायक कभी भी पचायतों को अधिकार नहीं देना चाहते थे। पचायतों के शक्ति-सपन्न होने से विधायकों को डर यह था कि वे अधिकारविहीन हो जायेगे, इसलिए वे बाहर से पचायती राज का समर्थन करने के साथ-साथ भीतर-भीतर उसे पलीता लगाते रहे।

नागौर शहर से बसनी ग्राम पंचायत लगभग 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ की आबादी 35 हजार है। गाँवों मे ज्यादातर मुसलमान है जो दूध का धंधा करते है। इस समृद्ध गाँव की पहचान मुंबई को दुधारू भैसे भेजनेवाले गाँव के रूप में होनी है। करीब 4,000 दूध न दे सकनेवाली भैसे बसनी में है, तो यहाँ की 8,000 दूध देने वाली भैसे मुंबई और राजस्थाान के अन्य हिस्सो में। गाँव के प्रवक्ता और प्रमुख व्यापारी मुहम्मद कासिम कश्मीरी के मुताबिक पंचायती राज से लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। 35 साल पुराने इतिहास के बावजूद उनकी ग्राम पचायत शैक्षिक रूप से पिछडी हुई है और वहाँ की 80 प्रतिशत महिलाएँ अनपढ़ है। वर्तमान ग्राम पचायत के 39 सदस्य हैं और वे सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

नागौर में पंचायती राज के विफल होने का अकेला सबसे बड़ा कारण यहाँ एक ही जाति जाटों का वर्चस्व है। जयाले पंचायत समिति के सदस्य (1970-73) जगदीशनारायण जोशी ने इस बात की पुष्टि की कि वर्तमान विकट परिस्थितियों के लिए जाट-गैरजाट संघर्ष जिम्मेदार है। उनके मुताबिक, 'शिक्षक जाट है, सरपच जाट है, बीडीओ जाट है; इसीलिए कोई किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करता। जाट का बोट जाट के लिए है; जाट की बेटी जाट के लिए है।'

वर्तमान नागौर पंचायत समिति में 47 सरपंच है। इनमें से 12 निरक्षर और 32 साक्षर (ये हस्ताक्षर भर कर सकते हैं) हैं, सिर्फ दो ने प्राथमिक शिक्षा पायी है और एक स्नातक है। समिति के 27 सदस्य है। उनमें से एक निरक्षर है, 8 साक्षर हैं, 14 प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं, एक आठवीं पास है, एक सेकंडरी पास है और 2 स्नातक हैं।

नवगठित समितियों में से एक की महिला अध्यक्ष से मैं मिलना चाहता था। नागोर से 20 किलोमीटर दूर मूलवा समिति में सेपू चौधरी 15 फरवरी को निर्विराध

निर्वाचित हुई थी। उनके पति शराब के व्यापारी है और वे 1987 से 1992 तक फिरोद (जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर) के सरपंच रह चुके हैं। अपने नवनिर्मित घर

के दरवाजे पर ही श्री चौधरी ने मेरे सारे सवालो का जवाव देने की पेशकश की, क्यांकि उनकी पत्नी न अंग्रेजी समझती हैं न पचायतों के बारे में कुछ जानती है। मेरे अन्रोध पर वे मुझे अपने आलीशान ड्राइंग रूम में ले गये ओर सेपू सक्चा कर

हमारे पास आ कर बैठ गयी। वे पाँचवी कक्षा तक पढ़ी हैं और उन्हे सामाजिक काय का कोई अनुभव नहीं है। वे 'सरकार' (पित का उपनाम?) के कहे अनुसार ही काम करती हैं, विशेषकर महिलाओं से संबंधित विषयों मे। समिति में सात महिला

प्रतिनिधि चुनाय लड कर निर्वाचित हुई हे, मगर सभी निरक्षर है। सरपच निर्वाचित होने के एक महीने बाद भी सेपू चौधरी अभी तक महिला प्रतिनिधियो से नहीं मिली है। सेपू के चुनाव लड़ने का कारण यह था कि इस समिति के सरपच का पद चूँकि महिलाओं के लिए आरक्षित था, इसलिए उनके पित यह चुनाव नहीं लड़ सकते थे।

लिहाजा उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया था। पचायती राज की विफलता को हर कोई स्वीकार करता है। युवाओं को यह

शिकायत है कि जनता के सरोकारों को सुनने के लिए कोई स्थानीय सस्था नहीं है। सडकें नहीं हैं। नागौर में पीने का पानी नहीं है। लोगों को छोटे-छोटं तालाबों का जनी पीना पड़ता है। श्री बागडिया जब पमस्त श्रे (1985-89) तब उन्होंने टॉक्ट

है। सड़क नहीं है। निगार में पान की पीनी नहीं है। लागा की छोट-छोट तालाबा का पानी पीना पड़ता है। श्री बागडिया जब प्रमुख थे (1985-89), तब उन्होंने टॉके (बारिश का पानी जमा करने के लिए जमीन के अंदर टॉकेयॉ) बनवाने पर विशेष

जोर दिया था। वर्ष 1987 के अकाल वर्ष में 10,000 टाँके बनाये गये थे, जिनके लिए 5,000 रुपये उन्होंने अपने चदे से तथा 5,000 रुपये पंचायत से अनुदान दिया था। नागौर के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तथा गिनी कृमि बहुत अधिक सख्या में हैं। नागौर तक राजस्थान नहर का जल लाने के लिए 17 अरब रुपये चाहिए।

सख्या में है। नागार तक राजस्थान नहेर की जल लान के लिए 17 जरब रुपय चाहिए। यह कोई असभव कार्य नहीं है, लेकिन दबाव डालने और इतनी बडी राशि जुटाने के लिए वहाँ कोई नेतृत्व भी नहीं है। क्या नया पंचायती राज ऐसा कर पायेगा? इस सवाल की इबारत नागौर रेलवे स्टेशन पर हमें छोड़ने आये युवाओं के चेहरे

पर साफ-साफ पढ़ी जा सकती थी। शादनगर (फारूकनगर), बगलूर राजमार्ग पर हैदराबाद शहर से 47 किलोमीटर

की दूरी पर स्थित है। वनपरती के राजा के बड़े वजीर थे, तहलुक। उनका तखल्तुस 'सहेद' था। वे इसी क्षेत्र के थे और 1930 से फारूकनगर को शादनगर के नाम से जाना जाने लगा। यह राज्य के पिछड़े जिले महबूबनगर का एक हिस्सा है।

2 अक्टूबर 1954 को शादनगर ताल्लुक पचायत समिति बन गया, जिसमे 105 गॉव शामिल थे। वर्ष 1959 मे शादनगर ब्लॉक में 66 गॉव थे, जिनकी कुल

173

आबादी 52,000 थी। इस समिति सहित लोकतात्रिक विकेट्रीकरण के प्रयोग के लिए कुल 20 ब्लॉक समितियों (तदर्थ) को चुना गया था। शादनगर पचायत समिति के नामांकित अध्यक्ष प्रताप रेड्डी थे।

तेलुगु देशम सरकार द्वारा जारी नये अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 1987 में शादनगर पंचायत समिति को चार मंडल प्रजा परिषदों में बॉट दिया गया (अन्य तीन परिषदे थीं कोठूर, केशमपेट और कोनदुर्ग)। आज शादनगर मंडल में 36 गाँव, 25 ग्राम पंचायतें तथा एक कस्बा है और कुल 56,759 लोग रहते है।

रामदेव रेड्डी की उम्र अभी 73 वर्ष है। जवाहरलाल नेहरू जब शादनगर पंचायत समिति का उद्घाटन करने आये थे, तब रामदेव उसके अध्यक्ष थे। वे कांग्रेस के तत्कालीन वामपंथी विचारधारावाले प्रदेश अध्यक्ष स्वामी रामनंदर्तीर्थ के अनुयायी थे। पी.वी. नरसिंह राव तथा जे. वेगलराव भी इसी गुट में थे, जब कि कांग्रेस में कोडरोगा रेड्डी के नेतृत्व मे एक प्रतिद्धी गुट भी था। इसी गुट के एक अन्य प्रमुख नेता हैदराबाद रियासत के पहले मुख्य मंत्री बी. रामकृष्णराव भी थे। वे बाद में उत्तर प्रदेश और केग्ल के राज्यपाल रहे। रामदेव रेड्डी ने बी. रामकृष्णराव के भाई वेंकटेश्वर राव को कुल 64 में से 48 वाट पा कर हरा दिया था।

रामदेव रेड्डी के अनुसार, नेहरू के शादनगर आने का कारण यह था कि यह बी रामकृष्णराव का चुनाव क्षेत्र था। वे शादनगर के पास बडगूल गाँव के रहनेवाले थे। सामुदायिक विकास की सफलता के पायदान पर चढनेवाले कुछ विलक्षण अधिकारी—खादरअली खाँ, के.बी. लाल, आबिद हुसैन—भी शादनगर के ही थे। दरअसल, मंडल पंचायत के वर्तमान कार्यालय की इमारत का उद्घाटन भी तत्कालीन विकास उपायुक्त के.बी. लाल ने ही आदर्श पंचायत घर के तौर पर 31 सितम्बर 1958 को किया था। पडित नेहरू ने 11अक्टूबर 1959 को समिति पंचायत कार्यालय से सटे मैदान में हुई ऐतिहासिक सभा में दोपहर दो बजे भाषण हिया था। वे हैदराबाद से सड़क मार्ग में आये थे। उनके साथ मुख्य मत्री नीलम संजीव रेड्डी, सामुदायिक विकास उपमत्री बी.एस. मूर्ति तथा भारत के पूर्व प्रधान मंत्री गी.वी. नरसिंहराव (उन्होंने ही नेहरू के भाषण का नेलुगु में अनुवाद किया था) भी मंच पर विराजमान थे। रामदेव रेड्डी ने याट करते हुए बताया कि सिमिति के अध्यक्ष के नाते उन्होंने ही पड़ित नेहरू का स्वागत किया था तथा दूर-दराज से लगभग 20,000 लोग उनका भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। नेहरू ने अपने भाषण मे कहा था कि 'सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा विकास की जिम्मेदारी लीगो को सौपने का यह महान कार्य आज विजयदशमी के शुभ दिवस से शुरू हो रहा है।' सभा के बाद नेहरू कृष्णदेव राय पॉलिटेकनीक का उद्घाटन करने के लिए वनपरती भी गये थे। शादनगर मे आवार्य विनोबा भावे की यात्रा को भी कुछ लोग ऐसे ही एक अन्य महत्वपूर्ण अवसर के रूप में याद करते हैं। वे 1956 में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए यहाँ आये थे।

शादनगर सिमिति की उपलब्धियाँ क्या थी? पचायत गाँववालो से वडे पैमाने पर श्रमदान करवाती थी, सडको और विद्यालयों की इमारतों के निर्माण में स्वयंसेवी

पर श्रमदान करवाता चा, सङ्का जार विचालवा का इमारता के निर्माण में स्वयसवा श्रमिकों की संख्या 50 प्रतिशत तक थी। जापानी प्रणाली से खेती शुरू की गयी थी। एम. दामोदर रेड्डी इस क्षेत्र के एक अन्य बुजुर्ग नेता हैं। वे नजदीक की कोनदुर्ग

पचायत समिति के 1959 में अध्यक्ष थे, 1962 में विधायक बने तथा 1981 में शादनगर पचायत समिति के अध्यक्ष भी रहें। उन्होंने स्वीकार किया कि उन दिनों कुछ काम ठेकेदारों द्वारा भी कराये जाते थे और इससे लगभग 25 प्रतिशत राशि उनके मुनाफ

के रूप में चली जाती थी। लेकिन 75 प्रतिशत राशि परियोजना में ही लगायी जाती थी। उन्होंने माना कि अब सिर्फ 25 प्रतिशत राशि खर्च होती है और 75 प्रतिशत

राशि कई हाथों में बॅट जाती है। जवाहर रोजगार योजना की राशि का भी दुरुपयोग हो रहा है। बड़े या छोटे अधिकारी ही नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी भ्रष्ट है।

आज तक सभी पचायत समिति के अध्यक्ष रेड्डी जाति के सदस्य ही बने है। ऐसा क्यो हुआ? रामदेव रेड्डी तथा दामोदर रेड्डी दोनों के ही अनुसार, इसका कारण यह था कि वे दोनों ही जनता की सेवा करते है। रेड्डी तथा जनता के बीच गहरा

रिश्ता है। रामदेव रेड्डी के अनुसार गाँवो में उन दिनों विषमता कम थी। उनका दावा था कि 1956 में उनके पास 1200 एकड खेत थे, लेकिन तभी उनकी सारी जमीन

बॉट दी गयी और उन्होंने अपने पास सिर्फ 40 एकड़ जमीन रखी थी। अपने जीवन के सत्तरवे दशक में चल रहे स्थानीय नेताओं से यह दिलचस्प जानकारी मिली कि पचायतों से राजनीतिक नेतृत्व की पूरी पीढी निकली है। नागोर

और शादनगर, दोनों ही जगहों पर कई पचायत अध्यक्ष विधायक बने और राजनीतिक दलो तथा सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण पद सॅभाले। पहली समिति मे दो नामांकित महिला सदस्य थीं—विमलम्मा ब्राह्मण थी ओर

लिख-पढ सकती थी तथा लकम्पा पिछड़ी जाति की थी और सिर्फ दस्तखत कर सकती थी। उनकी एकमात्र योग्यता काग्रेस के प्रति वफादारी थी। वे दोनों सक्रिय थीं, समस्याएँ उठाया करती थी तथा बैठको में नियमित हिस्सा लिया करती थीं। उन दिनो ग्राम सभावों की बैठक भागर ही कभी होती हो। समदेव रेडी ने लेडिकक सह तथा किया

सभाओं की बैठक शायद ही कभी होती हो। रामदेव रेड्डी ने बेहिचक यह दावा किया कि 'महिलाऍ पढ़े-लिखे पुरुषों से ज्यादा चतुर एवं व्यावहारिक है।' शादनगर के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने माना कि पंचायती राज का स्वर्णिम

काल 1959 से 1964 के वीच था। लेकिन उसके बाद 1964 से 1987 तक कुछ भी काम नहीं हो पाया। प्रगति कं बजाय वह पिछड़ने की अवधि रही। इसका एक कारण था पैसे की कमी ' आमदनी का मुख्य स्रोत भू-राजस्व के हरेक रुपये पर

25 पैसे की दर से लगनेवाला उपकर था। स्वर्णिम दौर में 1959-90 के दौरान शादनगर पचायत समिति की आमदनी थी 2,87,530 रुपये तथा खर्च था 1,81,670 रुपये। सामुदायिक विकास खंड के एक व्यय विवरण के अनुसार अक्टूबर 1954 में अपने

निर्माण के सात वर्ष बाट तक शादनगर ब्लॉक में 125 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। यह छोटी-सी रकम भी महबूबनगर मे सबसे ज्यादा थी।

वाद में अर्थाभाव का दौर आया, तो इसकी मार सबसे ज्यादा शिक्षा पर पड़ी। वर्ष 1908 के इम्पीरियल गजेटीयर के अनुसार, महबूबनगर जिले में साक्षरता की दर 3 3 प्रतिशत (पुरुष 5 9 प्रतिशत तथा महिलाएँ 0.65 प्रतिशत) यानी तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से काफी अधिक थी। वर्ष 1961 में यह दर 13.4 प्रतिशत हो गयी थी; 21 5 प्रतिशत पुरुष तथा 5.4 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थी। लेकिन शादनगर की 12.3 प्रतिशत साक्षरता दर (19 9 प्रतिशत पुरुष तथा 4 6 प्रतिशत महिलाएँ) जिले की औसत साक्षरता दर के मुकाबले कम थी। शादनगर की वर्तमान साक्षरता दर 23 5 प्रतिशत आज भी राज्य की 37 46 प्रतिशत औसत दर से बहुत कम है। इस धीमी प्रगति एवं दुखद परिस्थिति का खुलासा दामोदर रेड्डी द्वारा बतायी गयी इस बात से भी होता है: मादिलापुर गाँव शादनगर से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ के विद्यालय मे 200 विद्यार्थी है। प्राचार्य एक महिला हैं तथा उनकी सहायक है यादिगरी रेड्डी। हाल मे जब जिला स्कूल निरीक्षक निरीक्षण के लिए वहाँ आये, तां उन्हे एक भी शिक्षक स्कूल में नहीं मिला। जमादार की निगरानी में परीक्षा चल रही थी।

बुजुर्गों के अनुसार, पंचायती राज की विफलता का एक और कारण यह है कि सरकारी अधिकारी गाँवों से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को कोई अधिकार देना नहीं चाहते। इस मामले में राज्यस्तरीय नेताओं के साथ उनकी सॉठ-गॉठ है।

नागौर और शादनगर दोनों ही क्षेत्रों में पचायती राज की अत्यत सकुचित तस्वीर उभर कर सामने आती है। जवाहरलाल नेहरू तथा उनके द्वार किये गये उद्घाटन की ऐतिहासिक घटना को भी पूरी तरह भुला दिया गया है। हमारे इतिहास बोध की परंपरा के अनुरूप ही वहाँ उस घटना की याद में कोई स्मृति-चिह्न भी नहीं है। पंडित नेहरू ने नागौर के जिस चबूतरे से जब सभा को संबंधित किया था, वह अब पुलिस प्रशिक्षण शिविर के भीतर है। शिविर में मौजूद पुलिसवाले ने बताया कि उसके बास ने एक बार उससे कहा था कि इस चबूतरे को न तोड़ा जाये, क्योंकि यहाँ नेहरू जी आये थे। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वे किसलिए आये थे। शादनगर में सभा के मैदान पर हरिजन बस्ती बसा दी गयी है और उस मच के चवूतरे पर पानी की टकी बना दी गयी है। यह उपेक्षा और गिरावट पूरी व्यवस्था के ही नाकारा होने का प्रतीक है, जिस व्यवस्था से स्वतंत्र भारत की पहली पीढ़ी ने बड़ी उम्मीदें बाँध रखी थी।

इन दोनों पचायतों की विफलता का प्रमुख कारण जाति-वर्चस्व रहा है। चाहे नागौर के जाट हो या शादनगर के रेड्डी, उन्होंने सामाजिक यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। अपने वर्चस्व के लिए खतरा बन सकनेवाले, विकास के महत्वपूर्ण उपातानां — जैसे शिक्षा. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, महिलाओं में स्थिति म न्याय आरं — में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। नागीर में गांधी जयनी और शा स्नाय में उत्तयं प्रशास जैसे दो शुभ दिन' भी उन क्षेत्रों में प्रचलित सामतशादी नथा सामन्यार्थी मृन्यों म् टक्कर नहीं ले पाये। एक नये पचायती राज की शृहआत के मन्त्राप्त माफ पर देश के अधिकतर हिस्सी में चल रहे हालात का यह प्रतीक मात्र है। इन प्रशिक्षां नथा से उपजनेवाले खतरों के प्रति आगाह करते हुए निर्मत मृत्रार्थी न निष्या था, 'श्वारा में आयें, तो असली खलनायक सामतशाही और पितृसतात्मक सामाजिक राजा था। जब तक ग्रामीण समाज को सगठित करने के ये दोनों सिद्धान रहेंग नह नग स्वतानित्र पंचायतों से किसी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्यांक इनस भी पहन से ही आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ताकतवर तवके को ही पनने प्रतन का अवस्थ मिलेगा। स्वशासन के उपकरणों पर नियत्रण से उनके हाथ और प्राचन मन रहा वाचे। एक या दूसरी तरह के 'उपेक्षित' समूहों, विशेषकर गरीवों नथा महिला आ, पर अन्याचार का बोझ पहले से भी ज्यादा बढ़ सकता है। उनके निए विकार पर प्राचन पर जन की बजाय, अभिशाप साबित हो सकता है।

नागीर और शादनगर इन आशकाओं के जीवित उदाररण है।

मेलावलावु का मतलब

मेलावलावु धीरे-धीरे हमारे स्मृति पटल से गायब होता जा रहा है। 50 जून 1997 को दिनदहाड़े मेलावलावु पचायत के अध्यक्ष मुरुगेसन, उपाध्यक्ष मूकन और चार अन्य लोगों की जघन्य हत्या शीघ्र ही इतिहास का हिस्सा बन कर कंवल ऑकड़ो में दर्ज हो कर रह जायेगी और समाजविज्ञान के अध्ययन का एक विषय भर वन जायेगी। महज तिमलनाडु पर नहीं, बल्कि पूरे देश में पंचायतों के इतिहास पर लगे इस काले धब्बे को क्या हम यो ही भुला सकते है?

मुरुगेसन और मूकन देश के कानून के अनुसार और लोकतात्रिक प्रक्रिया के जिस्से मेलावलाबु पचायत के लिए चुने गये थे। सविधान के अनुसार, पंचायत स्वशासन की एक सस्था है। लेकिन विडंबना यह है कि इन जन प्रतिनिधियों को केवल काम करने से ही नही रोका गया, विल्क उनका जीना भी दूभर कर दिया गया। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और चुने जाने का दड उन्हें अपनी मौत के रूप में भरना पड़ा है। उनका अपराध केवल यह था कि वे एक नीची जाति मानी जानेवाली आदि-द्रविड के परिवारों में पैदा हुए थे और उन्होंने चुनाव लड़ने का दुस्साहस दिखाया था।

आज, मेलावलावु की यात्रा एक हृदय विदारक अनुभव है। मेन रोड के पास हिरिजन बस्ती मे एक पंक्ति में छह शव दफन हैं। गाँव के सभी स्त्री-पुरुष बेरोजगार हैं। इन्हें काम देनेवाले थेवरो और कल्लारो ने सामूहिक हत्या के बाद से इन लोगो को काम पर रखना बंद कर दिया है। जब यह लेखक इस गाँव मे गया, तो ये लोग स्थानीय प्रशासन और हिरिजन सेवा सघ द्वारा दिये गये कुछ बोरे चावलों पर किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। एक अध्यापक पाँच से 12 वर्ष के लगभग 80 बच्चों को ले कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। ये सभी बच्चे पहले गाँव के प्रमुख स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन दलितो की हत्या के बाद, इन्होंने स्वय को असुरक्षित महसूस किया और स्कूल जाना छोड़ दिया। गाँव की एकमात्र चावल मिल बद पड़ी है। मुरुगेसन की पत्नी ने अपनी पित की हत्या के 38 दिन बाद एक बेटी को जन्म दिया। मुरुगेसन

178: भारत में पचायती राज

के भाई राजा की विधवा भी गर्भवर्ता है। राजा भी मुरुगेसन के साथ ही मारा गया या।

हालॉकि मारे गये लोगों के रहने के लिए मकान और दो कमरो के स्कूल की इमारत बनाने का काम चल रहा है, फिर भी गाँव के इस हिस्से में उदासी की धुध छा रही है और भय व्याप्त है।

गाँव के जिस मुख्य हिस्से में पिछडी जातियों की बहुतायत है, वहाँ एक बड़े-से हॉल में सिपाहियों ने डेरा डाला हुआ है। समुदाय का एक भी पुरुष सदस्य वहाँ नहीं है, हत्या काड के बाद सभी लोग भाग गये। छोटी-माटी सभी दुकाने बंद है, बच्चे आवारा-से इधर-उधर घूमते रहते हैं। औरतें हालात से परेशान है। जाति के मुखियाओं के आदेश पर गाँव में अखबार नहीं बॅटता, क्योंकि उनकी औरतों को बाहर जो कुछ हो रहा है, उससे दूर रखा जाना चाहिए। जात-पाँत माननेवाले मर्द ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। अब यह इलाका किन्नस्तान जैसा बन गया है, लेकिन शायद पुरुष खुश हों, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गयी। वे तो यही चाहते थे कि उनकी जाति के लोग ही गाँव पर राज करें, लोकतंत्र रहे या न रहे।

जब अक्तूबर 1996 के चुनावों में मेलावलायु को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पचायत घाषित किया गया था, तब इस क्षेत्र की प्रभावशाली पिछड़ी जाति ने इसका विरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ चुनाव नहीं कराये जा सके। चुनाव कराने की दूसरी कोशिश भी हिसा और मतदान केहों पर कब्जे के कारण बेकार हो गयी। अंत में, जब 30 दिसम्बर 1996 को चुनाव हुए तो कल्लारों ने चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया। छह सीटें भर गयीं और तीन खाली रह गयीं। 35-36 साल के मुरुगेसन अध्यक्ष चुने गये और बीस से ऊपर के भूकन उपाध्यक्ष बने। लेकिन गाँव की प्रभावशाली जाति ने उन्हें पंचायत के दफ्तर में कदम तक नहीं रखने दिया। दफ्तर एक नये बने भवन में है। इमारत पर मुरुगेसन का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, लेकिन आज उस पर गोबर पुता हुआ है।

विल्लापुरम वार्ड में मदुरै निगम की पार्षद लीलावती की हत्या के कुछ ही सप्ताह के भीतर मेलावलाव हत्याकाड से कई सवाल उठते हैं।

मदुरै जिला, खास तौर से मेलूर तालुक, जाति संबंधों की दृष्टि से एक संवेदनशील इलाका है। मेलावलावु के बारे में 1952 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के स्वामी आनद तीर्थ ने लिखा था, 'मेलावलावु में जब मैं दो हरिजन लड़कों के साथ चाय की एक दुकान पर गया, तो कुछ लोगों ने मुझे धमकी दी और उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया। दुकानदार ने जानबूझ कर काँच का एक गिलास तोड़ा और माँग की कि इस गिलास के पैसे भरो नहीं तो मार पड़ेगी।'

यह बात 45 वर्ष पहले की है। मेलावलावु घटना से कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के मानवाधिकार आयोग को दी गयी एक रिपॉर्ट मे विधायक डॉ कृष्णस्वामी ने कहा था, 'स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान प्रभावशाली जातियों के अडगों की वजह से कई आरिक्षत निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं कराये जा सके। मटुरे जिले के मेलूर तालुक की मेलावलावु पचायत के आरिक्षत निर्वाचन क्षेत्र में दिलत उम्मीदवार चुनाव नहीं लड सके। मैंने व्यक्तिगत रूप से मामले में दखल दिया और लड़ाई भी की, लेकिन निर्वाचित दलित प्रतिनिधि मुरुगेसन को काम करने के लिए अपने कार्यालय में जाने ही नहीं दिया गया। मैंने इस मामले की कई बार शिकायत की, यहाँ तक कि विधान सभा में भी यह मामला उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।'

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिला प्रशासन को पता था कि मेलूर और मेलावलाबु में तनाव है। गॉववालों ने लेखक को बताया कि असल मे जिला अधिकारियों ने मुरुगेसन और उसके साथियों को धमकियों और हिसा के बावजूट नामजदगी के अपने पर्चे दाखिल करने को कहा था और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। लेकिन सुरक्षा नहीं दी गयी। दो-चार सिपाहियों को तैनात कर देना ऐसे सामाजिक तनावों का कोई हल नहीं है।

जिला, ब्लॉक और पचायत स्तरो पर शक्तिशाली स्वशासी सरकारी संस्थानो का कामकाज जन प्रतिनिधियो द्वारा सँभाले जाने के सदर्भ में, कलक्टर के अधीन काम करनेवाले पूरे प्रशासनिक तत्र मे आमूल परिवर्तन की जरूरत है। अब जिले का प्रशासन काफी जटिल हो यया है और केवल ऊपर से दिये जानेवाले आदेशो के वृते पर इसे चलाना समव नहीं रहा है।

मेलावलावु के हत्याकांड को जातिगत तनाव के एक और उदाहरण के रूप में देखना एक जबरदस्त भूल होगी। यह उस पंचायती राज संस्थान पर एक गंभीर हमला था, जो गाँवों में ताकतवर गुटबाजी को बदलने की क्षमता रखता है। नयी पचायतों को गाँव के ताकतवर गुटों द्वारा एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। जब पचायतों के पास न तो शक्तियाँ थी और न ही पैसा, तब भी ये स्थानीय निकाय बिना किसी प्रभाव के मौजूद थे, उनकी सदस्यता प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी जाती थी। अब उनका रुतबा भी है और ताकत भी। स्थानीय संसाधनों पर पंचायतों का नियंत्रण है। पंचायत का अध्यक्ष गाँव का प्रथम नागरिक होता है और मंदिर उत्सवों में उसे सम्मनित किया जाता है। मेलावलावु पंचायत के मामले में मछली पालन के तालाबों, मदिर की जमीन ओर वन क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले, राजस्व पर पंचायत का नियंत्रण है। जब अनंत काल से इन सभी विशेषाधिकारों पर ऊँची जातियों का कब्जा रहा हो और नीची जातियों का काम लकड़ी काटना या पानी लाना भर रहा हो, तब ऊँची जातियों पंचायत चुनावों के कारण भूमिकाओं की इस अदला-बदली को कैसे बर्दाश्त कर सकती है?

इस देश में लोकतंत्र कोई नयी बात नहीं है। लेकिन कई मामलों में लोकतत्र का इस्तेमाल असरदार वर्ग की ताकत को बरकरार रखने के लिए किया जाता रहा

180 : भारत में पंचायतीं राज

है और आज जब गाँव और वार्ड स्तर पर असल लोकतत्र आ रहा है, तब इसके साथ रक्तपात और हिंसा जुड गयी है। स्वाभाविक प्रश्न यह है कि आजादी के बाद

हमारे गाँवों में किस प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा पनप रही है? कमजोर वर्गी को अधिकार-सम्पन्न बनाने और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सगठित करने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो शुरू हो रही थी, लेकिन प्रभावशाली जातियों

को बदलते समय, लोकतांत्रिक मूल्यो तथा सामाजिक न्याय और समता के बारे में शिक्षित करने की कोई कोशिश नहीं की गयी। हाल के दिनों में दक्षिणी तमिलनाड़

की ताकतवर जातियों में कोई सुधारवादी आंदोलन गंभीर रूप से नहीं चला। मीनाक्षीपुरम में अप्रैल 1981 में 180 हरिजन परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से

धर्म परिवर्तन इस बात का स्पष्ट संकेन था कि दिलत समूह सम्मान और गरिमा से जीने के रास्ते ढूँढ रहे हैं। चेन्नई स्थित भारत सरकार के अनुसूचित जातियों/जनजातियों के निदेशक के कार्यालय की धर्मातरण के बारे में एक रिपोर्ट (1981) का साराश कहता है कि पुराने जमाने से चले आ रहे छुआछूत पर आधारित सामाजिक भेदभाव और साथ ही कमजोर वर्गों के खिलाफ होनेवाले अपराधों की रोकथाम के प्रति अधिकारियों की लापरवाही ने ही धर्मातरणों को खास तौर पर बढावा दिया है। रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों को परेशान किये जाने के लिए कई उदाहरण देते हुए बताया

गया है कि 'सर्वश्री परमशिवन और जेंबानी पंचायत सदस्य थे...जब भी वे पंचायत की बैठकों में शामिल होते, उन्हें पानी तक के लिए नही पूछा जाता था। उन्हें चाय नहीं दी जाती थी। अलग से बैठाया जाता था...बताया जाता है कि पीने का पानी भर कर रखने का प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन उस पर कभी भी अमल नहीं

तिमलनाडु में हालात सुधरे नहीं, बल्कि और बिगड़ गये। 1981 में अत्याचारों और बेइज्जती से बचने के लिए इन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन 1996 में जब लाकतात्रिक संस्थानों और लोकतात्रिक प्रक्रिया में उन्होंने भाग लेने की कोशिश की तो इसका अंजाम दिन दहाड़े हत्या के रूप में सामने आया। यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? सभ्य समाज की ओर या ऐसे

सवाल बार-बार उठ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? सभ्य समाज की ओर या ऐसे समाज की ओर, जहाँ 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की कहावत चरितार्थ होती है? मेलावलावु यह भी कहता है कि किस प्रकार राजनीतिक पार्टियाँ अपना वोट बैक बनाये रखने के लिए जातियों या गाँवो की राजनीति करती हैं। इस हत्याकाड

के बाद इस गाँव में छोटी और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के तरह-तरह के नेता आ गहें हैं। वे आते हैं, शोक जताते है, वादे करते हैं और चले जाते हैं। गाँवों की समस्या का स्थायी समाधान खोजने की कोई कोशिश नहीं होती। अपराधी भी पार्टियों की आड में छिप जाते हैं। वोट बैंक के रूप में जातियों का इस्तेमाल भारतीय समाज का अभिशाप रहा है। संसद और विधान सभा चुनावों के बाद यह और मजबूत हुआ है। इसे समाप्त करने की कोई वास्तविक कोशिश हुई ही नही है। प्रचायत चुनाब में इस वोट बैंक को तोड़ने की क्षमता हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां बिना स्वावी समाधान के इन दुखद घटनाओं को जिस तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है, उससे यह सवाल जस का तस बना रहता है।

मदुरै ऐसा जिला है, जहाँ काफी लंबे समय से अच्छी-खासी संख्या मे गाधीवादी सगठन और सस्थान काम करते आ रहे है। तमिलनाडु राज्य में स्वयंसेवी संगठने की कोई कमी नही है। फिर ऐसी वीभत्स घटनाएँ बार-बार क्यों घट रही है? जहाँ सरकार नाकाम रहती है, क्या वहाँ का नागरिक समाज यह शपथ नहीं ले सकता कि मेलावलाबु की पुनरावृत्ति किसी भी क्षेत्र, जिले और राज्य मे नहीं होगी? लेकिन ऐसी भी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है।

लीलावती हत्याकांड के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हरकत में आयी और अपना आधार मजबूत करने के उद्देश्य उसने मृतकों के परिवारों की मदद के लिए सभी राजनीतिक और वित्तीय उपाय किये तथा जमीनी स्तर पर लोकतत्र का संदेश फैलाया। लेकिन मेलावलावु में ऐसा कुछ भी नही है और है भी तो बेहद कमजोर है। दलित आंदोलन मे फूट, गुटबाजी और तनावग्रस्त इलाके में प्राणो के संकट को रोकने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के एकजुट प्रयास का अभाव चिंता का विषय है।

हरिजन बस्ती में बन रहे दो कमरों के छह मकान और स्कूल की इमारत (बिना किसी सुविधा के एक सादा-सा ढांचा) दुनिया के सामने इस बात का सबूत होगा कि इन छोटी-मोटी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दो निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके समर्थकों को अपनी जान गँवानी पड़ी।

मेलावलावु और इस तरह के गाँवों को नियमित रूप से पंचायत चुनाव न कराने और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत न करने की एक भारी कीमत चुकानी पड रही है। मदुरै में मुझे बताया गया कि उसीलमपट्टी इलाके में कीरीपट्टी और पप्पाकुडी पंचायतों तथा कल्लिकुडी पंचायत के मरुथनगुड़ी में सामाजिक तनावों के कारण आज तक पचायत यूनियन के चुनाव नहीं हुए हैं। क्या राज्य सरकार की नीद खुलेगी और वह हकीकत को समझेगी?

शोषित वर्ग के लिए मायने

डॉ आंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को सविधान सभा में कहा था: 'भारत के बुद्धिजीवियों का प्रामीण समाज से लगाव करुण नहीं तो निस्सीम है। इसका मुख्य कारण मेटकाफ द्वारा की गयी गॉवों की प्रशसा है। उन्होंने गॉवों को ऐसे छोटे-छोटे गणराज्यों के रूप में वर्णित किया जो अपनी जरूरत लायक प्रायः सब कुछ खुद पैदा कर लेते हैं और किसी प्रकार के वैदेशिक सबध से लगभग स्वतंत्र रहते हैं।'

'गॉवों ने अनेक समस्याओं के बीच जो अपना अस्तित्व बचाये रखा है, वह एक तथ्य हो सकता है। लेकिन सिर्फ बचे रहने का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न यह है कि उन्होंने जीवन किस स्तर का जिया है? निश्चय ही निचले और स्वार्थी स्तर का। मेरा मानना है कि ये ग्रामीण गणराज्य ही भारत की बरबादी का कारण रहे है। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग प्रांतीयता और साप्रदायिकता की निदा करते है, वहीं गॉवों के पक्षधर के रूप में सामने आते हैं। गाँव घोर स्थानीयता, अज्ञान, संकीर्ण मानसिकता और साप्रदायिकता के गढ होने के अतिरिक्त और क्या है?'

भारतीय गाँवो और ग्राम पंचायतों के बारे में आंबेडकर के इस कथन को आधी सदी बीत चुकी है। पंचायतों को नीति निदेशकों की धारा 40 से निकाल कर संविधान के नौवें खड में शामिल कर लिया गया है। राजनीतिक और अकादिमक बहसो में भी ये हाशिये से उठ कर मुद्दा बन चुकी है।

लेकिन आज हमारे गाँव क्या है? देश के अधिकाश गाँवों के बारे में डॉ. आंबेडकर ने 50 वर्ष पहले जो बाते कहीं थी, उनसे क्या ये भिन्न हैं? हम रोज चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक बदलाव हो रहे हैं लेकिन क्या गाँवों की सामाजिक व्यवस्था में सचमुच भारी, सारभूत परिवर्तन आया है?

मध्य प्रदेश की इन चार घटनाओं के अध्ययन में अन्य मुद्दों के साथ इन सवालों पर भी विचार किया गया है।

सविधान के 73वे सशोधन के बाद पंचायत चुनाव करानेवाला पहला राज्य

मध्य प्रदेश ही था। इन चुनावों के साल भर बाद अखबारों में रिपोर्ट आने लगी कि पचायतों के काम-काज में गड़वड़ियाँ हो रही है। भारतीय समाज का अध्ययन करनेवालों को ऐसी गड़बड़ियों का कुछ अंदेशा था भी। जब राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आयी रिपोर्टों से यह जाहिर हुआ कि महिला सरपच को सार्वजिनक रूप से नग्न किया गया, एक अन्य महिला सरपच के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, एक उपसरपच को प्रताड़ित किया गया और एक दिलत पंचायत सदस्य को मारा-पीटा गया, तो इन घटनाओं के पीछे काम कर रही सामाजिक ताकतों की विस्तृत छानबीन जरूरी हो गयी।

इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के शोध विभाग के एक सदस्य ने इन गाँवों में कई सप्ताह बिताये, गाँवों के रोजमर्रा के जीवन को देखा, उस इलाके के बारे में बुनियादी सूचनाएँ इकड्डा की, कई लोगों के साथ बातचीत की और जितने अधिक तथ्य जुटाना संभव था, उनके आधार पर इन घटनाओं को दुबारा लिखा।

लोगों की जीवन-स्थितियों से यह साफ है कि पचायत उसी समाज का एक लघु रूप है जिसका अंश गाँव है। 73वें सिवधान संशोधन में 'स्व-शासन की संस्थाओं' के उल्लिखित आदर्शों को मौजूदा अन्यायपूर्ण समाज में व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। कठोर जाति व्यवस्था, सामंती मूल्यों, स्त्री-पुरुष असमानता, अमानवीय दिस्ता और अमीर-गरीब के बीच भारी फर्कवाले ग्रामीण समाज के बदरंग कैनवस पर पंचायती राज की खूबसूरत तस्वीर नहीं उतारी जा सकती।

तो, अब सवाल यह है, क्या ग्रामीण भारत इन सभी स्थितियों के सुधरने का इतजार करता रहे? मसलन, लोग बाट जोहते रहें कि सबको शिक्षा मिले, भूमि सुधार लागू हो, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा मिले और सामाजिक विकास के साथ ही आर्थिक विकास भी हो? लेकिन बदलाव की मौजूदा रफ्तार से इस सबमें कितना वक्त लगेगा? क्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने तक स्थानीय शासन के लक्ष्य को पाने के लिए गाँव हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? इसलिए यथार्थवादी तरीका यही था कि पंचायते गठित हों और वे ही स्थानीय स्तर पर जीवंत राजनीतिक प्रक्रिया के जिये सामाजिक पुनर्निर्माण का माध्यम बनें। सविधान के 73वें संशोधन के जिये हमने यही हासिल करने की कोशिश की है।

मध्य प्रदेश की घटनाएँ हमारे गाँवों की जमीनी वास्तविकताओं को उजागर करती है। पर हर स्थिति स्वयं अपना प्रतिवाद भी उत्पन्न करती है। पचायती राज के माध्यम से भारतीय गाँवों के जाग्रत होने के पहले कदम के रूप मे ये संकेत अच्छे है।

एक ः द्रौपदी का वस्त्र-हरण

संक्षिप्त घटनाक्रम : प्राप्त जानकारी के अनुसार सल्हौना ग्राम पंचायत की सदस्य द्रौपदी वाई को 19 नवंबर 1995 को रायगढ़ जिले के सरीया प्रखड़ विकास पदाधिकारी के सामने निर्वत्र किया गया। इस घटना विश्व निर्वा में निर्वा के निर्वा के प्रति जायम्बद्धा के किया आप इस ग्री किया के किया आप इस ग्री किया के किया किया के किया किया के किया के किया

गाँव के बारे में : रायगढ़ जिला मध्य प्रश्न के पूर्वी किस्त स्व क्या । शक्ति, जशपुत्नगर और रायगढ़ के पुगर्व मामनी ब्याज्यों की विकास ।

जिला बना था।

जिते में मुख्य आबादी अनुसूचित जनगादिनों. अनुमनिक आंधा कि कि जीति जीति और उद्दिया कि निक्ति के कि कि लोग छत्तीसगढ़ी और उद्दिया कि निक्ति के कि कि कि कि निक्ति के कि जिते में कि जनभू प्रचारहरू के कि प्रचार प्रचारहरू के कि प्रचार प्रचारहरू के प्रचार प्रचार के कि प्रचा

स्वाद जिले की सारगगढ़ तहसील का सम्भीना गाँउ के सार्व कर कर कर किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1993 तक सम्भीना, ब्रागाय के हिस्से थे। 1994 में सल्योना की इस गोवा के वर्ष कर कर के प्रमायत के हिस्से थे। 1994 में सल्योना की इस गोवा के वर्ष कर कर के प्रमायत का दरजा दे दिया गया। यहाँ कुल ५९७ मन इस है। कर कर का पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आगशन है। यह गाउँ है।

पद्यास के दशक के शुरू में सल्हीना में पहला अगतन के एक करने उसने परचून की दुकान खोली। फिर उड़ीसा के सननाग दिन मु अने कि के कारण विस्थापित हुए तेली परिवार यहाँ आ कर बसे। पनान के कारण विस्थापित हुए तेली परिवार यहाँ आ कर बसे। पनान के कारण विस्थापित हुए तेली परिवार यहाँ आ कर बसे। पनान के कारण विस्थापित हुए तेली परिवार में तीन और अग्रवाल परिवाण न कि कि वोर पर पैसे देने का धधा शुरू किया। मांव में कि वार्य के सामाज के सामाज की वार्य की कोई दिलचस्पी नहीं है। निर्म कि का का कि वार्य के सामाज की की की की वार्य की लोगों में भी हुन के में कि प्रवार की वार्य की सामाजिक-आर्थिक जीवन पर इनकी कारी पर है।

परिवारों की संख्या : गाँव में 865 ए हैं। उनका काहिना किल्ला प्रकार है - अनुसूचित जनजातियाँ 292 (8775 फीसदी) अनुसूचित जार्का

मध्य प्रदश ही था। इन चुनावो के साल भर बाद अखबारो म रिपार्ट आने लगीं कि पचायतों के काम-काज में गडबडियाँ हो रहीं है। भारतीय समाज का अध्ययन करनेवालों को ऐसी गडबड़ियों का कुछ अदेशा था भी। जब राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आयी रिपोर्टो से यह जाहिर हुआ कि महिला सरपंच को सार्वजनिक रूप से नग्न किया गया, एक अन्य महिला सरपंच के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, एक उपसरपंच को प्रताडित किया गया और एक दिलत पंचायत सदस्य को मारा-पीटा गया, तो इन घटनाओं के पीछे काम कर रही सामाजिक ताकतों की विस्तृत छानवीन जरूरी हो गयी।

इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के शोध विभाग के एक सदस्य ने इन गॉवो में कई सप्ताह बिताये, गॉवों के रोजमर्रा के जीवन को देखा, उस इलाके के बारे में बुनियादी सूचनाएँ इकड़ा कीं, कई लोगों के साथ बातचीत की और जितने अधिक तथ्य जुटाना सभव था, उनके आधार पर इन घटनाओं को दुबारा लिखा।

लोगो की जीवन-स्थितियों से यह साफ है कि पंचायत उसी समाज का एक लघु रूप है जिसका अश गाँव है। 78वें सिवधान सशोधन में 'स्व-शासन की संस्थाओं' के उल्लिखित आदर्शों को मौजूदा अन्यायपूर्ण समाज में व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। कठोर जाति व्यवस्था, सामंती मूल्यों, स्त्री-पुरुष असमानता, अमानवीय दिद्रता और अमीर-गरीब के बीच भारी फर्कवाले ग्रामीण समाज के बदरग कैनवस पर पंचायती राज की खूबसूरत तस्वीर नहीं उतारी जा सकती।

तो, अब सवाल यह है, क्या ग्रामीण भारत इन सभी स्थितियों के सुधरने का इतजार करता रहे? मसलन, लोग बाट जोहते रहे कि सबको शिक्षा मिले, भूमि सुधार लागू हों, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा मिले और सामाजिक विकास के साथ ही आर्थिक विकास भी हो? लेकिन बदलाव की मौजूदा रफ्तार से इस सबमें कितना वक्त लगेगा? क्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने तक स्थानीय शासन के लक्ष्य को पाने के लिए गॉव हाथ पर हाथ धरे बैठै रहें? इसलिए यथार्थवादी तरीका यही था कि पंचायतें गठित हो और वे ही स्थानीय स्तर पर जीवत राजनीतिक प्रक्रिया के जिएये सामाजिक पुनर्निर्माण का माध्यम बने। संविधान के 73वे संशोधन के जिये हमने यही हासिल करने की कोशिश की है।

मध्य प्रदेश की घटनाएँ हमारे गाँवों की जमीनी वास्तविकताओं को उजागर करती हैं। पर हर स्थिति स्वयं अपना प्रतिवाद भी उत्पन्न करती है। पंचायती राज के माध्यम से भारतीय गाँवों के जाग्रत होने के पहले कदम के रूप में ये संकेत अच्छे है।

एक : द्रौपदी का वस्त्र-हरण

संक्षिप्त घटनाक्रम : प्राप्त जानकारी के अनुसार सल्हौना ग्राम पंचायत की सदस्य द्रौपदी बाई को 19 नवंबर 1995 को रायगढ़ जिले के सरीया प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने निर्वस्त्र किया गया। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। 29 नवबर 1995 को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन ने नयी दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन के सामने प्रदर्शन किया और इस घटना में शामिल दोनों आरोपित व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करने की माँग की। फेडरेशन ने एक निर्वाचिल प्रतिनिधि की सुरक्षा करने का दायित्व न निभानेवाले क्षेत्र प्रखंड विकास अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की माँग की। 10 जनवरी 1996 को हिन्दू जन जागरण मंच ने लोगों में अपने हितों की रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सल्हौना से लाटवोर तक जुलूस निकाला।

गाँव के बारे में : रायगढ़ जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। सारगगढ, शक्ति, जशपुरनगर और रायगढ के पुराने सामंती राज्यों को मिला कर 1952 में यह जिला बना था।

जिले में मुख्य आबाटी अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों की है। लोग छत्तीसगढ़ी और उड़िया बोलते हैं। जिले की तहसील सारंगगढ़ में उड़िया भाषी लोगो का बहुमत है। जिले में 17 जनपद पंचायतें और 1083 ग्राम पंचायतें हैं।

रायगढ जिले की सारंगगढ़ तहसील का सल्हौना गाँव जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1993 तक सल्हौना, बडगाँव और बिलाईगढ़ गाँव एक ही पंचायत के हिस्से थे। 1994 में सल्हौना को इन गाँवों में अलग कर स्वतंत्र ग्राम पंचायत का दरजा दे दिया गया। यहाँ कुल 937 मतदाता है। इसके सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित है। यह गाँव त्तरीया-लेंद्रा विकास प्रखड का हिस्सा है।

पचास के दशक के शुरू में सल्हौना में पहला अग्रवाल परिवार पहुँचा और उसने परचून की दुकान खोली। फिर उड़ीसा के सबलपुर जिले में बने हीराकूद बॉध के कारण विस्थापित हुए तेली परिवार यहाँ आ कर बसे। पचास के दशक के आखिर में बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ में तीन और अग्रवाल परिवारों ने छोटे-मोटे व्यापार खोले और सूद पर पैसे देने का धंधा शुरू किया। गाँव में इन सबकी दुकानें हैं। ये रायगढ़ और रायपुर की चावल मिलो को धान की आपूर्ति भी करते हैं। खेती में इन प्रवासी परिवारों की कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ एक अग्रवाल परिवार के पास साढ़े चार एकड जमीन है। ये सभी पढ़े-लिखे हैं। आस-पास के शहरों के व्यापारियों, स्थानीय अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लोगों से भी इनके संबंध हैं। इस प्रकार गाँव के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर इनकी काफी पकड़ है। वै

परिवारों की संख्या : गाँव मे 865 घर हैं। उनका जातिवार विवरण इस प्रकार हे : अनुसूचित जनजातियाँ 292 (37.75 फीसदी), अनुसूचित जातियाँ 278 शिक्षा: गाँव में सिर्फ एक प्राथमिक स्कूल है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। स्कूल में सिर्फ दो शिक्षक है, जिनमें से एक 'केन्द्र पाठक' शिक्षक है, जिनके अधीन नौ स्कूलों का काम भी है। इसलिए स्कूल में दाखिल सभी 151 छात्रों (114 लड़के और 37 लड़कियाँ) को पढ़ाने का काम दूसरे शिक्षक के जिम्मे है। केंद्र पाठक स्वय कोई क्लास नहीं लेते।

तालिका 1 जाति, हैसियत तथा व्यवसाय के सल्हौना के परिवारों की संख्या

क्रम जाति∕जनजाति संख्या	कानूनी हैसियत		ारिवारों संख्या
1. सओरा	अनुसूचित जनजाति	खेतिहर मजदूर	280
2. गंडा	अनुसूचित जाति	खेतिहर मजदूर	200
 अधिरया 	पिछडी जाति	किसान	100
4. साहिस∕घसिया	अनुसूचित जाति	खेतिहर मजदूर	60
5. पनिका	पिछडी जाति	जुलाहा	25
 त्यवत∕गौड़ 	पिछड़ी जाति	छोटे किसान	25
		खेतिहर मजदूर	
7. कैओत	पिछडी जाति	भडभूजा	15
8. कलहर	पिछड़ी जाति	किसान	10
9. धोबी	अनुसूचित जाति	धोबी	12
10. साहू∕तेली*	पिछड़ी जाति	छोटे व्यापारी/दुकानदार	12
11. कूडा	अनुसूचित जनजाति	खेतिहर मजदूर	08
12. चमार	अनुसूचित जाति	खेतिहर मजदूर	06
13. अग्रवाल*	सामान्य	धान व्यापारी/दुकानदार	04
14. गोंड़	अनुसूचित जनजाति	खेतिहर मजदूर	04
15. नाई	पिछड़ी जाति	नाई	03
16. पाणिग्राही*	सामान्य	पुरोहित	01
* बाहर से आये व	लोग		

राजनीतिक दलों का समर्थन : सल्हौना गाँव में 12 घर शिव सेना के समर्थक हैं। बाकी परिवार कांग्रेस या भाजपा के समर्थक है। चार अग्रवाल परिवारो में से हो काग्रेस के समर्थक है, एक भाजपा का और एक शिव सेना का समर्थक है। भूमि का वितरण : गॉव में नौ सौ एकड खेती योग्य और 100 एकड गोचर

भमि है। विभिन्न जातियो और आदिवासियो के वीच जमीन का बॅटवारा बहुत ही असमान है। गॉव में सबसे ज्यादा जमीन अघरिया जाति के लोगो के पास है। सिर्फ

नौ अघरिया परिवारो के पास 540 एकड़ जमीन है। इसके विपरीत 292 आदिवासी परिवारों के पास सिर्फ 100 एकड जमीन है और अनुसूचित जातियों के 278 परिवारो के पास महज 20 एकड जमीन है। गाँव के पूर्व-गोतिया परिवार के पास 280 एकड जमीन है। तीन अधरिया परिवारो के पास 100-100 एकड जमीन है। इस गाँव मे

100 एकड़ जमीन रखने वाले पूर्व-गोतिया निरजन पटेल ने सालाना ठेके पर 12 मजदूर रखे है, जिन्हें कामिया कहा जाता है।

फसर्तें : गॉव में मक्का, धान, मूॅगफली, मिर्च और अरहर की खेती होती है।

केवल पाँच ट्यूबवेल है, जो 30 से 40 एकड जमीन की ही तिचाई कर सकते है। चूँकि खेती बारिश पर निर्भर है, इसलिए यहाँ साल भर मे एक ही फसल हो पाती

है।

गोंतिया : गाँव के परपरागत प्रधान लोगो को गोतिया कहा जाता था, जो पीढी-दर-पीढ़ी चले आ रहे थे। उनमें से अधिकाश आदिवासी थे। अंग्रेज सरकार

ने मालगुजारी की वसूली का काम इन्हें सौपा हुआ था, सो ये मालगुजार भी कहलाते थे। इनकी सेवाओ के बदले सरकार ने इन्हे गाँव की एक-चौथाई कृषि योग्य भूमि दे दी थी, जिस पर कोई राजस्व नहीं लगता था। इस जमीन को भोगरा कहा जाता

था। इन गोतियाई गाँवों मे जमीन की मिल्कियत गोतिया की होती थी। लगान-मुक्त भोगरा जमीन के अलावा गोतियाओं के पास सैकड़ों एकड रैय्यती जमीन भी थी।

गाँव की सबसे अच्छी जमीन पर उनका ही कब्जा था। उन्हें बजर भूमि रैय्यतों को देने का अधिकार था, जो उसे खेती लायक बना लेते थे। इस प्रकार अंग्रेजी राज मे गोंतियाई व्यवस्था बहुत शोषक हो गयी थी और इससे सबसे ज्यादा पीडित आदिवासी थे। वक्त बदलने के साथ आदिवासी गोतियाओं की जगह कुलता या अघरिया जैसे

जमीन दी। 1952 मे गोतिया प्रणाली समाप्त की गयी। लेकिन पूर्व-गींतिया परिवारी के पास अभी भी सैकडों एकड़ जमीन है।

सवर्ण हिन्दुओं ने ले ली। वे बाहर से अपनी जाति के लोगों को ले आये और उन्हें

खेतिहर मजदूरों की बदहाली : सल्हौना में पुरुष मजदूर की दैनिक मजदूरी 25 रुपये और स्त्री की 20 रुपये है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पुरुष

के लिए 35 रुपये और स्त्री के लिए 30 रुपये हैं। जाहिर है, यहाँ सरकारी दर से काफी कम मजदूरी दी जाती है। साल भर काम करनेवाले कामिया मजदूर को रोज करीब दो किलो धान मिलता है। इस धान की कीमत सात रुपये है। कामिया को मालिक से खेती के लिए एक एकड जमीन भी मिलती है। इस पर खेती के लिए

हल-बैल भी मालिक ही देता है। वर्ष में दो-तीन माह के लिए ही काम मिलता है। गॉव में सूखा और अकाल के समय मजदूर उडीसा के धान के खेतों ओर चावल मिलों में चलें जाते हैं या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जा कर ईटो के भट्टां पर काम करते हैं। जंगल गॉव से काफी दूर है, इसलिए खेतिहर मजदूरों के लिए वहाँ से ईधन, चारा और दूसरे वन उत्पाद लाना भी संभव नहीं होता।

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के परिवार : सल्हीना गाँव के सभी 570 हरिजन-आदिवासी परिवार खेतिहर मजदूरों के है। उनमें से कुछ के पास अपनी जमीन भी है। लेकिन यह जमीन पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि जमींदार अनुसूचित जातियों के लोगों को उनके सामाजिक दरजे के चलते कामिया नहीं रखते। इस प्रकार गाँव के अधिरया जमींदारों और व्यापार सँभालने वाले अग्रवाल तथा तेली लोगों को गाँव की अनुसूचित जातियों और आदिवासियों पर काफी मजबूत पकड़ है। जमींदार उन्हें काम देते हैं और अग्रवाल तथा तेली उधार पर राशन।

1994 का पंचायत चुनाव और मुख्य प्रतिदंदी: 1994 के पचायत चुनाव में चार महिलाओं ने सरपंच पद का चुनाव लड़ा। ये सभी सओरा आदिवासी थीं। द्रौपदी बाई (भारतीय जनता पार्टी) को 254 वोट मिले और उन्होंने चमेली बाई (कांग्रेस) को 47 वोटों से हराया। सरपंच पद की अन्य उन्मीदवारों धर्मिनी बाई (कांग्रेस) को 137 और बुंदा बाई (कांग्रेस) को 87 वोट मिले थे।

अधरिया जाति के नवयुवक रामकुमार पटेल (भारतीय जनता पार्टी) उपसरपंच चुने गये। अन्य 12 लोग सदस्य चुने गये। पंचायत के 14 निर्वाचित सदस्यों में पाँच महिलाएँ और नौ पुरुष थे। इन नौ पुरुषों में चार आदिवासी और एक अनुसूचित जाति का था।

द्रौपदी बार्ड

द्रौपदी बाई 50 से कुछ ऊपर की हैं। उनके परिवार में छह लोग हैं—पति (60), विवाहित बेटा (27), वहू और दो पोते। गॉव में द्रौपदी बाई की चाय की दुकान है। उनका बेटा साइकिलें मरम्मत करने की दुकान चलाता है। इस परिवार के पास 75 डेसिमल जमीन है। द्रौपदी बाई ने स्कूल मे तो पढ़ाई नहीं की है, पर वह उडिया भाषी औरतों के साथ मिल कर एक शिक्षक से लिखना-पढ़ना सीखती हैं। इस अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को चटसाली कहते हैं। तीन से चार महीने मे ये औरते उडिया लिखना-पढ़ना सीख जाती है और जब वे उड़िया में धार्मिक और पौराणिक किताबें पढ़ना शुरू कर देती हैं, उनकी शिक्षा का अंत हो जाता है। ऐसा इसलिए कि औरतों से सिर्फ उडिया रामायण, भागवत गीता, महाभारत और हरिवंश जैसी धार्मिक किताबें पढ़ने की ही उम्मीद की जाती है। कार्तिक के महीने को उडिया

लाग पवित्र मानते है। इस महीने में औरते कार्तिक पुराण पढ़ती है। सारगगढ़ के गाँवों में गर्मियों के दिनों में औरते और पुरुष छमराई में साथ बैठ कर धार्मिक ग्रथ पढ़ते है और उन पर चर्चा करते है। इन अवसरों पर अकसर औरतों से ही पढ़ने

पढ़त ह आर उन पर चर्चा करत है। इन अवसरा पर अकसर आरता से हैं। की उम्मीद की जाती है। कई बार औरतें लिरिया भाषा में इनकी व्याख्या करती है। मओरा क्षेत्रवासी अन्य आदिवासियों की अपेक्षा ऊँचे माने जाते हैं।

द्रौपदी बाई ने एक कुम्हार शिक्षक से उड़िया सीखी थी। वे उड़िया की धार्मिक

किताबें पढ़ती है। हिन्दी मध्य प्रदेश की राजभाषा है, इसलिए उन्होंने हिंदी में दस्तखत करना सीख लिया है। धोवनीपली गाँव के पूर्व सरपच रामचंद्र पटेल (भारतीय जनता पार्टी) कहते है, 'द्रौपदी बाई दलगत राजनीति को नहीं मानती। किसी पार्टी से उसका रिश्ता नहीं है। वह कहती हैं कि राजनीतिक दल तो भिखमगो जैसे हैं। फूल छाप (भाजपाई) और पंजा छाप (कांग्रेसी) हमसे वोट की भीख माँगते हैं। हम उनको कैसे

मना कर सकते हैं!' उन्हें पार्टियों से मेल-मिलाप रख कर चलना होता है।

महेश अग्रवाल

पहले उनके पूर्वज हरियाणा से रायगढ़ के सरीया इलाके में आये थे। 1977 में महेश ने सरीया स्कूल से हायर सेकंडरी की परीक्षा पास की और कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गये। उनके पाँच भाई और तीन बहने है। उनके सभी भाई व्यापार करते हैं ओर बरगढ (उड़ीसा) में उनकी चावल मिल, लकड़ी मिल तथा दवा और मिठाई की दुकाने है। 1990 में महेश सरीया से सल्हीना आये और वहाँ उन्होंने परचून की दुकान खोली। 1986 में उन्होंने रायपुर की अग्रवाल लड़की से शादी की, जिससे उनके तीन बेटियाँ हैं। रायपुर की एक दलित (धासी) लड़की से उनके अवैध संबंध भी है। सल्होना में उन्होंने किशोर आदिवासी लड़की, बुदा बाई, को घरेलू काम के लिए रखा। जब उसे गर्भ ठहर गया, तो उन्होंने बिना शादी किये उसे दूसरी पत्नी बना कर रख लिया। बुदा बाई से भी उनके एक बेटी है।

42 वर्षीय महेश अग्रवाल कांग्रेस के इलाके में सिक्रय कार्यकर्ता है। करीब 80 वर्ष

महेश अग्रवाल पूरे इलाके में कुख्यात है। वे शराबी हैं और औरतो के पीछे भागते रहते हैं। वे अपनी दुकान नहीं चला पाये। उन्होंने बुंदा बाई को सरपंच बनवाना चाहा, ताकि उसकी आड मे वे पचायत के संसाधानों पर कब्जा कर सके। करीब 17 साल की बुंदा बाई ने सरपंच का चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गयीं। उसके बाद से ही महेश अग्रवाल पंचायत के कामकाज को प्रभावित करने के किसी अवसर की तलाश में थे। वे द्रौपदी बाई के काम में गलती ढूँढ़ने में लगे रहते थे। उन्होंने पचायत सदस्य शौकीलाल निषाद (भारतीय जनता पार्टी समर्थक) से दोस्ती गाँठी। उन्होंने

सदस्य शौकीलाल निषाद (भारतीय जनता पार्टी समर्थक) से दोस्ती गॉठी। उन्होंने अपने शक्तिशाली संपर्को से शौकीलाल को स्कूल के भवन के निर्माण का ठेका दिलाने में मदद भी की।

घटनाक्रम

सरीया प्रखंड के बीडीओं के अनुसार हर पंचायत को साल में चार चौपाले (ग्राम सभा) आयोजित करनी होती है। सल्हौना में चार चौपालें हो चुकी थीं। 19 नवबर 1995 को स्वर्गीय इदिरा गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए वैठक बुलायी गयी थी। बैठक करीब 12 बजे शुरू हुई। 70 से 100 लोगों ने इनमें भाग लिया। इनमें पंचायत की दो महिला सदस्य भी थीं। बैठक की शुरुआत इदिरा गांधी को श्रद्धांजिल देने से हुई। बाद में जनपद पंचायत सदस्य तुलसी पटेल ने विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा पढ़ा और महेश अग्रवाल ने सल्हौना पंचायत की अनेक समस्याएँ रखी। महेश ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और पंचायत के तालाब के बारे में सवाल उठाये। उन्होंने द्रौपदी बाई और पंचायत सचिव के खिलाफ कई शिकायतें कीं।

बैठक के बीच में ही वे लोग शराब ले आये और वही पीने लगे। महेश और उनके साथी पचायत के कार्यो के विवरण जानना चाहते थे। वे 20 अगस्त 1994 से 19 नवबर 1995 तक के आय-व्यय का विवरण और पचायत का रिजस्टर देखना चाहते थे। महेश अग्रवाल, शौकीलाल निषाद और उनके समर्थक नशे की हालत में ही बैठक में आये थे। उनकी माँगे और आरोप थे

- 1 ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता को हटाओ।
- 2 केंद्र पाठक और कुसुम पटेल का तबादला करो।
- 3 सरपंच (द्रौपदी बाई) ने जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति में तीस हजार रुपये की रिश्वत ली है।
 - 4. एक नये जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाये।
- 5. सरपच ने चार एकडवाला पुराना तालाब हर्दी गाँव के आशाराम सीदार को दस हजार रुपये में ही दस साल के लिए किराये पर दे दिया है। आशाराम पंचायत सिचव मनबोध सीदार का साला है और यह ठेका ग्राम सभा की सिफारिश के बिना ही दिया गया है। सल्हौना के रामरतन सीदार (अनुसूचित जनजाति) जैसे आवेदकों के सामने आने के बावजूद यह ठेका आशाराम को क्यों दिया गया है? नियमों के अनुसार सरपंच दस एकड़ से कम क्षेत्रफलवाले तालाव में मछली पकड़ने के लिए लीज ग्राम सभा की मजूरी के बाद ही दे सकता है। दस एकड़ से बड़े तालाब जनपद पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

महेश अग्रवाल, शौकीलाल निषाद और उनके समर्थक बड़े जोर-शार से यह कहते रहे कि अगर सरपच संतोषजनक जवाब नहीं दे सकतीं, तो वे इस्तीफा दे दें। शेष निर्वाचित सदस्य भी इस्तीफा दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बाबूलाल पटेल ने कहा, 'सरपंच से इस्तीफा मॉगने का हक गॉववालों को नहीं है।' भारतीय

जनता पार्टी के दो सदस्यों को छोड़ कर बाकी सभी ने अपने इस्तीफे सरपंच को सौप दिये। द्रौपदी बाई ने ये इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया। इससे महेश और उनके समर्थक नाराज हो गये। उन्होंने सरपच और सचिव को सभा स्थान से

जाने नहीं दिया। बाद मे सचिव को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे बीडीओ आर.एस. सिह, पचायत निरीक्षक ए. खाखलो और जिला पचायत के उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही को बुला लाये। वे लोग रात साढ़े दस बजे सल्हीना पहुँचे तब भी स्थिति

उतनी ही तनावपूर्ण थी। रजिस्टर लाने का बहाना बना कर मध्य रात्रि के करीब सचिव वहाँ से खिसक गये। कुछ देर बाद उपाध्यक्ष भी चले गये।

महेश अग्रवाल, शौकीलाल निषाद और उनके समर्थक अपनी माँग पर अडे रहे। करीब एक बजे रात को, जब द्रौपदी बाई ने भी वहाँ से जाने की कोशिश

रह। कराब एक बज रात का, जब द्रापदा बाइ न भा वहा स जान की काशिश की, महेश अग्रवाल और शौकीलाल निषाद ने उनका हाथ पकड़ कर खींचा। इस

खीचतान में उनकी साड़ी खुल गयी। यह सब बीडीओ और पंचायत निरीक्षक के सामने हुआ। बीडीओ ने पंचायत के सारे रजिस्टर जब्त कर तिये।

सामने हुआ। बीडीओं ने पंचायत के सारे रेजिस्टर जब्त कर तिथे। घटना के 48 घटे वाद 21 नवबर 1995 को द्रौपदी वाई ने जगुन्नाथ पाणिग्रही

की सलाह से सरीया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रायगढ कलक्टर के दफ्तर और वर्मकेला मे बीडीओ के दफ्तर

का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी बाई से रैली का नेतृत्व करने के लिए कहा। द्रौपदी ने भारतीय जनता पार्टी की रैली में हिस्सा लिया। भारतीय जनता

पार्टी आगामी लोक सभा चुनावों में इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी। पीडित महिला का नाम क्योंकि द्रौपदी है, इसलिए सल्हौना की घटना को

महाभारत में दुशासन और दुर्योधन द्वारा किये गये द्रौपदी के चीर हरण से जोड़ दिया गया। ऐसा आदिवासियों, हरिजनों और दिततों की धार्मिक भावनाएँ भड़काने के लिए किया गया। घटना के मुख्य आरोपियो महेश अग्रवाल (काग्रेस) और शौकीलाल (पहले भारतीय जनता पार्टी के और अब कांग्रेस के समर्थक) की तुलना दुर्योधन और दृशासन से की गयी।

सल्हौना ग्राम सभा को महाभारत की कुरु सभा का नाम दिया गया। 3 जनवरी 1996 को बिलासपुर के दैनिक भास्कर ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव और रायगढ़ के पूर्व सांसद नंदकुमार सहाय तथा जिला पचायत उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही का बयान छापा, जिसमे उन्होंने हिन्दू जन जागरण मच से आह्वान किया

था कि वे लोगों को उनके अधिकारा के बारे में जागरूक बनायें। सल्हीना से यशपुर नगर में लाटवोर तक एक ऐसी रैली की योजना बनायी गयी, जो पूरे रायगढ़ से हो कर गुजरे। धरधोड़ा, कुडुमकेला, धर्मजयगढ़, राजपुर, लेलुंगा, पथलगांव, लुडेग, कसबेला, महादेवदाड, बगीचा, दुलदुला, मनोरा, यशपुर नगर, डुलडुला कुनकुरी और

लाटबोर में 1 से 10 जनवरी 1996 तक जनसभाएँ करने की योजना भी बनायी शोपित वर्ग के लिए मायने : 191 गयी। इस पर वडे नबापाडा गाँव के रोहित कुमार सहाय ने, जो सारंगगढ के जिला प्रतिनिधि भी है, कहा, 'चूँकि सल्हौना गाँव मध्य प्रदेश काग्रेस अध्यक्ष परसराम भारद्वाज के लोक सभा चुनाव क्षेत्र में पडता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रग देना चाहती थी।'

दो : उपसरपंच की प्रताड़ना

गाँव के बारे में : कार्की गाँव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह जिला 1972 में पहली बार तब देश-विदेश मे चर्चित हुआ जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन मुख्य मंत्री प्रकाशचंद सेठी की मदद से कुख्यात डाकुओं मूरत सिह, मोनी राम सहाय, पूरन सिंह वगैरह को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया था। अपनी अद्वितीय वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मदिर भी इसी जिले मे है।

यह गाँव 1993 तक धिनोची ग्राम पचायत का हिस्सा था। 1994 में कार्की, गोचीपुरा, गोहरा और बमनेरा गाँवो को धिनोची पचायत से अलग किया गया और कार्की पंचायत गठित हुई। इस पंचायत क्षेत्र मे 315 मतदाता हैं। यह पंचायत बड़महलेरा जनपद विकास खड में पडती है।

गाँव मे चार मदिर है, जिनमें दो शिव के और एक-एक मंदिर हनुमान ओर देवी का है। शिव और देवी के मदिरों मे दिलतों समेत सभी जातियों के लोगों को आने-जाने की अनुमति है, पर हनुमान मदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकते है। गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पढ़नेवाले 40 छात्रों में से 15 पास के गोरहा गाँव के हैं। गाँव में दो सरकारी कुएँ हैं—एक दलितों के लिए और दूसरा ऊँची जातिवालों के लिए।

आबादी: कार्की गाँव में 73 घर है—45 पिछड़ी जातियों के, 26 अनुसूचित जाति के और दो अन्य जातियों के। गाँव में कुल मिला कर 400 लोग है। पिछड़ों में यादवों का बहुमत है। दलितों में सिर्फ चमार ही है। दूसरी जातियों में एक घर ब्राह्मण का और एक ठाकुरों का है। पिछड़ों में 30 घर यादव, चार-चार घर पाल और लोहार, तीन घर नाई, एक-एक घर नामदेव (दर्जी), कुम्हार, बढ़ई और धीमर (मछेरें) का है।

कृषि: गॉव मे खेती योग्य जमीन का रकबा 500 एकड़ है। सिर्फ तीन महीने (नवबर से जनवरी) तक ही पास के बॉध से सिंचाई हो पाती है। गॉव की भूमि उपजाऊ है। यहाँ गेहूँ, सोयाबीन, तिल, उडद और धान की खेती होती है। छोटे और मझोले किसानों मे एक-दूसरे के यहाँ जा कर मजदूरी करने का रिवाज यहाँ अब भी है। इस व्यवस्था में खेत पर काम करवानेवाला मजदूरी नहीं देता। बदलें में जरूरत पड़ने पर वह मजदूरी करनेवाले के यहाँ जा कर मजदूरी कर आता है।

भूमि का वितरण : कार्की गाँव के सभी 73 परिवारों के पास कुछ न कुछ मीन है। लेकिन गाँव में सबसे ज्यादा जमीन यादवों के पास है। आभाराम के पास ,0 एकड जमीन है और वे गाँव के सबसे बड़े भूमिपति हैं। उनके पास बहुत-से उधार पशु भी हैं, जिनका दूध वे पास के बड़महलेरा गाँव के चाय और मिठाईवालों के यहाँ बेचते हैं।

1994 का पंचायत चुनाव और मुख्य प्रतिदंदी

1994 के पचायत चुनाव में आशाराम यादव ने भरपच पद का चुनाव लड़ा था। उन्हें स्थानीय विधायक उमा यादव (कांग्रेस) का समर्थन हासिल था। उमा ने उन्हें अपनी विरादरी का होने के नाते समर्थन दिया था।

पास के गोचीपुरा गाँव के नोनेजु उर्फ दौलत सिंह (राजपूत) ने भी सरपच पद का चुनाव लडा था। उनके पास 60 एकड जमीन है। वे काग्रेसी नेता है। वे पहले दो वार धिनोची पचायत के सरपच रह चुके हैं। उनके और उनके चारों भाइयों के पास राइफले है। छतरपुर जिले के प्राय सभी समृद्ध अगड़े किसान राइफल रखते है। नोनेजु की दो बीवियों है और कहा जाता है कि अहीर, लोध, नाई और यादव जैसी पिछड़ी जातियों की कई महिलाओं से भी उनके संबंध है।

आशाराम यादव को कार्की गाँव में चमारों को छोड़ कर बाकी सभी का समर्थन हासिल था। चमारों ने नोनेजु को वोट दिया। आशाराम यादव 70 वोटों से हार गये। कार्की के यादव, ब्राह्मण और ठाकुर इस बात पर खासे नाराज हुए कि बड़ा गाँव होने पर भी उनका उम्मीदवार हार गया और छोटे गाँव के नोनेजु जीत गये। गाँव के एकमात्र ब्राह्मण परिवार के प्रमुख लित प्रसाद तिवारी को सभी जातियों के लोग गाँव का मुखिया मानते हैं। वे उम्र के पाँचवे दशक में हैं। गाँव के सभी लोग आपमी झगड़ों में तिवारी से फैसला करवाते हैं, इन मामलों को ले कर वे कभी-कभार ही पचायत में जाते हैं। सभी जातियों के लोग उनके फैसले का सम्मान करते हैं। उनके पिता भी गाँव के मुखिया थे। उनके चार भाई हैं, एक भाई बड़महलेरा प्रखंड विकास कार्यालय में ग्राम सहायक है। तिवारी ने पचायत के चुनाव में नोनेजु का सीधा विरोध नहीं किया। उपसरपंच पद के लिए उन्होंने सभी प्रभावशाली लोगों को हनुमान की मूर्ति के आगं शप्य दिलवायी थी कि वे माताटीन का विरोध नहीं करेंगे।

नोनेजु को मालूम था कि तिवारी ने पूरे कार्की गाँव को उनके खिलाफ बोट देने के लिए एकजुट किया है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनका कोई नजदीकी व्यक्ति ही उपसरपच बने। सो उन्होंने कार्की गाँव के ही सरमन अहीरवार को उपसरपच का चुनाव लड़ने के लिए चुना। अपने ही गाँव का उम्मीदवार खड़ा करने से द्सरे गाँववाले नाराज हो जाते, इसलिए उन्होंने यह सावधानी बरती। सरमन को नान का समर्थन हासिल था, इसलिए वे एक बोट से जीत गये। उन्हे छह और मातादीन

यादव को पाँच वोट मिले। गाँव के यादव और ब्राह्मण लड़के इससे बहुत नाराज हुए। वे अपने उम्मीदवार की हार का वदला लेना चाहते थे। इस क्षेत्र में जाति एक प्रमुख तत्व है और पार्टी का टिकट देने तथा राजनीतिक समर्थन हासिल करने में इसका खास तौर से खयाल रखा जाता है।

सरमन अहीरवार

सरमन अहीरवार 50 पार कर चुके हैं। वे चमार जाति के है। अपनी बिरादग्ने में उनका बहुत सम्मान है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। उनके पास 12 एकड़ जमीन है और कार्की गॉव में वे सबसे अधिक गाये रखनेवाले दिलत हैं। इससे पहले वे 15 वर्षों तक पंच रहे थे। वे कभी स्कूल नहीं गयं, पर जिला साक्षरता अभियान में भाग ले कर उन्होंने हस्ताक्षर करना सीख लिया है। सरमन अहीरवार कांग्रेस के समर्थक हैं, इमलिए नोनेजु सिंह से उनका अच्छा सबध है।

घटना का विवरण

पंचायत चुनाव के दो महीने बाद कार्की गाँव के चार नौजवान-दयाराम यादव, लक्ष्मण यादव, भगीरथ यादव और हरिचरण तिवारी--सरमन अहीरवार को गाँव क मुख्य चौराहे पर ने गये। उससरपंच अहीरवार का टोला गाँव से करीब एक किलोमीटर दूरी पर है। दयाराम मातादीन यादव का बेटा है जो उपसरपच के चुनाव में सरमन अहीरवार से हार गये थे। हरिचरण निवारी कार्की के मुखिया ललित प्रसाद तिवारी का भाई है। इन चारो ने एक डड़े से सरमन के दोनों हाथ बॉध दिये और उनके सिर पर गुड़ डाल दिया। थोड़ी देर में चीटियों ने सरमन को बुरी तरह काटना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्हे इस हालत में लगभग घटे भर तक गाँव मे घुमाया भी गया। असहाय और अपमानित सरमन को लगा कि उनका अंत पास आ गया है। उन्हें बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। बाद में एक बुजुर्ग ने डॉट-डपट कर नौजवानों को हटाया और सरमन को मुक्त किया। इसके बाद सरमन सरपच नोनेजु सिंह के पास पहुँचे। अगले दिन नोनेजु उन्हें ले कर बडमहलेरा थाने पहुँचे और प्राथमिकी दर्ज करायी। दोपी लोग पकडे गये। प्रशासन ने छतरपुर स्थित जिला उपन्यायाधीश की अदालत में मामला दायर किया। प्रशासन ने सरकारी वकील की सेवाऍ भी मुहैया करायी। नामजद अभियुक्तों ने वकील की फीस वगैरह पर 40 हजार रुपये खर्च किये।

कलक्टर ने हरिजन कल्याण विभाग के कोष से एक हजार रुपये का मुआवजा दिलवाया। लेकिन सरमन के हाथ में सिर्फ 800 रुपये ही आये। 200 रुपये अधिकारियों ने घूत में ले लिये।

सरमन अहीरवार के मॉग न करने पर भी कलक्टर ने उनकी सुरक्षा के लिए

नीन पुलिसवालों को तैनान कर दिया। ये लोग मददगार की जगह बोझ ही साबित हुए। ये तीनो ठाकुर, यादव और कुर्मी जातियों के थे। ये दो महीनों तक उनके घर में रहे और सुरक्षा प्रवान करने की जगह परेशानों का कारण बने रहे। पुलिसवालों ने रहने की अच्छी जगह और भोजन की मॉग की। सरमन ने उन पर दो हजार रुपयं खर्च किये। हर रोज वे सिपाहियों को ईधन, आटा और लकडियाँ देते थे। साथ ही, रोज पाव भर घी भी देते थे, जिसकी कीमत करीब 25 रुपये हैं। उनकी रोज-रोज की मॉगों से तग आ कर सरमन ने कलक्टर से उन्हें वापस बुला लेने के लिए कहा।

नोनेजु ने सोचा कि अगर विवाद जारी रहा तो उनकी लोकप्रियता और वोट घटेंगे। उन्होंने सरमन और अभियुक्तों के बीच मेल-मिलाप करा दिया। 12 अक्टूवर 1995 को यह करार हुआ और कोर्ट से मामला वापस ने लिया गया।

बुनियादी मुद्दे

अगर पिछडी जाति का उपसरपच अपने चुने जाने, काम करने और बचे रहने के लिए अगडी जाति के सरपच पर पूरी तरह आश्रित है, तो वह नयी पंचायती व्यवस्था में कैसे काम करेगा?

ग्राम पचायतों को अधिकार देने और औरतो तथा पिछडी जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने के बावजूद ऊँची जातिवालों का परपरागत दबदबा अब भी बरकरार है। गाँवों के मामलों में फैसले करने के समय ये समानातर व्यवस्था के रूप में काम करते हैं। गाँव के लोग अपने पारिवारिक या अन्य विवादों को ग्राम पंचायतों में ते जाने की जगह ऊँची जातियों के अगुआ लोगों के पास ही ले जाते हैं। निचले स्तर पर, मतदाताओं को अपने-अपने पक्ष में मोडने के लिए राष्ट्रीय पार्टियाँ भी जातीय विभाजन का उपयोग करती हैं। पचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चयन और उनके पक्ष में मतदान कराने में ऊँची जातियों (ब्राह्मण/ठाकुर) का प्रभाव कार्की गाँव में अभी भी जारी है।

तीन : दलित सदस्य की पिटाई

गाँव के बारे में : बर्बतपुर गाँव रायसेन जिले मे है। 1994 में चार गाँवों—खोआ, बोर्दा, साओतर और साओतर सोयासटी—को मिला कर वर्बतपुर पचायत का गठन हुआ। पहले ये सभी गाँव अब्दुलगज जनपद विकास मडल की चिकलोडकलाँ ग्राम पचायत में शामिल थे। चिकलोडकलाँ के सरपंच का पद आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। यहाँ बहु सख्या भी उन्हीं की है। लेकिन बर्बतपुर गाँव में ठाकुर बहुमत में हैं। उनके वाद चमारों और गोंडो का स्थान आता है।

परिवारों की संख्या : गाँव में कुल 96 परिवार है। कुल आबादी 1200 हैं।

इनमें से 52 परिवार अगड़ी जातियों के, 23 अनुसूचित जातियों के, 11 पिछड़ी जातियों के और 10 आदिवासियों के हैं। अगड़ी जातियों में ठाकुरों के 50 घर हैं और एक-एक घर ब्राझणों और देश बधुओं का है। हरिजनों में 20 घर जाटवों के और तीन घर भारोड़ों के हैं। पिछड़ों में चार घर कुशवाहों के, तीन घर विश्वकर्माओं के, तीन घर अहीरों के और एक-एक नाइयां और कुम्हारों का है।

भूमि का वितरण: गॉव में सबसे ज्यादा जमीन ठाकुरों के पास है। एक ठाकुर परिवार के पास तो 70 एकड़ जमीन है। गॉव के 33 हरिजन और आदिवासी परिवारा में से सिर्फ चार के पास जमीन है। ये लोग ठाकुरों के खेतों में काम करते है। गॉव के पास ही जगल है। करीब-करीब सभी हरिजन परिवारों ने जगलों की जमीन पर नाजायज ढग से कब्जा किया हुआ है, जिस पर वे खेती करते है।

फसर्लें: इस इलाके में मुख्यत गेहूँ, सोयाबीन, चना और धान पैदा होता है। तिचाई की कोई सुविधा नहीं है। खेतिहर मजदूरों को साल में मात्र दो या तीन महीने ही काम मिल पाता है। पुरुषों की दैनिक मजदूरी 25 रुपये और स्त्रियों की दैनिक मजदूरी 20 रुपये हैं और ये दोनों ही दरे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है।

शिक्षा : गाँव मे एक प्राथमिक विद्यालय है। 1988 मे बना इसका भवन बुरी

हालत में हैं। छत नहीं है और दीवारे भी टूट गयी हैं। छात्रों के लिए बेच तक नहीं है। वे खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठते हैं। भवन के अदर जाना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। बच्चे अपनी कक्षा के हिसाब से अधिक उम्र के हैं। स्कूल में 82 छात्र हैं और शिक्षक सिर्फ एक। जाति के हिसाब से छात्रों का बॅटवारा इस प्रकार है: ऊँची जातियाँ: 41, पिछड़ी जातियाँ: 13, दलित 23 और आदिवासी: 5। कुल 44 लड़के और 38 लड़कियाँ है।

घटनाक्रम

हो जाती है। दीयानी की रात जुआ खेलना तो रिवाज बन चुका है। 23 अक्टूबर 1995 को दीवाली की रात तीस पार के नौजवान धन सिह (वितत पच मनुलाल का भाई) और ठाकुर जाति के अर्जुन सिंह के बीच जुए के बाद लड़ाई हुई थी। धन सिंह ने गॅड़ासे से अर्जुन सिह पर वार किया। इससे वह बुरी तरह जख्नी हो गया। अर्जुन सिह ने चिकलोड़कलॉ पुलिस चौकी में इसकी शिकायत दर्ज करायी। घटना के बाद धन सिह जगल में भाग गया। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन

बर्बतपुर गाँव के ठाकुर और चमार जुआ खेलते है। कई बार खेल-खेल मे लडाई

वह पकड़ में नहीं आया। लेकिन यह मालूम हुआ कि धन सिंह का भाई मनुलाल जाटव उसे जगल में खाना पहुँचवाता है। धन सिंह के खिलाफ अब्दुलगंज थाने में फोजदारी का मामला दर्ज हुआ था जो आज भी लंबित पड़ा है। उसके पास चार

एकड नाजायज जमीन भी है।

धन सिंह गाँव में बहुत बदनाम था। कहा जाता है कि गाँव की अनेक लड़िकयाँ ओर विवाहित औरते उसकी हवस का शिकार हो चुकीं थीं। एक बार वह 14 साल

की एक ठाकुर लड़की (कालू बाई) को ले कर नागपुर भाग गया था। यह स्पष्ट

नहीं है कि वह लड़की को भगा ले गया या लड़की के बाप ने उसे बेच दिया था। लडकी की सगाई कही और हो गयी थी। उससे पहले फरवरी 1995 में उसका पिता

बाबूलाल सिंह अपने बड़ी बेटी सुनीता बाई को 10,000 रुपये में बेच चुका था। इस सींदे के पहले उसकी शादी करिया गाँव के गोपाल सिंह के साथ हो चुकी थी।

करिया गाँव करीब सौ किलोमीटर दूर है।

शादी के कुछ महीने बाद ही सुनीता मायके वापस आ गयी थी। उसके पिता ने उसकी दूसरी शादी करायी और पाँच हजार की रकम ली। सोना-चाँदी के रूप मे यह पैसा शादी के खर्च वगैरह के लिए दिया जाता है। कई बार लड़की के घरवाले

इस परंपरा का दुरुपयोग करते है। मायके आने के बाद जब सुनीता अपने पित के

घर वापस नहीं लौटी, तो गोपाल सिंह ने स्थानीय थाने में उसके गायब होने की रपट लिखवायी।

रायसेन जिले के कलक्टर डी एस राय ने साओतर सोसाइटी में 3 नवंबर 1995 को एक महिला जाग्रति शिविर लगाया। बर्बतपुर के पंच मनुलाल जाटव को भी इस

शिविर में बुलाया गया। वैठक दो बजे शुरू हुई। करीब 150 लोग इसमे शामिल हुए, जिनमें आधी औरते थी। जब कलक्टर ने पचायत की समस्याओं के बारे मे

पूछा तब अर्जुन सिंह ने उन्हे एक अर्जी दी कि धन सिंह ने मुझे मारा है। कलक्टर ने धन सिंह के बारे में पूछताछ की। थानेदार ने बताया कि धन सिंह का भाई मनुलाल तो बैठक मे ही है। तब कलक्टर ने मनुलाल से उसके भाई का अता-पता पूछा।

मनुलाल ने कहा, 'मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने अपने भाई का ठेका नहीं लिया है।' चिकलांडकलां के भाजपा कार्यकर्ता एस.एस. अहमद का कहना है कि मनुलाल का जवाब बहुत ही उजडु था। कलक्टर ने इसे दुर्व्यवहार माना। कहा जाता है कि

उसने दारोगा से कहा, 'मारो साले को।' कलक्टर के कहने पर पुलिस ने मनुलाल को निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया। मनुलाल की पिटाई तब जा कर रुकी जब चिकलोडकलाँ गाँव की जनपद सदस्य

शांति बाई ने कलक्टर को याद दिलाया कि मनुलाल पंचायत का निर्वाचित सदस्य है. और उसे न पीटने का अनुरोध किया।

पिटाई के कारण मनुलाल का दाहिना हाथ टूट गया, जिससे वह अपने राजमरें के काम-काज से भी लाचार हो गया। चिकलोड़कलाँ पुलिस चौकी के लोग उसे कहीं

बाहर नहीं जाने देते थे। चार दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद शिवराम सिंह चौहान को इस घटना की जानकारी मिली। वे मनुलाल को अब्दुलगंज थाने

शोषित वर्ग के लिए मायन : 197

में ले गये और प्राथमिकी दर्ज करायी। लेकिन कलक्टर का नाम आने से पुलिसवाले प्राथमिकी दर्ज करने में आना-कानी कर रहे थे। इसके बाद मनुलाल ने मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करायी।

मनुलाल काग्रेसी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के टिकट पर ही पंच का चुनाव जीता था। पिटाई और अपमान के बाद उनकी मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आगे आये, इसलिए वे अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो गये है। चिकलोडकलॉ गॉव के सुरेश कुशवाहा कहते है, 'भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को दलितों का सरक्षक दिखाने के लिए मनुलाल का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ दलित परपरागत रूप से काग्रेस के बोटर रहे हैं।'

मनुलाल की बीवी लबे समय से बीमार हैं। उनकी 17 साल की वेटी की शादी हो चुकी है। उनका बेटा सिर्फ 12 साल का है। वे कहते है कि उनकी आमदनी का और कोई जिरया नहीं है। कलक्टर से लड़ने की शिक्त भी उनमें नहीं है। बर्बतपुर के दिलतों का कहना है कि जिला, तहसील और प्रखंड कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी उन्हें परेशान करते है। जगल की जमीन का इस्तेमाल करने पर तहसीलदार जुर्माना लगाता है।

मानवाधिकार आयोग में मामला जाने के बाद कलक्टर ने वर्बतपुर और चिकलोडकलाँ गाँव के लोगों से कहा कि वे मनुलाल के पक्ष में गवाही न दे। इस मामले में कलक्टर के शामिल होने के कारण लोग काफी डरे हुए हैं। मनुलाल के पास दो एकड़ नाजायज जमीन है। उनके खिलाफ अब्दुलगंज थाने से पहले से ही दो मुकदमें दर्ज है। एक मुकदमा जमीन को ले कर है। दूसरा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का है। मनुलाल कहते हैं कि चिकलोडकलाँ चौकी के पुलिसवालों ने दो साल पहले इसी मामले में उनसे 250 रुपये ऐठ लिये थे।

चार : सरपंच के साथ सामूहिक बलात्कार

घटना का संक्षिप्त विवरण

समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की गुज्जरखंडी ग्राम पंचायत की पिछड़ी जाति की महिला सरपच कुसुम बाई के साथ 22 अगस्त 1994 की रात को उनके पित की उपस्थिति में चार लोगों ने बलात्कार किया। इन चारों लोगो—मानक, देवमन, नारायण और जगदीश—ने सरपच के पित घनश्याम को धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वे उसे मार डालेगे। बाद में उन्होंने इन दोनों को इस धमकी के साथ छोड़ दिया कि अगर मामले की रिपोर्ट थाने में लिखवायी तो बहुत बुरा होगा। कुसुम बाई ने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवायी। लेकिन इस घटना ने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया और दो दिन बाद 24 अगस्त 1994 को उन्होंने जहर खा लिया। सौभाग्य से वे बच गयीं। अस्पताल में अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस काड़ के बाद वे खुद को किसी के सामने जाने लायक नहीं

मानती थीं, इसीलिए उन्होने जहर खा लिया।

गाँव के बारे में : गुज्जरखेड़ी गाँव मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में है। यह जिला मुख्यालय खडवा से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचायत में तीन गाँव है--गुज्जरखेडी, निव्याखेडी, और जूनापानी। यह पुनासा जनपद पचायत का हिस्सा है। पुनासा मे

74 ग्राम पचायत और 24 वार्ड हैं।

गुज्जरखेडी ग्राम पंचायत में 249 घर है। इनमें से 157 घर गुज्जरखेड़ी गॉव

मे, 54 नेंदियाखेड़ी मे और 38 जूनापानी मे है। इन घरों का जाति/कबीले के आधार

पर विवरण इस प्रकार है : पिछड़े 126 घर (54.61 फीसदी), आदिवासी 64 घर

(25 70 फीसदी), दलित 37 घर (14 85 फीसदी) और अन्य 12 घर (4 81

फीसदी)। इस प्रकार गुज्जरखंडी में पिछडो का बहमत है। उनके बाद आदिवासियो

ओर दलितों का नंबर आता है। पिछडों में भी गुज्जरों का बहुमत है। उनके बाद

वजारों का नवर है। आदिवासियों में मुख्यत लोघ, कोर्क्, भील, नाहल और लोटा

है। पचायन क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन राजपूतो और गुज्जरों के पास है। गुज्जरखेडी

गॉव की आबादी 1200 है। इसमें 86 घर पिछड़ो के, 30 घर आदिवासियों के, 37

घर दिलतों के और चार घर दूसरी जातियों के है। 1994 के पंचायत चुनाव में

गुज्जरखंडी के सरपच का पद पिछडी जाति की महिला के लिए आरक्षित था।

खेती - विभिन्न जातियों के बीच जमीन का वितरण असमान है। दलितों और आदिवासियों के 67 परिवारों में से 49 भूमिहीन है। शेष 18 परिवारों के पास भी

एक या दो एकड़ से अधिक जमीन नहीं है। इसलिए दलित और आदिवासी परिवारी

के लोग खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करते है। कुछ का पूरा खर्च इसी से चलता हे, तो कुछ अपनी खेती के साथ-साथ मजदूरी करके गुजारा करते हैं। खेतिहर मजदूर को मात्र 20 रुपये दिहाड़ी दी जाती है, जो सरकार द्वारा तय

दर से काफी कम है। साल में बस चार महीने ही काम मिल पाता है। साल भर एक ही मालिक का काम करनेवाले मजदूरों (नौकरो) को साल मे चार हजार रुपये ओर रहने की जगह दी जाती है। 86 पिछड़े परिवारी में से पाँच परिवारी के पास

पॉच एकड़ से भी कम जमीन है। 10 से 15 परिवार ऐसे है जिनके पास 40-50 एकड जमीन है। यहाँ के पूर्व-मालगुजार राजपूत परिवार के पास 350 एकड से ज्यादा जमीन है। इस परिवार के पास एक ट्रैक्टर भी है। गाँव में कपास, गेहूँ, अरहर, मसूर

ओर चना पैदा होते है। अभीर किसानों के पास अपनी बोरिंग है और मुख्यत नलकूपी से ही सिचाई होती है।

शिक्षा : गाँव मे एक प्राथमिक और एक माध्यमिक स्कूल है, जिनमें 199 छात्र है।

1994 का पचायत चुनाव

1994 के पचायत चुनाव में पिछड़ी जानि की चार महिलाओं ने सरपच पद का चुनाव लड़ा था। दो महिलाए गुज्जरखेड़ी की थी, जब कि नदियाखेड़ी ओर जूनापानी की एक-एक महिला ने चुनाव लड़ा था। गुज्जरखेड़ी की कुसुम वाई ने चुनाव जीता। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक राणा रघुराज सिंह तोमर का समर्थन प्राप्त था।

कुसुम बाई

कुसुम वार्ड की उम्र 30 वर्ष से कुछ ही अधिक है। उनके परिवार के पास 25 एकड जमीन है। 15 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी हो गयी थी। उनके एक बेटा और एक बेटी है। कुसुम वार्ड अनपढ है, पर उन्होंने स्कूल मे पढ़ रही अपनी बेटी ने दस्तखत करना सीख लिया है।

सामाजिक परिटृश्य

आज भी निमाड़ क्षेत्र के गुज्जरों में वाल विवाह आम है। मॉ-वाप बच्चों के जन्म के समय ही उनका रिश्ता तय कर देते हैं। इसे सगाई कहते है। इसमें लडकेवाले कपड़े-गहने जैसी वस्तुएँ लड़की के यहाँ भेजते हैं। जब लड़की 14 या 15 वर्ष की हो जाती है तब शादी की जाती है। कई बार तो लड़की की शादी मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही कर दी जाती है। आम तौर पर लड़का और लड़की लगभग बराबर उम्र के होते है। गुज्जरों के रिवाज के अनुसार शादी के बाद कुछ महीने पति के घर रहने के बाद लड़की मायके लौटती है। शादी के शुरुआती वर्जी में दूल्हा-दुन्हन दोनों को कई समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है। लड़का इतना वड़ा नहीं होता कि वह दुनियादारी के मामले सुलझा सके। दूसरी ओर, कई बार लड़कियाँ मायके में रहते हुए किसी और मर्द से सपर्क बना लेती हैं, जो अकसर उनकी बिरादरी का या करीब का रिश्तेदार होता है। अनेक मामलो मे नजदीकी रिश्तेदार उनका शारीरिक शोषण भी करते है। यदि लड़की के ससुरालवालो को इस रिश्ते की भनक लग जाती है, तो वे उसे अपने वर नहीं ले जाते। कई वार तो ऐसी लड़की के मॉ-बाप ही उसे ससुराल नहीं जाने देते। वे उसकी दूसरी शादी करा देते हैं, जिसे 'नात्रा' कहा जाता है। रिवाज के अनुसार लड़की के मॉ-बाप दूल्हे के घरवालो से 'पैस-तोहफें' लेते हैं। बाज मामलों मे तो माँ-बाप अपनी बेटियो के आठ-आठ, नौ-नौ 'नात्रे' कराते हैं। अमीर गुज्जर मुखिया और नौजवान गरीब विवाहित लड़कियों का शारीरिक ओर मानसिक शोपण भी करते हैं। कई बार वे इन लडिकयों को ससुराल जाने ही नहीं देते। स्थानीय सरदार उनका नात्रा करा देते है और कुछ रकम दिला देते हैं। एक

200 : भारत में पंचायती राज

ही लड़की के लिए दो-दो, तीन-तीन लड़कों से रकम ले ली जाती है। यह पैसा वे लड़की के मॉ-बाप को भी नही देते। जिन परिवारों में पॉच-छह लड़कियाँ हों ओर खर्च चलाने लायक जमीन भी न हो, उन परिवारों के मुखिया नात्रा का उपयोग पेसा कमाने के लिए भी करते हैं। रकम कितनी होगी, यह लड़की के घरवाले और विरादरी

कं बड़े-बुजुर्ग तय करते हैं। नात्रा में कानूनी तलाक की जरूरत नहीं होती। कई बार तो लड़की पहली शादी से हुए बच्चे भी अपने साथ ले जाती है। इस तरह इलाके की गुज्जर औरतों का शोषण उनके समुरालवाले, घरवाले, रिश्तेदार और बिरादरीवाले सभी करते हैं।

को चाहता था। वह गुज्जरखेडी मे ही अपने मायकं मे रहती थी। पचायत चुनाव के दो महीने बाद बसंता बाई पास के पश्चिम निमाड़ जिले के सनाबाद गाँव में अपनी वडी बहन के यहाँ गयी। वहाँ से गोविंदा उसे भगा कर इंदौर ले गया। तीन दिन बाद उसकी माँ ने सनाबाद थाने मे रपट दर्ज करायी। दो महीने बाद वसता बाड सनाबाद लौट आयी। कुसुम बाई से बलात्कार करनेवाले नारायण डोडे, मानक पटेल, जगदीश साद और देवचन साद ने कुसुम बाई और उनके पति घनश्याम पटेल से

घटना

सरपच कुसुम बाई का भाई गोविंदा 17 वर्षीय विवाहित गुज्जर लडकी बसता बाई

कहा कि बसता बाई दो महीने तक गोविंदा के साथ रही है, उसके ससुरालवाले अब उसे मंजूर नही करेंगे; इसलिए गोविदा उसकी माँ को 15 हजार रुपये दे। साथ ही, गोविदा ने बसंता बाई के चाँदी के जो गहने बेच डाले है, उन्हें वह फिर से खरीद कर दे। कुसुम बाई इतनी रकम देने को नैयार नहीं थी। दोनों पक्षों ने अपनी जाति के सरदार और निमाइखेड़ी इलाके के सम्मानित कांग्रेसी नेता नारायण पटेल से

राय-मश्चिरा करने का फैसला किया।
22 अगस्त 1994 की सुबह तीन मोटरसाइकिलो पर सवार हो कर कुसुम बाई, उनके पति, मानक पटेल, नारायण डोडे, जगदीश साद और देवचन साद सनाबाद स्वान हो हो हो हो हो है कुसता बाई की माँ द्वार मनाबाद थाने में दायर शिकायत

रवाना हुए। वे चाहते थे कि बसता बाई की माँ द्वारा सनाबाद थाने में दायर शिकायत वापस ले ली जाये और कुसुम बाई द्वारा दी जानेवाली रकम का फैसला हो जाये। अपनी बिरादरी के बड़े नेता से बातचीत (क्या बात हुई, यह बताने को कोई भी तैयार नहीं है) के बाद रात 8.30 बजे सभी लोग गुज्जरखेडी रवाना हुए। नारायण

भा तयार नहां है) के बाद रात 8.30 बज सभा लाग गुज्जरखंडा रवाना हुए। नारायण डोडे और मानक पटेल नशे में थे। घनश्याम पटेल की मोटरसाइकिल पर उनकी पत्नी कुसुम बार्ड बैठी थी। अतुट गाँव के पास नारायण डोडे और मानक पटेल ने घनश्याम पटेल से मोटरसाइकिल रोकने को कहा। फिर चारों ने उनके सामने ही उनकी पत्नी

कुसुम बाई के साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को खबर की, तो उनकी हत्या कर दी जायेगी। नारायण डोडे कुसुम बाई का जीजा है

शोषित वर्ग के लिए मायने : 201

और मानक पटेल उनका चाचा। जगदीश और देवचन पडोसी है। ये सभी उनकी ही जाति के है। सरपच के चुनाव में कुसुम बार्ड ने गुज्जरखेड़ी गाँव की ही सधी बार्ड को हराया था। जगदीश राधी बार्ड का पित है और उसने इस बलात्कार द्वारा अपनी पत्नी की हार का बदला लिया। देवसन कुसुम वार्ड से नाराज था, क्योंकि उसका भाई ही उसकी भाँजी बसता बार्ड के साथ भागा था। मानक पटेल काग्रेसी नेता हैं और खंडवा जिला किसान कांग्रेस के सचिव हैं। वे खंडवा जिला परिषद की उपप्रमुख मारू बाई का भतीजा है।

घटना के दो दिन बाद मानक और नारायण ने फुसुम बाई के साथ वलात्कार की खबर सब जगह फैला दी। अपमान न सह पाने के कारण कुसुम बाई ने जहर खा कर आत्महत्या करने की कोशिश की, पर वे बच गयीं। उनकी हालत गभीर थी। पूर्व-सरपंच जैनेंद्र सिंह तोमर उन्हें ले कर पुनासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गये। डॉक्टरों ने उन्हें खंडवा ले जाने की सलाह दी। आत्महत्या की कोशिश के बारे में कुसुम बाई ने कहा, 'अपमान न सह सकने के कारण मैने जहर खाया।' घनश्याम ने पुरासा थाने मे मामला दर्ज कराया। नारायण, जगदीश और देवचन पकड़े गये। उन्हें दो महीने खडवा जेल में रखा गया। मुख्य अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया है। स्पष्ट है कि कुसुम बाई ने माँग के अनुसार 15 हजार रुपये देने से इनकार किया, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए यह सब किया गया।

बदली नहीं है तस्वीर

1946 में एशियन रिलेशंस कांफ्रेस में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए महात्मा गाधी ने कहा था, 'आप लोग दिल्ली को देख रहे हैं—यह भारत नहीं है। गॉवों में जाइए, वहीं भारत है। वहीं भारत की आत्मा निवास करती है।'

लेकिन आज भारत की आत्मा की क्या स्थिति है² वह आहत, दमित और तनावग्रस्त है।

हर ओर शोषण और गरीबी है, उत्पादन के साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, शक्तिशाली लोगों पर कोई अकुश नहीं है। सवर्णों के अधिकारों को चुनौती देनेवाला कोई नहीं है। लड़िकयों को सताया जा रहा है तथा शादी से पहले और बाद में उनका यौन शोपण होता है। इन सब चीजों ने भारत की आत्मा को रोद डाला है। नयी पंचायते और कुछ नहीं, बल्कि आज के गाँव में फैली हुई गंदगी ओर उसके सामाजिक जीवन में आयी गिरावट को ही प्रतिबिबित करती है।

यथास्थिति में किसी भी बदलाव का प्रतिरोध होता है और कई बार तो हिसक तरीकों से भी परहेज नहीं किया जाता। दलितों, आदिवासियों और औरतों के लिए आरक्षण को नियम के स्तर पर तो स्वीकार कर लिया जाता है, पर आचरण के स्तर पर नहीं। सारी चोट समाज के कमजोर वर्ग के हिस्से पड़नी है। पाँच दशक पहले डाँ. आबेडकर ने जो बाते कही थी, वे आज भी उतनी ही सही है। इस बीच बस इतना हुआ है कि सरकार ने सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ कानून बना कर हस्तक्षेप किया है। इस दिशा में नवीनतम कदम हैं संविधान का 78वाँ संशोधन और फिर राज्यो द्वारा तदनुरूप बनाये गये अधिनियम। मध्य प्रदेश

की पचायतों की घटनाएँ सामाजिक समर्थन की अनुपस्थिति में सरकारी हस्तक्षेप की सीमाओं और सभावनाओं के बारे में बताती हैं। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों और औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ एक स्पृहणीय आदर्श हैं। अनेक विधायी कदमों से सरकार ने समाज के

तौर-तरीको को बदलने की लगातार कोशिश की है, पर समाज सुधार, भूमि सुधार या शिक्षा जैसे किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक असरवाले बड़े बदलाव नहीं हुए है। यहाँ जिन जिलों से जड़ी घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है, उनमें साक्षरता

यहाँ जिन जिलों से जुड़ी घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है, उनमें साक्षरता का औसत स्तर मात्र 33 फीसदी है। औरतो मे साक्षरता की दर तो 11.5 फीसदी ही है। कानून की जरूरतो को पूरा करने के लिए लोग कठपुतली उम्मीदवार सामने

कर देते हैं, जब कि वास्तविक नियंत्रण मजबूत जातियों और जमीदारों के पास ही रहना है। जो वार्ड या पंचायत सीटें स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं, वहाँ मुख्य भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। कमजोर लोग संवैधानिक अधिकारों का फायदा उठा कर खुद को सक्षम बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस अध्ययन में दिये गये मामलों में, अपने अधिकारों का प्रयोग करने में अशक्त लोगों की असमर्थता ही सभी समस्याओं की जड़ है।

इन अध्ययनों से पता चलता है कि स्थानीय शासन में न तो सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों का सम्मान है और न ही मानवता का। इन दो अध्ययनों में महिलाओं से जुड़े मामलों में यह बात खास तौर से सामने आती है। निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तिहीन हे ओर निर्वाचित सदस्यों के सम्मान की रक्षा के लिए तैनात अधिकारी स्थानीय राजनीति ओर सत्ता के खेल में लिप्त। सभी मामलों में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं जो निजी और सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के सम्मान की धिज्जयों उडाती

इस निराशाजनक स्थिति में भी आशा की एकमात्र किरण यही है कि जो सभावनाएँ अभी तक परदे के पीछ ही छुपी थी, पचायत व्यवस्था ने उन्हें सामने ला दिया है। अब कुछ भी गोपनीय नहीं रह गया है। पचायत जोड़-तोड की राजनीति का अखाड़ा ही नहीं, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर खुली लड़ाई और उठा-पटक का लोकतांत्रिक मंच भी है। ऐसा मंच पहली बार मिला है और अब इसे सवैधानिक तथा कानूनी समर्थन भी है।

है।

ऐसे मे राजनीतिक पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। सर्वानुमति

शोषित वर्ग के लिए मायने : 203

(जिसका व्यावहारिक अर्थ ताकतवर की बात मान लेना ही था) की पुरानी व्यवस्था की जगह अव लोगों को यह हक मिला है कि वे पचायत के मामलों की पूरी जानकारी हासिल करें और जहाँ सटेह हो वहाँ सवाल उठाये। एक राजनीतिक पार्टी शोपण का समर्थन करती है, तो दूसरी पार्टी शोपित की मददगार बन जाती है। स्थानीय स्तर पर राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय विचारधारा का कोई खास महत्व नहीं है। वर्तमान स्थिति में तो जाति या परिवार की पुरानी तानाशाही प्रणाली को चुनौती दने के लिए पचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी ही सबसे कारगर चीज है।

मीडिया के फैलाव और संचार तकनीक की उन्नित ने गाँवों को तेजी से नयी दुनिया से जोड़ा है। दूर-दराज के गाँवों की घटनाएँ भी एकदम राज्य और देश के स्तर पर उठल जाती है। नयी पचायत व्यवस्था ने, अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद, गाँव को एक बृहत्तर सामाजिक दायरे में ला खड़ा किया है।

मध्य प्रदेश की इन चार घटनाओं के अध्ययन में ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही वातें साफ दिखाई दंती हैं। मध्य प्रदेश जातिवाद से ग्रस्त और पुरुष-सत्तात्मक पिछडा प्रदेश होते हुए भी जागरूक समाज है। हर पाँच साल बाद चुनाव होने से इन पिछडे इलाकों में बदलाव की यह प्रक्रिया तेज होगी, पर शोषण-चक्र की प्रक्रिया बदलने में वक्त लग सकता है।

(इस लेख के सह-लेखक रमेश सी नायक है।)

संदर्भ

- 1 पद्मायती राज एज द बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटी एन एक्स्प्लोरेशन इनटु दी प्रासीडिंग्स ऑफ द कास्टीट्रयुएंट असेबली, नयी दिल्ली, अवार्ड, 1992, पुष्ठ 24
- पायनियर, नयी दिल्ली, 30 नवबर 1995, साथ ही देखें, भारकर, बिलासपुर, 3 जनवरी 1996
- अग्रवाल बधुओं में से एक ने एक आदिवासी का मकान किराये पर लिया। वहाँ परचून की दुकान खोली। दो साल बाद उन आदिवासी को बहुत कम पैसे दे कर उसके घर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उस आदिवासी ने वेषट्टर जमीन पर एक और मकान बनाया।
- 4 'महिला सरपच के साथ वलात्कार? विधान सभा में भारी हगामा', स्वदेश, इदीर, 27 अगस्त 1994
- 5 'महिला सरपच के साथ दुष्कृत्य—आरोपियों पर सख्ती होगी। भाजपा द्वारा सरकार पर आरोपियो को बचाने का आरोप।' नई दुनिया, इदौर, 27 अगस्त, 1994
- 6 संविधान सभा में बहस के दौरान एल कृष्णस्वामी भारती द्वारा उद्धृत, 22 नववर 1948

पंचायतों के बगैर गुजरात

भूकप के बाद मीडिया मे जब चारो तरफ केंद्र, राज्य सरकार, सेना, नौकरशाही तथा गैरसरकारी स्वयंसेवी सस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासो की चर्चा हो रही थी, उस समय पंचायतो का कही जिक्र तक नही था। आज किसी को भी इसमे लेश मात्र भी सदेह नही है कि स्वयसेवी संस्थाओं तथा सेना के अलावा पीडित नागरिको को तत्काल सहायता मुहैया कराने में अन्य सभी संस्थाएँ पूरी तरह विफल रहीं। इस परिदृश्य से पंचायतें, खासकर ग्राम पंचायते, ओझल ही रही और इसका एकमात्र कारण राज्य सरकारो का राजनीतिक खेल है—राज्य के नेताओं का, विशेषकर सत्तारूढ राजनीतिक वल के नेताओं का। गुजरात में पंचायते यदि वास्तव में क्रियाशील और प्रभावकारी होतीं तो निस्सदेह इस गभीर आपदा के समय मे वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। अपनी जिम्मेदारी से बच कर चुपचाप बैठी नहीं होती।

कानून के मुताबिक गुजरात में 13,316 ग्राम पंचायतें, 210 तालुक पंचायतें तथा 25 जिला पंचायतें होनी चाहिए। सामान्य स्थिति में इन तीनो स्तरों पर कुल मिला कर लगभग एक लाख तीस हजार निर्वाचित पचायत सदस्य होने चाहिए। किंतु आज राज्य का प्रजातात्रिक ढाँचा एव स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था एक ऐसी इमारत है, जिसकी नीव ही नदारद है।

गुजरात में त्रिस्तरीय पचायतो का कार्यकाल मई-जून 2000 मे पूरा हो गया था। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा तथा पाँच वर्ष की यह अवधि पंचायत की प्रथम बैठक से आरभ होगी। नयी पंचायतो के गठन के लिए पाँच वर्ष की यह अवधि के पूरा होने से पूर्व ही चुनाव हो जाने चाहिए। किंतु सवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए और एक अनोखे तर्क का सहारा ले कर गुजरात सरकार ने केवल जिला एवं तालुक पंचायतों के चुनाव गत वर्ष (2000) सितंबर मे करवाये—वह भी सवैधानिक रूप से निश्चित

तिथि से छह माह के बाद।

जिला, तालुक एवं ग्राम पंचायतो को एक एकीकृत इकाई के रूप मे काय करना चाहिए। एक की भी अनुपस्थिति में दूसरा सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकता। मितंबर 2000 में केवल जिला एवं तालुक पंचायती के चुनाव करवा कर राज्य सरकार ने सविधान की आत्मा और शब्दो का हनन किया। उस समय कहा गया कि ग्राम पचायतो के स्थागित चुनाव दिसंबर में होगे। यह पहला आधात था। दूसरा आधात तब लगा जब सितंबर में ग्राम पचायतों के चुनावों को एक बार पुन स्थिगित कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि सूखे की स्थिति जारी रहने के कारण चुनाव करवाना सभव नहीं है। बड़ी ही आसानी से इस तथ्य की उपेक्षा कर दी गयी कि तीनो पचायतों के लिए मतदाता सूचियाँ एक ही थी। यदि कोई मतदाता सुखे के कारण ग्राम पंचायत के लिए मतदान नहीं कर सकता, तो वही मतदाता उसी परिस्थित में जिला एवं तालुक पचायत के लिए मतदान कैसे कर सकता था? स्पष्ट है कि गुजरात सरकार पंचायत चुनावों से बचना चाहती थी। गुजरात सरकार द्वारा केवल जिला एव तालुक पचायतों का चुनाव करवाने से आज ग्राम पचायतो पर छोटे अधिकारियों एवं क्लर्कों का वर्चस्य हो गया है। गुजरात की जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए कितनी वेताब थी, इसका पता जिला एव तालुक पचायत चुनावों के दौरान हुए भारी मतदान से लगाया जा सकता है। जिला पचायतो के लिए 78 51 प्रतिशत मतदान हुआ तथा तालुक पचायतों के लिए 73.39 प्रतिशत। मेहसाना जिले मे महिलाओ ने बढ़-चढ कर भाग लिया। ऐसी स्थिति में हम यह कैसे कह सकते हैं कि सुखे के कारण मतदाता चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते धंः

पूरा देश जानता है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव टालने का कारण सूखा नहीं, राजनीतिक स्वार्थ था। जिला एवं तालुक पचायतों में गुजरात के सत्तारूढ राजनीतिक दल को मुँह की खानी पड़ी थी और उसमें दुबारा जनता के सामने जाने की हिम्मत बाकी नहीं थी।

24 सितंबर 2000 को संपन्न हुए 210 तालुक पंचायतों तथा 25 में से 23 जिला पंचायतों के चुनावों में कांग्रंस दल को 22 जिला पंचायतों में जीत हासिल हुई (1995 में कांग्रेस केवल डॉग जिले में ही जीती थी)। अधिकाश तालुक पंचायतों में भी कांग्रेस ही छायी रही। छह तालुक पंचायतों में भाजपा एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। क्या यह गुजरात सरकार को उसकी अलोकतात्रिक कार्य पद्धित के लिए दंड नहीं था? अब समय आ गया है कि हमारे राजनेता यह जान लें कि

सरकार के तीसरे स्तर के चुनाव सत्तारूढ़ दल की इच्छा और मनमानी का इतजार

करते नहीं रह सकते। राज्य सरकारों को सविधान का पालन करना ही होगा। 6 नवबर को ग्राम पचायत चुनावों को मुलतवी करने के लिए गुजरात सरकार ने जब अध्यादेश जारी किया, तब हमने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री वेकैया नायडू को पत्र लिखा था कि गुजरात सरकार ने सूखा और लोकतत्र दोनों का ही मखौल उडाया है। क्या अमर्त्य सेन ने इसे एक स्वयसिद्ध सत्य नहीं बना दिया है कि सूखे

और अकाल की सबसे अच्छी दवा प्रजातंत्र है? वैसे भी, ग्राम पचायतें हर हाल में सूखा, भूकप अथवा ऐसी ही किसी आपटा से निबटने के लिए छोटे सरकारी कर्मचारियों से बेहतर हैं। कितु गुजरात की जनता से उनकी ग्राम पंचायते छीन ली गयी है।

ग्राम पचायते ही एक मात्र ऐसे प्रजातांत्रिक निकाय है, जहाँ एक आम ग्रामवासी की पहुँच है।

गुजरात में ग्राम पचायत चुनावो को स्थिगित करना वस्तुत गहराई से जड़े जमाये हुए एक ऐसी बीमारी का लक्षण है जिसने भारतीय राज्य की व्यवस्था को अरसे से जकड़ रखा है। तिहत्तरवे सविधान संशोधन से पूर्व बलवंतराय मेहता समिति

की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप ढली पचायतो की अनेक उपलब्धियाँ थी—बहुत हद तक सफलतापूर्वक चलाये गये परिवार नियोजन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, वन विकास, आवास स्थलो का आवटन, कमजोर वर्गो के लिए मकानो का निर्माण, सुखा

एव बाढ के दौरान किये गये सहायता कार्य तथा विकेदीकरण की दिशा में राज्य का प्रशसनीय रिकॉर्ड। यह सब उस समय हुआ, जब पडोसी राज्य महाराष्ट्र ने जिला

विकास एव योजना परिपदों का गठन किया, जिसमे जिला परिषदों की स्वायत्तता का हनन निहित था। लेकिन अदूरदर्शी राजनीतिज्ञो तथा नौकरशाही ने योजनाबद्ध

तरीके से पंचायतों को कमजोर करना शुरू कर दिया। ग्राम सभाएँ निष्क्रिय हो गर्यी, न्याय पचायते अक्रिय। पचायतो के पास नियामक शक्तियाँ नहीं थीं और थी भी तो बहुत ही मामूली। हाँ, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) और जिला

योजना बोर्ड जरूर गठित किये गये और इन्हें बेहद ताकतवर बना दिया गया। इन सस्थाओं मे कलक्टरो तथा अन्य सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व था। इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेज द्वारा किये गये एक अध्ययन में प्रवीन एन. शाह ने कहा है कि जमीनी स्तर की भागीदारी के केंद्र बिंदु के रूप में अथवा प्रजातात्रिक विकेदीकरण

के रूप में पंचायतों की आत्मा क्षीण हो चुकी थी। 1995 के बाद पंचायतों में गिरावट की गति तीव्र हो गयी, क्योंकि उसी समय

1995 के बाद पंचायता में गिराबंद का गांत तीव हा गया, क्यांक उसी समय से गुजरात की राजनीतिक संस्कृति में क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान (खाम) के स्थान पर उच्च जातियों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था।

पचायतों की बदनर होती स्थिति निम्न तथ्यों से स्पष्ट है : (1) संसद तथा विधान सभा सदस्यों का पंचायतों पर प्रभुत्व . प्रतिवर्ष विधान सभा सदस्य 20 लाख रुपये तथा संसद सदस्य दो करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत

रुपये तथा संसद सदस्य दो करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत कर मकते है; और (2) राज्य के विभागों के अंग के रूप मे पचायतों के कार्यों की सख्या कम करना तथा उन्हें सरकारी विभागों द्वारा संचालित प्रकल्पों को कार्यान्वित करनेवाली एजेंसी बना देना। (98 प्रतिशत व्यय इसी प्रकार के अनुवानों के पैसे से होता है), उन प्रकल्पों को, जो जनता एवं क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करते है,

कम करना। वैधानिक एव सामाजिक दायित्वा के निर्वाह के लिए पंचायतो को न तो प्रशासनिक सहयोग मिलता है, न ही उन्हें कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता दी जाती

हे जो स्व-शासन का अतरग हिस्सा है, विकेद्रित जिला योजना के प्रावधानो का ध्यान

नहीं रखा जाता; राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को पेश करने तथा उनके क्रियान्वयन में देरी की जाती है जब कि आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझाव भी आधे-अधूरे मन से

दिये जाते हैं। त्रिस्तरीय पचायतो को आवयविक रूप से जोड़ने तथा उन्हें सुझाय देने के उद्देश्य से गठित राज्य पचायत परिपद कुल मिला कर निष्क्रिय ही रही है। यद्यपि पचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को

गुजरात पंचायत अधिनियम, 1998 में शामिल कर दिया गया था, किंतु लाइसेस देने तथा लघु खनिजो वाली खटानो को लीज पर देने का अधिकार पंचायतों के पास

नहीं है। यही नहीं, ग्राम सभा के स्थान पर एक तालुक स्तरीय निकाय को सत्ता

का केंद्र बना दिया गया है। आज तक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पचायत निकायों के चुनाव नहीं हुए है।

राज्य के नेताओ एव नौकरशाहो का कहना है कि स्थानीय निकायो को सत्ता न सौपने का कारण यह है कि शहरी निकाय और खासकर पंचायत अक्षम, अयाग्य

तथा भ्रष्ट है। 26 जनवरी कां समूचे राज्य और जनता को हिला देनेवाली प्राकृतिक आपदा ने सपूर्ण विश्व को बता दिया है कि कौन अक्षम, अयोग्य और भ्रप्ट हे।

भूकप से 10 जिले गभीर रूप से प्रभावित हुए हैं—अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, सूरत एव बड़ोदरा। इन जिलों में कुल मिला कर 95 तालुक पंचायते हैं। ग्राम पंचायतों के विना तालुक एव जिला पंचायते जनता

के दुख-दर्द को कैसे मिटाये? उनके नुकसान की भरपाई के लिए क्या जतन करे? उन्हें कैसे सात्वना दे? ग्राम पंचायते तो अब छोटे अधिकारियो एव तलातियों के नियत्रण में काम कर रही हैं। यदि इन क्षेत्रों में निर्वाचित पंचायते होती तो निस्मदेह स्थिति कुछ और ही.होती। भूकप प्रभावित पंचायतों की मदद के लिए पडोसी और

निकटवर्ती पंचायते आ खड़ी होती। इस पंचायत संस्कृति को विकसित करने के लिए स्थानीय निकार्यों को मजवूत करना होगा। उन्हें संसाधन सौपने होगे। कर्मचारियां एव संरचनात्मक सुविधाओं से भरा-पूरा बनाना होगा।

सूरत का प्लेग मानव निर्मित आपदा थी। वह भयकर महामारी सूरत नगर निगम के अक्षम और निष्क्रिय प्रशासन की देन थी। यदि सूरत नगर निगम सक्षम, कार्यकुशल तथा जनता की जरूरतों की ओर उन्मुख होता तो प्लेग जैसी महामारी

को समय रहते फैलने से राक लिया जाता समय पर महामारी की चेतावनी दी जा

*

सकती थी। सूरत ने इस महामारी से सीखा जरूर, कितु वहुत बड़ी कीमत चुका कर। आज सूरत देश के सर्वाधिक साफ-स्वच्छ तथा सुप्रशासित नगरों में से एक है। दुर्भाग्यवश शेष गुजरात ने सूरत के अनुभव से कुछ नहीं सीखा।

अब यह सर्वमान्य है कि स्थानीय सरकार को जनता की समस्याओं को सही हम से हल करने योग्य बनाने के लिए इन चार चीजों का होना जरूरी है । (1) लीक सभा एव विधान सभा चुनावों की तर्ज पर स्थानीय निकायों के चुनाव निश्चित समय पर हों; (2) प्रजातात्रिक तरीके से निर्वाचित स्थानीय निकायों को कमजोर नहीं बनाना; (3) निर्वाचित सदस्यों को यह अधिकार हो कि वे नौकरशाहों को काम करने के लिए बाध्य कर सके, और (4) मजबूत विपक्ष की उपस्थित, जो सदन और समाज, दोनों में सरकार की कमियों की खिंचाई कर सके।

उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज यह कहा जा सकता है कि गुजरात—महात्या गांधी, बलवतराय मेहता, अशोक मेहता, जादवजी मोदी, जी.सी. पटेल, झीनाभाई दारजी, रिखरदास शाह, त्रिकमलाल पटेल तथा रलिसिह महीदा को जन्म देनेवाले गुजरात—ने हाल की प्राकृतिक आपदा के समय आम जनता के सामने अपने को अक्षम और निरुपाय पाया, तो इसका एकमात्र कारण था: सत्तारूढ़ दल भाजपा दारा स्थानीय लोकतंत्र की सतत उपेक्षा।

महाराष्ट्र का ग्राम सेवक राज

तुलजापुर तालुक के उस्मानावाद कस्बे से करीब तीस किलोमीटर दूर बसे तीर्ध के गाँव के करीब तीन सौ घरो की कुल आबादी 1,672 है। इसके बायजूद यहाँ सिफ सातवी कक्षा तक का एक प्राथमिक शिक्षा विद्यालय है और एक ही ऑगनवाडी है। पूरे गाँव के लिए सिर्फ हैंडपम्पवाला एक ही बोरवेल है। पीने के पानी का यही अकेला स्रोत है। गाँव में लगभग एक सौ पन्द्रह घर गरीबी रेखा के नीचे ऑके जा चुके

जहाँ तक पचायतों का सवाल है, महाराष्ट्र को काफी प्रगतिशील राज्य माना जाता है। लेकिन तीर्थ ग्राम पचायत का दौरा करने पर हमारी ऑखें खुल गर्या। इस पंचायत में सात सदस्य हैं। गाँव के सरपंच अनुसूचित जाति (मॉग) के काशीनाथ सिरसत है। उनकी आदत कम बोलने की है। उपसरपंच शोभा पठाड़े ऊँची जाति की है, बारहवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और काफी समझदार भी है। उनके पति भी

उन्हीं जैसे हैं। पूर्व महिला सरपच मंगल स्वामी भी अनुसूचित जाति की हैं। वे सातवी

हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 11 नवम्बर 1997 को इस गाँव का दौरा किया था।

कक्षा तक पढ़ी हैं। उन्होंने माना कि पहले पाँच साल के उनके कार्यकाल के शुरुआती साढ़े तीन साल में उनकी जगह उनके पति एव ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम

काशीराम, शाभा एव मगल सहित करीब 50 गाँववाले वहाँ के सामुदायिक कक्ष में बातचीत के लिए इकड़ा हुए थे। हमारी बातचीत गाँवों के लिए वित्तीय ससाधनो पर होने लगी। मैंने ग्राम पचायत के बजट के बारे में पूछा। सरपंच का जवाब था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानते और ग्राम सेवक ही हमें यह जानकारी दे सकते हैं। यह पूछने पर कि पिछले साल के आय-व्यय विवरण का क्या हुआ, उनका

जवाब था, वह भी ग्राम संवक के ही पास है। गाँव के बारे में उनके पास कोई दस्तावेज है? नहीं, ग्राम पचायत के सभी कागज-पत्र ग्राम सेवक के ही पास है। रिकॉर्डवाली अलमारी की चाबी वे अपने साथ ही ले जाते है। महाराष्ट्र में आम तौर

210 भारत में पचायती राज

सेवक ही सरपच का काम देखते थे।

पर ग्राम सेवक को छह से सात पंचायतें देखनी पड़ती है और गाँव के सभी संसाधन उसी के सुपुर्द रहते है। ग्राम पचायत के सारे कार्य ग्राम सेवक की मर्जी से ही होते है. उसके बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास चावी

ग्राम सेवक कैसा है? कायदे से उसे जन सेवा के प्रति असाधारण रूप से

का एक अतिरिक्त गुच्छा भी नहीं है, क्योंकि ग्राम सेवक की नजर में वे विश्वासपात्र नहीं है। तो यह है संशक्तीकरण!

किया गया तो सामुदायिक भवन में छायी चुप्पी को उन्होंने ही तोड़ा। ग्राम सेवक की जवाबदेही ग्राम पचायत के बजाय सिर्फ खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) तक सीमित है। मंगल जब सरपंच थीं तब तत्कालीन ग्राम सेवक ने गाँव से सात हजार रुपये कर के बतौर वसूला था और राज्यपाल के दौरे के मौके पर ग्राम पचायत की

प्रतिबद्ध होने के साथ ही साथ खासा ईमानदार भी होना चाहिए। मेरे इस सवाल पर वहाँ खामोशी छा गयी। मंगल स्वामी हॅसी। जब उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित

इमारत की पुताई पर एक हजार रुपये खर्च किये थे। दिलचस्प यह है कि महाराष्ट्र मे ग्राम सेवक बैक से पैसा भी सिर्फ अपने ही हस्ताक्षर से जब चाहे तब निकाल सकता है। इस मामले में भी ग्राम सेवक ने ग्राम पचायत को खाते दिखाने से मना कर दिया और जब उसकी शिकायत की गयी तो उसका तबादला कर औपचारिकता

पूरी कर दी गयी। पिछले साल नये ग्राम सेवक ने भी बैक से सोलह सौ रुपये निकाले थे। उसका भी कोई हिसाब-किताब अथवा उसके इस्तेमाल का ब्यौग पंचायत को नहीं दिया गया। जब यह मामला उजागर हुआ तो उस ग्राम सेवक का भी तबादला

कर दिया गया। यह भी कोई सजा हुई? नहीं। क्योंकि कथित दोषी ग्राम सेवक तबादलें के बाद दूसरे खंड विकास के अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में चला गया है, इसलिए अव तुलजापुर के बीडीओं के लिए उसे सजा देना संभव नहीं है। दिलचस्प तथ्य

यह भी है कि ग्राम सेवक ग्राम पचायतों के सदस्यों को पटाने में भी निपुण हैं। वे पचायत सदस्यों के घर जाते है और केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध रकम की उन्हें जानकारी देते हैं। फिर उनकी निजी अर्जियों को मजूर

कराने के लिए कुछ प्रतिशत दलाली तय कर लेते हैं। ग्राम पंचायत के अपेक्षाकृत सपन्न सदस्यों का समर्थन हासिल करके ग्राम सेवक अपने कार्यक्षेत्र में लोकप्रिय हो जाते हैं। इस मिलीभगत के कारण ग्राम पचायत और उसके ज्यादातर निर्वाचित सदस्य बेअसर हो जाते हैं। वैसे भी, गॉवों में चुनाव एवं लोकतंत्र तो महज सविधान द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ ही हैं।

तीर्थ गाँव के इस मामले को अपवाद मान कर मैंने राज्य के अन्य गाँवों की पचायतों के कामकाज का जायजा लेने का फैसला किया। मैं उस्मानाबाद कस्बे के 60 किलोमीटर के दायरे में बसे वाखरवाड़ी, तुगाँव, वदगाँव और यादशी ग्राम पंचायतों और लातूर जिले के चिंचौली एव रामवाडी ग्रामों की पंचायतों में भी गया। इन गाँवों

महाराष्ट्र का ग्राम सेवक राज : 211

मे मै जिससे भी मिला, लगभग सभी ने तीर्थ गाँव से मिलते-जुलते किस्से ही सुनाये—कही भी निर्वाचित प्रतिनिधियो या सरपचों अथवा तालुक एवं जिला स्तर पर निर्वाचित अध्यक्षो के हाथ मे सत्ता नही है। गाँववालो के साथ एक बैठक मे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि नजदीक के जिले मे उन्होंने देखा है कि जिला परिषद के मुख्य अधिकारी के सामने जिला परिषद अध्यक्ष को बैठने के लिए कुर्सी भी नही दी जाती और उन्हें खड़े-खड़े ही अपना काम करना पडता है।

जिले में सबसे ज्यादा पैसा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के तहन आता है। लातूर जैसे छोटे-से जिले मे चौदह लाख लोगों की ग्रामीण आबादी के लिए साल 2000-01 में कुल 2516.4 लाख रुपये (123.87 राज्य सरकार के कोष से आने बाकी हैं) आये थे। लेकिन डीआरडीए का नियत्रण किसके हाथ मे हैं? यह पालक मंत्री (जिले का प्रभारी मंत्री) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियत्रण में है। मंत्री महोदय सर्वोच्च सभा (आम सभा) के सभापति हैं और कार्य समिति के अध्यक्ष के नाते मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसकी वित्तीय एव प्रशासनिक देखरेख के प्रभारी है। केन्द्र सरकार के एक आदेश के मुताबिक जिला परिषद के अध्यक्ष उसकी संचालन समिति की अध्यक्षता औपचारिक प्रमुख के तौर पर करते हैं। संचालन समिति के अधिकतर सदस्य सबद्ध विभागों के अधिकारी हैं।

महाराष्ट्र में निचले स्तर पर नियोजन की अभी कोई परंपरा नहीं है और नियोजन का कार्य पचायतों के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। जिला नियोजन का कार्य जिला नियोजन एवं विकास परिषद के जिम्मे है, जिसके अध्यक्ष पालक मत्री है और उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिला कलक्टर की है। सविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक जिला योजना समितियों का गठन नहीं किया।

पंचायतो से संबंधित अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में पूछने पर लातूर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार तो चारों तरफ फैला हुआ है और उसमे हर कोई हिस्सेदार है। गांवों मे विकास गतिविधियाँ ठप रहने के लिए उन्होंने वहाँ के निर्वाचिन प्रतिनिधियों को दोषी ठहराया। उनका कहना था कि अपनी लोकप्रियता खोने के डर से निर्वाचित सरपंच एवं अन्य सदस्य लगान जमा करने आदि जैसे कडे फैसले लागू करने से बचते है और इसी वजह से विकास के लिए पैसो की कमी पड़ती है।

महाराष्ट्र में भी जातिचाद कटु सामाजिक यथार्थ है। अग्रणी जातियाँ हर कीमत पर पिछडी जातियों पर अपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहती हैं। लिहाजा जिन जिलो में यह अध्ययन किया गया, वहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होता दिखाई नहीं दिया। कई जिलों में चुनाव के दौरान अग्रणी जातियों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के आगे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होने की हिम्मत ही नही जुटा पाता। मिसाल के तौर पर पिछले पच्चीस सालों से लातूर जिले के रामवाड़ी गाँव मे चुनाव

के दौरान कोइ उम्मीदवार ही सामने नहीं आता था। वहाँ के मौजूदा सरपच एक अनपढ बुजुर्ग व्यक्ति हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि वहाँ के गाँववाले भी चुनाव मे कोई उम्मीदवार न होने को अपनी बड़ी भारी सफलता मानते है। इसकी मिसाल

काइ उन्तायकार के लक्ष जा जाका बड़ा कार्य संकलता मानत है। इसका मिसल मुझे एक रात करीब सौ गॉववालों की बैठक में देखने को मिली, जब उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव में काई उम्मीदवार न होने के कारण अपने गॉव पर गर्व है. क्योंकि

चुनाव से वहाँ की शांति एव सौहार्द में दरार पड़ सकती है। यहाँ सवाल यह उठता है कि शांति किसकी? किसका भाईचारा? निचली जातियों का तो कदापि नहीं। सदियों से अछत माने जानेवाले लोगों को अब भी अप्रत्यक्ष रूप से समाज से अलग-थलग

रखने की कोशिश वहाँ जारी है। गाँव में यदि दो बोरवेल लगाने की मजूरी मिलती है. तो उनमें से एक वहाँ के सबसे ताकतवर व्यक्ति के घर के पास लगेगा और

दूसरा मंदिर के पास। इससे दोनों ही नलों से निचली जाति के लोग पीने का साफ पानी नहीं भर पाते।

पानी नहीं भर पाते। ग्राम सेवकों से ले कर जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तक पचायतों का नियत्रण तीन स्तर पर होता है। संबद्ध विभाग ही सारे कामकाज करते हैं। उनकी

नियत्रण तीन स्तर पर होता है। संबद्ध विभाग ही सारे कामकाज करते हैं। उनकी मजूरी के लिए अकसर ग्राम सभाओ की बैठक भी नहीं बुलायी जाती और निर्वाचित प्रतिनिधियों का काम महज शिकायते सुनने, ज्ञापन लेने और प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित है। उन्हें प्रशासनिक फैसले करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके

पास कोई ससाधन भी नहीं है। उन्हें लगान और केंद्र द्वारा प्रायोजित इक्का-दुक्का योजनाओं से आनेवाली राशि से ही गुजारा करना पड़ता है। ग्राम पंचायत के स्तर पर लगान जमा करने के बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही जच्छा है, क्योंकि

पर लगान जमा करने के बार में जितना कम कहा जाये उतना हा अच्छा है, क्यांकि वहाँ यह भावना है कि समर्थ लोग भी बिना फायदे के लगान क्यों जमा करे?

यादशी ग्राम पंचायत की आबादी करीब दस हजार है और उसके सरपच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े और स्नातक डिग्रीधारी हेमंत विहल राव सास्ते है। पचायतों पर विभिन्न विभागो के नियत्रण के बारे मे सास्ते ने भी यही बातें कहीं। उनका कहना था कि उनके पास बहुत ही सीमित अधिकार है और हर एक काम

के लिए उन्हें खंड विकास अधिकारी या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की चिरोगी करनी पड़ती है। सरपच को सिर्फ पाँच सौ रुपये तक खर्च करने का अधिकार है और उसका अपना भला महज चार सौ रुपये मासिक है। उन्हें इस बात की जानकारी है कि सरकार ने ग्राम पंचायतों की समस्याओं की समीक्षा के

लिए एक समिति बनायी थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक तो कोई सुधार दिखाई नहीं देता। महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए यह दुर्माग्यपूर्ण है कि वहाँ अभी तक जिला ग्रामीण

महाराष्ट्र जस राज्य के लिए यह दुमान्यपूर्ण है कि वस जना तक त्यां प्राप्त है विकास अभिकरण को पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है, जब कि कई अन्य राज्य उसे पंचायतों से जोड चुके हैं। तातूर जिले की ही मिसाल लीजिए। यदि डीआरडीए के तहत सालाना मिलनेवाली 2640 34 लाख रुपये की राशि ग्राम सभाओं से न कर जिला परिपद तक की भागीदारी सुनिश्चित कर ईमानदारी से गॉववालो पर खर्च की जाये, तो औसतन पंद्रह सौ से दो हजार आबादीवाली पचायतों के अधिकार क्षेत्र को इससे कितना ज्यादा फायदा पहुँचेगा! पूरे तत्र पर अभी भी सासदों, विधायकों, कलक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का कब्जा होने के कारण गॉव अभी तक कई दशक पहले जैसे ही पिछड़े हुए है। एक महिला खेतिहर मजदूर की मजदूरी अभी तक पच्चीसतीस रुपये और पुरुष खेतिहर मजदूर की पैंतीस-चालीस रुपये प्रतिदिन हैं। इनमें से ज्यादातर जिलों में आधी से ज्यादा आबादी निरक्षर है। कई गाँवो में स्कूल भी नहीं है। एक महिला की आपबीती सुन कर काफी तकलीफ हुई, क्योंकि पढाई-लिखाई में तेज होने के बावजूद हाई स्कूल गाँव से बहुत दूर होने और वहाँ तक आने-जाने का कोई सुरक्षित साधन उपलब्ध न होने के कारण उनकी बेटी को पढ़ाई छोड़ कर घर बैठना पढ़ा है।

महाराष्ट्र की समस्या यह है कि राज्य अभी तक बलवतराय मेहता समिति की रिपोर्ट के खॉचे से उबर नहीं पाया है। सविधान के 73वें सशोधन की भावना के प्रति कहीं भी जागरूकता नहीं दिखती और अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट की तो वात ही जाने दीजिए जिसके तहत पंचायतों को स्वशासी संस्थाएँ बनाने पर जोर दिया गया था, न कि सिर्फ योजनाओं को कार्यान्वित करने की एजेंसियाँ।

महाराष्ट्र भी राजनैतिक नेतृत्व और नौकरशाही द्वारा सत्ता और लोकतत्र के सही मायनों में विकेद्रीकरण में कोताही की देशव्यापी प्रवृत्ति का शिकार है। यहाँ प्रोफेसर दाँतवाला का कथन याद आता है कि राजनैतिक नेतृत्व भले ही कितना दम भरे, मगर वह विकेद्रीकरण के विचार के खिलाफ हैं। इसकी एक वजह विपक्षी राजनैतिक ताकतो पर अकुश लगाये रखने की राजनैतिक मजबूरी भी है। कर्नाटक के स्वर्गीय अब्दुल नजीद साव ने भी बहुत सही कहा था कि नौकरशाही अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनके विभागीय अधिकारों में कटौती हो और ये अधिकार ऊपर से नीचे तक लोकतात्रिक फैसले करनेवाली सस्थाओं में बँट जाये जिनके बूते वे सस्थाएँ विभागीय योजनाओं को बदलने में सक्षम हों। महाराष्ट्र के सदर्भ में यह बात और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश में सबसे पहले वहीं पर, साठ के दशक की शुरुआत में ही, जिला परिषदों के तहत 'जिला सेवा' (तकनीकी एवं सामान्य) का गठन किया गया था। इसके जिरये राज्य सरकार ने पंचायतों के लिए अलग से कर्मचारी तंत्र विकसित करने का रास्ता दिखाया था, लेकिन वहाँ मौजूदा हालात इसके ठीक विपरीत हैं।

इसी के समानांतर देखें तो महाराष्ट्र मे सहकारिता का प्रबंध तंत्र एकदम उलट है। शक्कर सहकारी समितियों का नियत्रण वेतनभोगी कर्मचारियों के बजाय निर्वाचित काग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार को अब चेतना चाहिए और निर्वाचित पचायतों को असली अधिकार देने चाहिए। जिला परिषदों और पचायत समितियों के अध्यक्षे का कार्यकाल एक या दो साल तक घटाने, पचायत सदस्यों पर दो बच्चों की बिहश लगाने, कार्यक्रम, वित्त एवं पदाधिकारियों सहित अठारह विषय पचायतों को सौंपने आदि सबधित कागजी घोषणाओं को लागू न करने के गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। इन सब के अलावा यशवत ग्राम समृद्धि योजना के तहत पचायतों को राशि सीधे मुहैया कराने के प्रस्ताव को इस साल के शुरू में मंत्रियों द्वारा रोके जाने की खबर से और भी ज्यादा निराशा फैली है। इस योजना के तहत ग्राम स्तरीय परियोजनाओं को लागू करने के लिए सात सी पचास करोड़ रुपये की राशि सीधे ग्राम पचायतों को दी जानेवाली थी। महाराष्ट्र के लोगों में इन सब की चिताजनक प्रतिक्रिया पूरे देश को दिखाई दे रही है।

जहाँ तक पंचायती राज को मजबूत बनाने का सवाल है, निस्सदेह महाराष्ट्र के लोगों ने शिव सेना-भाजपा गठबंधन से इससे अधिक उम्मीद नहीं की थी। लेकिन काग्रेस-राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बनने से उम्मीदें काफी बढ गयी हैं। फिर भी, जमीनी हकीकत अधिक विश्वास नहीं जगाती। क्या वितासराव देशमुख और शरद पवार सुन रहे हैं? स। द्वीर के विष् में इट तर ज, पर

के हों में ख

त स

ì

नायडू को पंचायतें नहीं चाहिए

नवबर 2000 में विश्व बैंक के अध्यक्ष जेम्स डी. वुल्फुनसन ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया था। उस समय विश्व बैंक की एक टीम ने अपने एक नोट में इस राज्य के बारे में टिप्पणी की थी कि 'एन. चद्रबाबू नायडू देश के अग्रणी राज्य सुधारक है। स्थानीय ग्रामीण निकायों (पंचायतों) के आगामी चुनाव नायडू की लोकप्रियता सिद्ध करेगे। पचायत चुनावों का अक्तूबर में होना सुनिश्चित था, लेकिन बिजली क्षेत्र में सुधारों के राजनीतिक परिणामों को दृष्टि में रख कर नायडू ने सभवतः उन्हें मुलतवी कर दिया।'

इस कथन का सबसे ज्यादा परेशान करनेवाला पहलू यह है कि सविधान के भाग नी के तहत पचायतों को संवैधानिक निकायों का दर्जा प्राप्त हुए आठ वर्षों के बाद, आज भी, इन स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य के मुख्य मन्नी की मर्जी और सुविधा पर निर्भर हैं। विश्व बैंक के दल ने गत वर्ष नवंबर में होनेवाले पंचायत चुनावों के टाले जाने का जब जिक्र किया था तब उन्हें इस बात का संभवत. लंश मात्र भी अदाजा नहीं था कि तेलुगु देशम पार्टी ने उसके नी माह पूर्व फरवरी 2000 में जिला एव मडल परिषदों के चुनाव भी स्थगित कर दिये थे। कारण यही था, राजनीतिक स्वार्थ की चिंता।

पंचायत चुनाव स्थगित करने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के अजीबोगरीब तरीके रहे हैं, यद्यपि स्थानीय लोकतात्रिक निकायों का दम घोंटने के उनके पागलपन में एक तरह की तर्क-पद्धति दिखाई देती है। चूँिक राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है और संविधान के आदेश के लिए सम्मान नहीं है, इसलिए पंचायतों का गला घोटना उनके लिए आसान भी है। उन्होंने एक अध्यादेश द्वारा जिला एवं मंडल परिषदा को प्रशासकों के हवाले कर दिया और चुनावों से पीछा छुड़ा लिया, जब कि सविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस सबका कारण यह बताया गया कि आध्र प्रदेश विधान सभा ने केंद्र सरकार से सविधान की अनुच्छेद 243सी को संशोधित करने

जी अपीन की थी और इसीनिए जब तक ससद द्वारा इसे मंशोधित नहीं किया जाता, ज्य सरकार जिला एवं मडल परिषदों के चुनाव नहीं करवा सकती। पचायत चुनावों हो टालने का सबसे ज्यादा बेतुका बहाना सभवत और कोई नहीं हो सकता और रह भी तब, जब कि सविधान में पंचायतों का पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही चुनाव कराने का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है। उपर्युक्त अध्यादेश निरस्त होने के बाद सविधान का 87वाँ संशोधन ससद में पेश कर दिया गया, जिसका उद्देश्य था अनुच्छेद 243सी को सशोधित करना। ऐसा करने से पूर्व अन्य दलों या राज्य सस्थाओं से विचार-विभर्श भी नहीं किया गया।

सत्ता के गिलियारों में सिवधान से खेलते राजनेताओं के साथ-साथ इस देश में राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक भी रहते हैं, जिनके दिलों में अपने देश के सिवधान के लिए बेहद सम्मान है। ये देशवासी तेलुगु देशम दल की सरकार को कभी भी क्षमा नहीं करेगे। इनमें से कुछ ने सिवधान की आत्मा के हनन के लिए दोषी आंध्र प्रदेश सरकार के विरोध में जनिहत याचिकाएँ दायर कीं। जैसी कि उम्मीद थीं, उच्च न्यायालय ने देशवासियों की मदद के लिए जो जायज था, वहीं किया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 31 मई 2000 तक चुनाव कराने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने 'अपनी भूल नहीं सुधारेंगे' की जिद पर अमल करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय में भी राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी महमित की मुहर लगाते हुए 31 मार्च तक जिला एव मडल परिषदों के पचायत चुनाव कराने का आदेश दिया।

इसी दौरान ग्राम पंचायत चुनाव, अपने निर्धारित समय पर, अक्तूबर 2000 में सिर पर आ गये। इसलिए इस समस्या से जूझने की सबसे आसान राह थां सिवधान के अनुच्छेद 243डी(6) की मदद लेना। यह अनुच्छेद राज्य विधायिका को पंचायतों में सीटों एव पदों पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का 1993 से अब तक प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री अथवा सत्तारूढ़ दल ने अनुचित प्रयोग किया है। अपने फायदे के लिए। पंचायत चुनाव टालने के लिए। किसी भी राज्य में एक पिछड़ा हुआ नागरिक किसे कहेंगे? इस तरह के पिछड़े वर्गों की न जनगणना हुई है न ही इनकी पहचान का कोई एक सर्वसम्मत आधार है। वस्तुत. यह धारा भानमती का पिटारा है। चुनाव मुलतवी करने के लिए एक खूबसूरत बहाना। मेरे विचार से, ससद को इस धारा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा अनुच्छेद 243डी के खण्ड (6) को ही समाप्त कर देना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जब ससद तथा विधान सभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तब पद्मायतों के लिए यह जरूरी क्यों हो?

अदालतों मे दाखिल याचिकाओं से इस खंड के उपयोग तथा पदों के आरक्षण

के लिए अन्य पिछडे वर्गो की पहचान के तरीको पर प्रश्निविह लग जाता है। 1995 के पचायत चुनावो में आध्र प्रदेश पिछडा वर्ग विन्त निगम द्वारा 1981-87 में किये गये सर्वेक्षण को आधार मान कर लॉटरी प्रणाली से पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण किया गया। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि चूँकि लॉटरी प्रणाली एक अवैज्ञानिक तरीका है, इसलिए कोई तर्कपूर्ण विधि अपनायी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को मान लिया तथा पिछड़े वर्गो की जनसंख्या की वैज्ञानिक विधि से गणना करने का समय 31 मई तक निश्चित कर दिया।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: पिछले पाँच वर्षों से ये याचिकाकर्ता क्या कर रहे थे? यदि लॉटरी प्रणाली अवैज्ञानिक और अतार्किक थी, तो वे चुनाव की पूर्व-संध्या को ही क्यो जागे? पिछले अनेक वर्षों से 'ई-गवर्नेन्स' और 'स्मार्ट गवर्नेन्स' के दावे करनेवाली नायडू सरकार इस अवधि में क्या कर रही थी? सरल, नैतिक, जवाबदेह, सवेदनशील एवं पारदर्शी समझी जानेवाली यह सरकार इस मामले में क्यों निक्रिय थी? क्या यह बिना किसी राजनीतिक एजेंडा के सभव है? सबसे अधिक दुखदायी है वह जगह जो मुख्य मंत्री चद्रबाबू नायडू ने 'आध्र प्रदेश भविष्य का स्वप्न 2020' शीर्षक दस्तावेज मे पचायतो को दी है। 352 पृष्ठों के इस दस्तावेज मे पंचायती राज संस्थाओं को सिर्फ एक पैराग्राफ मे निपटा दिया गया है। स्पष्ट है कि तेलुगु देशम पार्टी ने 73वे एव 74वे संविधान सशोधनों में विहित विकेंद्रीकरण के सिद्धान्त को ठीक से समझा ही नहीं है। उसका कहना है कि 'पंचायती राज संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों के जिम्मेदार प्रबंधन के माध्यम से राज्य अपने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है।' (पृष्ठ 325)

क्षमा करें, मुख्य मत्री नायडू जी, आप पचायतो को सामुदायिक संगठनों के साथ नहीं जोड सकते। देश के सविधान ने पंचायतों को स्वशासन की सस्थाओं के रूप मे परिभापित किया है (अनुच्छेद 243जीं)। सभी सरकारी कामों के लिए पचायते देश में सरकार का तीसरा स्तर है। निस्सदिह चन्द्रबाबू नायडू की यह सोच तेलुगु देशम पार्टी की 1984 की विचारधारा के विपरीत है। 1984 में तेलुगु देशम पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया था कि वह देश की संधीय नीति में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित ऐसे जिला प्रशासन के लिए काम करेगी, जिसे संवैधानिक मान्यता हो, ताकि लोग स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक स्व-शासन हासिल कर सके, जो जिला नौकरशाही के अधीन नहीं, बल्कि उसके शीर्ष पर होगा और अंततः जिला सरकार को एक स्थायी संस्था बन जाना चाहिए। (पृष्ठ 14) तेलुगु देशम को निस्संदेह इसका श्रेय देना पड़ेगा कि अस्ती के दशक में इस दल ने आंध्र प्रदेश में स्थानीय शासन का अपना ही तरीका विकसित करने का प्रयास किया था। सबसे गरीब वर्ग के दरवाजे तक स्थानीय स्वशासन की सस्थाओं को ले जाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। यह कदम उसका अपना था—पश्चिम बंगाल अथवा कर्नाटक

ज अनुकरण नहीं। लेकिन खेद है कि एक वर्ष से भी अधिक समय से आज उसी लिग देशम के शासन में पचायतें प्रशासकों के चगुल में फँसी कराह रही हैं।

पचायती राज और विकेदीकरण के आग्रही सभी लोग आध्र प्रदेश की ओर रख रहे थे कि वहाँ की सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिला एवं मडल पंचायतों के चुनाव 31 मार्च तक संपन्न कराने के लिए क्या करती है। क्या किया आध्र प्रदेश की स्मार्ट सरकार ने—अपने चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की अध्यक्षता में (चन्द्रबाबू नायडू स्वयं को आंध्र प्रदेश लि. का सी.ई.ऑ. कहलाना पसंद करते हैं) र उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वे पूर्णतः निष्क्रिय बैठे रहे।

बहरहाल, सरकार चार महीने की नींद से जगी और सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर चुनाव करवाने में असमर्थता जाहिर करते हुए चुनावों को पुन मुलतवी करने की प्रार्थना की। 4 अप्रैल 2001 को सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई हुई तब उम्मीद की एक किरण जगी कि न्यायपालिका को धता बता कर राजनेता अपने निहित स्वार्थों के लिए जनतंत्र एवं जनतांत्रिक सस्थाओं को कुचल नहीं सकते।

वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. गागुली ने जब सर्वोच्च न्यायालय मे आध्र प्रदेश राज्य का पक्ष प्रस्तुत करते हुए दलील दी कि चुनावो के लिए और अधिक समय की माँग पिछड़े वर्गी के मतदाताओं की गणना करने संबंधी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को पूरा करने के लिए की गयी है, तो प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है कि राज्य किसी न किसी बहाने मार्च 2001 से चुनाव टाल रहा है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने जानना चाहा कि प्रशासन की स्थिति क्या है। बताया गया कि जिला परिषदों के दायित्वों का वहन करने के लिए विशेष अधिकारी के रूप मे जिलाधीशों की नियुक्ति की गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान स्थिति पर अपना असतोष जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को परे रख कर राजनीतिक दलीं द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रशासन चलाना न्यायालय को कदापि मान्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय देने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वकील ने एक दूसरी दलील रखी कि सीटो की पहचान के बाद आयोग को 40 दिन चाहिए, अतएव इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। कितु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार का आपसी मामला है और इस बारे मे जो भी किया जा सकता है, वह किया जाना चाहिए, किंतु चुनाव 31 जुलाई 2001 तक होने ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा सत्तारूढ़ दलों के लिए एक सामयिक चेतावनी है कि राज्य विधायिकाएँ पंचायतों के साथ गरीब सौतेले भाई जैसा व्यवहार न करें। पंचायत चुनावो की उपेक्षा न करे। पचायतों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का

नायडू को पंचायतें नहीं चाहिए : 219

साधन न वनायें। स्थानीय लोकतत्र के बीज को वृक्ष बनने से पहले ही न उखाड़ फेंके।

यह कैमी विडबना है कि तेलुगु देशम दल की 'परिकल्पना 2020' गाधी के इस कथन के साथ समाप्त होती है, 'कंद्र में बैठे 20 व्यक्तियो द्वारा सच्चा लोकतत्र स्थापित नहीं हो सकता। यह तो प्रत्येक ग्रामवासी के द्वारा ही संभव है।' लोकतंत्र की नींव अर्थात निर्वाचित पंचायतो के प्रति तेलुगु देशम की यह अश्रद्धा निस्संदह गंभीर चिता का विषय है। यद्यपि राज्य सरकार ने एक विशेष याचिका दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि मडल एव जिला परिषदों के चुनाव इस वर्ष जून में एवं ग्राम पचायतों के चुनाव जुलाई में संपन्न होंगे, राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों को संपन्न कराने का एक आखिरी मौका देने की प्रार्थना करने पर सर्वोच्च न्यायालय चुनाव प्रक्रिया को फिर स्थगित करने के विचार से नाखुश है, फिर भी उसने राज्य को 31 जुलाई 2001 तक पचायत चुनाव अवश्य कराने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि वह अब तारीख नहीं बढ़ायेगा। हो सकता है, इस बार समय पर चुनाव हो जायें, पर लोकतात्रिक रूप से निर्वाचित पंचायती राज सस्थाओं के प्रति तेलुगु देशम का समग्र रवैया गहरी चिंता का विषय है—इसलिए भी कि यही रवैया कई अन्य राज्यों मे भी देखने को मिल रहा है।

स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेताब कश्मीर

कश्मीर में स्थानीय लोकतत्र की चाहत देश के अन्य भागो में रहनेवाले अधिकाश लोगो के लिए अजीब बात लग सकती है, क्योंकि मीडिया द्वारा कश्मीर की जो भयावह छवि निर्मित की गयी है वह उग्रवाद एवं आतकवाद की है।

कंगन ब्लॉक कारगिल-लेह राजमार्ग पर श्रीनगर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इस दूरी को तय करने मे डेढ़ घटा लग जाता है, क्योंकि यह नाम मात्र का राजमार्ग है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध घोषणा के तुरत बाद मेने जव ब्लॉक का दौरा किया तो सरपंचो, नायब सरपचों और पचो के रूप मे चुने गये डेढ सी के करीब लोग बीडीओ के दफ्तर में इकड़ा हुए थे। हिमालय की गोद में बसा यह एक खूवसूरत गाँव है। श्रीनगर जिले के चार ब्लॉकों में से एक, कगन में हलका (ग्राम) पचायतों के चुनाव इस साल मार्च में हुए थे। अखाल पचायत के सरपच जलालुद्दीन शेख को आठ सी वोट मिले। अखाल में 1990 वाटर हैं, जिनमें में 1200 ने मार्च के चुनावों में अपने मताधिकारों का इस्तेमान किया। महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया। छह उम्मीदवारों में जलालुद्दीन चुने गये। क्या चुनावों के दौरान उम्मीदवारों को उग्रवादियों से धमिकयाँ मिल रही थीं? जवाब था, नहीं। क्या उग्रवादियों ने वोटरों को डराया-धमकाया? उत्तर फिर 'नहीं' में था। इस ब्लॉक में महिलाओ एवं पुरुषों की लबी कतारे थीं जो हलका पचायतों को चुनने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे।

क्या पंचायते सरकारी तौर पर गठित कर दी गयी है? नहीं, उग्रवादियों से मिली किसी धमकी की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की रेंगनेवाली रफ्तार के कारण पचायतें गटित नहीं हो पायी थी। सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना नहीं है। पचायतों की बैठक करने के लिए जगह भी नहीं है। हालाँकि अधिकारियों का कहना है कि 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी गयी थीं, लेकिन चुने गय सरपचों और पंचायत सदस्यों का एकमत से कहना है कि उन्हें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला

है। एक सरपच पूछता है, 'हमारे लिए बैठने की कोई जगह नहीं है, इसलिए पंचायत की बैठक कैसे वुलाये?' कगन ब्लॉक में पंचायतों के लिए 27 इमारतों की जरूत है, जब कि है केवल सात। जिस पंचायत भवन में हम मिले, वह अच्छा था, लेकिन उस पर ब्लॉक पदाधिकारियों ने कब्जा कर रखा है और चुनाव के छह महीने बाद भी इसे पंचायत को नहीं सौपा गया है।

इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू-कश्मीर सरकार जिन गाँवों में पंचायत घर नहीं है वहाँ पचायत घर बनाना चाहती हैं। इनमें से कई तो उग्रवाद के दौरान नष्ट हो गये थे, कुछ को 1990 के दशक के शुरू में ही उग्रवादियों ने आग लगा दी थी और कइयो पर सुरक्षा बलों का कब्जा है। पचायत भवनों का वर्तमान वजट पाँच लाख रुपये का है और फर्नीचर के लिए 25 हजार रुपये का बजट है। खाका तैयार है, बजट आवटित है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। लोग अधीर हो रहे है।

कगन मे बैठक के दौरान सामान्य वार्तालाप से बातचीत शुरू हुई, लेकिन धींगे-धीरे माहौल गरमाता गया। सरपचों और पंचो ने अपने कष्टों, समस्याओं और चिंताओं को ले कर शोर मचाना शुरू कर दिया। एक सरपच ने कहा, 'जब छह महीने पहले हम चुने गये थे तब हमें लोगों का समर्थन था। जैसे-जैसे बक्त बीतता जा रहा है, वे असमजस मे है। हममें से प्राय सभी दिहाड़ी मजदूर है। पास में एक पनबिजली परियोजना थी। परियोजना को बीच मे ही रोक दिया गया। उद्योग-धंधे नहीं है। मवेशी नहीं हैं, भेड़ें नहीं हैं। हमारे गॉवों में वुनियादी सुविधाएँ नहीं है। सडके नहीं है, पुल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, दवाखाना नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल नहीं है।' वह समस्याओ पर समस्याएँ गिनाये चला जा रहा था। जब अभी तक 'पंचायत प्रशासन' के नियम तय नहीं हुए हैं या चुने गये पदो की रिक्तियाँ नहीं भरी गयी है, तो हताश होना स्वाभाविक ही है।

जम्मू-कश्मीर में दिसंबर 2000 से मार्च 2001 के दौरान तीन चरणों में पंचायत चुनाव हुए थे। यह तो हारी हुई बाजी का मामला था। चुनावों के लिए सही समय तो 1996 के विधान मभा चुनावों के फौरन बाद का था। (जे एंड के पंचायत ऑन एजंडा, द हिन्दू, 30 अक्नूबर 1996)। लेकिन नेशनल कांफ्रेस और सरकार मामले को खींचती रही। छोटी-छोटी घटनाओं के कारण ये स्थिगित होते रहे। भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, करिगल संघर्ष और छत्ती सिहपुरा (दक्षिण कश्मीर) में सिखों की हत्या जैसी घटनाओं ने राज्य की पवित्र इच्छाओं को खत्म कर दिया और अततः जब चुनाव हुए, तो कश्मीर में स्थानीय लोकतंत्र की ललक दिखाई पडी। लहाख इलाके में चुनाव सामान्य थे। जम्मू में भी डोडा जिले के बनिलाल, वारवान और मरवाह ब्लॉकों की 10-15 पंचायतो को छोड़ कर पंचायत चुनावों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही (75 से 80 प्रतिशत वोट पडे)। कश्मीर डिवीजन

64 ब्लॉक पड़ते है, 1470 हलका पचायतें है और इनके लिए 1042 सरपच चुने ।ये। 10,458 सदस्यों (पंचों) में से 5155 चुने गये तथा शेष 5303 जगहे खाली डी रही। घाटी की स्थिति देखते हुए यह कोई कम बड़ी उपलब्धि नही थी। सदेश मध्द व जोरदार था। कश्मीरियों मे जमीनी लोकतंत्र की चाह है।

पंचायत का यह पहला चुनाव था. इससे पहले 1979 में चुनाव हुए थे। दिलचस्प गत यह थी कि पहली बार गुप्त मतदान के जरिये चुनाव हुए थे। 1979 में अतिम बार हुए चुनावों में हाथ खड़े करके चुनाव हुए थे। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 1996 के विधान सभा चुनावों में तत्कालीन हालात के चलते राज्य सरकार के कर्मचारियों ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इन पचायत चुनावों में सभी ने पूरे मन से भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष थे। ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। घाटी में कई स्थानों पर मैंने जिन चरिष्ठ अधिकारियों और गॉववालों से बातचीत की, उनके अनुसार इस बार शिकायत की कोई रिपोर्ट नहीं थी। खबरों के अनुसार चुनावों के दौरान और बाद में 14 उम्मीदवार मारे गये। गुलमर्ग में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक में मुझे बताया गया कि कृपवाडा और बारामूला जिलो में ही नौ व्यक्तियों की जान गयी। लेकिन जब मैने जॉच-पहताल की तो केवल तीन मामले ही चुनावी हिंसा के मिले। उग्रवादियों द्वारा मारे गये तीन व्यक्तियों में से एक अवामी लीग से सबधित था। उसने मुलगम पंचायत मे निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में 40 नामाकन पत्र जमा कराये, जिसके बाद उसे गोली मार दी गयी। बॉटीपुर ब्लॉक में नेशनल काफ्रेस के दो कार्यकर्ताओं की सरपच निर्वाचित होते ही सुरक्षा के बावजूट मार डाला गया।

निस्सदेह बहुत-से क्षेत्र ऐसे थे जिनमें उग्रवादी लोगों को डराने-धमकाने में सफल रहे। इन लोगों ने पचायत चुनावो को गभीरता से लिया था। संयोग से ड्यूटी पर तैनान एक भी सरकारी कर्मचारी को उग्रवादियों ने न तो धमकाया और न ही उसे चोट पहुँचायी।

अगर जम्मू-कश्मीर मे स्थानीय शासन की जीवंत प्रणाली होती, तो क्या स्थिति भिन्न होती? जिसमे भी मैने चर्चा की, उसका कहना था कि लोकतात्रिक तरीके से चुनी गयी स्थानीय सरकारों से काफी फर्क पड़ता। यह एक आवश्यक स्थिति थीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। अभाव और हताशा मुख्य कारण थें, जिन्होंने नौजवानों और बुजुर्गों को उग्रवादी मॉगों की ओर आकर्षित किया था। यदि मामुदायिक भागीदारी से लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान मे रख कर विकास होता तो उग्रवाद काफी हद तक रोका जा सकता था। जबरदस्त ठंड के कारण, घाटी में विकास कार्यों के लिए समय कम ही मिल पाता है। लोगों की लगातार शिकायत है कि सरकार इन्वास्तविकताओं को समझती नहीं है। चूंकि केंद्र के अधिकारी भी गंभीरता को नर्ह

समझतं, कश्मीर कुचक्र में फॅस कर रह गया है। आम तौर पर धारणा है कि दिल्ली की केद्रीय सरकार को कश्मीरियों के सोच का पता नहीं है। आर्थिक अभाववाले इस राज्य को पचायत चुनावों पर अपनी जेब से 14.5 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे, जब कि विशेप स्थिति होने के कारण यह राशि और जरूरी सुरक्षा कर्मचारी केद्रीय सरकार में आ सकते थे।

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में पचायती चुनावों को विफल करने की पूरी कोशिश की थी। वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि कश्मीर की जनता घाटी में किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले। हैरानी होती है कि 1996 या 1997 में पचायत चुनाव नहीं करा कर राज्य ने कीमती समय क्यों वरबाद कर दिया। उससे पाकिस्तान को ही नहीं, विल्क शेष विश्व को सही सदेश जाता। इसके विपरीत, ये चुनाव दिसंबर 2000 में पाकिस्तान में स्थानीय निकायों के पहले दौर के चुनावों के वाद हुए। नेशनल कांफ्रेस को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि पिछले पाँच वर्षों में उसने अनेक नाजुक संस्थानों को पटरी पर ला दिया है। गंभीर धमिकयों के बीच राज्य सरकार द्वारा जनगणना अभियान चलाना कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। लोगों के असाधारण उत्साह से हुए पंचायत चुनावों ने उग्रवादियों की कुछ हवा तो निकाल ही दी है।

अमेरिका पर हुए 11 सितम्बर के आतंकवादी हमलो और बाद के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हुए, कश्मीरियो को उम्मीद होने लगी है कि घाटी में उग्रवाद धीमा पड़ जायेगा। कुछ भी हो, हाल के दिनो में उग्रवादियों का निशाना नागरिक नहीं रहे हैं। क्या राज्य सरकार इस अद्भुत अवसर का फायदा उठायेगी? यही सवाल कश्मीर से सबद्ध और कश्मीरियों के कल्याण से जुड़े सभी लोगों के मन में उठ रहा है।

जम्मू-कश्मीर हाशियं पर धकेले जाने की दुखदायी हकीकत को झेल रहा है। केंद्र में जिम्मेदार लोग इस हकीकत को मानने को राजी नही हैं। कश्मीर और उसकी बहुआयामी समस्याओं को अकसर गलत समझा गया है और उनकी गलत व्याख्या की गयी है, जिससे ये लोग शेष भारत के लोगों से और कट गये है। उनके इस अलग-धलग पड़ने को रोकने का सबसे अच्छा तरीका विभिन्न स्तरों पर जीवत लोकतांत्रिक सस्थानों को बहाल करना है। राज्य सरकार को इन सस्थानों को मजबूत करने में सिक्रय भूमिका निभानी होगी। उग्रवाद व आतकवाद से निपटने की कोशिश में केंद्र को इन बुनियादी मुद्दों से गंभीरता से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्हें कश्मीरियों में विश्वास बहाल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। स्थानीय निकायों के चुनावों ने दर्शा दिया है कि अदरूनी और सीमा पार के उग्रवाद के कारण कश्मीरियों की भावनाओं को कम करके नहीं ऑका जा सकता।

निर्वाचित स्थानीय निकायों के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कगन के लोगों की जबर्दस्त भावनाएँ वास्तव में कश्मीर के सभी लोगों की भावनाओं का प्रतीक हैं, जिसका मैं स्वयं गवाह हूँ। शानदार पहाड़ियों से घिरे श्रीनगर की आंर झाइविंग करते हुए, मेरे मस्तिष्क में इकबाल के ये मंशहूर शब्द गूँज रहे थे - 'वह धरती जिसकी मिट्टी में चिनार की आग छिपी हुई है, कभी ठंडी नहीं हो सकती, न ही वह अपना स्वाभिमान छोड़ सकती है।'

था। की। और न के

में इट

वा

त्तर ज,

षर ारी

> के कों में

ख *ती* त

हिं स

र स रु

ì

पंचायती राज के दुश्मन

'पचायती राज संस्थाएँ अभी तक कई वजहों से टिकाऊ और जवाबदेह जन-निकाय का दर्जा और सम्मान हासिल नहीं कर पायी हैं। इन वजहों में नियमित चुनाव न होना, निरंतर दमन, कमजोर वर्गो—मसलन अनुसूचित जातियो-जनजातियों और स्त्रियो—का असंतोषजनक प्रतिनिधित्व, शक्तियो का अपर्याप्त विकेद्रीकरण और वित्तीय संसाधनों का अभाव आदि शामिल हैं...इन दिखाई पडनेवाली खामियों की वजह से यह समझ में आता है कि पचायती राज सस्थाओ को सुदृढता, सुनिश्चितता और निरंतरता प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ मूलभूत और आवश्यक तत्वो का समावेश करना निहायत जरूरी है।'

इन्हीं शब्दों के साथ तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जी. वेकटस्वामी ने सितबर 1991 में संसद में 72वॉ संविधान सशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। 22 और 23 दिसबर 1992 को लोक सभा और राज्य सभा ने इस विधेयक को 73वें सविधान सशोधन विधेयक के रूप में पारित कर दिया और बाद में कुछ महीनों के भीतर संविधान में पंचायतों के कुछ मूलभूत और अनिवार्य तत्वों का समावेश कर दिया गया।

क्या अब पचायते कुछ अलग है जब 73वें संविधान संशोधन विधेयक की सर्वसम्मत स्वीकृति अपने दसवें साल में दाखिल हो रही है? क्या वीते नौ वर्षों ने उन्हें सुदृढ़ता, निरंतरता और सुनिश्चितता प्रदान की है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देश भर के करीब 1500 निर्वाचित प्रतिनिधि 22-23 दिसबर 2001 को नयी दिल्ली में इकड्ठा हुए। एकाधिक वजहों से यह समागम अनूठा था। 73 वें सविधान सशोधन के वाद यह पहली बार था जब नागरिक समाज की पहल पर ऐसा अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह सिर्फ उत्सव मनाने का अवसर नहीं था, यह प्रशासन के तीसरे

स्तर के लिए संवैधानिक रूप से चुने गये सदस्यों के अनुभवों को साझा करने का

ग अवसर था और साथ ही हर एक राज्य की मोजूदा परिस्थितियों के मुताबिक रापने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का भी। प्रतिनिधियों ने पंचायतों को और री मजबूत बनाने और पटरी पर लाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा भी की।

हालॉकि नब्बे के दशक के प्रारभ से ही कुछ उपलब्धियों को ले कर वहाँ तकारात्मक स्वर थे। मगर जमीनी लोकतत्र के प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन का सामान्य रुख हताशा से भरा था। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास काम नहीं हैं, उनके पास काम करनेवाले नहीं हैं। संविधान ने पचायतों को स्वशासन की सस्थाओं का दर्जा दिया है, मगर वे इस आदर्श के कही भी आसपास नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ इस बात को ले कर भी आत्मनिरीक्षण हो रहा था कि इस निराशाजनक परिदुश्य के लिए कौन जिम्मेदार है। व्यवस्था? व्यवस्था के भीतर काम करनेवाले लोग? या, दोनों? देश भर में यह एहसास आम है कि कुछ शक्तियाँ है जो 73वे संविधान संशोधन के शब्दों और भावनाओं के साथ, प्रत्यक्षतः और परोक्षतः, छल त करने में लगी हुई है। निश्चय ही पंचायतों के संवैधानिक लक्ष्यो की ओर बढ़ने से जिन्हे कुछ गँवाना पड़ा हे, वे इनके दुश्मन हो जाते है। क्या केंद्र के और राज्य के स्तर के राजनीतिज्ञ कुछ शक्तियो और विशेषाधिकारों को-जो उनके पास थे और जिनका मजा वे अब तक ले रहे है-जीवत लोकतत्र, तेज विकास और जिला स्तर और उससे नीचे के कुशल प्रशासन के लिए छोड़ने को तैयार हैं? क्या अफसरशाही ग्राम स्तर पर जन प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता को तहेदिल से मान्यता दे सकती है और उनके मातहत काम कर सकती है? क्या यह हमारे समय की तल्ख सच्चाई नहीं है कि हमारे देश के सामाजिक ढाँचे में अभी भी सक्रिय सामती तत्व-जमींदार. सवर्ण-पचायती राज संस्थाओं के जरिये दिखनेवाले जनशक्ति के उभार के विरुद्ध अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? कहने की जरूरत नहीं कि पंचायतों के इन दुश्मनों से केंद्र सरकार और उसके विभिन्न मत्रालयों की मिलीभगत है।

पंचायती राज संस्थाओं के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता के बारे में बार-बार लिखा गया है। किसी न किसी बहाने चुनावों को टालना रूटीन बन चुका है। लगातार लड़ी जानेवाली कानूनी लडाइयों और नागरिको और सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेप के बाद अब जा कर सभी राज्यों में (झारखड़, अरुणाचल प्रदेश, और पांडिचेरी को छोड़ कर) चुनाव संपन्न हुए हैं। केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्य, जिन्होंने पचायतों को प्रशासन का तीसरा स्तर बताते हुए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बड़े कदम उठाये थे, अब पीछे हट रहे हैं। हमारे राजनैतिक नेता समुदाय में कुछ अजीब-सी बात है। जब वे विपक्ष में होते है तो स्थानीय निकायों की शक्तिवाँ सौंपने के बारे में बेहद स्पष्ट और मुखर होते है। मगर जैसे ही उन्हें सत्ता मिलती है, वे रंग बदर, लेते हैं। पंचायतों के लिए यह ऐसी वचनवीरता है जो वस्तुतः स्थानीय निकायों क

दुर्वल बनाना चाहती है। लोगी को अब ज्यादा से ज्यादा यह महसूस हो रहा है कि राजनैतिक दल और राजनेता पंचायतो और उन्हें शक्तिमान करने के लिए संवैधानिक आदेश के नाम पर सिर्फ घडियाली आँसू बहा रहे हैं। ज्यादातर राज्यों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करना (भाग नौ के वहाने) एक रूटीन हो गया है। कुछ उदाहरण देखते है।

अनुच्छेद 243जेडडी के तहत राज्य सरकारों को जिला नियोजन समितियों का गठन करना है, ताकि प्रत्येक जिले में गाँवो और शहरो की जरूरतों को जोड़ कर मिश्रित योजनाएँ तैयार की जा सकें और विकेंद्रीकृत नियोजन को बढावा मिल सके। नौ साल बीत गये हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा और गुजरात में भी इन समितियों का गठन होना बाकी है। कई राज्यों में जिला नियोजन समितियों के अध्यक्ष की कुर्सी पर राज्य सरकार के सदस्य काविज हैं, हालाँकि यह 73वे सविधान सशोधन की भावना के विरुद्ध है। मसलन, तमिलनाडु मे जिला नियोजन समितियों को कार्य आरंभ करने के सरकारी आदेश का जारी होना अभी बाकी है। पंचायतो को वित्त हस्तातरण के लिए गठित राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टे एक अन्य मामला है, जिसकी घोर उपेक्षा हो रही है। उन्हे राज्य सरकारे गंभीरता से लेतीं ही नहीं। फिर एक अन्य परेशान करनेवाली प्रवृत्ति पंचायतों की शक्तियों को सीमित करने के लिए समानातर निकायों का उदय है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले मे एक-दूसरे से होड ले रही है। आंध्र प्रदेश का जन्मभूमि कार्यक्रम, हरियाणा की ग्राम विकास समितियाँ, गुजरात की सयुक्त वन प्रवंधन समितियाँ, राजस्थान का वाटरशेड कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के जल उपभोक्ता समूह और परियोजना स्थल क्रियान्वयन समितियाँ, मध्य प्रदेश की जिला सरकार इसके कुछ उदाहरण है। यह मत्रियों, इन समानांतर निकायो में मनोनीत अन्य ताकतवर तत्वों और, सर्वोपरि, जिला कलक्टरों के हाथ मजबूत करने का राज्य सरकारों का खुला प्रयत्न है, जिसमें वे खासा पैसा बहा रही हैं। राजनैतिक दलों और राजनीतिज्ञ (केंद्र और राज्य दोनो के) स्पष्टतया पचायती राज के मुकाबले कलक्टर राज को तरजीह देते हैं।

कंद्र सरकार इन समानांतर सरचनाओं को मजबूत करने में ज्यादा पीछे नहीं है। मसलन, ग्रामीण विकास मत्रालय पचायतों को अँगूठा दिखाते हुए ग्रामीण विकास के लिए आबंदित हजारों करोड़ रुपये का इस्तेमाल करते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलेपमेंट एजेसी) को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अगर सिर्फ केंद्र सरकार और मत्रालय ने 73वें संशोधन को गंभीरता से लिया होता तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अब तक अतीत की चीज हो गये होते। इसके बजाय जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के प्रशासन को पेशेवर और मजबूत बनाने के नाम पर पंचायती राज संस्थाओं से अलग इसकी अलग पहचान बनाये रखने के लिए एक नयी पहल हो रही है। मंत्रालय की 2000-2001 की वार्षिक

रिपोर्ट बताती है कि उसका यह रुख कोई तात्कालिक कदम भर नहीं है। वह बनाती है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों 'पंचायतों से अलग' अपनी पहचान बनाये रखेंगी। इस कदम से मंत्रालय ने साफ तौर पर दांहरे शासन की व्यवस्था प्रस्तुत कर दी है। 'यह शब्दो और भावनाओं दोनों में सविधान के साथ खिलवाड से कम नहीं है और इससे विकेदीकरण की समूची योजना का नष्ट हो जाना तय है, जैसा कि पिछले पचास वर्षों में होता रहा है।'—यह संविधान समीक्षा समिति के समक्ष पेश की गयी एक रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है।

पचायती राज संस्थाओं को प्रभुत्वहीन बनानेवाला जो सबसे नुकसानदेह कदम केंद्र सरकार और ससद ने उठाया है, वह है स्थानीय विकास के लिए प्रतिवर्ध 1580 करांड़ रुपयं सांसदों के अधीन करना। जिम्मेदार नागरिक इस तथ्य से बहुत सुब्ध है कि सांसद क्षेत्रीय विकास योजना में पचायतों और नगर निगमों के निरीक्षण से परे सासदों को क्षेत्रीय विकास की योजनाएँ चलाने का अधिकार दे कर न सिर्फ सिवधान के 78वे और 74वे सशोधन के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के केंद्र और ससद के नैतिक अधिकार के नाथ समझौता किया गया है, बल्कि नौकरशाही के तंत्र को मजबूत भी किया गया है। सविधान समीक्षा समिति के समक्ष रखे गये एक अन्य दस्तावेज के मुताविक 'अनुच्छंद 243जी के तहत स्वशासन की जिन संस्थाओं को उन्होंने खुद जन्म दिया, यह उनके शीलहरण सरीखा है।' एक अन्य स्तर पर पचायतों में होनेवाले लोकतात्रिक चुनावों के प्रति केंद्र के शासक दल ने बहुत कम सम्मान प्रदर्शित किया है। गुजरात में भाजपा के मुख्य मंत्री ने अपने निर्देश पर चलने को तैयार पचायतों के लिए एक लाख रुपये तक के पारितोषिक देने की घाषणा करते हुए और सर्वसहमति पर जोर देते हुए निर्वाचन मडल को सीधे-सीधे रिश्वत देना चाहा है। मगर गुजरात के लोगों ने पिछलग्यू लोकतत्र के इस सिद्धांत को अर्खाकार कर दिया है –90 प्रतिशत से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जम कर चुनावी मुकाबले हुए।

जहाँ हर कोई पंचायत के सदस्यों और अध्यक्षों पर यह कहते हुए उँगली उठा रहा है कि वे अक्षम, अकुशल और श्रष्ट हैं, कोई यह नहीं समझ रहा कि अतत तो वे उसी तत्र के पुर्जे हैं जो अक्षमता, अकुशलता और श्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। उनके लिए 73वें सशोधन के पारित होने से पहले के ही चार दशकों में उच्चतर स्तरों पर चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा बनाये गये रोल मॉडल हैं कि किस तरह चुनाव लड़े जाते हैं, किस तरह विकास योजनाओं के संदर्भ में दफ्तरशाही के साथ मिलीभगत की जाती है और किस तरह अगले चुनाव के लिए साधन जुटाये जाते है। जॉन ड्रेज के एक अध्ययन के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में किसी सरपंच की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न विकास योजनाओं, मसलन जवाहर रोजगार योजना. इंदिरा आवास योजना आदि का निरीक्षण करने की होती है। कई मामलों में इन योजनाओं के साथ सार्वजनिक साधनों की लूट का एक सगठित तंत्र जुड़ा हुआ है, जिसमें सरपंच को विकास का

कुछ पैसा विभिन्न अधिकारियो ग्राम सेवक से ले कर जूनियर इ गीनियर, प्रखड विकास अधिकारी और कतार के विभिन्न पायदानो पर खडे लोगों तक —के बीच 'पुनर्वितरित' होता है। अकसर सभी के हिस्से पहले से ही नियत होते हैं। नीरजा गोपाल जयाल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 'विभिन्न अधिकारियो और प्रतिनिधियों को दिया जानेवाला प्रतिशत तय होता है. कमीशन की रकम पचायत की बैठक में खुले आम घोषित की जाती है और शायद ही कभी इसका विरोध होता हो।'

इन हालात के लिए किसे दोष दिया जाये? पंचायतों को, उनके प्रतिनिधियों को या तत्र को? केंद्र और राज्य सरकार के राजनीतिज्ञ, सभी स्तरों के अधिकारी, उच्च जातियों के नेता, समृद्ध और ताकतवर और निहित स्वार्थी तत्व खुश ही होंगे, अगर पंचायती राज नाम के इस शिशु की हत्या हो जाये।

मगर पचायतें तो रहेंगी। जो पंचायतो को 'स्वशासन की सस्थाएँ' घोषित

करनेवाले सविधान संशोधन को नष्ट करने पर तुले हैं, उन्हें वह पत्र पढ लेना चाहिए जो प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 अप्रैल 2001 को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री चंद्रबाबू नायडू को लिखा था, 'आप याद करे कि सविधान के खंड नौ के रूप में शामिल सविधान (73वें सशोधन) विधेयक के पारित हो जाने के साथ ही पंचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा हासिल हो चुका है। इस संघीय ढॉचे में पचायतो की परिकल्पना शासन के तीसरे स्तर के रूप में की गयी है...इस बीच आनेवाले वर्षों मे पचायती राज के प्रतिनिधियों और कुल मिला कर ग्राम समुदाय के क्षमता विकास का काम प्रमुखता पर रहना है। मै यह भी ध्यानं दिलाऊँ कि समानांतर मंरचनाएँ (जो पचायती राज संस्थाओं को हाशिये पर ले जाती हैं) गठित नहीं की जानी चाहिए!

क्या राजनैतिक नेता, सरकारें और विभिन्न स्तरो पर उनके कर्ता-धर्ता और साथ ही स्थानीय दबंग लोग सुन रहे हैं?



धा। ही। हीर न के वा में इट

त्तर

ज, पर परी

के की में खबी तं छ

ल

इस "फ

री शी

75

ग से





संप्रदायीकरण - केरल राज्य में अंतर्विरोध र 1890-1980। वे 1981-82 में शिकागों वि दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र में और 19 विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। विश्वविद्यालय में काम करने के लिए यृत्ति प्रदान की गयी। उन्होंने 1968 से एशि अमेरिका तथा पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप में ध राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतत्र एव मान

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनो तथा परिसवा

की और परचे पढे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने प उनके शोध कार्य का विषय या धर्मनिर

राज्य ओर समाज के सुधी अध्येता डॉ अध्ययन और लेख राष्ट्रीय दैनिकों, पत्रिकार मे प्रकाशित होते हैं। हिंदी तथा अन्य भारत् भी उनके काम का अनुवाद प्रकाशित हो चुका कृतियाँ है कम्यूनल रोड टु अ मेक्यूलर केरात राज : फ्रॉम लेजिस्लेशन टु मूवमेट। उनके कृतियाँ है : डिग्निटी टु ऑल : एस्सेज इन डेमोक्रेसी, पचायती राज इन कर्नाटका टुडे डाइमेंशन्स, पंचायती राज इन जम्मू एड कश

इंडिया, 2000। डॉ मैथ्यू इंस्टीट्यूट ऑफ मोशल साइ के संस्थापक-निदेशक हैं। नागरिक अधिकार वे सक्रिय रहे हैं। सप्रति उनके शोध और अ विषय है भारत में स्थानीय शासन प्रणाली, फ

ऑफ पचायती राज इन द स्टेट्स एड यूनियन

तृणमूल स्तरीय लोकतत्रः वे अनेक सामाणि विभिन्न हैसियतों में सबद्ध हैं